राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

खंड:11] दसवीं विधान सभा के ग्यारहवें सत्र का बीसवां दिवस [संख्या:13

शनिवार;

25 जुलाई, 1998

राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री समर्थलाल मीणा, अध्यक्ष, पदासीन)

सूचना प्राप्ति प्रश्न

सदन के कार्य का विन्यास

श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम) : हाथ जोड़कर निवेदन है हमारा तो, राजस्थान के इस पद पर ....(व्यवधान) आप बिराजे हो। कल का दिन तो स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा।

श्री खेतसिंह राठौड़ (शेरगढ़) : अध्यक्ष महोदय, मैं एक निवेदन करना चाहता हूं। आपकी अध्यक्षता में 20 तारीख को बिजनस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग हुई थी और हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बिजनस एडवाइजरी कमेटी में क्या-क्या आगे विषय लिये जाने वाले हैं, वे यहां सुनाएं जाएंगे और माननीय सदस्यों को भेजे जाएंगे। लेकिन आज 25 तारीख हो गयी है, बिजनस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग को इतने दिन हो गये हैं, पहले ऐसा कभी नहीं हुआ कि बिजनस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग के 5-5 दिन बाद भी आपकी क्या कार्य-सूची रहेगी, यह नहीं निकालें। आज मेहरबानी करके, इनको हिदायत दीजिए कि ये आज की आज ही बतलाएं कि आगे कब तक ये असैम्बली चलाना चाहते हैं, उसमें क्या-क्या विषय लाना चाहते हैं, कौन-कौन से बिल लाना चाहते हैं ताकि माननीय सदस्य उसी हिसाब से अपना प्रोग्राम बनाएं।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक) : माननीय अध्यक्ष महोदय, ये बिल्स सर्कुलेट होने वाले थे, वे नहीं हो सके। इसलिए आज वे सर्कुलेट हो जाएंगे और आज बिजनस एडवाइजरी कमेटी की रिपोर्ट भी प्रस्तुत कर दी जाएगी।

श्री रामस्वरूप मीणा : हमारे प्रश्नों का उत्तर नहीं आ रहा है। न 295 के आ रहे हैं, न ध्यान आकर्षण प्रस्ताव के आ रहे हैं। (व्यवधान) कृपया इन उत्तरों को तो मंगवा दें डिपार्टमेंट्स से, साहब।

श्री अध्यक्ष : कृपया, माननीय सदस्य, सदन का श्रीगणेश अध्यक्ष करता है, आप नहीं कर सकते हैं, बिराजिए।

(2)

श्री रामस्वरूप मीणा : ठीक है, साहब ।

श्री अध्यक्ष : मुझे माननीय सदस्यों को यह निवेदन करना है कि आज जलदाय विभाग, जिसका राजस्थान के जन-जीवन से सम्बन्ध है उस पर चर्चा है । दूसरा, मुखबन्द भी है । दोनों ही महत्वपूर्ण विषय हैं जो सदन को पास करने हैं । इसलिए यह जो स्थगन प्रस्ताव, प्रक्रिया के नियम 295 हैं, पढ़े हुए माने जाएं । याचिकाओं का उपस्थापन मैं करवा दूंगा । इसके अलावा दो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव और हैं, वह भी हम कोशिश करेंगे नैक्स्ट टर्न में लेने की । तो यह ढाई-तीन घन्टे का समय सदन का बच जाएगा । इससे जलदाय विभाग पर विस्तृत चर्चा हो जाएगी और सरकार की ओर से भी जवाब आ जाएगा । यह मेरा माननीय सदस्यों से निवेदन है ।

श्री रामस्वरूप मीणा : अवसर तो सभी को दे देना, साहब ।

श्री बृजेन्द्र सिंह सूपा (बयाना) : अवसर तो दे दीजिएगा बोलने का ।

श्री अध्यक्ष : सबको अवसर देने के लिए ही समय बचाया है । पर इसमें से आप समय कम मत करिये । बिराजिए, बिराजिए आप । याचिकाओं का उपस्थापन । श्री भीमराज भाटी ।

याचिकाओं का उपस्थापन

श्री भीमराज भाटी (पाली) : अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नांकित 2 याचिकाएं उपस्थापित करता हूं ।

पाली के ग्राम गाजनगढ़ से बल्दों की ढाणी तक अधूरे सड़क निर्माण कार्य को पूरा करना

(1) जिला पाली के ग्राम गाजनगढ़ से बल्दों की ढाणी तक अधूरे सड़क निर्माण कार्य को पूरा कराने बाबत, चार व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित, एवं

पाली के ग्राम सज्जनपुरा में घरेलू विद्युत कनेक्शन दिलवाने हेतु

(2) जिला पाली के ग्राम सज्जनपुरा में घरेलू विद्युत कनेक्शन दिलवाने बाबत, 4 व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित । धन्यवाद ।

श्री अध्यक्ष : श्री कमल कोली ।

श्री कमल (हिण्डौन) : अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नांकित 3 याचिकाएं उपस्थापित करता हूं :—

करौली के हिण्डौन में नये रोडवेज बस स्टैण्ड का निर्माण

(1) करौली जिले के हिण्डौन शहर में नये रोडवेज बस स्टैण्ड का निर्माण कराने बाबत चार व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित,

करौली के हिण्डौन में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान या बहुतकनीकी महाविद्यालय खोलने बाबत

(2) करौली जिले के हिण्डौन शहर में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान या बहुतकनीकी महाविद्यालय खोलने बाबत 3 व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित, एवं

(श्री कमल)

करौली के हिण्डौन में स्टेट हाइवे संख्या 22 पर रेलवे स्टेशन के निकट ओवर ब्रिज बनवाने बाबत

(3) करौली जिले के हिण्डौन शहर में स्टेट हाइवे संख्या 22 पर रेलवे स्टेशन के निकट ओवर ब्रिज निर्माण करने बाबत तीन व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्न स्थगन प्रस्ताव की सूचना प्राप्त हुई है:—

श्रीमती यशोदत्ता एवं 14 अन्य सदस्य, विधान सभा की ओर से राज्य में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़े वर्ग के रोस्टर प्रणाली की जारी संशोधित सूची से इस वर्ग के व्यक्तियों की पदोन्नति प्रभावित होने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्ताव की विषय वस्तु पर कल सामाजिक सुरक्षा व कल्याण विभाग की मांग पर काफी चर्चा हो चुकी है, अतः इस पर अनुमति देने में असमर्थ हूं।

नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाएं

(1) श्री बृजेन्द्र सिंह सूपा, सदस्य, विधान सभा की ओर से आवासन मण्डल की मानसरोवर कालोनी में विधायकों को आवंटित कतिपय निवासों के पीछे चरपेटा बनाकर अनुचित तरीके से दुकानें बना देने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(2) श्री आर.पी.शर्मा, सदस्य, विधान सभा की ओर से विधान सभा क्षेत्र भरतपुर की कतिपय सड़कों की हालत जीर्ण-शीर्ण होने के सम्बन्ध में।

(3) श्री मगराज चौधरी, सदस्य, विधान सभा की ओर से राजकीय अस्पताल, जालोर में चिकित्सकों के समय पर नहीं आने, अस्पताल में नहीं बैठने एवं सफाई की वहां समुचित व्यवस्था नहीं होने के सम्बन्ध में।

(4) श्रीमती कमला, सदस्य, विधान सभा की ओर से जिला जयपुर के विराट नगर को पर्यटन स्थल घोषित नहीं करने से क्षेत्रवासियों में व्याप्त भारी रोष के सम्बन्ध में।

(5) श्री राकेश मेघवाल, सदस्य, विधान सभा की ओर से नागौर जिले के गच्छीपुरा की बाका पट्टी जल योजना को स्वीकृत करने के सम्बन्ध में।

(6) श्री रामगोपाल बैरवा, सदस्य, विधान सभा की ओर से विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा में वर्ल्ड बैंक योजना के अन्तर्गत स्वीकृत सड़कों का निर्माण कार्य लम्बे समय से बन्द होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(श्री अध्यक्ष)

(7) श्री रिछपाल सिंह, सदस्य, विधान सभा की ओर से राजस्थानी भाषा को संविधान की आठवीं सूची में सम्मिलित कर मान्यता प्रदान करवाये जाने के सम्बन्ध में।

(8) श्री महादेव सिंह, सदस्य, विधान सभा की ओर से खण्डेला उप तहसील को तहसील में क्रमोन्नत करने के सम्बन्ध में।

(9) श्री अर्जुनलाल जीनगर, सदस्य विधान सभा की ओर से विधान सभा क्षेत्र गंगरार की कतिपय सड़कों का डामरीकरण करवाये जाने के सम्बन्ध में।

(10) श्री बद्रीप्रसाद गुरुजी, सदस्य, विधान सभा की ओर से माण्डलगढ़ नगर पालिका से कतिपय गांवों को निकालकर उनमें पंचायत समिति बनाने के सम्बन्ध में।

(11) श्री राधेश्याम गंगानगर, सदस्य, विधान सभा की ओर से श्रीगंगानगर शहर में आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु धनराशि स्वीकृत करने के सम्बन्ध में।

(12) श्री हीरालाल इन्दोरा, सदस्य, विधान सभा की ओर से गंगानगर जिले के सीमावर्ती क्षेत्र में हदबन्दी में आयी भूमि का किसानों को मुआवजा दिलवाये जाने के सम्बन्ध में।

(13) श्री शम्भूदयाल बड़गूजर, सदस्य, विधान सभा की ओर से राजकीय चिकित्सालय, केकड़ी को 100 रोगी शय्याओं में क्रमोन्नत करने के सम्बन्ध में।

(14) श्री नाथूराम आहूरी, सदस्य, विधान सभा की ओर से डूंगरपुर जिले में प्रशिक्षित अध्यापकों को जिला परिषद में रोजगार उपलब्ध करवाने के सम्बन्ध में।

(15) श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास, सदस्य, विधान सभा की ओर से जनगणना विभाग में छंटनीशुदा महिला कर्मचारियों को कनिष्ठ लिपिक के पद पर तदर्थ नियुक्ति देने के सम्बन्ध में।

(16) श्री बनवारीलाल बैरवा, सदस्य, विधान सभा की ओर से तहसील टोडारायसिंह के ग्राम खरेड़ा की चरागाह भूमि पर कतिपय व्यक्तियों द्वारा अतिक्रमण कर लिये जाने के सम्बन्ध में।

(17) श्री शंकरलाल अहारी, सदस्य, विधान सभा की ओर से डूंगरपुर जिले के पिथापुर व पालिसोड़ा ग्राम में सड़क नहीं होने के सम्बन्ध में।

(18) श्री गोपीराम जाट, सदस्य, विधान सभा की ओर से कृषि उपज मण्डी समिति द्वारा निर्मित की गयी सड़कों का रखरखाव नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(श्री अध्यक्ष)

(19) श्रीमती मीना अग्रवाल, सदस्य, विधान सभा की ओर से अलवर शहर में सड़कों की हालत खराब होने के सम्बन्ध में।

(20) डा. शंकर भानुदा सदस्य, विधान सभा की ओर से जिला चित्तौड़गढ़ की नगर पालिका बड़ी सादड़ी के अध्यक्ष पद के लिए हुए उप चुनाव कथित निष्पक्ष ढंग से नहीं होने के सम्बन्ध में।

(21) श्री शैलेन्द्र जोशी, सदस्य, विधान सभा की ओर से मुस्लिम शिक्षण संस्थाओं में नियुक्त अध्यापिकाओं पर हो रहे कथित शोषण की रोकथाम के सम्बन्ध में।

(22) श्री जगदीप धनखड़, सदस्य, विधान सभा की ओर से जाट जाति को राज्य में अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण देने के सम्बन्ध में।

माननीय सदस्यों द्वारा दी गयी सूचना पढ़ी हुई मानी जाएगी।

(नियम 295 के तहत प्राप्त प्रस्तावों के लिए कृपया परिशिष्ट देखें)

विधायी कार्य : विधेयक का पुरःस्थापन

राजस्थान आवासन बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 1998

विधायी कार्य। श्री भंवरलाल शर्मा, प्रभारी मंत्री राजस्थान आवासन बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 1998 को पुरः स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करेंगे।

श्री भंवरलाल शर्मा (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान आवासन बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 1998 (1998 का विधेयक संख्या–12) को पुरः स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान आवासन बोर्ड (संशोधन) विधेयक 1998 को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की गयी।

प्रभारी मंत्री विधेयक को पुरः स्थापित भी करेंगे।

श्री भंवरलाल शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान आवासन बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 1998 (1998 का विधेयक संख्या–12) को पुरःस्थापित करता हूं।

श्री अध्यक्ष : वे प्रक्रिया के नियम 63 (1) के अन्तर्गत राजस्थान आवासन बोर्ड (संशोधन) अध्यादेश, 1998 (1998 का अध्यादेश संख्या-1) को जारी करने के कारणों का विवरण भी सदन की मेज पर रखेंगे।

(6)

श्री भंवरलाल शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया के नियम 63 (I) के अन्तर्गत राजस्थान आवासन बोर्ड (संशोधन) अध्यादेश, 1998 (1998 का अध्यादेश संख्या-1) को जारी करने के कारणों का विवरण सदन की मेज पर रखता हूं ।

राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम सीमा अधिरोपण (संशोधन) विधेयक, 1998

श्री अध्यक्ष : श्री गंगाराम चौधरी, प्रभारी मंत्री राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम—सीमा अधिरोपण (संशोधन) विधेयक, 1998 को पुर: स्थापित करने की आज्ञा के लिये प्रस्ताव करेंगे ।

श्री गंगाराम चौधरी (राजस्व मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम सीमा अधिरोपण (संशोधन) विधेयक, 1998 (1998 का विधेयक संख्या-II) को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिये प्रस्ताव करता हूं ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम सीमा अधिरोपण (संशोधन) विधेयक, 1998 को पुर:स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति प्रदान की गयी ।

प्रभारी मंत्री विधेयक को पुर:स्थापित करेंगे ।

श्री गंगाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम–सीमा अधिरोपण (संशोधन) विधेयक, 1998 (1998 का विधेयक संख्या-II) पुर:स्थापित करता हूं ।

श्री अध्यक्ष : वे प्रक्रिया के नियम 63 (1) के अन्तर्गत राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम सीमा अधिरोपण (संशोधन) अध्यादेश, 1998 (1998 का अध्यादेश संख्या-2) को जारी करने के कारणों का विवरण भी सदन की मेज पर रखेंगे ।

श्री गंगाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया के नियम 63 (1) के अन्तर्गत राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम सीमा अधिरोपण (संशोधन) अध्यादेश, 1998 (1998 का अध्यादेश संख्या-2) को जारी करने के कारणों का विवरण भी सदन की मेज पर रखता हूं ।

श्री अध्यक्ष : श्री भंवरलाल शर्मा, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री अनुदान की मांग संख्या 27-पेयजल विचार एवं मतदान हेतु प्रस्तुत करेंगे ।

श्री भीमसेन चौधरी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है ।

श्री बनवारीलाल शर्मा : अध्यक्ष महो-दय, मेरा....

श्री अध्यक्ष : एक मिनट ।

(7)

अनुदान की मांग

मांग संख्या 27-पेयजल की प्रस्तुति

श्री भंवरलाल शर्मा (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 27-पेयजल के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1999 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 12,00,85,98,000/- (बारह अरब पिच्यासी लाख अठ्यानवे हजार) तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाए।

श्री अध्यक्ष : पहला नाम कौनसा है, आप बताइये न ?

श्री भीमसेन चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मेरा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है वह सोमवार को ले लीजिये।

श्री अध्यक्ष : क्या ?

श्री भीमसेन चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मेरा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है, उसको सोमवार को ले लीजिये।

श्री अध्यक्ष : मैंने व्यवस्था दे दी। नेक्स्ट टर्न में कह दिया मैंने।

श्री बनवारीलाल शर्मा (धौलपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने 18 तारीख को ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिया था कि मेरे धौलपुर में एक मात्र बारूद फैक्ट्री है, वह बन्द हो गयी है। उद्योग मंत्री की तरफ से अभी जवाब प्राप्त नहीं हुआ है। आप मेहरबानी करके ऐसी व्यवस्था करें कि वह जवाब जल्दी से जल्दी प्राप्त हो जाए जिससे कि उसकी चर्चा हो सके।

श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम) : अध्यक्ष महोदय, टोडाभीम के अन्दर एक कालेज खोलने के बारे में हमारा एक आन्दोलन चला है, उसके बारे में मैंने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लगाया था। आपने कहा कि अभी जानकारी दे रहा हूं मैं और....(व्यवधान)....

श्री अध्यक्ष : मेरा आप तीनों ही माननीय सदस्यों से निवेदन है कि आप मेरे चैम्बर में पधारें।

श्री रामस्वरूप मीणा : अच्छा साहब।

श्री अध्यक्ष : वहां आपको कुछ न कुछ लाभ होगा।

श्री रामस्वरूप मीणा : कालेज खुलवा देंगे, मुझे विश्वास है, साहब।

श्री अध्यक्ष : श्री इन्द्रसिंह पूनिया।

श्री मोहनलाल मोदी (नीमकाथाना) : अध्यक्ष महोदय, शून्य काल हो, कुछ भी हो, आज तो क्या है ? मैं तो शून्य काल नहीं हो तो अपनी बात कहने का तो अवसर मिलेगा आखिर....

एक माननीय सदस्य : चैम्बर में।

श्री मोहनलाल मोदी : मैं तो अपना व्यक्तिगत स्पष्टीकरण देना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : क्या ?

श्री मोहनलाल मोदी : व्यक्तिगत स्पष्टीकरण देना चाहता हूं। जो मदन दिलावरजी, मंत्रीजी ने मेरे खिलाफ आरोप लगाये थे, उनके खिलाफ मैंने विशेषाधिकार का एक प्रश्न दिया था।

श्री अध्यक्ष : विराजिये-विराजिये। मैंने सुन लिया, मैं आपको उपयुक्त अवसर दे दूंगा। आप विराजिये। विराजिये अभी।

श्री मोहनलाल मोदी : स्पष्टीकरण का अवसर देंगे मेरे को ?

श्री अध्यक्ष : मैं अवसर दे दूंगा।

मांग संख्या 27 पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या 27 मुख्य शीर्षक पेयजल योजना के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय, इस आशय के प्रस्ताव निम्नांकित सदस्य प्रस्तुत करेंगे/करेंगी कि:-

श्री ओमप्रकाश शर्मा (बूंदी)

1. बून्दी जिले की बून्दी तहसील में बुधपुरा, गोरधनपुरा, बडफू, सूतड़ा, आम्बालोह, राजपुरा, लक्ष्मीपुरा, लाडपुर, कैथूदा, आमथून, आदि गांवों में पीने के पानी की भारी समस्या के समाधान नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री रामनारायण किसान (फुलेरा)

2. फुलेरा विधान सभा क्षेत्र में रेनवाल लोंदर, अणतपुरा, मुण्डोती आदि विचाराधीन स्कीमों को तत्काल स्वीकृत करने, ग्राम भैंसलाना में जर्जर टंकी को नई बनाई जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री चन्दनमल बैद (तारानगर)

3. गंघेली सहावा लिफ्ट क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना में सरकारी अव्यवस्था एवं लापरवाही के कारण लाभान्वित होने वाले ग्रामों को पेयजल वितरण नहीं होने से उत्पन्न समस्या पर चर्चा के लिये।

श्री मोहनलाल मोदी (नीमकाथाना)

4. ग्राम बोपथा तहसील नीमकाथाना में पेयजल सप्लाई हेतु टैंक बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हीरालाल विश्नोई (सांचोर)

5. पराबा चितलवाणा स्कीम में फ्लोराइड की मात्रा बढ़ने व पानी का स्तर कम होने से ग्रामीणों को पेयजल उपलब्ध नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

6. सांचोर निर्वाचन क्षेत्र के टापी व बंधा कुआ स्कीम से मेड इलाके में खारा व फ्लोराइड युक्त पानी व अन्तिम छोर के गांवों में पेयजल का वितरण बिलकुल नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री शैलेन्द्र जोशी (बांदीकुई)

7. बांदीकुई क्षेत्र में हैण्डपम्पों की मरम्मत न होने व पंडितपुरा में नलकूप न खोदने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री शांतिलाल खोईवाल (राजसमंद)

8. राजसमन्द विधान सभा क्षेत्र में चौकड़ी, सांसेरा--गमेरपुरा एवं सापोल पेयजल योजनाओं की स्वीकृति में विलम्ब करने से ग्राम लोगों में उत्पन्न असंतोष पर चर्चा के लिये ।

9. रेलमगरा (राजसमन्द) पेयजल योजना में हर वर्ष भारी राशि खर्च करने के बावजूद पेयजल समस्या का निराकरण नहीं होने से स्थाई निराकरण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

10. पेयजल योजनाएं, लापसीया-खण्डेल, गोगाथला (राजसमन्द) स्वीकृत नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

श्री भीमसेन चौधरी (लूणकरणसर)

11. सम्बल गांव सावर्णिया का स्वीकृत ट्यूबवैल्स का जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग की गफलत से डी.आर.डी.ए. मे समय पर सूचना न दिये जाने से फण्ड्स लैप्स होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर) :

12. निर्वाचन क्षेत्र सीकर में दूषित पेयजल वितरण रोकने हेतु नई पाइप लाइन डलवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

13. क्षेत्र सीकर में कमेला टंकी के जल वितरण हेतु खटीकान प्याऊ से मोहल्ला खटीकान होते हुये मोहल्ला ब्यापारियान तक नई पाइप लाइन डलवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

14. सीकर शहर में पेयजल वितरण सुधार हेतु मोहल्ला नारवान (सालासर रोड) काबरा धर्मशाला पुरानी जेल रोड, मोहल्ला बिसायतियान, देवीपुरा रोड जाटिया बाजार, अम्बेडकर बाजार नगर, बाल्मिकी बस्ती, औद्योगिक क्षेत्र में नवीन ट्यूबवैल निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

15. ग्राम पंचायत जेरठी की इन्द्रा आवासीय बस्ती में ट्यूबवैल व भूतल जलाशय निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

16. राजपुरा पंचायत के ग्राम गुढ़ाकला में भूतल जलाशय निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री हीरालाल इन्दौरा (केसरीसिंहपुर)

17. निर्वाचन क्षेत्र केसरीसिंहपुर में हरिजन बस्तियों में पीने का पानी

(10)

(श्री हीरालाल इन्दौरा)

उपलब्ध करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

18. निर्वाचन क्षेत्र केसरीसिंहपुर में स्वच्छ पीने का पानी देने के संबंध में चर्चा के लिये।

19. जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग की डिग्गीयों की सफाई की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

20. पेयजल योजना से पाइपों से लीक होने वाले पानी को रोकने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री इन्द्रसिंह पूनिया (सादुलपुर)

21. गन्धेली-साहवा पेयजल योजना से ग्राम नांगल छोटी-धोबोटी बड़ी छोटी ढुमकी ताम्बा खेडी आदि गांवों में आज तक एक बून्द भी पानी नहीं पहुंचाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

22. गन्धेली साहवा पेयजल योजना से लाभान्वित ग्रामों को सुचारू रूप से पीने का पानी उपलब्ध नहीं करवाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री कालूलाल गूजर (मांडल)

23. भीलवाड़ा जिले के ग्राम बड्डू, कालू–खेड़ा, मालीखेड़ा, करणवास, माणकि–यास, माल्यास, बेरा गोमास आदि में पानी खारा होने व फ्लोराइड युक्त होकर पीने के लिये अनुपयुक्त होने से विभाग के स्थानीय अधिकारियों द्वारा भेजी गई क्षेत्रीय जल प्रदाय योजनाओं की स्वीकृति की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

24. भीलवाड़ा जिले के ग्राम नोगांवा के लिये कलेक्टर भीलवाड़ा द्वारा अल्प बचत योजना से पेयजल योजना स्वीकृति प्रदान कर दी परन्तु अभी तक विभाग द्वारा कार्य आरम्भ नहीं कराये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

25. भीलवाड़ा जिले की मांडल तहसील की ग्राम लेसवा, जोरावरपुरा, नवल-पुरा, बांकली, चांदखेड़ा एवं चांदरास क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना योजनाओं के प्रथमचरण का कार्य पूरा हो जाने पर भी अभी तक द्वितीय चरण की स्वीकृति जारी नहीं करने के कारण लोगों को पीने का पानी नहीं मिल पाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री खेतसिंह राठोड़ (शेरगढ़)

26. प्रदेश की पेयजल योजनाओं की क्रिया-न्विति में राज्य सरकार की विफलता पर चर्चा के लिये।

27. जोधपुर शहर एवं शेरगढ़, विधान सभा क्षेत्र से पेयजल उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती मीना अग्रवाल (अलवर)

28. निर्वाचन क्षेत्र अलवर में पीने के पानी की समस्या के त्वरित समाधान की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री शांतिकुमार धारीवाल (हिण्डोली)

29. कोटा शहर में पेयजल समस्या के समाधान की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

30. बारा शहर में पेयजल समस्या के समाधान की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री अर्जुनलाल जीनगर (गंगरार)

31. पेयजल के लिये गंगरार में अतिरिक्त योजना की स्वीकृति एवं पेयजल योजना हिण्डोली की क्षतिग्रस्त टंकी को नया बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

32. 1500 से अधिक की आबादी के ग्राम बूढ़, ग्रामों का जबासिया बाबलास, खारखन्दा, जाड़ाणा में पेयजल योजनाओं की स्वीकृति दिलाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री महादेव सिंह (खण्डेला)

33. खण्डेला विधान सभा क्षेत्र में खराब पड़े हैण्डपम्पों की मरम्मत नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

श्री लक्ष्मीनारायण बैरवा (फागी)

34. इसरदा बांध का निर्माण नहीं होने से पेयजल की स्थिति पर चर्चा के लिये ।

श्री शम्भूदयाल बड़गूजर (केकड़ी)

35. टौंक जिले में पाइलेट फ्लोराइड प्रोजेक्ट की क्रियान्विति नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

श्री रमाकान्त शर्मा (थानागाजी)

36. पम्प एव टैंक योजना से उच्च जलाशय के निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री उगमराज मेहता (ब्यावर)

37. ब्यावर शहर में पेयजल की पाइप लाइन की मरम्मत एवं सभी कालोनियों को पानी की पाइप लाइन से जोड़ने के सम्बन्ध में ।

38. ब्यावर विधान सभा क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्रों में से अधिक मात्रा में फ्लोराइड युक्त पेयजल समस्या का समाधान ग्राम पंचायत सुरजपुरा–लोरियाना दोनों पंचायतों संयुक्त जनता जल योजना एव ग्राम पंचायत कोटड़ा व राजीयावास पंचायत के कालिजर की पेयजल योजना बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

डा० जितेन्द्र सिंह (खेतड़ी)

39. माधोगढ़, कालोटा, डूरडिया, सुनारी, नवरंगपुरा, दौलापुरा, बबाई, गाडदाटा पपूसा, सीहोड, बसई, जमालपुर नालपुर, पंचायतों में हैण्ड पम्प स्वीकृत कराये जाने, नकारा हैण्ड पम्पों के स्थान पर नये एवं प्राथमिक शालाओं में हैण्ड पम्प लगाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

40. खेतड़ी तहसील की माधोगढ़, बेसटड़ा, माणोता कलां, ढोसी, मुकन्दपुरा, ढाढबाड़ी, बीलवा सोधेड की जलदाय योजना शुरू करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री रतनलाल ताम्बी (जहाजपुर)

41. जहाजपुर तहसील कोटड़ी की विभिन्न विचाराधीन जल प्रदाय योजना को पूर्ण करने, क्षेत्र की फ्लोराइड युक्त ग्रामों में पेयजल समस्या का समाधान करने एवं बनास नदी से जहाजपुर क्षेत्र के लगभग 50–60 ग्रामों की तीन योजना का क्षेत्रीय सर्वेक्षण कर पेयजल समस्या का समाधान कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री भीमसेन चौधरी (लूणकरणसर)

42. ग्राम मीकनेरा पंचायत समिति लूणकरणसर की विचाराधीन संशोधित पेयजल योजना को अविलम्ब स्वीकृति की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

43. क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना आर.डी. 535 पंचायत समिति लूणकरणसर के अन्तिम गांव अजीतमाना व लाखर में पेयजल सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

44. पेयजल योजना किस्तूरिया-हाफासर के जल होज तक पाइप लाइन डालने व हुसेरा-खियेरा योजना से लाभान्वित होने वाले गाँवों को पेयजल उपलब्ध हो सके इसके लिये मध्यम पम्पिंग स्टेशन खियेरा पर बड़ा जल होज बनाकर तीनों गांवों के लिये तीन अलग-अलग बूस्टर लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री नारायण सिंह (दांतारामगढ़) :

45. दांतारामगढ़ विधान सभा क्षेत्र सीकर में पीने का पानी की भयकर समस्या के समाधान हेतु धनाभाव के कारण विचाराधीन योजनाएं तथा जिन योजनाओं में और धन की आवश्यकता है उनको शीघ्र स्वीकृत करने तथा चालू करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

46. ग्राम गोबटी व पचार तहसील दांता–रामगढ़ सीकर के टैंक व पम्प स्कीम को पंचायतों द्वारा ठीक प्रकार चलाने में असमर्थ होने से विभाग द्वारा चलाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

47. सीकर जिले के खराब हैण्ड पम्पों को ठीक करवाये जाने, नकारा के स्थान

(श्री नारायण सिंह)

पर नये हैण्ड पम्प लगाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

48 ग्राम चक मिठाई से खारा-पानी होने के कारण भयंकर जल समस्या से उत्पन्न जनाक्रोश पर चर्चा के लिये।

श्री बनवारीलाल बैरवा (निवाई)

49. टौंक शहर में पेयजल के घोर संकट के समाधान की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

50. ग्राम सीतारामपुरा को ग्राम मण्डावर से जी.एल.आर. सुविधा मुहैया कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

51. निवाई विधान सभा क्षेत्र के ग्राम बहड़, सिरस, सिरोही दतवास, हथौना मोहेला व हाड़ी कलां में समुचित पेयजल व्यवस्था की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

52. निवाई के मासी बाँध से जल उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री शम्भूदयाल बड़गूजर (केकड़ी)

53. केकड़ी के स्वीकृत पायलेट फ्लोराइड प्रोजेक्ट के क्रियान्वियन की धीमी गति से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री नाथूराम अहारी (डूंगरपुर)

54. डूंगरपुर जिले में हैण्ड पम्पों के पाइप नहीं बदलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

55. डूंगरपुर शहर में पेयजल की व्यवस्था ठीक नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

56. डूंगरपुर जिले में बड़े ग्रामों में नल योजना स्वीकृत नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

57. डूंगरपुर जिले में उचित पेयजल की व्यवस्था नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री मगराज चौधरी (आहोर)

58. जालौर जिले की आहोर तहसील के ग्राम देबावास, मूती, कुण्डमाल की ढाणी, संखवाली, मोरडा, नीलकंठ आदि में पेयजल की समस्या के समाधान हेतु स्वीकृत पाइप लाइन लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

59. जालौर जिले की आहोर तहसील के ग्राम भवरानी, बाला, मोनीसरा जोगणीखेडा, दूदीया, महेशपुरा, गुडा बालोतान, मंडला में पेयजल समस्या के निवारण हेतु नवीन ट्यूबवैल बनाने एवं जल आपूर्ति से जोड़ने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(14)

श्री शंकरलाल अहारी (चौरासी)

60. डूंगरपुर जिले में गम्भीर पेयजल की समस्या के निराकरण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम)

61. टोडाभीम विधान सभा क्षेत्र में पीने के पानी की टंकियों में पर्याप्त मात्रा में जल उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

62. टोडाभीम कस्बे की विचाराधीन जलदाय योजना की शीघ्र स्वीकृति की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

63. विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम में हैण्ड पम्पों की स्वीकृति एवं खराब हैण्ड पम्पों को ठीक कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री भंवरलाल शर्मा (सरदारशहर)

64. सरदारशहर क्षेत्र के वर्षों से पुराने फटे हुये पाइपों को नहीं बदलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

65. गम्घेली-साहवा पेयजल योजना में दो दो माह तक नहर का पानी गांवों को उपलब्ध नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

66. सरदारशहर क्षेत्र के गांव बिल्यूबास महिपाल व अमरासर के कुओं को चालू नहीं करने से उत्पन्न पेयजल संकट पर चर्चा के लिये।

67. सरदारशहर क्षेत्र में पंचायतों द्वारा निर्मित होजों को पाइप लाइन से नहीं जोड़े जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

68. सरदार शहर क्षेत्र में कुओं की मोटरों के जल जाने से उत्पन्न पेयजल संकट की स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री रामरिछपाल नुवाल (भीलवाड़ा)

69. कान्या खेड़ी व गुवाडी बांध की भराव क्षमता बढ़ा कर भीलवाड़ा शहर की पेयजल व्यवस्था हेतु पानी सुरक्षित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

70. बीसलपुर परियोजना से भीलवाड़ा, शाहपुरा बनेड़ा, जहाजपुरा एवं मांडल को पेयजल हेतु पानी उपलब्ध कराकर पीने के पानी की समस्या के समाधान की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री मांगीलाल मेघवाल (केशवरायपाटन)

71. प्रदेश के जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग में नियमानुसार अनुसूचित जाति, जनजाति के आरक्षित कोटे को पूरा नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

72. लाखेरी (बूंदी) नगर की 35 हजार की आबादी एवं क्षेत्र विस्तार को मध्य नजर रखते हुये इस नगर की पेयजल समस्या के समाधान हेतु

(श्री मांगीलाल मेघवाल)

प्रस्तावित योजना की इसी वित्तीय वर्ष में स्वीकृति करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

73. केशवरायपाटन पंचायत समिति क्षेत्र को विशाला आबादी की संख्या आदि को मद्य नजर रखते हुये जनता एवं जनप्रतिनिधियों की मांग पर केशवरायपाटन में सहायक अभियन्ता कार्यालय खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

74. केशवरायपाटन विधान सभा क्षेत्र में स्वीकृत पेयजल योजनाओं के मन्द गति से चलाने से केशवरायपाटन नगर, कापरेन नगर एवं रोटेटा, लबान, चरड़ाना की जनता में व्याप्त आक्रोश पर चर्चा के लिये।

75. केशवरायपाटन सिंचित क्षेत्र में जहाँ रास्ते आठ-दस महीनों बंद रहते है, में विशेष मशीने, विशेष महीनों में, विशेष कार्यक्रम बनाकर हैण्डपम्प लगाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री भरत सिंह (खानपुर)

76. 32 जिले 32 कार्य योजना के तहत झालावाड़ जिले में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को आवंटित राशि का समय पर उपयोग नहीं होने की स्थिति पर चर्चा के लिये।

77. ग्राम आवा व ग्राम ब्यावर जिला कोटा में उच्च लेवल की नई टंकी निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री शम्भूदयाल बड़गूजर (केकड़ी)

78. केकड़ी तहसील में पाइलेट फ्लोराइड प्रोजेक्ट योजना का द्वितीय चरण प्रारम्भ न होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

79. केकड़ी तहसील की गोरधा पंचायत में पेयजल योजना न होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री आर.पी.शर्मा (भरतपुर)

80. भरतपुर विधान सभा क्षेत्र जधीना, कूम्दा मुखारा, सूची, गुण्डवा, स्योराना रामनगर, चररामनगर, अघाहपुर, चिचावा वत्सों, जाटोलीघना, सुनारी, नगला, वरताई गाँवों की पेयजल समस्या के समाधान की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

81. भरतपुर विधान सभा क्षेत्र की सभी प्रस्तावित पेयजल योजनाओं को शीघ्र स्वीकृत करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

82. भरतपुर शहर में शुद्ध पीने योग्य पेयजल उपलब्ध कराने हेतु दूसरा फिल्टर प्लांट की स्थापना की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रामगोपाल बैरवा (पीपल्दा)

83. विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा में तीस

(श्री रामगोपाल बैरवा)

जिला तीस काम योजना में ढीरगी पंचायत में नल योजना का कार्य लम्बे समय से पूरा नहीं होने पर चर्चा के लिये।

84. ग्राम नीमोला में खारे पानी की समस्या समाधान हेतु नल योजना स्वीकृत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

85. विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा के ग्राम अपाना लुहापद व तालाब में स्वीकृत जी.एल.आर. योजना लम्बे अर्से से पूर्ण नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

86. विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा में स्वीकृत पेयजल योजना इटावा, खातोली, जेला, पीपल्दा में अनुसूचित जाति जनजाति की ढाणियों में पाइप लाइन नहीं बिछाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

87. हैण्ड पम्प सुधार अभियान को प्रभावी ढंग से लागू करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रामेश्वर भारद्वाज (किशनपोल)

88. जयपुर शहर की कच्ची बस्तियों में पानी की लाइन डालने एवं जहां छोटी लाइन है उसे बड़ी लाइन में बदलने के संबंध में चर्चा के लिये।

89. जयपुर शहर में जहां पानी का प्रेसर काफी कम है वहां उच्च जलाशय (टंकी) बनवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

90. जयपुर शहर में सोसायटियों द्वारा बसी बस्तियों में जहां पानी की लाइन नहीं है शीघ्र डलवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

91. बीसलपुर से जयपुर को शीघ्र जल उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

92. शहर के मुख्य स्थानों पर नये हैण्ड पम्प लगाने एवं पुराने ठीक कराने तथा जो निष्क्रिय हो गये उनकी जगह दूसरे हैण्ड पम्प लगाने के संबध में चर्चा के लिये।

श्री भीखा भाई (सागवाड़ा) :

93. सागवाड़ा क्षेत्र में पेयजल के लिये ट्यूबवैल नहीं खोदने से उत्पन्न जन आक्रोश पर चर्चा के लिये।

94. सागवाड़ा क्षेत्र के ग्राम चीखली, ग्राम कुआं और सागवाड़ा शहर में पाइप लाइन बिछाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री भीमराज भाटी (पाली)

95. जिला पाली पंचायत समिति रोहट के छोलेरिया शासन, छोलेरिया, जागिर, फेकरिया, मुरडिया, दिवान्दी आदि गांवों को जवाई बांध का मीठा पानी

(श्री भीमराज भाटी)

पीने के लिये उपलब्ध करवाने के संबध में चर्चा के लिये।

96. जिला पाली पंचायत समिति पाली के बोमादड़ा, मोगेसर, खेतावास, सोवगिया, सार्पा, निम्बलाखेड़ा, पडासला कल्ला आदि गाँवों को जवाई बांध का मीठा पानी पीने के लिये उपलब्ध करवाने के संबंध में चर्चा के लिये।

97. जिला पाली की पाली जैनपुर जलदाय योजना की स्वीकृति करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री लक्ष्मीनारायण बैरवा (फागी)

98. तहसील चाकसू की पायलट फ्लोराइड योजना को तुरन्त पूरी करा कर गांवों को शुद्ध मीठा पानी उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

99. तहसील फागी की पानी की पायलट फ्लोराइड योजना बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

100. तहसील चाकसू के ग्राम तितरिया की जल स्कीम को क्रियान्वित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

101. तहसील फागी एवं चाकसू की ढाणियों व प्राथमिक पाठशालाओं में हैण्ड पम्प लगाने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री अमराराम (धोद)

102. लोसल नगर की पेयजल योजना के पुनर्गठन की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

103. धोद विधान सभा क्षेत्र के सरवड़ी सीहोर छोटी सेवद गांवों को सीधी विद्युत लाइन से पेयजल स्रोतों को जोड़ने के संबंध में विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

104. धोद विधान सभा क्षेत्र की प्राथमिक शालाओं में पेयजल हेतु हैण्ड पम्प लगाने के संबंध में चर्चा के लिये।

105. सीकर जिले के ग्राम ताखरो की ढाणी जोशीयों की ढाणी तन भगतपुरा; मूण्डवाड़ा, किरडोली ग्राम में उत्पन्न पेयजल समस्या से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री रूपाराम (मकराना)

106. मकराना शहर जिला नागौर में रामसिया, रामफूल बिलू गांव में पेयजल समस्या के समाधान हेतु चर्चा के लिये।

श्री श्रवण कुमार (पिलानी)

107. क्षेत्र पिलानी के गांवों में पेयजल की व्यवस्था करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालोर)

108. जालोर की जिले की जालोर एवं आहोर तहसीलों के गांवों में जवाई बांध से पेयजल उपलब्ध करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री किशन गोपाल कोगटा (मसूदा)

109. गांव केसरपुरा पंचायत बाडी पंचायत समिति मसूदा में फ्लोराइडयुक्त पानी से जनता को राहत दिलाने के आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

110. मसूदा विधान सभा क्षेत्र के 1550 की जनसंख्या वाले गांवों में पनघट योजना स्वीकृत कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

111. मसूदा विधान सभा क्षेत्र में 1500 की आबादी से ज्यादा पंचायत शेरगढ़ नन्दवाड़ा, मोयणा गोहाना सरमालिया पनघट योजना स्वीकृत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

112. नगरपालिका क्षेत्र विजयनगर में पेयजल की समस्या में सुधार करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर)

113· श्रीगंगानगर जिले में शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

114. श्री गंगानगर विधान सभा क्षेत्र में बने जी.एल.आर. में पानी उपलब्ध नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

115. श्रीगंगानगर विधान सभा क्षेत्र की सर्वे के दौरान हुई छूटी हुई ढाणियों व गांवों को राजीव गांधी पेयजल मिशन योजना के अन्तर्गत जोड़ने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

116. श्रीगंगानगर शहर में पाइप लाइने जर्जर हो चुकी हैं और गटर का गन्दा पानी पेयजल के साथ सप्लाई हो रहा है इन पाइप लाइनों को बदलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये ।

117. श्रीगंगानगर की पेयजल योजना का कार्य तीव्र गति से शुरू करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री भीमसेन चौधरी (लूणकरणसर)

118. चक के.पी.एम. की स्वीकृत चक आबादी में पेयजल हेतु डिग्गी का निर्माण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं)

119. विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र लाडनूं में पेयजल व्यवस्था से वंचित ढाणियों में पेयजल व्यवस्था उपलब्ध करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

120. कस्बा लाडनूं में जो पुरानी लाइने अवरुद्ध हुई है उनको बदलने व जहां गरीबों की बस्तियों में लाइने नहीं है वहां पर लाइन डालने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

121. कस्बा लाडनूं की पुनर्गठित जल योजना स्वीकृत नहीं किये जाने के कारण उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

(श्री हरजीराम बुरडक)

122. स्थानीय स्रोत से जल आपूर्ति होने वाले गांवों में विभाग द्वारा घरेलू कनेक्शन नहीं दिये जाने के कारण विभाग को होने वाली राजस्व हानि से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

123. उप खण्ड लाडनूं में ग्राम निम्बोजोधा की खिचड़ों की ढाणी का नलकूप चालू करने की स्वीकृति होने से लम्बे समय बाद भी नलकूप चालू नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा)

श्री भीखा भाई (सागवाड़ा)

124. झुन्झुनूं जिले में खारेपानी के गांवों को नहर द्वारा मीठा स्वच्छ पानी देने की योजना में गतिशीलता लाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

125. खराब हैण्ड पम्पों को सुधारने की व्यवस्था में सुधार लाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा)

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा)

126. झुन्झुनूं जिले में बनी हुई पानी की टंकियों को चालू करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

127. जनता जल योजना में सुधार लाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा)

128. उदयपुरवाटी(झुन्झुनूं) पंचायत समिति क्षेत्र में हैण्ड पम्प तथा अन्य स्वीकृत योजनाओं से पूरा करने में हो रहे अत्यधिक विलम्ब को दूर करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री लक्ष्मणसिंह रावत (भीम)

129. राजसमंद जिले की भीम व देवगढ़ पंचायत समिति में टंकी व पाइप्स योजनाएं 1500 की आबादी वाले गांवों यथा बरजाल, मियाला, आमनेर आदि में प्रारम्भ नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

130. भीम व देवगढ़ (जिला राजसमंद) तहसीलों के फ्लोराइड से प्रभावित गांवों में टंकी व पाइप लाइन को योजना लागू करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री कन्हैयालाल पाटीदार (पिड़ावा)

131. विधान सभा क्षेत्र पिड़ावा (झालावाड़) में 1500 की आबादी वाले ग्रामों की पेयजल योजना इसी वर्ष स्वीकृत कर कार्य प्रारम्भ कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

132. विधान सभा क्षेत्र पिड़ावा (झालावाड़) के खारा पानी वाले गाम भिलवाड़ी, गुणदो जेता खेड़ी सूलीया धरोनिया, हरवापदा कोटडा में पेयजल स्कीम स्वीकृत कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

20

(श्री कन्हैयालाल पाटीदार)

133. झालावाड़ शहर में पीने के पानी की समस्या के समाधान हेतु बनाई गई योजना को प्राथमिकता से स्वीकृत कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

134. झालावाड़ जिले में काफी अरसे से ड्रिल्ड हैण्ड पम्पों को चालू कराया जाने व स्वीकृत हैण्ड पम्पों को शीघ्र लगाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

135. झालावाड़ जिले में सरकार द्वारा घोषित जनता जल योजना के वर्कर को 500 रुपये प्रति माह देना बंद कर देने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

श्री अमरचन्द मिड्ढा (सूरतगढ़)

136. विधान सभा क्षेत्र सूरतगढ़ के टिब्बा क्षेत्र के गांवों में जल पूर्ति हेतु योजनाओं में आमूलचूल परिवर्तन करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री भीमराज भाटी (पाली)

137. पाली शहर में पेयजल आपूर्ति हेतु जवाई नहर की मरम्मत जीर्णोद्धार एवं उसमें हो रहे प्रदूषण की रोकथाम हेतु प्रशासनिक, तकनीकी स्वीकृति के बावजूद वित्तीय संसाधन उपलब्ध नहीं करवाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा के लिये ।

श्री हरिनारायण (खण्डार)

138. खण्डार क्षेत्र ग्राम के बसोकला व बसोखुर्द की स्वीकृत पेयजल योजना को शीघ्र चालू करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

139. खण्डार सवाईमाधोपुर क्षेत्र के ग्राम कुश्तला डेहकवां व खांजना चौड के अधूरे पड़े पेयजल के कार्यों को पूरा कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

140. सवाईमाधोपुर क्षेत्र में पुराने हैण्ड पम्पों की अपेक्षा नये हैण्ड पम्प अधिक नकारा होने से उत्पन्न स्थिति पर पर चर्चा के लिये ।

141. खण्डार, सवाईमाधोपुर क्षेत्र के नकारा हैण्ड पम्पों के स्थान पर नये हैण्ड पम्प लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

142. खण्डार सवाईमाधोपुर के ग्राम भूरी पहाड़ी, डूंगरी, तलाबड़ा, कोसरा, बयारढाकलां, पांवाडेरा, खिवापच, गम्भीरा व झोपड़ा जिनकी आबादी 1991 से 1500 की है, को पेयजल योजना से जोड़ने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री शम्भूदयाल बड़गूजर (केकड़ी)

143. भिनाय पंचायत समिति में कुम्हारिया, खेड़ा, सांगानेर, खिरारिया गोयला, अखंड, चावंडिया आदि गांवों

(श्री शम्भूदयाल बड़गूजर)

को पेयजल योजना से जोड़े जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर (नसीराबाद)

144. नसीराबाद नगर को पेयजल एम.इ.एस. के मार्फत न देकर सीधे छावनी बोर्ड को उपलब्ध कराने सम्बन्धी दिये गये आश्वासन को पूरा न करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

145. राज्य में हैण्ड पम्पों पर अपेय (दूषित) जल का उपयोग रोकने एवं शुद्धजल उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

146. बीसलपुर योजना के रख-रखाव को ठेके पर देने एवं पूर्व बनास योजना में पदस्थापित कर्मचारियों को बगैर काम के घर बैठे वेतन देने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

147. वर्ष 1996-97 में बजट भाषण में 1500 की आबादी के सभी गांवों को पेयजल उपलब्ध कराने हेतु पम्प एण्ड टैंक स्कीम से जोड़ने में विभाग की विफलता एवं नसीराबाद क्षेत्र के एक भी मात्र गांव को पेयजल उपलब्ध न कराने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए ।

148. नसीराबाद निर्वाचन क्षेत्र के पंचायत लोहरवाड़ा के गांव हनुवनत्या को पेयजल योजना की स्वीकृति के बावजूद पूर्ण नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

श्री राजेन्द्र चौधरी (बिलाड़ा)

149. निर्वाचन क्षेत्र बिलाड़ा के ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

150. जोधपुर जिले में लम्बे समय से निर्मित जी.एल.आर. व एस.एल.आर. को पाइप लाइन से नहीं जोड़ने के कारण इसके लिये दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करने एवं उन्हें प्रारम्भ करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

151. पिपाड़ शहर एवं बिलाड़ा शहर के लिये स्वीकृत योजना के अनुसार कार्य शुरू होने में विलम्ब एवं बिलाड़ा एवं पिपाड़ के मोहल्लों में पेयजल आपूर्ति नहीं होने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री परसादीलाल मीणा (लालसोट)

152. पंचायत समिति लालसोट के ग्राम रामगढ़, पचवारा में उच्च जलाशय नहीं होने के कारण पेयजल संकट से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

153. पंचायत समिति लालसोट के ग्राम मण्डावरी में पेयजल योजना का वर्तमान जनसंख्या के आधार पुनर्गठन नहीं करने के कारण पर्याप्त पेयजल नहीं मिलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

154. पंचायत समिति लालसोट के ग्राम

(22)

(श्री परसादीलाल मीणा)

तलाब गांव में स्कीम से पर्याप्त पानी नहीं पहुंचने के कारण उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

155. पंचायत समिति लालसोट की 50 से अधिक आबादी वाली ढाणियों में राजीव गांधी मिशन योजना से पेयजल उपलब्ध नहीं कराये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में चर्चा के लिये ।

156. पंचायत समिति लालसोट में स्वीकृत पेयजल योजना किशोरपुरा, महारिया एवं खुर्री का कार्य स्वीकृत होने के 2 वर्ष बाद भी पेयजल उपलब्ध नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

श्री हरिसिंह (महुवा)

157. पंचायत समिति टोडाभीम की फोजीपुर ताजपुर क्षेत्रीय जलदाय योजना में सम्मिलित गांवों को पेयजल उपलब्ध नहीं होने के कारण उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

158. दौसा जिला की तहसील महुवा में स्वीकृत क्षेत्रीय जलदाय योजनाओं की विफलताओं से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

श्री जयन्तिलाल कोली (रेवदर)

159. रेवदर सिरोही के ग्राम मण्डार निम्बज रेवदर सिरोही, दांतराई में स्वीकृत पाइप लाइनों को जोड़ने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

160. थला गांव तहसील रेवदर जिला–सिरोही में जनता जल योजना के अधूरे पड़े कार्यों को पूर्ण करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

161. रेवदर कस्बा तहसील रेवदर जिला सिरोही की जनता को कुआ खुदवाकर शुद्ध पेयजल मुहैया करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

162. ग्राम झवाणी के फ्लोराइडयुक्त पानी के स्थान पर पास क गांव में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

163. तहसील सिरोही के गांव सिलदर व हालीवाड़ में पेयजल की किल्लत से व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये ।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य (उदयपुर)

164. उदयपुर में टूटी फूटी पाइप लाइन तथा पुरानी लाइनों को बदलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

165. उदयपुर की झामड़ कोटड़ा से मिलने वाली पानी को बन्द कर दिये जाने व तत्सम्बन्धित कोई करार आर.एस. एम. से नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

166. हिरणमगरी उदयपुर के सेक्टर्स में स्वच्छ पानी की सप्लाई की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

(श्री शिवकिशोर सनाढ्य)

167. दूध तलाई फिल्टर प्लान्ट से निकलने वाले दूषित अवशेष को दूध तलाई में डालकर पिछोला के पीने वाले पानी को दूषित करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

168 मानसी वाकल योजना पर कार्य प्रारम्भ नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

श्री भीमराज भाटी (पाली)

169. विश्नोईयों की ढाणी (मूलियावास मार्ग पर) ग्राम पचायत खण्डावास पचायत समिति रोहट, पचायत समिति कुनथाना में पीने के पानी की व्यवस्था की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर)

170. ग्राम गुसरा (कुम्हेर) तथा ग्राम खेडली गड़ासिया तहसील बयाना की पेयजल योजनाओं को शीघ्र स्वीकृति की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

171. कुम्हेर विधान सभा क्षेत्र के क्षारीय भूमि के ग्रामों में बाणगंगा नदी से पेयजल उपलब्ध कराने हेतु योजना की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

172. पढ़ोला ग्राम के हैण्ड पम्पों का पानी खारा होने के कारण ट्यूबवैल लगा कर मीठा पानी उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

173. कुम्हेर के ग्राम महगाया में स्रोत खारी होने के कारण दूसरा मीठा पानी का स्रोत उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्रीमती तारा भण्डारी (सिरोही)

174. सिरोही नगर में फ्लोराइडयुक्त पानी पीने से जनता के स्वास्थ्य में आ रही गिरावट रोकने के लिये सिरोही में फिल्टर प्लान्ट लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

175. सिरोही विधान सभा के गांव बादला, अबाणा, गोडाणा आदि में उपलब्ध पेयजल अत्यधिक खारा होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

176. सिरोही विधान सभा क्षेत्र में चलने वाली रीजनल स्कीमों (क्षेत्रीय जल प्रदाय) पालडी, फालन्द्री, नून-फूंगणी-गुडा एवं अन्य में पर्याप्त पानी नहीं मिलने से जनता में उत्पन्न रोष के बारे में चर्चा के लिये ।

177. सिरोही विधान सभा क्षेत्र के गांव वेरापुरा, नयाखेडा, माकरोडा, धान्ता, मीरपुर, नून, फूंगणी, गुडा, बावली, नवारा आदि गांवों में फ्लोराइडयुक्त पानी पीने से लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ रहे बुरे प्रभाव को रोकने तथा पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

178. शिवगंज नगर एवं आस पास के गांवों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने हेतु

(24)

(श्रीमती तारा भण्डारी)

पूर्व में स्वीकृत योजना जवाई बांध से आपूर्ति न करने एवं निष्क्रिय हैण्डपम्पों के नहीं बदलने से उत्पन्न जन आक्रोश पर चर्चा के लिये।

श्री टीकमचन्द कान्त (सिवाना)

179. सिवाना क्षेत्र की 36 चिन्हित ढाणियों की पेयजल योजना स्वीकृत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

180. खण्ड सिणधरी के ग्राम बरखाली एवं नीम्बली में पानी का बहुत ही संकट होने एवं मलखाडी योजना में खुदे हुये कुओं को गहरे करवाना एवं कुओं की संख्या बढ़ा कर पानी उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

181. पंचायत समिति सिणधरी के ग्राम डंडाली में निर्बन्ध योजना में (विधायक) राशि में से एक लाख रुपये कुआ खोदने के लिये स्वीकृत होने के पश्चात भी दो वर्ष में अभी तक कार्य नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

182. पंचायत समिति सिणधरी के ग्राम सड़ा धनजी, सड़ा-जूड एवं मटाला में स्वीकृत शुदा योजना को बन्द कर अन्यत्र पानी के स्रोत ग्राम कौशल द्वारा इस महत्वपूर्ण योजना को शुरू करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

183. पंचायत समिति सिणधरी (बाड़मेर) के ग्राम पायला कलां को मलखाड़ी पेयजल योजना से जोड़ने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री कमल (हिण्डौन)

184. हैण्ड पम्प लगाने का खर्चा वास्तविक खर्चे से कई गुना अधिक भुगतान करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

185. हिण्डौन क्षेत्र के ज्यादातर हैण्डपम्प खराब पड़े रहने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

186. जिला करोली व सवाईमाधोपुर को चम्बल से पेयजल उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

181. जिन गांवों में पेयजल स्कीम चालू है वहां हैण्ड पम्प लगाने पर पाबन्दी लगाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

188. गांव कोटड़ा बहुर, खोहरा, सेडली मुजेव में ट्यूबवैल योजना स्वीकृत कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री बनवारीलाल शर्मा (धौलपुर):

189. धौलपुर के अमरोली पेयजल योजना पर फिल्टर प्लांट व बिरोधा ग्राम की मंजूर शुदा पाइप स्कीम पर निर्माण कार्य शीघ्र शुरू कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

190. धौलपुर क्षेत्र के 1500 व इससे ऊपर की आबादी वाले ग्राम मैसेना

(श्री बनवारीलाल शर्मा)

सतवाडा, मोलोनीखुर्द कासिमपुर आदि में पम्प एण्ड टेंक स्कीम द्वारा पेयजल उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

191. बसई नीम धौलपुर में गंधक युक्त पानी होने व हैण्डपम्प सफल नहीं होने के कारण पेयजल की समस्या से निपटने हेतु पाइप लाइन डाले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

192. धौलपुर के सैंपऊ व ग्राम तसीमा की जीर्ण-शीर्ण टंकियों की मरम्मत एवं पेयजल की विकट समस्या के समाधान हेतु विचाराधीन पुनर्गठित योजनाओं को शीघ्र मंजूर करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

193. मोरोली धौलपुर में हैण्ड पम्प नहीं लगाने, मोरोली जल योजना पर चम्बल नदी से बिना फिल्टर पेयजल सप्लाई करने व फिल्टर प्लांट नहीं लगाने से व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये ।

श्री रामचन्द्र रावत (कोटपूतली)

194. कोटपूतली तहसील के ग्राम बनेटी की हरिजन कालोनी एवं नांगला कालोनी में जलदाय का पानी नहीं मिलने से उत्पन्न समस्या पर चर्चा के लिये ।

195. विधान सभा कोटपूतली के ग्राम सुन्दरपुरा, मोरधा, गोनेडा में पानी की टंकी मंजूर है लेकिन अभी तक कार्य आरम्भ नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

196. कोटपूतली तहसील के खारे एवं कड़वा पानी वाले गांव, बिजाहेंडा खड़व, कल्याण पुरा कलां, ससड, कंवरपुरा इत्यादि गावों मे मीठा एवं अच्छा पानी की सप्लाई नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

197. कोटपूतली तहसील के सभी खराब हैण्ड पम्प को ठीक नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

198. कोटपूतली तहसील के मंजूर शुदा हैण्ड पम्पों को पाइपों की कमी के कारण नहीं लगने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

श्री रामनारायण डूडी (भोपालगढ़)

199. भोपालगढ़ क्षेत्र के पेयजल समस्या एवं उनके समाधान की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

200. भोपालगढ़ एवं बिलाडा क्षेत्र में हैण्ड पम्पों के सूख जाने पर नल कूप योजना लागू करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री भवानी जोशी (बांसवाड़ा)

201. बांसवाड़ा के ग्रामीण क्षेत्रों में पीने के पानी की समस्या को दूर करने के लिये जनजाति क्षेत्र में अधिक हैण्ड पम्प

(श्री भवानी जोशी)

लगाने एवं शहर में पुरानी पाइप लाइन को नई में बदलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री चुन्नीलाल गरासिया (उदयपुर ग्रामीण)

202. उदयपुर शहर स्थित प्रतापनगर, सुन्दरवास, आयड़, केशवनगर क्षेत्रों के पानी के कम दबाव को सुधारने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

203. उदयपुर में स्थित कच्ची बस्तियों में पीने के पानी की माकूल व्यवस्था की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

204. 1990 से स्वीकृत नल योजनाओं को गांव कैलाशपुरी चीरवा में पूरी कराने हेतु एवं घरों में नल कनेक्शन देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

205. मानसी वाकल बांध योजना को पूरा कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

206. उदयपुर ग्रामीण विधान सभा के तहत उदयपुर शहर में पुरानी पाइप लाइनों को बदलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (जोधपुर)

207. जोधपुर शहर विधान सभा क्षेत्र में पेयजल लाइन गटर लाइने पास–पास होने से पेयजल प्रदूषित होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

208. जोधपुर शहर व विधान सभा क्षेत्र जोधपुर में बढ़ती जनसंख्या व पुरानी पाइप लाइनों को देखते हुए नई पाइप लाइन डालने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

209. हैण्ड पम्प दुरूस्ती अभियान को गति प्रदान करने व पुराने एवं बेकार सामान की जगह नया सामान तत्काल उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

210. जोधपुर शहर विधान सभा क्षेत्र में सीवरेज लाइन के अभाव में उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

211. जोधपुर शहर के पेयजल हेतु प्राचीन जलाशयों, तालाब व कुओं की मरम्मत कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री जीतराम (मालपुरा)

212. मालपुरा क्षेत्र की डोरिया पेयजल योजना स्वीकृत नहीं होने से उपखण्ड मालपुरा में व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये।

213. मालपुरा क्षेत्र को ग्राम लाम्बा हरीसिंह में पेयजल हेतु टंकी का निर्माण नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

(श्री जीतराम)

214. मालपुरा क्षेत्र ग्राम इन्दोली में फ्लोराइडयुक्त पानी होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल (गंगापुर)

215. सन् 1991 में स्वीकृत थली-दोलतपुरा (गंगापुर) जल प्रदाय योजना अब तक पूर्ण नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

216. विधान सभा में मंत्री के आश्वासन के पश्चात भी गंगापुर सिटी में तीसरी टंकी का निर्माण एवं कर्मचारी कालोनी में पाइप लाइन नहीं डालने के कारण जनता में आक्रोश से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

217. गंगापुर विधान सभा क्षेत्र के ग्रामों में स्वीकृत विभिन्न योजनाओं में हैण्ड पम्प लगाने हेतु एवं समय पर विभाग द्वारा पाइप उपलब्ध नहीं करवाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

218. पनघट जल योजना ग्राम नोगावा ग्राम तलावड़ा एवं ग्राम विदरधा ओघूपुरा की आज तक स्वीकृति नहीं प्रदान करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

219. सन् 1996 में स्वीकृत, प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के बाद भी मालपुर-अेडई परियोजना (बारह ग्रामो) का कार्य धीमी गति से करने के कारण आज भी पूर्ण नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

मांग संख्या 27 पर विचार

श्री इन्द्रसिंह पूनिया (सादुलपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, आज इस सदन में एक बहुत महत्वपूर्ण विभाग की अनुदान मांग पर चर्चा हो रही है और मैं ऐसा मानकर चल रहा हूं कि इस चर्चा में पूरे राजस्थान की जनता जुड़ी हुई है। इसमें कोई वाद-विवाद की बात नहीं है। पानी एक ऐसी चीज है कि हर गरीब-अमीर को पानी की आवश्यकता होती है। जो भी सरकार राजस्थान में आयी, चाहे कांग्रेस की आयी हो, चाहे दूसरी पार्टियों की सरकारें आयी हों, अपने समय में कुछ न कुछ योजनाएं हर सरकार बनाती है। लेकिन, माननीय अध्यक्ष महोदय, देखना यह है कि कौन आदमी, कौन पार्टी उन योजनाओं की क्रियान्विति कैसे करती है। और जनता को उससे लाभ किस प्रकार से कितना मिल रहा है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं ऐसे जिले से आ रहा हूं जहां पीने के पानी की गम्भीर समस्या है। वैसे राजस्थान में हर जिले में पीने के पानी की समस्या है लेकिन खास तौर से चूरू, बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर, नागौर, सीकर, झुंझनू ये जिले ऐसे हैं, जहां पर पीने के पानी की भयंकर समस्या है। हमारे चूरू जिले में तो तलसीर में भी खारा पानी है, पीने के मीठे पानी का नाम नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, यहां पर तारानगर से आने वाले माननीय सदस्य बैठे

(श्री इन्द्रसिंह पूनिया)

है। कैलाशजी की गर्दन हिल रही है, नाम लेते ही इनके पता नहीं क्या +++ हो रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मैं उनको धन्यवाद देना चाहूंगा, मैं ही नहीं देना चाहूंगा, चूरू जिले का और गंगानगर, नोहर, भादरा का हर इन्सान इनको धन्यवाद देगा कि इन्होंने उस समय में चूरू जिले में गंधेली-साहवा क्षेत्रीय जलप्रदाय योजना का शुभारम्भ करवाया था। मुझे याद है कि चूरू जिले में पानी की भयंकर समस्या थी। इनके समय में खेतसिंहजी केबिनेट मंत्री थे। इन्होंने वह स्कीम बनाकर जब मंत्रिमण्डल में पेश की बहुत-से सदस्य इन पर हंसे थे कि कैसी बचपनी बातें कर रहे हैं ये। कहां गंधेली, कहां तारानगर, राजगढ़, चूरू ? क्या पाइपों से पीने का पानी आना सम्भव है ? लेकिन, अध्यक्ष महोदय, वह स्कीम बनी, उसका शुभारम्भ हुआ और उसका कार्य चालू हुआ। कांग्रेस के शासन में काम चला, भारतीय जनता पार्टी उस टाइम जनता पार्टी के शासन में चला और अब आठ साल के शासन में वह काम चला। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे बड़े दुःख के साथ कहना पड़ता है, मैं किसी के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाने नहीं खड़ा हुआ हूं। न मैं किसी की बुराई करना चाहता हू, न मैं किसी अधिकारी के खिलाफ बोलना चाहता हूं, मुझे एक बात का बड़ा दुःख है। इस स्कीम से हमारे शासन में जहां तक पानी पहुंचा, मैं यह नहीं कहता कि पूरे राजगढ़ तहसील को, तारानगर को, चूरू को, डूंगरगढ़ और सरदारशहर को पानी मिला, लेकिन जहां तक मिला, वहां तक तो सुचारू रूप से मिल रहा था। लेकिन पिछली बार दो बार इस भारतीय जनता पार्टी का शासन आया है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि क्या इनके दिल में है ? एशिया की सबसे बड़ी स्कीम सोचकर जर्मन सरकार ने 800 करोड़ रुपये देने स्वीकार किये लेकिन इस भारतीय जनता पार्टी के शासन में इस स्कीम को तोड़-मरोड़ दिया गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, गर्मियों में पूरे राजस्थान में यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार ढिंढोरा पीट रही है कि हम एक बड़ी कल्याणकारी सरकार हैं, पीने का पानी लोगों को मुहैया करा रहे हैं। लेकिन फिर आपने अखबारों में जगह-जगह प्रदर्शन भी देखा होगा, पानी के मटकों के लिये लोग तरसते हुए फिर रहे थे। उसी समय भीषण गर्मी में चूरू जिले के नागरिक पीने के पानी के लिये त्राहि-त्राहि मचा रहे थे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे दो-तीन बात खास कर निवेदन करना चाहूंगा। पिछली बार जब कांग्रेस का शासन था, उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी का शासन आया। इस महत्वपूर्ण योजना में द्वितीय चरण जो मेरे निर्वाचन क्षेत्र राजगढ़-सादुलपुर से जुड़ा हुआ है, उससे पानी पहुंचाना था। हमने मांग की कि एक गांव है मनीम और मावदा, पानी का सोर्स है, इसको आप कृपा करके जोड़ें। तो मुझे

+++ शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री इन्द्रसिंह पूनिया)

यह जवाब मिला कि 90 एम. एम. के पाइप राजस्थान में कहीं उपलब्ध नहीं है। हमने बहुत जानकारी की लेकिन मैं उसमें सफल नहीं हो सका और मुझे यह जानकारी दी गयी कि 90 एम. एम. के पाइप उपलब्ध नहीं हैं और उस कारण से स्कीम को मलाउटीबा से जोड़ नहीं सकते। लेकिन अध्यक्ष महोदय, गवर्नर शासन 1994 में लगा, राष्ट्रपति शासन आया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ज्यों ही गवर्नर शासन लगा, पन्द्रह दिन के अन्दर अजमेर से 90 एम. एम के पाइप चार किलोमीटर लाइन के हमें मिले और मनीम से मलाउटीबा वे पाइप जोड़कर 25 किलोमीटर गवर्नर शासन में बिजली की लाइन मेरे क्षेत्र में जोड़ी गयी, फिर वह काम चालू हुआ। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार लोगों के साथ पानी के नाम पर खिलवाड़ कर रही थी। हमने लगातार यह मांग की कि इस पाइंट को जोड़ा जाए, 90 एम. एम. के पाइप दिये जाएं लेकिन, अध्यक्ष महोदय, हमें यह बताया गया कि पाइप नहीं हैं। और गवर्नर शासन में वे ही पाइप उपलब्ध हुए, जुड़े मेरा यह कहना है, हमारे जलदाय मंत्रीजी की इच्छा नहीं थी कि पाइप लाइन दी जाए।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक निवेदन करना चाहूंगा, यह स्कीम एशिया की इतनी बड़ी स्कीम है कि इस स्कीम को देखकर ही राजस्थान में जोधपुर, बीसलपुर सब स्कीमें बनायी गयीं। 33 के. वी. सब ग्रेड स्टेशन से इसको दो-तीन जगह से जोड़ा गया है ताकि बिजली की आपूर्ति पूर्णतया हो सके। पूर्णतया वायरलैस सैट्स से इस स्कीम को जोड़ा गया। गंधेली से ललानिया, स्योरानी और तारानगर-राजगढ़, यह टोटल तंत्र वायरलैस सैट्स से जुड़ा हुआ है। लेकिन, माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे मालूम नहीं क्या परेशानी है इनको? इतनी बड़ी स्कीम को किस कारण से इन्होंने फेल कर दिया। क्यों नहीं इसके ऊपर ध्यान दिया? यह तो इनका अन्तर मन ही जाने, लेकिन, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह कह सकता हूं इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस स्कीम के साथ खिलवाड़ किया। विगत समय में आपने देखा होगा कि हमारे चूरू जिले में पानी के लिए त्राहि-त्राहि मची है। इसलिए मेरा निवेदन है कि 353 गांवों को पानी देने वाली इस स्कीम का रख-रखाव अच्छे प्रकार से किया जाए।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि पीने के पानी की कोई समस्या नहीं है। न आई. जी. एन. पी. कैनाल में पीने के पानी की समस्या है, न इसमें आने की समस्या है। समस्या है तो हमारे बी. जे. पी. के माननीय भंवरलालजी के मन की इच्छा की है। अब भगवान जाने इनका क्या चन्दनमल जी से आपस में मनमुटाव है। मैंने पिछले सत्र में भी इनको कहा था कि आपके मनमुटाव को कृपा करके चूरू जिले की जनता के बीच में मत लाइए, इस स्कीम के साथ खिलवाड़ मत कीजिए।

(श्री इन्द्रसिंह पूनिया)

माननीय अध्यक्ष महोदय, ललानिया एक पाइंट है, छह मोटरें ढाई सौ हार्स पावर की चलती हैं, वहां से लगभग ढाई करोड़ लीटर पानी साहबा पहुंचता है और साहबा से मलाऊ पानी पहुंचता है। लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय, छह मोटरें वहां काम नहीं करती हैं, वहां मात्र दो मोटरें चलती हैं, स्टैंड बाई मोटरें हैं विभाग की बाकी सब खराब पड़ी हैं। इस प्रकार से जब वहां मोटरें ही नहीं चलेंगी तो पानी कैसे पहुंचेगा ? क्या मोटरों का नियन्त्रण इनके बश में नहीं है ? क्या अधिकारी इनको इतनी मानते नहीं हैं ? अध्यक्ष महोदय, मैं फिर साफ कहना चाहता हूं कि इनकी नीयत साफ नहीं है चूरू जिले को पानी देने की।

माननीय अध्यक्ष महोदय, भाभड़ाजी जिस समय यहां स्पीकर थे, उन्होंने पूरे चूरू जिले का भ्रमण किया था, पानी की समस्या के बारे में जानकारी ली थी। चाहे उनके मन में कुछ भी हो लेकिन जहां-जहां ये गये थे, वहां के अधिकारियों को निर्देश दिये थे उस समय, कि पानी की समस्या नहीं आनी चाहिए। कुछ एग्जीक्यूशन हुआ। लेकिन अब जब ये हमारे उप मुख्य मंत्री हैं, सिवाय रतनगढ़ के तारानगर, राजगढ़ कहीं जाकर नहीं संभाल रहे हैं। पता नहीं क्यों नहीं जा रहे हैं। या तो भंवरलालजी इनको जाने नहीं देते या इनके मन में अब लगाव नहीं रहा। लेकिन मैं आपको ईमानदारी से कह रहा हूं कि पीने के पानी की समस्या मानव से रिलेटेड है। खास कर इस विभाग से राजनैतिक भेदभाव के कारण मैं स्पष्ट आरोप लगाऊंगा भारतीय जनता पार्टी के मंत्री जी पर, कि इनका यह स्पष्ट इरादा है कि इस क्षेत्र में पीने का पानी नहीं पहुंचे, यह स्कीम किसी प्रकार से फेल्योर दिखाई दे ताकि लोगों में यह आए। आए दिन वहां ये कहते रहते हैं कि आप कांग्रेस को वोट दो और ले लो पानी।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने कहा कि इस योजना को देखने के लिए दो बार माननीय राजेन्द्र सिंहजी राठौड़ और मंत्रीजी के साथ हमने टूर किया। जब आप वहां पधारे, वह स्कीम हमारे क्षेत्र से जुड़ी हुई है, आपका कम से कम यह दायित्व तो बनता था, ओब्लीगेटरी ड्यूटी आपकी थी, कि वहां के क्षेत्रीय विधायक को बुलाते। मैं भी हूं, क्योंकि मेरा क्षेत्र भी वहां जुड़ा हुआ है। आपने कभी आपके प्रोग्राम की कापी तक नहीं भेजी ताकि हम आपके साथ रहते आपको मौके पर बताते कि ये-ये परेशानियां हैं, यहां पानी है। लेकिन आपने कभी यह भी नहीं समझा। आपने देखा कि ये साथ रहेंगे तो आपके अधिकारियों की और आपकी पोल खुल जाएगी। आपने टूर में क्या किया ? सिर्फ एक जे. ई. एन. को सस्पेण्ड किया, उसके सिवाय आपने कुछ भी नहीं किया।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि बजट में भाभड़ा जी ने यह बताया है कि इतनी ढाणियों को पानी देंगे, वह देंगे। ठीक है, सरकार भी रही है, खर्चा कर रही है लेकिन जितनी स्कीमें

(श्री इन्द्रसिंह पूनिया)

चली हैं हमारे चूरू जिले में, ये कह रहे हैं आंशिक रूप से चूरू जिले के तारानगर, राजगढ़ क्षेत्र के आधे गांवों को आज तक बरसात हो गयी, लेकिन पीने का पानी नहीं पहुंच रहा है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको दो-तीन बातें इनकी बता रहा हूं कि इनके मन में जनता के प्रति कैसा लगाव है। जब राष्ट्रपति शासन पिछली बार लागू हुआ था... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप तो कोई सुझाव दें जिससे इस पर कोई कारगर कदम सरकार उठाए।

श्री इन्द्रसिंह पूनिया : सुझाव तो मैं सिर्फ एक ही दूंगा कि ये मन साफ कर लें। पानी की कोई कमी नहीं है, ये मन में यह कर लें कि मुझे पानी देना है, राजनैतिक भेदभाव नहीं करना है तो कोई दिक्कत नहीं है।

श्री भंवरलाल शर्मा (जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर यही इनका सुझाव है कि मेरा मन साफ कर लूं तो यह इनका बड़ा भ्रम है कि चन्दनमलजी से मेरे कोई सम्बन्ध खराब हैं।

श्री इन्द्रसिंह पूनिया : मुझे तो यही लग रहा है।

श्री भंवरलाल शर्मा (सरदारशहर): यह किसी ने बहका दिया आपको। (व्यवधान) आप एक मिनट ठहरो, भाईसाहब। आपका सामान्य ज्ञान बहुत कम है, मेरे इनके सम्बन्ध खराब बता रहे हो आप।

श्री इन्द्रसिंह पूनिया : देखिये, मैं तो बच्चा हूं आपके सामने। ज्ञान तो मेरा है ही नहीं।

श्री भंवरलाल शर्मा (सरदारशहर) : मेरे सम्बन्ध इनके कहां से बता रहे हो आप ? किस बात के ? ये वहां राज करते हैं, वहां काम करते हैं, मैं जयपुर में हूं। मेरा और इनका क्या लेना-देना है ? किस बात की लड़ाई हो गयी मेरी इनसे ?

श्री इन्द्रसिंह पूनिया : भंवरलाल जी, आपकी बड़ी तड़फन है वहां।

श्री भंवरलाल शर्मा (सरदारशहर) : हैं, क्या कह रहे हो ?

श्री इन्द्रसिंह पूनिया : आपकी राज–गढ़–तारानगर में बड़ी तड़फन है। आप कहां काम कर रहे हो, क्या कर रहे हैं, मुझे मालूम नहीं।

श्री भंवरलाल शर्मा (सरदारशहर) : नहीं, वह तड़फन अलग बात है। चन्दनमल जी से मेरा कोई मतभेद नहीं है।

श्री इन्द्रसिंह पूनिया : मुझे मालूम नहीं, लेकिन मतभेद नहीं है तो ...(व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा (सरदारशहर) : मालूम नहीं है, तो बोल रहा हूं न आपको। मैं तो इनको बड़े भाई की तरह मानता हूं।

श्री इन्द्रसिंह पूनिया : फिर हमें लाठियां क्यों खानी पड़ीं ? अगर भेदभाव नहीं है आपका तो यहां आने पर हमें लाठियां क्यों खानी पड़ीं ?

श्री भंवरलाल शर्मा (सरदारशहर) : अब वह तो अलग बात है लेकिन ...

श्री इन्द्रसिंह पूनिया : अलग बात क्या है ? पानी के लिए ही था, हमारा कोई आपसे मनमुटाव नहीं है ।

श्री भंवरलाल शर्मा (सरदारशहर) : मेरा भी इनसे कोई मनमुटाव नहीं है ।

श्री इन्द्रसिंह पूनिया : आप हमारे आदरणीय हैं, हमारे लिए पूजनीय हैं । हमारे लिए तो बुजुर्ग हैं आप ।

श्री भंवरलाल शर्मा (सरदारशहर) : आप ऐसा करो, आप तो चन्दनमल जी से कहलवा दो कि मेरे मन में इनके प्रति मनमुटाव है क्या । ये खुद ही कह दें ।

श्री इन्द्रसिंह पूनिया : चन्दनमल जी और आपकी, चूरू जिला थोड़े ही मानता है । चूरू जिले के अंदर ये कह रहे है कि ये लड़ रहे हैं इसलिए हमें पानी नहीं दे रहे हैं । हमें यही मालूम है ।

श्री भंवरलाल शर्मा (सरदारशहर) : कोई लड़ाई नहीं है मेरी ।

श्री इन्द्रसिंह पूनिया : लड़ाई नहीं है तो फिर पानी क्यों नहीं दे रहे हैं आप ? कोई न कोई मनमुटाव तो है ही ।

श्री अध्यक्ष : यदि मनमुटाव ही है तो चन्दनमल जी कहते क्यों नहीं हैं ?

श्री इन्द्रसिंह पूनिया : अब चन्दनमल जी से थोड़े ही ... (व्यवधान)

श्री चन्दनमल बैद (तारानगर) : मुझसे क्यों कहलाते हैं आप ? मुझसे कहलाएंगे तो इनकी पोल खुल जाएगी ।

श्री भंवरलाल शर्मा (सरदारशहर) : खोल दो । खोल दो ।

श्री चन्दनमल बैद : जानबूझकर वहां पानी नहीं पहुंचाया जा रहा है, यह साबित करने के लिए कि यह योजना चन्दनमल जी ने शुरू की थी, चन्दनमल के वक्त में इसका उद्घाटन हुआ था । यह योजना फाल्टी है इस वास्ते इसमें पानी नहीं पहुंच रहा है यह साबित करने के लिए । ये बार-बार खुद कहते हैं और इनके मंत्री जो साथ जाते हैं, वे कहते हैं । कभी कहते हैं यह योजना गलत बन गयी, कभी कहते हैं पाइप गलत आ गए । मैं तो 1976 में इस विभाग को छोड़ चुका था, उसके बाद पाइप गलत आ गए तो मेरा क्या कसूर है ? 22 साल तक पाइप गलत पड़े रहे और पानी आता रहा, तो आज क्या बात है ? पानी क्यों नहीं आ रहा है उसमें ? इन लोगों का मन साफ नहीं है । ये जनता को यह बताना चाहते हैं कि यह योजना फाल्टी है । जबकि यह योजना एशिया की सबसे बड़ी रीजनल योजना है और जर्मन सरकार ने यही देखकर 800 करोड़ रुपये की सहायता दी इस योजना के लिए । मन साफ की बात क्या कहूं अब मैं इनसे ? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आपका कहना किसी सीमा तक ठीक-सा लगता है ।

श्री इन्द्रसिंह पूनिया : लग रहा है न ? मैं कभी असत्य बात कहूंगा ही नहीं ।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (राज्य मंत्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य) : इसमें कोई शक नहीं है कि पीने के पानी की समस्या का समाधान आपने करने की कोशिश की थी और इस समस्या के समाधान के लिए इस सरकार ने भी कोशिश की । परन्तु, बैद साहब, पानी के नाम पर जब राजनीति होती है, पानी के अंदर से वोट निकालने की कोशिश होती है तो उसके तो प्रतिवाद स्वरूप लोगों को वस्तुस्थिति बतानी पड़ेगी। सारी उसी की बात है मनमुटाव की कोई बात ही नहीं है । आपका उद्देश्य भी लोगों को पानी पहुंचाना है और हमारा उद्देश्य भी लोगों को पानी पहुंचाना है ।

श्री जगदीप धनखड़ : मंदिर के नाम पर राजनीति कर लो और ये पानी के नाम पर नहीं कर सकते ?

श्री अध्यक्ष : नहीं, यह मामला नहीं है ।

श्री चन्दनमल बैद : पानी नहीं मिल रहा, उसके लिये अगर मैं हल्ला मचाता हूं कि लोगों को पानी नहीं मिल रहा है, उसको आप राजनीति समझते हो । और क्या करूं फिर ? पानी के लिए बोलूं ही नहीं ? अगर पानी नहीं आ रहा है उसके लिए मैं कहता हूं, उसके लिए मैं अगर कहीं घेराव करता हूं, डिमास्ट्रेशन करता हू, प्रदर्शन करता हूं, शांति से जुलूस निकालता हूं, यह भी इनको नामंजूर होता है, कहते हैं राजनीति कर रहे हैं । फिर और क्या करूं पानी के लिए ? चुपचाप घर पर बैठा रहूं ?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : माननीय अध्यक्ष महोदय, चन्दनमल जी गांधीवादी विचारों के हैं, इसमें मुझे कोई डाउट नहीं । पर मैं निवेदन करना चाहता हूं, पानी की समस्या का समाधान कोई जाकर के नारों से, प्रदर्शन से और चुनाव के आखिरी साल में नहीं होता । आज तक चूरू जिले के अंदर अप्रेल के थर्ड वीक से मीटिंगें चालू हुई और कम से कम छह मीटिंगें ऐसी थीं जिनमें माननीय बैद जी को, इन्द्रसिंह जी पूनिया को आमन्त्रित किया गया । हर साल, कोई साल ऐसा नहीं गया जिसमें भंवरलाल जी शर्मा ने विशेष तौर पर, मैंने तो कई बार कहा भी कि आपका तारानगर से मोह क्या है, ये बोले चन्दनमल जी के प्रति मेरा स्नेह है, इसलिए मैं चाहता हूं कि वहां जाकर आंखों से देखूं । वहां जाकर आंखों से समस्या देखी । परन्तु पानी की समस्या के समाधान के लिए हम जिला स्तर पर समाधान की बैठक करें पर उसके अंदर ये कभी आए नहीं, विचार हम करें नहीं और उसके बाद चुनाव के लिए हम आखिरी समय में बात करें और आरोप लगाएं तो मैं इसको उचित नहीं समझता ।

श्री चन्दनमल बैद : आप मीटिंग बुलाते हैं उसकी सूचना मिलती है मीटिंग के बाद मुझे । कैसे आ जाऊं मैं ? आप कहें तो सबूत दे दूं मैं । आपने मीटिंग

(34)

(श्री चन्दनमल बैद)

जुलाई 7 तारीख की सूचना मुझे मिलती है 8 तारीख को। मैं कैसे आ जाऊं वहां पर? फिर दौरा किया आपने और आपके मंत्री महोदय ने, जलदाय मंत्री ने मुझे और इन्द्रसिंह जी को आपने सूचित किया। ये कह सकते थे, आप कलक्टर को कह सकते थे कि चन्दनमल जी कहीं भी हों, उनको सूचित कर दो कि हम लोग आ रहे हैं। अपनी तकलीफ हमको बताएं। यह सारा आपका मन मैला था दोनों का, आप दोनों मैले मन से वहां गये थे। आपने वहां योजना नहीं देखी, आपको मालूम नहीं पड़ा कि कहां कमी है। ललाणिया में 6 मोटरें लगी हुई हैं उसमें से 3 मोटरें खराब हैं, एक मोटर ललाणिया से पानी दे रही है गोहर को और दो मोटरों से पानी आ रहा है। दो मोटरें बराबर चलती रही हैं। जो 25 मिलियन लीटर प्रतिदिन पानी वहां आना चाहिये सलोव टीबा में, उसकी जगह 12–13 मिलियन लीटर प्रतिदिन पानी आता है, तो कहां से पानी मिलेगा? यह चीज तो आप देख नहीं पाते हैं, यह तो आपकी अक्ल में आती ही नहीं है और दोष मुझे देते हैं कि राजनीति करते हैं।

श्री इन्द्रसिंह पूनिया : रामेश्वरजी, आप बैठ जाइये, आपके पानी की दिक्कत नहीं होगी। रामेश्वरजी, लोग बता रहे थे कि रामेश्वरजी भाटी को तो अब के बताएंगे पानी समाप्त हो गया चूरू जिले में।

श्री रामेश्वरलाल भाटी (सुजानगढ़): अध्यक्ष महोदय, मुझे कुछ कहना है। सादुलपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने माननीय चन्दनमलजी के रैफरेंस से जो चूरू जिले के पीने के पानी की समस्या का विषय लिया है, यह निश्चित है कि माननीय चन्दन मलजी ने पानी के लिए पूरे जिले में अपनी दृष्टि से विषय को आकर्षित किया है। अपने अभिविचारों में उन्होंने यह भी दर्शाया कि मैं चूरु जिले के लिए पानी चाहता हूं और माननीय मंत्री महोदय द्वारा भी इस समस्या को सीधे और साफ मन से हल करने का विषय रखा गया है, परन्तु मेरा एक आरोप है....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया आप अपने टर्न पर बोलें। बिराजें आप। आपको समय दे दूंगा मैं, आप बिराज जाएं। (व्यवधान)

श्री रामेश्वरलाल भाटी : पानी के लिए मन साफ चन्दनमलजी का नहीं था। पानी के लिए चन्दन मलजी का मन साफ इसलिए नहीं था। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : नहीं, यह कोई वाद–विवाद नहीं है। कृपया आप बिराज जाएं, माननीय सदस्य। (व्यवधान)

श्री रामेश्वरलाल भाटी : विधायकों द्वारा पांच–पांच लाख रुपया पानी की समस्या के लिए देने का जब तय हुआ तो सबसे पहले इन्होंने इन्कार किया।(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कृपया आप बिराज जाएं (व्यवधान) यह मूल्यवान समय है, इसको खराब नहीं करें, माननीय सदस्य। (व्यवधान) श्री पूनियाजी, अब समाप्त करें।

(35)

श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम) : आपका मन साफ नहीं है, आप क्यों लांछन लगा रहे हो ?

श्री इन्द्रसिंह पूनिया : अध्यक्ष महोदय, मैं दो मिनट में इनका प्रतिवाद प्रस्तुत कर रहा हूं ।

श्री अध्यक्ष : प्रतिवाद को तो छोड़ो, आप अपनी बात कहिये । वह तो हो गया ।

श्री इन्द्रसिंह पूनिया : माटीजी ने ये जो बातें कहीं उनका निवेदन कर रहा हूं मैं । माननीय मंत्रीजी, राजेन्द्र सिंहजी ने जो....

श्री अध्यक्ष : हो गया । चन्दन मलजी और भंवर लालजी का दिल थोड़ा हल्का हुआ है, आप अपनी बात कहें ।

श्री इन्द्रसिंह पूनिया : अध्यक्ष महोदय, इन्होंने इन्टरवीन किया, उसका थोड़ा जवाब दे रहा हूं । ये कह रहे हैं पानी की राजनीति कर रहे हैं, अध्यक्ष महोदय, मेरा स्पष्ट कहना है कि यहां तो पानी की राजनीति का नाम लिया जा सकता है ...

श्री रामेश्वरलाल माटी : अध्यक्ष महोदय, मेरा भी स्पष्ट कहना है कि इनका मन साफ नहीं था । (व्यवधान)

श्री इन्द्रसिंह पूनिया : आप बैठ जाइये, आप अपने समय पर बोलना ।

श्री अध्यक्ष : यह जवाब मंत्री महोदय दे देंगे, माननीय सदस्य, कृपया बिराजें ।

श्री इन्द्रसिंह पूनिया : जनता आपको बताएगी । मेरा निवेदन यह था कि यहां तो यह कहा जा सकता है कि चन्दन मलजी पानी की राजनीति कर रहे हैं लेकिन जहां पीने के पानी का घोर संकट है, समस्या तो वहां के लोगों की है । राजेन्द्र जी, यह निर्णय चूरू जिले की जनता पर छोड़ रखा है, अगर हमने पीने के पानी की राजनीति की है, लोगों की समस्या नहीं है तो लोग समझ जाएंगे हमें और अगर वहां समस्या है और आप यह बोल रहे हैं तो आपको समझ जाएंगे ।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : ठीक है, जनता पर छोड़ दिया ।

श्री इन्द्रसिंह पूनिया : इसलिए विवाद का मुद्दा यह नहीं है कि पानी की राज–नीति कर रहे हैं । क्या कह रहे हैं वह तो वहां की जनता पर छोड़ा हुआ हो है, समय आ रहा है, समय इन्तजार कर रहा है । (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आ गया समय ।

श्री अध्यक्ष : अब आप बिराजें । और कुछ कहना चाहते हैं ?

श्री इन्द्रसिंह पूनिया : अध्यक्ष महोदय, मैं दो शब्द और कहना चाहता हूं । अध्यक्ष महोदय, आप कह रहे हैं ये पानी की राजनीति कर रहे हैं....

श्री अध्यक्ष : नहीं, यह तो छोड़ो, इससे आगे चलो ।

श्री इन्द्रसिंह पूनिया : इस टोपिक पर इनको साबित कर रहा हूं कि पानी की राजनीति कौन कर रहा है ।

(36)

श्री अध्यक्ष : वह तो हो चुका।

श्री इन्द्रसिंह पूनिया : हुआ नहीं है, मैं अभी बताने जा रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय, जब पिछले चुनाव थे तो मैंने चुनाव की सभा में यह घोषणा की थी कि आने वाली होली के दिन राजगढ़ और तारानगर तहसील के गांव को हम मीठे पानी में चावल रंधवाएगे। यह मेरी घोषणा थी।

श्री अध्यक्ष : राजगढ़, चूरू बोलिये आप। राजगढ़ अलवर में भी है। (व्यवधान)

श्री इन्द्रसिंह पूनिया : राजगढ़ तारानगर आ रहा है न फिर साथ। अलवर भी आपका और हमारा एक ही है।

मैंने यह घोषणा की थी कि अब की आने वाली होली के चावल नहर के मीठे पानी में हम आपको रंधवा कर देंगे, पका कर देंगे। अध्यक्ष महोदय, उसी दिन से यह राजनीति इन्होंने शुरू की। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने यह सोचा, मंत्री महोदय ने और हमारे राजेन्द्र सिंह जी, मैं तो नाम नहीं लूंगा, इनके मन में यह खिचड़ी उबलने लगी कि अगर यह होली के चावल मीठे पानी में पकेंगे तो कांग्रेस के इन्द्रसिंह पूनिया और चन्दनमल जी बैद का, कांग्रेस का नाम होगा। अध्यक्ष महोदय, उसी दिन से उस स्कीम के साथ खिलवाड़ शुरू हुआ। भंवरलालजी, आप नोट कीजिये, इसकी जांच करना, वहां तीन पाइंट हैं पानी डिस्ट्रीब्यूट करने के। एक मानपुरा गांव है जहां हमारा हौद है, वहां 20 गांवों को पानी डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। एक ढिगारला गांव है, एक बुंगी गांव है। जब राष्ट्रपति शासन खतम हुआ, चुनाव शुरू हुए उस दिन इन गांवों में इन हौदों में पानी लबालब भर चुका था। अध्यक्ष महोदय, इन हौदों से ये गांव जो मैं नाम ले रहा हूं, मात्र 10 किलोमीटर हैं। मेरा स्वयं का गांव नांगल छोटी, धानुठी छोटी, धानुठी बड़ी, तापाखेड़ी ये गांव इस पाइंट ढिगारला से मात्र 10 किलोमीटर हैं। अध्यक्ष महोदय, राजनीति पानी की ये कर रहे हैं। ये चाहते हैं कि इनके गांव में पानी नहीं पहुंचे। पांच साल हो गये, 10 किलोमीटर तक इन 15 गांवों में आज तक पानी नहीं दे सके, अगर वे राजनीति यह नहीं कर रहे हैं तो कौन कर रहे हैं? क्या 10 किलोमीटर पांच साल में 10 गांवों में पानी नहीं दे सकते थे?

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रमुख शासन सचिव, श्रीमती भटनागरजी से भी मिला। मैंने कहा कि इन गांवों में पानी क्यों नहीं दे रहे हो, बहुत नजदीक हैं? उन्होंने मुझे आश्वासन दिया था आज से ढाई साल पहले कि, पूनियाजी, दिसम्बर में इन गांवों में पानी पहुंच जाएगा। अध्यक्ष महोदय, मैं चैलेंज करता हूं, आप जांच करवा लीजिये, अगर इन 10 गांवों में पानी पहुंचा हो तब तो हम राजनीति कर रहे हैं और पांच साल में मात्र 10 किलोमीटर आप पानी नहीं दे सके तो पानी की राजनीति आप कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे हैं। आपके दिल में यह मलाल है कि अगर

(श्री इन्द्रसिंह पूनिया)

पीने का पानी पहुंच गया तो नाम इन एम. एल.एज. का होगा, हमारा नहीं होगा इसलिए जानबूझकर के राजगढ़, तारानगर और चूरू जिले को माननीय भंवरलालजी बरबाद करने पर तुले हुए हैं। यह मेरा स्पष्ट आरोप है। अध्यक्ष महोदय, क्या पांच साल में पांच किलोमीटर पानी नहीं पहुंच सकता ? यह तो मान सकते हैं कि पूरी स्कीम में कहीं न कहीं लैकूना रह जाए, और कुछ रह जाए लेकिन मैं इनके प्रमुख शासन सचिव, भटनागरजी से मिला हूं; इनको लैटर लिखा हूं। मेरा गांव उस स्कीम से मात्र आठ किलोमीटर है और आठ किलोमीटर में पांच साल में आज तक इन्होंने पानी टैस्टिंग शुरू नहीं किया, मैंने बार-बार कह दिया। इसका मतलब साबित है कि पानी की राजनीति चन्दनमलजी और इन्द्रसिंह पूनिया नहीं कर रहे हैं, पानी की राजनीति किसी के दबाव में आप कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : अब आप बैठें।

श्री इन्द्रसिंह पूनिया : इसलिए, अध्यक्ष महोदय, राजनीति कौन कर रहा है, क्या कर रहा है, वह तो चूरू जिले की जनता बताएगी। यहां लोगों पर लाठी प्रहार हुआ था पीने के पानी के लिए। पानी से पतली कोई चीज नहीं होती है और, रामेश्वरजी भाटी, आप कह रहे हैं हमारे चूरू जिले में पानी की कमी नहीं है तो ठीक है, सुजानगढ़ की जनता आपको बताएगी। कमी नहीं है तो आपको धन्यवाद देगी और पानी की कमी है तो आप सलटना उनसे। वह तो समय बताएगा। आपने मुझे समय दिया, धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री कालूलाल गूजर।

(अनुपस्थित)

श्री अमरचन्द मिड्ढा।

श्री अमरचन्द मिड्ढा (सूरतगढ़) : अध्यक्ष महोदय, आज पेयजल की मांग संख्या- 27 पर बहस हो रही है। मैं इसमें अपने आपको शामिल करते हुए भारतीय जनता पार्टी सरकार को व भंवर लालजी को धन्यवाद देना चाहता हूं। हमारे क्षेत्र में बहुत काम हुआ है परन्तु हमारे क्षेत्र में टीबा क्षेत्र पड़ता है उसमें कुछ हिस्सा श्री रामप्रतापजी कासनियाँ के क्षेत्र में आता है और कुछ मेरे क्षेत्र में आता है, वहां पानी की यह हालत है कि गर्मियों में लोगों को पीने के लिए पानी नहीं मिलता और जब हम कभी चले जाएं तो हम को देख कर रोना आता है। मैं कई दफा अधिकारियों को कह चुका हूं कि हमारे देवीदासपुरा में 35 किलोमीटर से पानी उदयपुर से आता है। देवीदासपुरा से जाता है लघेर, लघेर से जाता है सांवलसर और भोजुसर। तो मैंने कहा कि राज्यासर में अब लिफ्ट कैनाल आ गयी है, आप लिफ्ट कैनाल से जोड़ दो तो सिर्फ 12 किलोमीटर देवीदासपुरा पड़ता है। 23 किलोमीटर दूरी से पानी आता है तो कोई न कोई चरवाहा नाल काट देता है कुल्हाड़ी से पानी पीने के लिए और तोड़ कर चला जाता है। उसको कोई भी कर्मचारी संभाल नहीं

(श्री अमरचन्द मिड्डा)

सकता। न वहां पक्की सड़क है, न कोई रास्ता है, इस वास्ते लोग टीबों में जाते हैं। इस वास्ते नालें जो लगी हुई हैं, मैं मंत्री महोदय से यह प्रार्थना करता हूं कि उनको राज्यासर से जुड़वाएं, गांवों को एक सीधी लाइन देवें। जैसे देवीदासपुरा से जाता है लघेर और लघेर से जाता है सांवलसर, तो लघेर से वो पानी आगे जाने नहीं देते, सांवलसर वाले इस वास्ते रह जाते हैं। मेरा मंत्रीजी से यह कहना है कि उनको सीधा जुड़वाएं। चाहे कितना ही पैसा लगे, उसको सरकार को बर्दाश्त करना चाहिये और उनको पीने के लिए पानी देना चाहिये। एक तो मेरा यह निवेदन है।

दूसरा निवेदन यह है कि लालगढ़ से स्कीम जाती है कूमकड़िया और सोनाथपुरा। कूमकड़िया में जब पानी जाता है तो वो सोनाथपुरा को जाने नहीं देते। गर्मियों में उनके ये हालात हो जाते हैं कि 20-25 किलोमीटर से पानी के लिए पैदल चल कर आना पड़ता है। नहरी क्षेत्र में तो पानी किसी जगह स्कीम दें या नहीं दें, वहां लोग फिल्टर पानी चाहते हैं जबकि उन लोगों को पीने का पानी नसीब नहीं होता। नीचे जो कुंए हैं उनका पानी खारा है। मेरी माननीय मंत्रीजी से यह प्रार्थना है कि इस समस्या को हल करें। इनके अधिकारी आज आये हुए हैं इनको कहें कि ये स्कीम्स बनाये और लोगों को पानी देवे। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : बहुत बढ़िया। श्री भीमराज भाटी।

श्री भीमराज भाटी (पाली) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सबसे पहले तो धन्यवाद देना चाहता हूं अल्प बचत मंत्रीजी और जलदाय मंत्रीजी को कि सरकार की विभिन्न एजेंसियों से चाहे वह डी.आर.डी.ए. हो, चाहे जे.आर.वाई. हो और चाहे अल्प बचत हो, जी.एल.आर्स. बने, बहुत सारे टांके बने। लेकिन, माननीय अध्यक्ष महोदय, ये टांके और जी.एल.आर्स. पाइपों की खरीद-फरोख्त के कारण जुड़े नहीं, चार--साढ़े चार साल हो गये। वे जी.एल.आर्स. जर्जर होने की स्थिति में आ गये हैं लेकिन अभी तक पाइप लाइन से जुड़े नहीं हैं। पहले पाइप खरीदे गये तो वे पाइप खराब खरीदे गये, बेकार क्वालिटी के खरीदे गये। पाइप खरीद लेते हैं तो जोइंट्स नहीं होते हैं, जोइंटस होते हैं तो रिंग नहीं होते हैं और रिंग होते हैं तो वाल्व नहीं होते। पाली शहर में इतनी बड़ी योजना चल रही है, अध्यक्ष महोदय, पाइप लाइन के लिए सड़कें तोड़ दी गयीं, पाइप उसमें बिछा दिये गये लेकिन अभी तक उसमें वाल्व नहीं हैं, रिंग्स नहीं हैं। जिस मकसद से आप करोड़ों रुपया खर्च कर रहे हैं वह करोड़ों रुपया आपका लग जाता है, सड़कें दो--दो बार टूट जाती हैं लेकिन वे जुड़ते नहीं और पीने के पानी के लिए जनता वैसे की वैसे दुखी रहती है।

दूसरा मैं निवेदन करता हूं कि ये पानी की राजनीति की जो बात कर रहे हैं, तो पानी की राजनीति का काम शुरू से चल रहा है पानी के मामले में राजनीति हमारे इलाके में हुई है। जब पुराना

(श्री भीमराज भाटी)

शासन था उस वक्त भी यह राजनीति हुई। हमारे यहां रोहित का तालाब पहले भरा जाता है, उस रोहित के तालाब से बड़े लोगों ने अपने घरों में कनेक्शन ले रखे हैं। तो रोहित का तालाब भरने के लिए हमारे रोहित का चौराहे का इलाका आज दिन तक पीने के पानी के बिना प्यासा है। पाली से जयपुर की एक जलदाय योजना है, उस जलदाय योजना में भी राजनीति की जा रही है। वह तीन तरफ से और चार तरफ से बनायी जा रही है। मेरा, अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय से यह निवेदन है कि मेहरबानी करके पीने के पानी के मामले में कोई राजनीति नहीं करके टैक्निकली और इकोनोमिकली जो फिजीबल और वाइबल हो कि पानी इधर से पहुंच सकता है, उधर से पानी पहुंचा दीजिये। आप टंकी यहां से सैंक्शन करते हैं, अल्प बचत मंत्रीजी ने कई टंकियाँ यहां के लिए सैंक्शन कीं, और आपके अधिकारी लोग गांव में जाकर उल्टा-सीधा करके गांव के लोगों को आपस में लड़ा देते हैं। विश्नोई बिरादरी के लोग हैं वे कुछ कम समझते हैं तो उन लोगों को कह देते हैं कि यह टंकी यहाँ करनी है या कहां करनी है। इस तरह यह राजनीति मत करिये।

दूसरा आपके कार्यकर्ता जो वहां बैठे हुए हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, लोगों ने अवैध कनेक्शन अपनी फैक्ट्रियों में ले रखे हैं। अपने घरों के टांके भर रहे हैं। उसकी वजह से आपके जी. एल. आर्स. में पानी नहीं आता है। हम वहां के जिलाधीश को कह-कहकर तंग हो गये, चिट्ठियां लिख-लिखकर परेशान हो गये लेकिन गांवों और शहरों में जो अवैध कनेक्शन लगे हुए हैं उन अवैध कनेक्शन को तोड़ने और हटाने की हिम्मत किसी की नहीं है। मैं विधान सभा का जब से सदस्य बना हूं, केशवनगर जो आर.एस.एस. के सर्वेसर्वा हैं, उनके नाम से जो नगर बना हुआ है, मंत्री महोदय ने उसके ऊपर कृपा की और उस केशवनगर को पानी पहुंचाने के लिए आपने पाइपों की व्यवस्था की, आपने पैसे मंजूर किये। उस व्यवस्था से वहां के आपके कार्यकर्ताओं ने गरीब लोगों को तो पानी नहीं पीने दिया लेकिन अपनी फैक्ट्री में वे पाइप लाइन उठाकर ले गये। आप जब वहां बिराजमान थे तब वे लोग आपसे मिले थे लेकिन कुछ नहीं हुआ।

दूसरा, अध्यक्ष महोदय, हमारे पाली जिले के माननीय मंत्री महोदय यहां नहीं हैं, उनके इलाके देसूरी की बात है। किशन-पुरा गांव है, रावड़िया गांव है। हालत यह है, ऐसा गन्दा पानी पिलाया गया कि 27 लोग मर गये। माननीय मंत्री महोदय के इलाके की बात है।

श्री अध्यक्ष : यह पानी कहां से लाये हैं आप ?

श्री भीमराज भाटी : अध्यक्ष महोदय, उस कुंए से लाया हूं।

श्री अध्यक्ष : जयपुर....

श्री भीमराज भाटी : और यह कैसेट है मेरे पास। 27 लोग जो मरे हैं उनमें से 19

(श्री भीमराज भाटी)

एक गांव के हैं और आठ दूसरे गांव के हैं। जिनके घर से ये लोग मरे हैं, जिला प्रशासन ने और अधिकारियों ने उन लोगों को डरा-धमका दिया। यह मैं सैम्पल लाया हूं उस कुंए से इसमें जीव–जन्तु हैं। मतलब यह है कि जो छोटे-छोटे बैक्टीरियाज हैं वो इतना बड़ा रूप ले चुके हैं कि आप नैकेड आई से देख सकते हैं। अध्यक्ष महोदय, उन लोगों को पिलाया गया। 19 आदमी मर गये और बाजू के गांव में आठ आदमी मर गये, इस प्रकार 27 लोग मर गये। यह कैसेट है। चाहे मंत्री महोदय देख लें और चाहे कोई सदन की समिति देख ले। उन परिवारों के लोगों की और उस कुंए की हकीकत है इसमें। किसी तरह से गांव के लोगों ने एक सार्वजनिक कुंआ बनाया था, चन्दा करके बनाया था। उस चन्दे वाले कुंए से पानी पीना चाहते थे, उसका ज्यादा अच्छा था। लेकिन किसी तरह मजबूरी में या राजनीति करके उस कुंए के नाम से पैसे मंजूर किये गये, एक बार नहीं, दो-दो बार पैसे मंजूर किये गये। वहां पाइप लाइन बिछायी गयी। गांव वाले कुआ खोदकर पानी पीना चाहते थे वह नजदीक था, लेकिन जबरदस्ती उस कुंए से पानी नहीं पिलाया। क्योंकि कुछ लोग, राजनीति यहां आती है, इच्छुक थे कि नहीं, मेरे ही कुंए का होना चाहिए। जो आदमी उसमें इनवाल्व था वह पूरे गांव को पता है, उसने एम. फोर्ट मामले में भी उन गांव वालों को धोखा दिया था। गांव वालों ने बहुत हाथ जोड़े लेकिन पता नहीं क्या कारण हुआ। मेरे विधान सभा क्षेत्र का मामला तो नहीं है लेकिन वह मेरे विधान सभा क्षेत्र से लगते हुए क्षेत्र का मामला है। माननीय मंत्रीजी यहां बिराजमान नहीं हैं, मंत्री महोदय, वहां गये थे, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्षजी भी वहां गये थे और मैं भी गया था। मैं जाकर आया हूं, यह कैसेट बनाकर लाया हूं मैं। वहां के लोगों ने बहुत हाथाजोड़ी की।

अध्यक्ष महोदय, आज हालत यह है कि जब अखबारों में यह चर्चा आयी कि प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्षजी वहां गये, मंत्रीजी वहां गये तब तो जिला प्रशासन ने वहां पर एक्टिविटी की। लेकिन इतनी तकलीफ होने के बावजूद भी उस गांव में आज दिन तक पीने के पानी की कोई व्यवस्था नहीं की गयी। पांच-दस दिन के लिए टैंकर जरूर भेजे गये लेकिन वे टैंकर भी अब बन्द हो गये और आज उस गांव में पीने के पानी की समस्या ज्यों की त्यों बनी हुई है। उस गांव में आज तक समस्या का कोई हल नहीं हुआ है। अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन है कि पीने के पानी के मामले में इसको फारमल्टी के रूप में मत लीजिये, मेहरबानी करके औपचारिकता निभाने की बात मत कीजिये। जब हम लोग यहां कुछ करते हैं, जब हम लोग चिट्ठियां लिखते हैं तो आपके कुछ लोग एक-दो दिन के लिए तो हरकत में आ जाते हैं लेकिन उसका स्थायी हल कुछ नहीं करते। उस स्थायी हल के लिए पानी जैसी इस मानवीय समस्या को गम्भीरता से लिया जाना चाहिए।

मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से

(श्री भीमराज भाटी)

निवेदन करता हूं कि जो आपका कोल्ड स्नब हो जाता है, चाहे आपका छोटे से छोटा कर्मचारी हो, चाहे आपका बड़े से बड़ा अधिकारी हो, तो पानी भी एक जगह स्थिर हो जाता है तब उसमें भी गन्दगी फैलती है। आपको कोई न कोई ऐसा सिस्टम इन्वाल्व करना चाहिए कि उस सिस्टम के माध्यम से आपके जो कर्मचारी हैं- छोटे तबके के हों या बड़े तबके,के उनका एक दूसरी जगह पर आदान प्रदान होता रहे। नहीं तो वे कर्मचारी वहां राजनीति करने लग जाते है, अधिकारी वहां पर राजनीति करने लग जाते हैं। मुझे ऐसे-ऐसे उदाहरण पता हैं कि जो गरीब बस्तियों की टंकियां थी उन गरीब बस्तियों की टंकियों को भी उठाकर कहीं और बना दिया गया। गरीब बस्तियों में जहां टुकड़ों की पाइप लाइन स्वीकृत थी, वहां पर पाइप लाइन नहीं बिछाकर जो पैसे वाले लोग थे, जो असरदार लोग थे, जो प्रभाव डाल सकते थे चाहे वे नगर पालिका में प्रभाव डाल सकते थे चाहे वे पंचायत समितियों में प्रभाव डाल सकते थे, उन प्रभावशाली लोगों ने आपकी स्वीकृत योजना को तोड़-मरोड़ दिया। आफिसर्स टैक्निकली इस ढंग से उस स्कीम को बनाते हैं उस स्कीम को तोड़-मरोड़ करके उन स्कीम्स का +++ कर दिया। आपने खर्चा भी किया लेकिन जिन लोगों के फायदे के लिए खर्चा किया उन लोगों को फायदा नहीं मिला। मेरे उस रोहिट पंचायत समिति क्षेत्र में छः गांव ऐसे हैं जिनको एक नया पैसा खर्च किये बिना जवाई नहर का पानी मिल सकता है, उन गांवों में पाइप लाइन आलरेडी जुड़ी हुई है लेकिन वे कुछ करना ही नहीं चाहते हैं। हमने जिलाधीश महोदय को कहा। मैंने कहा कि आप स्वयं देखिये, खुद साथ चलकर देखिये। उन्होंने साथ चलकर देखा उसके बावजूद भी एक नये पैसे का खर्चा नहीं। खाली वाल्व को इधर से उधर करना है। उस वाल्व को इधर उधर करने में काहे की राजनीति है। इसका मतलब किसी को मीठा पानी आप पीने ही नहीं देना चाहते हैं। छः सात गांव हमारे वहां रोहिट पंचायत समिति क्षेत्र में चौराहों के ऐसे हैं जिन गांवों में खराब ट्यूबवैल से पानी पिलाया जा रहा है। माननीय मंत्री महोदय, आपने मौका ही नहीं दिया, पिछले 3-4 साल में कभी पधारे ही नहीं पाली। आपसे बात भी हुई थी, आपने कहा भी कि मैं चलता हूं और यह करता हूं। उन गांवों के ट्यूबवैलों का पानी ऐसा है कि जानवर कुछ भी खाता है तो वह उसके पेट में नहीं पच सकता है। अध्यक्ष महोदय, मुझे यहां कहते हुए शर्म आती है कि औरतों के एवोर्शन हो जाता है उस पानी को पीने से। उस गांव की बर्थ रेट घट गयी है। गांव में जो बच्चे पैदा हुए हैं, कम से कम तीस बच्चों के फोटोज मेरे पास हैं, उन तीस बच्चों के या तो कूब निकली हुई है या हाथ-पैर में कहीं न कहीं पोलियों है। हम लोग यहां विधान सभा में कह-

---

+++ शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री भीमराज भाटी)

कह कर दुखी हो गये, जिला लेवल पर हम कह-कहकर दुखी हो गये । उन पांच-छह गांवों को जोड़ने के लिये हमें कोई करोड़ों रुपये की योजना नहीं चाहिये, कुछ भी नहीं चाहिये। लेकिन कहीं किसी को फायदा न हो जाए। कोई फायदे और नुकसान की बात नहीं है, गांव में जो लोग बैठे हैं, विशेषकर जानवर बहुत हैं, वे जानवर जैसा चारा खाते हैं, जैसा खांखला खाते हैं । वह खांखला एज इट इज बाहर आ जाता है। मतलब शरीर को पचता ही नहीं ...

श्री अध्यक्ष : पांच-छह गांवों का नाम तो बताएं । पांच-छह गांवों का नाम।

श्री भीमराज भाटी : मैं गांव का नाम बताता हूं। बड़ोरिया खालसा, बड़ोरिया जागीर, सहकारिया, मूंडिया, बोबानदी,....

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक) : अध्यक्ष महोदय, इनको तो हैण्ड पम्प देखने कई जगह जाना पड़ता है।

श्री भीमराज भाटी : हैण्ड पम्प हैं ही नहीं । हैण्ड पम्प का अंडरग्राउंड वहां पानी ही नहीं है । वहां नैचुरल जो अंडर ग्राउंड में पानी होना चाहिये, वह पानी हमारे इलाके में है ही नहीं । अगर पानी होता हम हमारे कुंओं से भी पीते। जिन गांवों में है उन गांवों में हम पीते ही हैं ।

अब जैसे मैं मीठे पानी की बात कर रहा था, तो गुमादड़ा, पड़ासुला, नीमलाखेड़ा, राजकीयावास और बागियावास, ये जो पांच-छह गांव हैं यहां मीठे पानी के लिये एक नये पैसे के खर्चे की जरूरत नहीं है। अब बिना पैसे की, बिना खर्चे की स्कीम हम बताएं कोई, कि खाली वाल्व को इधर-उधर घुमाना करना है, उसमें किसी को क्यों तकलीफ होनी चाहिये ? मेहरबानी करके इसके लिये तो कुछ व्यवस्था कराएं। तो, अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं मंत्री महोदय को यही निवेदन करना चाहता हूं कि पानी के मामले में मेहरबानी करके किसी तरह की कोई राजनीति न लाएं । कम से कम जो उपयोगी सजेशंस हों, उन उपयोगी सजेशंस की तो जिला प्रशासन को भी पालना करनी चाहिये । आपको भी चिट्ठी लिखते हैं तो आपको भी पालना करनी चाहिये । आपकी दी हुई मंजूरी को लोगों ने छोटे-छोटे लेवल पर तोड़-मरोड़ कर अपनी पोलिटिक्स चलाकर आगे-पीछे कर दिया ।

पाली से जयपुर की जो तीन करोड़ बीस लाख की योजना है, वह बिलकुल नैचुरल ग्रेडियन से पानी जाता है। कुछ भी सरकार को मोटरें लगाने की जरूरत नहीं, कुछ भी करने की जरूरत नहीं, आपका आलरेडी मूलियावास तक पानी जा रहा है। मूलियावास से सीधा जयपुर जाना चाहिये। जयपुर जाने के बजाय कुछ लोग जो असरदार हैं, वे अपने गांवों से ले जाना चाहते हैं । 40 साल पहले से पानी के मामले में राजनीति होती रही है । असरदार लोगों ने उस वक्त भी अपना काम किया है, अपना मकसद हल किया है लेकिन गरीब लोगों को पीने का पानी उपलब्ध कराने की कोई नीयत नहीं रखते । यह जो गरीब

(श्री भीमराज भाटी)

को गणेश मानकर चलने वाली सरकार है, या जो आपके नीति से चलने वाले लोग हैं उन नीतिवान लोगों से मैं यहां राजस्थान के पवित्र सदन में निवेदन करना चाहता हूं कि मेहरबानी करके पानी के मामले में बिलकुल भेदभाव से ऊपर उठकर, राजनीति से ऊपर उठकर संवेदनशीलता का परिचय दें। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री रामचन्द्र रावत।

श्री भंवरलाल शर्मा (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्यों के सुझावों को बहुत गंभीरता से ले रहा हूं। आपने कहा, बिना पैसे ही यह स्कीम चालू हो सकती है, केवल थोड़ा कोई टैक्निकल परिवर्तन करना है। तो अभी आज ही इस विधान सभा के सत्र के बाद, मतलब इसी सोमवार का थोड़ा आप मुझे बताइये कि कौनसी योजना है जो बिना पैसे ठीक हो सकती है, तो जल्दी चालू कर देंगे। अभी नहीं बाद में बताना।

श्री भीमराज भाटी : मैं आपके साथ बैठकर चर्चा करके बता दूंगा।

श्री भंवरलाल शर्मा : आप मेरे साथ तो बैठते ही नहीं हैं न। आज बैठ जाइये।

श्री भीमराज भाटी : नहीं, जब आप रिक्वेस्ट करें।

श्री भंवरलाल शर्मा : आज ही कर रहा हूं, बैठ जाइये ....(व्यवधान).... हां, मैं बैठा दूंगा, अभी तो अध्यक्षजी बैठाएंगे।

मेरा यह निवेदन है जो आप बात करते हैं पानी के मामले में राजनीति की तो मैं राजनीति वैसे भी नहीं करता हूं और पानी के मामले में राजनीति करने को पाप समझता हूं। अब आपके..(व्यवधान)..

श्री अध्यक्ष : सुनिये-सुनिये।

श्री भंवरलाल शर्मा : नीचे क्या है, आपके नीचे क्या टसल है और कैसे लोग कर देंगे, यह तो मेरे को जानकारी नहीं है लेकिन मैं सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं और खुले मन से कहना चाहता हूं कि पानी के मामले में राजनीति का सवाल नहीं है। पानी के मामले में जो राजनीति करता है, मैं यह समझता हूं, वह पाप करता है।

श्री भीमराज भाटी : मुझे आपके व्यवहार से पूरी तसल्ली है। आप और सदन के जो लोग हैं वे आपस में भेदभाव नहीं कर रहे ...

श्री भंवरलाल शर्मा : वह तो कर दिया मैंने। अब स्थानीय बात अलग है।

श्री भीमराज भाटी : लेकिन जो नीचे के स्तर पर हो रही है....

श्री अध्यक्ष : विराजिये।

श्री भीमराज भाटी : उसको मेहरबानी करके रोकने की व्यवस्था होनी चाहिये। आपके अधिकारियों को सीधे निर्देश मिलने चाहिये कि पानी के मामले में जो जायज

५५

(श्री भीमराज भाटी)

है वह करो, कोई जरूरी नहीं है मेरी बात करो ।

श्री अध्यक्ष : भाटी साहब । बिराजें, उन्होंने अपनी बात कह दी । आप बिराजें। श्री रावत ।

श्री रामचन्द्र रावत (कोटपूतली) : माननीय अध्यक्षजी, आज सदन में मांग संख्या–27 पेयजल पर चर्चा हो रही है; मैं भी इसमें अपने आपको शामिल करता हूं ।

माननीय अध्यक्षजी, मैं आपके माध्यम से जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्रीजी को निवेदन करना चाहता हूं कि जो आज पेय-जल जैसे अहम मुद्दे पर चर्चा हो रही है, यह दरअसल में कोई तहसील और जिले की समस्या नहीं है, यह समूचे राजस्थान की समस्या बनी हुई है । कोई भी सरकार आए-चाहे वह कांग्रेस की हो, चाहे बी.जे.पी. की हो, कोई समूचे राजस्थान को पानी देने की कोई न कोई कारगर योजना जरूर बनाती है । मुझे ऐसा लगता है कि इसमें विचार करते–करते चार साल, साढ़े चार साल तो आपने जो दिये, मगर ये दो-तीन महीने बचे हुए हैं, कोई कारगर योजना इस समूचे राजस्थान को पानी देने के लिए आप जरूर बनाएं....

श्री अध्यक्ष : आपका कोई सुझाव ?

श्री रामचन्द्र रावत : मै सुझाव दे रहा हूं । वैसे तो राजस्थान भर की समस्या है । हमारे सारे विधायक आए हैं वे सारे राजस्थान की समस्या कहेंगे ।

मैं कोटपूतली क्षेत्र से आया हूं उसमें बहुत सारी समस्याएं हैं । माननीय मंत्री जी हमेशा कोटपूतली जाते रहते हैं, इनका बहुत लगाव है कोटपूतली से । मुझे ऐसा लगता है कि ये चुनाव कोटपूतली से लड़ेंगे, परन्तु वहां पानी के बारे में इनका कोई विचार नहीं है । माननीय मंत्रीजी, हमारे कोटपूतली में पांच बड़े शहर हैं पावटा, प्रागपुरा, कोटपूतली, राजनुता, नारेरा और बनेठी, जहां आप जलदाय विभाग से पानी देते हो । मगर आपकी स्कीम समूचे गांव को, शहर को पानी नहीं देती । आधे हिस्से को पानी मिल रहा है, आधे हिस्से को पानी नहीं मिल रहा है ।

मैं आपसे बनेठी का जिक्र करूं । बनेठी में आप पधारे थे, बनेठी के लोगों ने आपसे शिकायत की थी । वहां एक हरिजन बस्ती है, एक नांगला बस्ती है, उन दोनों में जबसे यह आपकी स्कीम चालू हुई है आज तक पानी नहीं पहुंचा है । आपने पाइप लाइन वहां डाल दी है और यह कह दिया कि पानी हम आपको दे रहे हैं, लेकिन माननीय अध्यक्षजी, बनेठी गांव में हरिजन बस्ती को, नांगला बस्ती को पानी नहीं दिया गया । वे पानी के लिये त्राहि-त्राहि करते हैं । कई मर्तबा मेरे पास आए, मैंने माननीय मंत्रीजी से बात की । एक चीज के लिए मैं जरूर माननीय मंत्रीजी को धन्य-वाद देता हूं कि इस पांच साल में आपने अपनी योजना के तहत बनाड़ गांव में बहुत बड़ी समस्या थी वह आपने मंजूर की ।

(श्री रामचन्द्र रावत)

इसके लिये मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

दूसरा इसी तरह से एक नारेड़ा गांव में भी यही हालत है कि जो ऊंचे वाले इलाके हैं जिसमें मीणा लोग रहते हैं, खटीक रहते हैं, उनमें नाम मात्र को यह कहने के लिये कि लोग बाग कहेंगे कि मीणों, हरिजनों, खटीक, हरिजन बस्तियों को पानी नहीं दिया जा रहा है, पाइप लाइन डाल दी गयी है मगर आज तक उन मोहल्लों में पानी नहीं गया है। थोड़े-से हिस्से में थोड़ा पानी जा रहा है, बाकी वह टंकी बेकार जा रही है। जलदाय विभाग वाले बैठे रहते हैं, कोई योजना नहीं बनाते, न पानी देने की कोई व्यवस्था करते हैं। इस तरह के मैंने पांच गांव गिनाये हैं जो शहर के माफिक कस्बे हैं, उनमें आधे गांव में पानी आता है, आधे मे पानी नहीं आता है। इसलिये मेरा सुझाव है कि उनको पानी दिया जाए और हरिजन बस्तियों के लिये भी समुचित व्यवस्था की जाए।

मेरे कोटपूतली जिले में 9-10 ऐसे गांव हैं जिनका पानी कड़वा है, खारा है, उस पानी को पी नहीं सकते। अध्यक्षजी, मैं आपको निवेदन करूं समय-समय पर मैंने यहां क्वेश्चन भी लगाये हैं, मंत्रीजी का भी मैंने ध्यान आकर्षित किया है। उन गांवों का नाम है बिजाला, सरुंड, कंबलपुरा, पवानाहीर, खरब। ये 9-10 गांव ऐसे हैं जिनका पानी पीने से दांत खराब हो जाते हैं, हड्डी कमजोर पड़ जाती है, लकवा आ जाता है। मैंने समय-समय पर आपको अवगत भी कराया। इसके लिये दो तीन साल पहले मीठे पानी की स्कीम बनाकर सरकार के पास भेजी गयी, मगर आज तक उस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा और ठंडे बस्ते के अन्दर वे फाइलें पड़ी हैं। क्या फायदा हुआ? उन अधिकारियों से कह-सुनकर हमने कोई फाइल तैयार करवायी, कोई फायदा नहीं हुआ और ज्यों की त्यों वह फाइल पड़ी है। मेरा इसमें एक सुझाव है। मैं कल्याणकला गया था, जिसकी मैंने आपको एप्लीकेशन भी दी थी, मैं मिला भी हूं। उस गांव में पीने के लिये कोई साधन नहीं, केवल एक हैण्ड पम्प है। मेरे ख्याल से दो हजार की बस्ती होगी पानी उस गांव

(12.00 बजे)

का खराब हो चुका है। कुंए दो थे, कुओं का पानी भी खराब हो गया और धीरे-धीरे और पानी खराब होता जा रहा है। भगवान जाने किस वजह से। वह पहाड़ की तलाई पर है, पता नहीं पहाड़ के रिसने से खराब हो रहा है या वैसे हो रहा है। पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। आपको हैण्ड पम्प के लिए कहते हैं तो आप हैण्ड पम्प मंजूर नहीं करते हैं। अगर आपने कर दिये भी हैण्ड पम्प, तो आप हैण्ड पम्प 6 महीने में लगाते हैं। आपका प्रोसीजर इतना लम्बा है कि आपने आज हैण्ड पम्प मंजूर किया तो 6 महीने में लगेगा। मेरे यहां आपने कई हैण्ड पम्प मंजूर किये कोई विधायक कोटे से किया है, कोई किसी से किया है, लेकिन 6-6 महीने, एक-एक साल हो गये वे लगे नहीं। बहाना क्या

(श्री रामचन्द्र रावत)

होता है कि साहब, पाइप ही नहीं आये, सामान ही नहीं आया या अभी मंजूरी नहीं आयी, एक्स ई एन.साहब का वर्क आर्डर नहीं आया। आप हमको राजी करने के लिए कह देते हैं कि आपके हैण्ड पम्प मंजूर कर दिया। कि खारा पानी है, जब तक टंकी नहीं बने तब तक हम आपको हैण्ड पम्प दे देंगे। मगर उस प्रोसीजर में 6 महीने लगते हैं और जनता को पानी मिलता नहीं है। 6 महीने में पता नहीं क्या-क्या हो जाता है। ऐसे गांव के नाम जो मैंने आपको गिनाये हैं वे दूसरे गांव से जाकर एक मील और दो मील से पानी लाते हैं, आपको हकीकत बात मैं कहता हूं। आपको हम पर विश्वास करना चाहिए। जो हम यहां कहते हैं कुछ जिम्मेदारी से बोल रहे हैं, आप इसको गंभीरता से लीजिए। आप एक हैण्ड पम्प मंजूर कर रहे हैं, दो हैण्ड पम्प कर रहे हैं गांव की समस्या मिटाने के लिए। आप उसको 6 महीने में लगाएंगे तो क्या समस्या मिटेगी लोगों की? यह प्रोसीजर आपने बना रखा है कि एक विधायक कह दे, एक सांसद कह दे तो आप हैण्ड पम्प की मंजूरी दे नहीं सकते। आप जे.ईएन.से लिखवाएंगे, आप ए.ईएन. से लिखवाएंगे, आपका एक्स.ईएन. लिखेगा, आपका एस.ई. लिखेगा, इसके बाद एडीशनल....

श्री अध्यक्ष : यह थोड़ी टेक्निकल रिपोर्ट भी जरूरी है इसमें।

श्री रामचन्द्र रावत : नहीं। मान्यवर, कई ऐसे गांव हैं जहां जरूरी पानी नहीं हो। जब जनता का प्रतिनिधि है, जो लाख आदमियों का प्रतिनिधित्व करता है, वह कोई एक छोटी-सी मांग कर दे कि इस गांव में पानी नहीं है तो आप उसके कहने के अनुसार एक हैण्ड पम्प मंजूर नहीं कर सकते हैं? उसके लिए प्रोसीजर यह होता है कि दो महीने तो कागज चलते-चलते चले जाते हैं। तो इतनी विले होने का मतलब यह हो गया कि आप पर भरोसा नहीं रहता है। आपका डिपार्टमेंट फेल हो रहा है। मेरा सुझाव यह है।

दूसरा, मेरे यहां जिला विकास अभिकरण के द्वारा दो साल पहले गोनेड़ा, सुन्दरपुरा, मोरड़ा की टंकियां मंजूर की गयीं किन्तु डी.आर.डी.ए. ने अभी तक उनका काम चालू नहीं हुआ, वर्क आर्डर किये नहीं गये। अधिकारी कुछ न कुछ उसमें आनाकानी करते हैं और काम नहीं करने की वजह से कुछ न कुछ धोखा लगाकर उस फाइल को वापस भेज देते हैं। पैसा आपको डी.आर.डी.ए. ने दे दिया, मंजूर कर दिया तो इनको क्या परेशानी आई? वर्क आर्डर देने में एक ठेकेदार क्यों नहीं करते वे लोग? दो साल से जो स्कीम थी, डी.आर डी.ए. का पैसा था, आपने क्या किया? इनसे कोई पूछे कि आप क्या कर रहे हैं? आपका डिपार्टमेंट क्या कर रहा है? बड़ी मुश्किल से हम कांग्रेसियों का छोटा-मोटा काम होता है, टंकियां मंजूर कराते हैं, वह भी ये अधिकारी लोग नहीं करते हैं। मंत्री जी सुनते जरूर है मगर मंत्री जी से मुझे ऐसा लगता है कि अधिकारी मानते नहीं है। प्यार से बोलेंगे, बिठाएंगे, आओ जी, एम.एल.ए.

47

(श्री रामचन्द्र रावत)

साहब, ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, मगर नतीजा कुछ नहीं निकलता । निल है नतीजा । चाय भी पिलाते हैं, बिठाते भी हैं, इसके लिए तो आपको धन्यवाद देता हूं । आदर पूरा देते हो आप, सम्मान पूरा देते हो मगर आपके अधिकारियों को थोड़ा-सा आप डांटिये कि कुछ काम करें । काम तो करते नहीं हैं । दो साल से स्कीम बनी हुई पड़ी है । आपका इलाका है, आपका नाम चलता है, लोग यह कहते कि कोटपूतली के अन्दर आपने 5 टंकी बनवा दीं । लेकिन हम चले जाएंगे उसके बाद आप उनको वर्क आर्डर देंगे, यह कहने के लिए कि दूसरे एम.एल.ए. ने काम करवाया है ।

एक मेरा यह सुझाव है कि थोड़ी-सी काम में गति दीजिये और अधिकारियों को कहिये । गति देने का मतलब यह है कि डी.आर.डी.ए. से मंजूर हो गयी, पैसा आपके पास आ गया । आपको वर्क आर्डर देना है, टंकी बनवानी है, बोरिंग बनाने हैं और काम क्या करना है ? इसलिए गति थोड़ी-सी इस काम में आप दीजिये, मेरा यह सुझाव है ।

दूसरा, मेरा एक निवेदन है कि एन कैटेगरी की स्कीम सेन्ट्रल की है जिसमें 100 लोगों की आबादी की ढाणियों में हैण्ड पम्प मंजूर होता है । मेरे क्षेत्र में बहुत-सी ऐसी ढाणियां रह गयी हैं जो 100 से ज्यादा आबादी वाली ढाणियां हैं, उनमें हैण्ड पम्प मंजूर नहीं हुए हैं । आप कृपया दुबारा सर्वे करवा लें अगर हम पर विश्वास नहीं हो तो और दुबारा सर्वे करवाकर....

श्री भंवरलाल शर्मा : 100 से अधिक आबादी वाली कोई ढाणी रह गयी है तो आप सूची मुझे दीजिये । कैसे पूरी नहीं होती हैं ? आज ही दीजिये । 1991 की जनसंख्या के हिसाब से 100 से अधिक आबादी की कोई ढाणी रह गयी है तो आप सूची मुझे दे दें ।

श्री रामचन्द्र रावत : यह बात तो सही है, आपने कह दिया, मगर 100 से ज्यादा आबादी वाली जो ढाणियां आपके एडीशनल चीफ के यहां पड़ी हुई हैं उनके वर्क आर्डर देने हैं, वह उनको मंजूर नहीं कर रहे हैं । मेरा अर्थ दूसरा है । आपने यह नियम तो बना दिया है कि 100 से अधिक आबादी वाली ढाणियां मंजूर हो गयीं, मगर देंगे कब ? ये तीन महीने चले जाएंगे, इसके बाद में आप देंगे ? 6 महीने बाद में देंगे ? 100 वाली आबादी की स्कीम है, एन कैटेगरी की है, आप एडीशनल चीफ से कहकर उन ढाणियों में हैण्ड पम्प मंजूर करवाएं ।

श्री अध्यक्ष : आप लिस्ट नहीं दे सकते क्या ?

श्री रामचन्द्र रावत : लिस्ट तो मैं दे दूंगा ।

श्री अध्यक्ष : दे देना ।

श्री रामचन्द्र रावत : मैं इनको 10-15 मिनट के बाद में लिस्ट दे दूंगा । यह लिस्ट है, यह तो एडीशनल चीफ के पास पड़ी हुई है, मगर वे उनके वर्क आर्डर नहीं दे रहे हैं, उनको लगवा नहीं रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष : वे तो आपको ओब्लाइज करना चाहते हैं, आप इनको दे दें।

श्री रामचन्द्र रावत : हां, बिलकुल। मैं इनको धन्यवाद देता हूं ओब्लाइज कर रहे हैं तो।

एक मेरा रायकरनपुरा गांव है। जलदाय विभाग की तरफ से इनकी एक स्कीम थी, ये पानी देते थे। तीन साल के करीब हो गये इनकी स्कीम फेल हो गयी, ना वहां टंकी बनी, ना वहां आपका बोरिंग बना और आज रायकरनपुरा आपकी स्कीम बिलकुल फेल है। एक हैण्ड पम्प मैंने विधायक कोटे से दिया था, वे लोग अभी उससे पानी पी रहे हैं। आपकी दो साल से स्कीम बनी हुई है, आप पानी देते आ रहे हो हमेशा से और दो साल से आपको कोई चिंता नहीं है उस गांव की कि हमारी स्कीम फेल हो गयी ? वहां बोरिंग बनाना है, टंकी बनानी है, आपको इस बात की चिंता करनी चाहिए।

पानी के बगैर कुछ भी नहीं है, जीवन ही पानी है। अगर आपको जीना है तो पानी की जरूरत है। पानी ही जीवन है और मनुष्य को ही नहीं पशुओं को भी पानी की जरूरत पड़ती है। मंत्री महोदय, मेरा एक सुझाव और है कि आप पशुओं के लिए भी पानी की व्यवस्था कीजिये। पशुओं को भी पानी की जरूरत पड़ती है। बरसात बहुत कम होती है तो जलाशय और जोहड़ हों तो जोहड़ों में भी ऐसी व्यवस्था करिये कि उनमें पानी आ जाए और पशुओं को भी थोड़ा-सा पानी पीने के लिए मिल जाए।

श्री अध्यक्ष : अब आप विराजें।

श्री रामचन्द्र रावत : हां, मैं कटमोशन एक-दो दे रहा हूं। उनके बारे में एक ही मिनट बोलूंगा।

श्री अध्यक्ष : अब तक क्या बोल रहे थे ?

श्री रामचन्द्र रावत : बोल तो उसी पर रहा था, मगर कुछ रह गये हैं।

कोटपूतली तहसील में आपने अभियान चलाया था हैण्ड पम्पों को ठीक करने के लिए। यह बात तो ठीक है मगर जिस ढंग से आपने अभियान चलाया उसमें गति नहीं हुई। आपने प्रशासन तो दे रखा है पंचायत समिति को, हैण्ड पम्प ठीक करने का सामान पंचायत समिति को दे रखा है और आप ठीक जलदाय विभाग से करवा रहे हैं। यह दोहरा प्रशासन जो हैण्ड पम्पों पर है वह एक तरह से गलत लगता है।

श्री अध्यक्ष : यह लोकतांत्रिक व्यवस्था है, माननीय सदस्य।

श्री रामचन्द्र रावत : एक सुझाव ही तो है मेरा। आप इसको एक को ही दीजिये चाहे पंचायत समिति को ठीक करने के लिए दीजिये, चाहे जलदाय विभाग के अधिकारी को दीजिये। सामान के लिए पंचायत समिति में जाते हैं तो पंचायत समिति वाले कहते हैं हमारे पास सामान नहीं है। जो कर्मचारी हैं पंचायत समिति के वे हैण्ड ओवर करते हैं उनको जलदाय

(श्री रामचन्द्र रावत)

विभाग वालों को इस तरह यह जो कर्मचारियों का आदान-प्रदान, रुपयों का आदान-प्रदान और सामान का आदान-प्रदान होता है इसमें लोग-बाग हैण्ड पम्प ठीक कराने के लिए कभी पंचायत समिति के चक्कर लगाते हैं, कभी जलदाय विभाग के चक्कर लगाते हैं। उन गरीब जमीदार आदमियों को, किसानों को यह मालूम नहीं पड़ता है कि अब अभियान चला है कि नहीं, इन हैण्ड पम्पों को ठीक कौन करेगा, कौनसा डिपार्टमेंट ठीक करेगा। एकरूपता लाए इसमें। पंचायत समिति में जाना हो तो ठीक है आप यह कह दीजिये कि हम पंचायत समिति में जा रहे हैं, वहां से लगातार ठीक कराते रहेंगे। तो यह मेरा एक सुझाव है।

दूसरा, मैं मेरे गांव की ही बात करूं। मेरा गांव चिमनपुरा है। टंकी आपने बनायी, हमारे कोटे से बनी है। उसमें मैटीरियल और पाइप इतने घटिया लगे हैं कि आज दिन तक पानी उससे मिल नहीं सका। जब टंकी चालू करते हैं, पाइप टूट जाते हैं और पानी लीकेज हो जाता है, निकलता रहता है। टंकी ठीक करते हैं दूसरी जगह से हो जाता है। कभी वाल्व नहीं मिले, कभी छल्ला नहीं मिले। आप इस चीज को देखें। जब टंकी में आप 10 लाख रुपये खर्च करते हो तो मैटीरियल लगाने में एक लाख रुपये और खर्च कर दीजिये। बात हो गयी कि घटिया किस्म का आप मैटीरियल लगाएंगे, अधिकारी लोग उसमें कमीशन खाएंगे, या और कोई इसमें बात है? अच्छा माल लगाएं, बहुत दिनों तक वह चलेगी। टंकी ठीक बन गयी, पानी ठीक आ गया पर पाइपों की वजह से दो साल से पानी नहीं पहुंच रहा है। जो भी मैटीरियल आप लगाएं–चाहे हैण्ड पम्प में लगे, चाहे टंकी में या पाइप लाइन लगे अच्छा लगाएं। यह व्यवस्था भी आप देखें।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे समय दिया इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं और आशा करता हूं कि मंत्रीजी इसमें मेरा पूरा-पूरा सहयोग करेंगे। जो आपने काम किए हैं इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री किशन गोपाल कोगटा।

श्री किशन गोपाल कोगटा (मसूदा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपके अध्यक्ष पद के अन्दर मैं पहली बार बोल रहा हूं।

आज मांग संख्या 27 पेयजल पर चर्चा हो रही है, मैं उसमें अपने आपको शामिल करता हूं। मानव जीवन में पानी का बड़ा महत्व है, अति प्राचीनकाल से पानी का महत्व है। महत्व के साथ-साथ उसके उपयोग के बारे में भी प्राचीन इतिहास में चर्चा रही है। इसके साथ–साथ पुराने इतिहास में जितनी भी नदियां और पानी के स्रोत हैं, उनकी पूजा का जिक्र है। इससे यह प्रदर्शित होता है। महसूस होता है कि पानी का महत्व और उसके उपयोग का मानव जीवन में बहुत बड़ा स्थान रहा है। लेकिन आज के इस आधुनिक युग में पानी

(श्री किशन गोपाल कोगटा)

का जिस प्रकार से दुरुपयोग हो रहा है, जिस प्रकार से जमीन से उसका दोहन हो रहा है, उसी का परिणाम है कि प्रति वर्ष जैसे-जैसे समय निकलेगा, पीने के पानी की समस्या, शुद्ध पेयजल की समस्या आएगी। इसका एक बड़ा कारण जनसंख्या का बढ़ना भी है। जनसंख्या जिस रफ्तार से बढ़ रही है, पानी के स्रोत और पानी का ठहराव नहीं बढ़ रहा है। हिन्दुस्तान में अधिकांश पीने का पानी बारिश के माध्यम से इकट्ठा होता है या नदियों के माध्यम से इकट्ठा होता है उसमें जिस प्रकार से गिरावट आ रही है, वह निश्चित रूप से सोचनीय विषय है। शुद्ध पीने के पानी के बारे में केवल सरकार ही नहीं, माननीय मंत्री महोदय ही नहीं, हम सबको सोचना पड़ेगा और उसके महत्व को समझना पड़ेगा।

एक पुरानी बात कहूं, पहले गांव के कुंए पर पानी भरने के लिए जाते थे तो निकालते बाल्टीभर कर उसके बाद उसको छानते, और जितनी जरूरत होती उतना छुण्डा भरकर अपने घर ले जाते। उस पानी को दूर से लाते इसलिए उसका बहुत बड़ा महत्व रहता, उसका उपयोग होता। पश्चिमी राजस्थान में बारिश के पानी को मकानों के नीचे टांका बनाकर एकत्रित करते हैं और सालभर उस पानी का उपयोग करते हैं। लेकिन आज जितनी सुविधाएं पानी की मिल रही हैं, उसका उसी प्रकार से दुरुपयोग हो रहा है, चाहे फ्लश लेट्रिन हो, चाहे हाथ धोने का बेसिन हो, वहां नल चालू रहेगा, पानी बहकर निकल रहा है। बाश बेसिन में और फ्लश में एक बार में दो बाल्टी पानी चला जाता है। पहले हाथ-मुंह धोने जाते थे तो लोटा लेकर जाते थे तो पानी का महत्व था, इस महत्व को हमें समझना पड़ेगा। प्राचीन काल में जो नियम-व्यवस्थाएं बनाई गई थीं, उनको वापस अपनाना पड़ेगा, नहीं तो भविष्य में शुद्ध पानी की व्यवस्था बहुत संकटमय होगी।

मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि जब माननीय अटल बिहारी वाजपेयी की भारतीय जनता पार्टी सरकार केन्द्र में बनी तो राष्ट्रीय एजेण्डा में इसे शामिल किया गया और पूरे देश के नागरिकों को शुद्ध पेयजल मुहैया कराने की योजना बनाई। यही नहीं, राज्य सरकार ने भी इसके महत्व को समझा और एक साल का बजट पीने के पानी को समर्पित किया, जल नीति बनाई आज राजस्थान की स्थिति है, बारिश के पानी का लगातार कम होना, जमीन का वाटर लेवल नीचे जाया जा रहा है। उसको सोचा और इसे ध्यान में रखकर जल नीति बनाई। अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना नहीं भूलूंगा कि जिस प्रकार से पूर्व में अनबैलेंस्ड ट्यूब वैल खुदे बिना योजना के उसी कारण यह स्थिति आई है कि किसी एरिये में पानी की प्रोब्लम है, पानी इतना नीचे चला गया है कि खारा हो गया है और कहीं बहुत ज्यादा पानी है। तो बिना योजना के, बिना नियंत्रण के जिस प्रकार से पानी का दोहन किया गया, उसके बारे में विचार होना चाहिए। निश्चित रूप से इसके लिए राज्य सरकार

(श्री किशन गोपाल कोगटा)

कानून बनाए। ये अनबैलेंस्ड ट्यूब वैल जो खुद रहे हैं, उनके कारण पीने के पानी की अव्यवस्था हो गई है। इसके लिए निश्चित रूप से मैं राय दूंगा कि इस पर कानून बने और जो ट्यूबवैल खुदते हैं उनकी परमीशन लेने की व्यवस्था हो। किसी एरिये में तो 100 खुद गए और किसी एरिये में बिलकुल नहीं हैं। जिस एरिये में 100 ट्यूब वैल खुद गये वहां तो पानी मिलना मुश्किल है।

अध्यक्ष महोदय, मैं पुष्कर का उदाहरण देता हूं। पुष्कर सरोबर के वर्षों के इतिहास में यह नहीं लिखा हुआ है कि वह सूखा हो, लेकिन जब से ये ट्यूब वैल खुदे हैं, जब से गुलाबों की खेती हुई है, पुष्कर के आसपास अनबैलेंस्ड ट्यूबवैल खुदे हैं, इतने पानी के दोहन से आज हर साल पुष्कर के पवित्र सरोबर का पानी समाप्त हो जाता है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : यह पानी का प्रश्न है।

श्री किशन गोपाल कोगटा : मैं इसी से अपनी बात को महत्व दे रहा हूं कि ये जो अनबैलेंस्ड ट्यूबवैल खुदे हैं, उन पर निश्चित रूप से रोक लगनी चाहिए। इनके उपयोग को देखना चाहिए और इसके बाद उनको परमीशन देनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार ने पानी की नीति बनाई कि 4000 की जनसंख्या वाले गांवों में जलदाय योजना बनेगी, 1500 की जनसंख्या वाले गांवों में पनघट योजना बनेगी, 250 की आबादी वाली कालोनी में या गांव में एक हैण्ड पम्प लगेगा; यही नहीं, 25 घरों की एक ढाणी में भी हैण्ड पम्प लगाकर पानी की व्यवस्था की जाएगी। इसके लिए निश्चित रूप से माननीय मंत्री महोदय को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं।

मैं आपके माध्यम से यह बताना चाहूंगा कि इस वर्ष बजट में 352 करोड़ 20 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है। जहां 1990-91 में 382.87 करोड़ रुपये का प्रावधान था, वहीं 1996-97 में 831.03 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया और 1997-98 में 1029.18 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई और इस वर्ष 1998-99 में 1118.21 करोड़ रुपये की व्यवस्था है। यह इस बात का द्योतक है कि राज्य सरकार पीने के पानी के बारे में बहुत चिन्ताशील है और आम नागरिकों को शुद्ध पीने का पानी मिले, इसके लिए लगातार बजट में व्यवस्था की जा रही है। इस वर्ष 48 नए गांवों और ढाणियों को तथा 700 नए गांवों को शुद्ध पानी उपलब्ध कराने की व्यवस्था का लक्ष्य रखा गया है।

अध्यक्ष महोदय, हमारे अजमेर जिले की भोगोलिक स्थिति ऊंट के ऊपर बैठने का स्थान, कमर जैसी है। अजमेर जिले में कोई भी बारह माह बहने वाली नदी नहीं है और कोई साधन नहीं है इसलिए अजमेर जिले में पीने के पानी के लिए प्राचीन काल से तालाब या कुंओं की व्यवस्था थी। अजमेर जिले में साढ़े चोदह सो छोटे मोटे तालाब हैं जिसके माध्यम से वहां के नागरिक और

(52)

(श्री किशन गोपाल कोगटा)

पशु और अन्य सब पीने का पानी उपयोग में लेते हैं। पिछले 10–15–20 साल से वर्षा न होने के कारण यह जो व्यवस्था है, वह डगमगा गई है। इसके लिए बीसलपुर योजना बनी, मैं माननीय मंत्री महोदय को धन्यवाद दूंगा कि आपके कार्यकाल में अजमेर जिले को बीसलपुर का पानी उपलब्ध होने लगा है। यही नहीं अजमेर, ब्यावर, किशनगढ़, नसीराबाद, केकड़ी, सरवाड़ इन म्यूनिसिपल एरिया में बीसलपुर का शुद्ध पीने का पानी उपलब्ध होने लगा लेकिन दुर्भाग्य से कहूंगा कि मेरे अजमेर जिले में एक ही म्यूनिसिपल एरिया विजयनगर बच गया है। वहां की स्थिति आज अजमेर जिले में सबसे बदतर है। आज भी वहां 72 घण्टे या 90 घण्टे से जल वितरण होता है और पानी का सोर्स केवल ट्यूबवैल है। अगर बारिश न हो तो वे ट्यूब वैल भी ड्राई हो जाते हैं और पीने के पानी की भयंकर समस्या हो जाती है। अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से कहूंगा कि विजयनगर की स्थिति पर आप विचार करें। आप अपने अधिकारियों के साथ बैठकर वहां की वास्तविक स्थिति का जायजा लें। उसे बीसलपुर योजना से जोड़ सकें तो निश्चित रूप से बहुत आभार है। लेकिन वहां के लिए बीसलपुर योजना आसान नहीं है, क्योंकि ट्रंक केकड़ी से या नेकड़ा से आएगा तो रास्ते के गांव वाले कहेंगे, पहले पानी हमको चाहिए। पानी के लिए अजमेर जिले के ग्रामीण क्षेत्र के 644 गांवों की फ्लोराइड की योजना बनी जिसको चार भागों में वितरित किया गया केकड़ी, नसीराबाद, मिनाय और उसके बाद मसूदा-विजयनगर। हमारा तो टेल में है। जब तक ये तीन भाग पूरे नहीं होंगे तब तक विजयनगर और मसूदा को पानी नहीं मिलेगा। तो मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय को सुझाव दूंगा कि सरवाड़ा जहां बीसलपुर का लास्ट पानी भरा रहेगा वहां से अगर सीधी पाइप लाइन विजयनगर गुलाबपुरा के लिए हो, जो इण्डस्ट्रियल एरिया भी है, तो वे निश्चित रूप से लाभान्वित होंगे। उससे दूरी केवल 60 किलोमीटर है। आप किसी भी योजना के माध्यम से करें, निश्चित रूप से यह क्षेत्र लाभान्वित होगा।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मेरे ग्रामीण क्षेत्र की चर्चा करूंगा। पी.एच.ई.डी. में जितने भी आपके अधिकारी लगे हुए हैं, टाप तक, चीफ इंजीनियर तक वे सब अजमेर जिले से और अजमेर जिले के मसूदा क्षेत्र से परिचित हैं। वहां के जितने गांव हैं चाहे केसरपुरा हो, चाहे बाड़ी हो, चाहे कानपुरा बेगल्यावास हो, चाहे जालिया, बाडी, आसन, केलू, दौलतपुरा, लोडियाना गांव हो, उनमें पीने का पानी फ्लोराइडयुक्त है। उनमें न तो हैण्ड पम्प से शुद्ध मीठा पानी पीने के लिए निकलता है, न ही कुंओं से। कोई एकाध पुराने कुंए जो तालाब के नीचे हैं, उनमें जरूर पीने का पानी मिलता है। चाहे गांव हो या और कहीं हो, क्षेत्र में जालिया बाड़ी, लोडियाना, शेरगढ़, मसूदा और रामगढ़ के नीचे की बैल्ट है उसमें पीने के पानी के जितने भी हैण्ड पम्प हैं वे सब फ्लोराइड–युक्त हैं। सब फेल हैं, उनका कोई उपयोग

(श्री किशन गोपाल कोगटा)

नहीं हुआ। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय को कहूंगा कि इस समस्या के निदान के लिए आप इसको थोड़ा सीरियसली लें। आप एक कमेटी बनाएं और अधिकारियों की रिपोर्ट लें। रिपोर्ट तैयार है, आप मंगाएंगे तो निश्चित रूप से आएगी। इन गांवों में हैण्ड पम्प में फ्लोराइडयुक्त पानी है, कुओं में फ्लोराइडयुक्त पानी है, पी नहीं सकते, इसकी कोई न कोई योजना बनाएं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इसके साथ-साथ मेरे ब्यावर के आसपास के एरिये की चर्चा करूंगा। जब ब्यावर की प्राब्लम थी तो मकरेड़ा, सरमालिया के आसपास के ट्यूब वैल और आसपास के कुओं से पानी का ट्रांसपोर्टेशन होता था। कुछ गांव वाले भी सोचते थे कि शहर वालों को पानी पहले पिलाया जाए, हम तो जैसी स्थिति होगी उसमें रह लेंगे। लेकिन आज ब्यावर की स्थिति सुधर गई, वहां बीसलपुर का पानी आने लग गया और जितने साधन हैं वे अब फ्री हो गए। उन गांवों में चाहे प्रतीतमण्ड हो, चाहे भोजपुरा हो, चाहे नरपतखेड़ा हो, चाहे सरमालिया हो, चाहे छीपा कालोनी हो, उनमें इस पुरानी स्कीम की पाइप लाइन से पानी जा रहा है। एक नूंदरी में दलतान ऐसी पंचायत है जिससे पता ही नहीं लगता कि ब्यावर कब शुरू हुआ और नूंदरी में दलतान पंचायत कब चालू हुई। लेकिन वह पंचायत क्षेत्र है और वहां पानी की व्यवस्था नहीं है, और एक फीट इधर ही ब्यावर शहर है, वहां नल योजना है, घरों में नल लगे हुए हैं। ब्यावर के आसपास का एडजोइनिंग एरिया है, जैसे सरमालिया है, सरमालिया के पास में दो ट्यूब वैल बने हुए हैं जिससे पहले पानी जाता था अब उनसे पानी नहीं लिया जा रहा है। बिजली का कनेक्शन भी है, पानी भी है। उससे सरमालिया गांव को पानी दिया जा सकता है। इसी प्रकार छीपा कालोनी, मकरेड़ा और गोपालपुरा गांव हैं जहां फ्लोराइडयुक्त पानी है। मकरेड़ा की स्कीम अब फ्री होने लगी है। वहां पम्पिंग स्टेशन भी है, वहां पाइप लाइन भी है, वहां पानी की व्यवस्था उससे हो सकती है।

मैं एक और बात आपके माध्यम से कहूंगा। यह नीति बनी कि 1500 से ज्यादा आबादी वाले गांवों में पनघट योजना बनेगी। मेरे क्षेत्र में पनघट योजना के लिए लगभग 15 पचायत मुख्यालय हैं जिनकी 1500 से ज्यादा आबादी है, जैसे देलवाड़ा, बलाड़ा, अंधेरी देवरी, चिवाना, नंदवाड़ा, मोहणा, बेगल्यावास, शेरगढ़, बाड़ी, दौलतपुरा, इनमें आप पनघट योजना की व्यवस्था करेंगे तो हो सकता है आसपास में कोई ट्यूब वैल ऐसा खुदे जिसमें मीठा पानी निकल जाए और उसको पनघट योजना से लाभान्वित किया जाए।

मैं आपके माध्यम से एक और बात कहना चाहता हूं। जालिया मसूदा विधान सभा क्षेत्र में मसूदा के बाद सबसे बड़ा गांव है जिसकी पापुलेशन 8-9 हजार है। लेकिन जालिया बांध बनने की वजह से उसके नीचे की जितनी भी बैल्ट है वह सारी पानी

(54)

(श्री किशन गोपाल कोगटा)

से सूख गई और पीने लायक पानी नहीं रहा। सारा पानी फ्लोराइडयुक्त हो गया, क्योंकि जल का स्तर बहुत नीचे हो गया। जालिया के लिए चाहे बांध के ऊपर कोई ट्यूब वैल खुदे या आसपास 2-3-4 किलोमीटर दूर से पानी आए, लेकिन एक बहुत बड़ा गांव है, पंचायत मुख्यालय है उसमें पानी की व्यवस्था करें।

मैं एक बात और कहूंगा। मेरे से पूर्व वक्ताओं ने भी कहा कि पंचायत समितियों में जो हैण्ड पम्प मिस्त्री हैं उनकी स्थिति बहुत दयनीय है। आपने उनको पंचायती राज विभाग से स्थायी किया उसके लिए तो बहुत-बहुत धन्यवाद, लेकिन न तो उनका फिक्सेशन हुआ, न उनको टी.ए., डी.ए. मिलता है। कभी तो आप उनको पी.एच.ई.डी. के साथ लेते हो, कभी पंचायत समिति में भेजते हो। उनका मन नहीं है। उनको कहीं न कहीं एक बार स्थिर करना पड़ेगा, उनकी व्यवस्था ठीक करनी पड़ेगी और उनका भविष्य क्या होगा इसके बारे में तय करना पड़ेगा जिससे हैण्ड पम्प व्यवस्था ठीक हो, मरम्मत ठीक हो। आपने समय दिया उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री फतेह सिंह।

श्री फतेह सिंह (कुशलगढ़) : अध्यक्ष महोदय, आज पेयजल के ऊपर चर्चा हो रही है। मैं इस मौके पर यही कहना चाहूंगा कि पेयजल की समस्या हर साल सामने आती है और हर साल बजट में प्रावधान रखा जाता है लेकिन समस्या ज्यों की त्यों खड़ी रहती है। उसके लिए या तो जो धन हम सरकार की तरफ से विभाग को देते हैं उस धन का उपयोग नहीं हो रहा है या फिर कहीं न कहीं बेईमानी है। इसीलिए जो समस्याएं हर साल आती रहती हैं वे अभी भी मौजूद हैं। इसका कारण यही है कि एक तो हमारे देश में आबादी बढ़ी और दूसरी तरफ हमारे देश के अंदर या प्रदेश के अन्दर पहले जो जंगल थे उन जंगलों की वजह से बरसात टाइम पर होती थी, बरसात भी अच्छी होती थी और पानी का स्तर ऊपर था, धीरे-धीरे वन बर्बाद हुए और बरसात भी समय पर नहीं होने लगी। उससे पानी का स्तर नीचे चला गया। मेरा तो यह मानना है, जैसे सभी माननीय सदस्यों ने बताया है कि बड़े-बड़े शहरों की मोटे रूप में योजनाएं चल रही हैं उनकी कई तरह की कमियां पाइप लाइन की हैं, बिजली की हैं या रख-रखाव की हैं, उसमें सुधार लाया जाए। जिस इलाके में पानी की कमी है और वहां पर पेयजल योजना लागू नहीं है, ऐसे छोटे गांव हैं उनके लिए भी टंकी बनायी जाए या और कहीं से पानी लाकर उन छोटे गांवों को दिया जाए तो ये समस्याएं दूर हो सकती हैं।

मेरा दूसरा निवेदन यह था कि पानी की समस्या हमेशा आती रहेगी और पानी का स्तर नीचे गया, यह भी हम सब जानते हैं। मेरा मानना यह है कि हमारे प्रदेश में पेयजल बजट से हम एनीकट बनाएं, स्टाप डैम बनाएं और बरसात के पानी को रोकें

(श्री फतेह सिंह)

या फिर नदी-नालों में पानी जाता है उस पानी को रोककर इकट्ठा करें तो हम ट्यूब वैल खोदेंगे उनमें भी पानी आएगा, हैण्ड पम्प खोदेंगे उनमें भी पानी आएगा और कुंए खोदेंगे तो उनमें भी पानी आएगा और लोगों को पानी मिलेगा। मेरा निवेदन है कि राज्य सरकार बड़ी योजनाओं के ऊपर ही धन दे रही है। बड़े-बड़े शहरों में सक्षम लोग हैं, लड़ाकू लोग हैं, आंदोलन करते हैं, लड़ते हैं, भिड़ते हैं और अपनी समस्याओं का समाधान करा लेते हैं। लेकिन जो बिखरी आबादी है, ग्रामीण आबादी है उसकी हालत खराब है। ऐसे इलाके के लोगों के लिए शुरू से अब तक राजस्थान में कांग्रेस की भी सरकार रही, भारतीय जनता पार्टी की भी सरकार रही, सबने बजट पेश किए, खर्चा भी किया, हैण्ड पम्प भी लगाए, लेकिन उससे समस्या हल नहीं हुई। उसका कारण यह रहा कि जो राजनीति में सक्षम व्यक्ति था, आबादी के अनुपात में एक रेवेन्यू विलेज था, आबादी में अनुपात में उसमें हैण्ड पम्प तो लगे, लेकिन लगे कहां ? कोई नेता हो, कोई कर्मचारी हो या कोई प्रभावशाली व्यक्ति हो, उसी मोहल्ले में लग गये और बाकी जो ग्रामीण एरिया है वह एक तरफ रह गया। सरकारी आंकड़ों में यह माना जा रहा है कि इस गांव की आबादी इतनी है इसमें इतने हैण्ड पम्प लग गये। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि बिखरी आबादी में पानी की जो व्यवस्था बिगड़ी हुई है उसको सुधारने के लिए आप सर्वे कराएं। सर्वे किया हुआ विभाग के पास में है, पंचायत समितियों के अन्दर है, वह मंगवा लें और जो एरिया छूटा है, जो ढाणी छूटी है उस ढाणी में अगर हैण्ड पम्प लगवा दें या कुंआ खुदवा दें तो उन लोगों को भी पानी की व्यवस्था हो सकती है। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में कुंआ खोदने से तो पानी मिलेगा नहीं, गहरा चला गया। मैंने इसके लिए जैसे पहले सुझाव दिया, उस इलाके में नदी—नाले बहते हैं, कई ऐसे खांचे हैं उनके अन्दर आप छोटे-छोटे तालाब बनाएं, पेयजल का बजट उसमें खर्च करें। छोटे तालाब बनाकर, एनीकट बनाकर उसमें पानी को रोकें तब जाकर हैण्ड पम्प में पानी आएगा।

साथ-साथ मेरा यह भी सुझाव है कि हैण्ड पम्प के बजाय अगर हम कुंए खोदें, ओपन वैल खोदें तो उसमें इतना खर्चा नहीं आएगा। 25 हजार में कुंआ खुद जाएगा, पक्का बन जाएगा। ओपन में कुंआ रहेगा तो लोगों को पानी पीने को मिलेगा, मवेशियों को भी पानी पीने को मिलेगा। लेकिन कुंए की स्कीम बन्द करके हर जगह हैण्ड पम्प खोदने की बात की तो मेरा, अध्यक्ष महोदय, यह मानना है, मेरा सुझाव है कि हैण्ड पम्प भी खुदे लेकिन साथ साथ में कुंआ भी सार्वजनिक गांव के हित में खुदे ताकि मवेशियों को पानी मिले।

हैण्ड पम्प की एक समस्या मैं और बताना चाहूंगा। आपके मार्फत मंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहूंगा कि प्राइवेट पार्टियां 200 फीट हैण्ड पम्प खोदती

(श्री फतेह सिंह)

है तो मय फिटिंग के उसमें 20 हजार के आसपास खर्चा आता है और विभाग की मशीन अगर हैण्डपम्प को खोदेगी 200 फीट तो उसमें 40 हजार रुपये बराबर खर्चा आ जाएगा। 50 हजार भी आ सकता है। इतना अन्तर क्यों है? मेरे यहां पर 40-40, 50-50 हजार रुपये उसमें खर्चा मंडा जाता है और वह स्वीकृति एक जैसी दी जाती है कि 40 हजार 50 हजार। जबकि हमारे इलाके में कई लोगों ने, कुछ सक्षम पार्टी हैं, कुछ व्यापारिक लाइन हैं उन लोगों ने प्राइवेट पार्टी से उसी नाम के उतने ही गहरे हैण्ड पम्प खुदवाये तो उनकी 20 हजार में फिटिंग भी हो गयी। लेकिन डिपार्टमेंट की जो मशीन खोदती है उसमें 40–50 हजार होता है। इतना अन्तर क्यों है? इस सम्बन्ध में आप जानकारी लें, जांच करें कि क्या वजह है कि सरकारी मशीन से खोदने पर इतना खर्चा आता है।

दूसरा, मेरा निवेदन यह था कि इन्सान के लिए तो हम पानी की व्यवस्था कर देते हैं हैण्ड पम्प से, कुंए से लेकिन जो मवेशी हमारे हैं, नदी-नालों में पानी रहता नहीं है, टांके कहीं बने हुए हैं नहीं, न ओपन पानी मिलता है। आये दिन मवेशी हैण्डपम्प पर पानी पीने आते हैं और वे उस हैण्ड पम्प से टकराते हैं जिससे वह हैण्ड पम्प खराब होता है। जहां इन्सान के लिए हम सोचते हैं तो मवेशियों के लिए भी हमें सोचना चाहिए। मेरा सुझाव है कि छोटे-छोटे तालाब बनें या जहां पानी है उस जगह हौद जैसा बने और खुला पानी मवेशी को पिलाने के लिए भी व्यवस्था करें। तब तो हम मानेंगे कि इन्सान और मवेशी के लिए बराबर सरकार की तरफ से कोई पहल हो रही है। मेरा मानना है कि मवेशी के लिए कोई न कोई रास्ता निकाला जाए, मवेशी को भी पानी मिले।

अब मैं निवेदन करना चाहूंगा कि कुशलगढ़ हमारा विधान सभा क्षेत्र है, बिखरी हुई आबादी है। कुशलगढ़ में एक नगरपालिका क्षेत्र है जो स्टेट के जमाने से बन्दी बस्ती है और आये दिन वहां पर पानी की परेशानी आती है। पेयजल के अधिकारी हैं उनके साथ भी मारपीट होती

(12.35 बजे)

(श्रीमती तारा भण्डारी, सभापति, पदासीन)

है, विद्युत विभाग के कर्मचारी होते हैं उनके साथ भी मारपीट होती है। पानी की कमी है। कुशलगढ़ में एक सुनारिया डैम है उसके लिए विभाग ने एक योजना बनायी थी। योजना बनाकर राज्य सरकार को उन्होंने भेजा है कि अगर इतना पैसा राज्य सरकार इरिगेशन विभाग को दे देती है तो उस तालाब को रेज किया जाएगा, उतना पानी उसमें इकट्ठा किया जाएगा और वह पानी कुशलगढ़ को दिया जाएगा। मंत्री महोदय, कुशलगढ़ में जो सुनारिया डैम बना हुआ है वह सिंचाई के परपज से बना है, उसका कमांड एरिया भी उतना माना है। दो पानी-तीन पानी मिलने के बाद शहर के लोग कलक्टर से मिलते हैं,

(श्री फतेह सिंह)

अफसरों से मिलते हैं, नेताओं से मिलते हैं और यह कहते हैं कि कुशलगढ़ को पानी देना पड़ेगा, इसलिए आप पानी बन्द कर दो। अब नगरपालिका को पानी देने के लिए ये रोक देते हैं और किसानों की खेती सूख जाती है, आये दिन झगड़े होते हैं। पिछले साल भी फसल सूखी थी। तो मेरा यह निवेदन है कि जो स्कीम बनाकर विभाग ने आपके पास में भिजवायी है, मेहरबानी करके आप इरिगेशन डिपार्टमैंट को वह पैसा दें ताकि उस तालाब को रेज किया जाए। उतना पानी उसमें इकट्ठा होगा तो कुशलगढ़ में जो लोगों को पानी चाहिए उसकी पूर्ति हो जाएगी।

दूसरा यह था कि कुशलगढ़ में छोटी सरवा और बस्सी दो गांव हैं। 1000-1200 की आबादी के गांव हैं, बन्दी बस्ती है। वहां पर पनघट योजना चालू की है। किसी ठेकेदार को काम दिया है, 2-3 साल हो गये, वे धीरे-धीरे पाइपों को खोदते रहते हैं और लाइनों को जोड़ते रहते हैं। मेरा निवेदन है कि आप उसको दिखवाएं। वास्तव में लोगों को पानी देना चाहते हैं तो उस स्कीम को जल्दी तैयार करवाकर उन लोगों को पानी दें। एक तो बस्सी गांव, एक छोटी सरवा और एक कसारवड़ी गांव, इन तीन गांवों की योजना है। बनास नदी से स्कीम को लागू किया, स्वीकृत है लेकिन 2-3 साल हो गये, अभी तक काम पूरा हुआ नहीं। डिपार्टमैंट के अधिकारी निगरानी रखते नहीं और ठेकेदार बीच में काम छोड़कर चले जाते हैं। ठेकेदार के ऊपर पैनल्टी लगाकर दूसरे ठेकेदार को काम दिया जाता है उससे काम डिले होता है, लोगों को समय पर पानी मिलता नहीं है। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि 2-3 गांव मैंने बन्दी बस्ती के बताये हैं उनको आप दिखवाएं और जल्दी उन स्कीमों को पूरा करके उन लोगों को पानी देने की व्यवस्था करें।

तीसरी समस्या यह है कि पेयजल की व्यवस्था में बिजली विभाग और पेयजल विभाग, दोनों का एक सम्बन्ध है। अब आपके बिजली में कोई गड़बड़ होगी तो पेयजल में गड़बड़ निश्चित रूप में शुरू हो जाएगी। मेरा यह मानना है कि दोनों डिपार्टमैंट का सम्बन्ध जुड़ा रहेगा, दोनों डिपार्टमैंट समय समय पर बैठकर इस तरह की समस्या के लिए सोच विचार करेंगे तो आये दिन इस तरह की शिकायत सामने नहीं आएगी। हमारे इलाके में पिछले साल पेयजल वालों को भी मारा गया, पीटा गया और विद्युत विभाग के मिस्त्री, ए.ईएन. वगैरह हैं उनको भी पीटा गया। उनके मुकदमे बनें। जिन लोगों के पेयजल संकट था वे एक मुसीबत में फंसे हुए थे, उन लोगों पर मुकदमे बने। वे जेल भी गये, उनकी बाद में जमानत भी हुई और आज भी केस चल रहे हैं। मेरा निवेदन है कि इस तरह की कोई घटना नहीं घटे उसके लिए दोनों डिपार्टमैंट को आप सचेत करें। उनका सम्बन्ध जोड़कर अगर इस व्यवस्था को आप चलाएंगे तो मैं समझता हूं कि पेयजल समय पर लोगों को मिल पाएगा।

(श्री फतेह सिंह)

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

दूसरा मेरा निवेदन यह था कि उस इलाके में ट्यूब वैल भी खोद सकते हैं। मैंने पहले सुझाव दिया था कि आप डैम बनाओ, चैक डैम बनाओ, तालाब बनाओ। आप हैण्ड पम्प खोदो, हमारे इलाके में ट्यूब वैल खुद सकते हैं। सभापति महोदय, आपकी मार्फत मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि सरकार को उस इलाके में पानी देना है तो बांसवाड़ा जिले के अन्दर आपकी पेयजल की एक मशीनरी है पानी चैक करने वाली, उससे आप जांच कराइये। अगर जांच कराने के बाद में उस इलाके में आप ट्यूब वैल खुदवाने की कोशिश करेंगे, उसका लोगों को लाभ मिलेगा। मैं उदाहरण के लिए आपको कहना चाहूंगा, छोटी सरवा में टैस्ट के रूप में ट्यूब वैल खोदा गया था, उसमें पानी बढ़िया आया, जोरदार आया। उन्होंने 48 घण्टे तक उसके अन्दर 10 हार्स पावर की मोटर लगाकर पानी खींचा, पानी जरा भी नहीं कटा, इतना पानी उस एरिया में है। इस तरह का सर्वे कराकर उस इलाके में अगर आप कोई जांच करें, लोगों के हितों के लिए ट्यूब वैल खुदवाएंगे तो खेती के काम में भी आएगा, मवेशी के काम में आएगा और लोगों के पानी पीने के हित में भी आएगा। इतना ही कहते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। जय हिन्द।

श्री सभापति : श्री पूनमचन्द विश्नोई।

श्री पूनमचन्द विश्नोई (फलोदी) : सभापति महोदया, मैं आपसे और इस सदन से निवेदन करना चाहता हूं, पिछले लगभग 40 सालों से मैंने इस सभा में कोई ऐसा भाषण नहीं दिया है जिसमें पेयजल की समस्या का मैंने जिक्र नहीं किया हो। बराबर करता रहा हूं और विभाग ने किस तरह से शुरूआत की वे बातें और क्या कमियां हैं वह भी सदा बताता रहा हूं। उसके बाद में मेरे सुझावों से या उनको खुद भी समझ में आया, बाद में काफी कुछ इम्प्रूवमैंट हुआ है। आप और हम अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारे इंजीनियर, वैज्ञानिक संसार प्रसिद्ध हैं लेकिन ज्यादातर शहरी हैं, उच्च वर्ग के हैं, ग्रामों का उनको ज्ञान नहीं है कि पहले पेयजल की समस्या का क्या हल निकाला गया था। पेयजल की योजना चाहे तालाब हो, कुएं हों, कैसे चलते थे, कैसे चलाये जाते थे, इसका इंजीनियरों ने ध्यान नहीं किया और अपने किताबी ज्ञान के आधार पर योजना बनानी शुरू कर दी। ये योजनाएं शुरू हुई, जयपुर शहर से, अजमेर से, बीकानेर से, तो उनका क्षेत्र उतना ही था उन-उन में पानी देने का था। वहां पानी का छोटा–सा स्रोत था। डिपार्टमैंट बढ़ने लगा, इसका आकार बढ़ गया। ग्रामीण क्षेत्रों को सबको इसमें ले लिया तो समस्या दूसरी तरह की हो गई। प्रारम्भ में जब पेयजल योजना बनाई तो उस समय यह निश्चय किया गया कि प्रति व्यक्ति इतना पेयजल उपलब्ध करवाया जाएगा। उसमें पशुओं का ध्यान नहीं रखा। ये नहीं जानते थे कि मरुस्थल के अन्दर पशुओं और मनुष्यों का पेयजल स्रोत एक ही

(श्री पूनमचन्द विश्नोई)

होता है। यह उनको ज्ञान ही नहीं था। उन्होंने सोचा कि मनुष्यों को पानी दे देंगे तो फिर जानवर कहां पियेंगे? मैं उस प्रदेश की बात कर रहा हूं जहां लड़की कहती है, एक पुरानी कहावत है "बाबा मां देई मारवां बरी कुंवारी रहे, स हाथ कचोलो सिर घड़ो; सींचती ही मरे"। आज यहां कोटा में पेयजल की समस्या है, भरतपुर में है, सवाईमाधोपुर में है। डेढ़ किलोमीटर दूर से पानी ला रहे हैं। वह भी एक समस्या है। मैं बात कर रहा हूं फलोदी, शेरगढ़ क्षेत्र की। सबसे गहरा कुआं कितना गहरा है? 90 पुरुष। पुरुष है, जितनी आदमी की ऊंचाई है उतना ही यह एक पुरुष है, करीब पौने छह फीट। 90×6=करीब 525 फीट गहरे कुएं हैं। कइयों ने देखे भी नहीं होंगे। वे चलाये कैसे जाते हैं? चरस लाव। लाव में समझते होंगे, ऊंट के जोतते हैं तो फिर झोल पड़ जाती है, अध बीच में जाते हैं जब तो जमीन में रगड़ खाने लगती है। ऊंट खींच नहीं सकता तो फिर दूसरा ऊंट जोतते हैं। बहुत दूर चला जाता है। हवा चल रही होती है तो चरस आ गया। यह सुनाई नहीं देता तो एक नगाड़ा या ढोल रखते हैं, वह बजाते हैं कि चरस बाहर आ गया। एक तरफ तो 15 फुट, 20 फुट, 30 फुट पर पानी और एक तरफ वह हालत। तो मेरे कहने का आशय यह है कि शुरू में जब योजना बनाई तो सब कुछ मनुष्यों के लिए थी, उन्हें इतना जल मिलना चाहिए, लेकिन पशुओं को बाहर छोड़ दिया और आधार बना दिया। शहर हैं तो बाहर में भी ट्यूब वैल लगा दिये या पुराने तालाब थे या बावड़ियां थीं, उनसे बनाना शुरू कर दिया। लेकिन आबादी बढ़ी और इसका फैलाव हुआ तो उनसे काम चल नहीं सकता था इसलिए जगह जगह नलकूप लगाये। इन्होंने अपने स्रोत तो निर्मित किये नहीं। पुराने चाहे सिंचाई के बांध थे, तालाब थे या सिंचाई के जहां पर कुओं में खूब जल था, वहां पर इन्होंने नलकूप लगा दिये। रणसी गांव का मैं उदाहरण दूंगा, मथानिया और ध्यूरी इनका उदाहरण दूंगा, पाल का उदाहरण दूंगा। जहां कहीं भी जल था जमीन में, जोधपुर शहर को पानी देने के लिए उस सबको खाली कर दिया। इरिगेशन के लिए जवाई बांध बनाया हुआ था, पाली के पास में बांध है वह बनाया हुआ है। वह सब पानी इनको दे दिया फिर भी पूरा नहीं हो सका। तब इसको जोड़ा गया राजस्थान नहर से। कोगटा साहब ने बिलकुल सही कहा, बहुत व्यर्थ खर्च कर रहे हैं पानी को, इतना पानी आखिर आएगा कहां से? लेकिन यह भी एक हकीकत है कि पांच इंच से कम बरसात कहीं पर नहीं होती राजस्थान में, कम से कम पांच इंच होती है। एक एकड़ के अन्दर एक इंच बरसात होती है तो 25000 गैलन पानी देते हैं। तो 25×5 यानी सवा लाख गैलन से कम तो एक एकड़ से दुगुने एरिये में हर जगह पानी बरसता है। लेकिन उस बात पर हम जोर नहीं दे रहे हैं। वाटर हार्वेस्टिंग की फिलोसोफी आई है, अब टांकों की भी थोड़ी-थोड़ी आने लगी है, तालाबों की भी आने लगी है। क्योंकि शहर में साफ पानी देना है और तालाब में पानी गंदा होता है, उसमें जीव पड़े होते हैं तो कहा गया कि तालाब को बिलकुल ही छोड़

(श्री पूनमचन्द बिश्नोई)

थे। शिवारंजन साहब, क्या पता जिन्दा हैं या नहीं, आई.सी.एस. अफसर थे, ऐसे समझदार मैंने बहुत कम आदमी देखे हैं, मैंने जाकर उनको 1963 में शिकायत की। मैंने कहा कि ये तालाब की खुदाई बन्द कर रहे हो, देश बरबाद हो जाएगा। मैंने कहा, मवेशी कहां पानी पियेंगे ? निष्क्रमण पर 10000 मवेशी आ गये, 10000 ट्यूब वैल या हैण्ड पम्प का पानी पी लेंगे ? कौन पिलाएगा। उस समय मान लीजिये बिजली नहीं चल रही हो, वन्य जीव पानी कहां पियेंगे ? तालाब का पानी तो वन्य प्राणी हो चाहे चीड़ी-कमेड़ी हो, निष्क्रमण पर जाने वाले हों, जानवर हों, सबको उपलब्ध होता है। तो बन्द करवा दिया कि नहीं, ये तालाब होने ही नहीं चाहिए। मैं उनको ले गया ठेठ गगावा एक तालाब है बहुत बड़ा, पचपदरा जिला बाड़मेर में, रास्ते में बताता गया। मैंने कहा कि यह हकीकत है और आपने बन्द कर दिया। उन्होंने उनको चालू कराया लेकिन उसके बाद में अपन ने तालाबों की कभी चिन्ता नहीं की। जब तक आप तालाबों का चाहे पुराने हैं, रख-रखाव नहीं करेंगे, तालाबों को छोड़ने का नतीजा यह हुआ कि उनका कैचमेंट एरिया पायथन कहते हैं, उसके ऊपर लोगों ने अनधिकृत कब्जे कर लिये। जोधपुर में गुलाब सागर और बढ़िया बढ़िया तालाब हैं, आज 50 करोड़ में नहीं बन सकता, उसके अन्दर सीवरेज लाइन लगाकर डाल दी। वाटर हार्वेस्टिंग का अगर सिस्टम देखा जाए तो विश्व में सबसे बढ़िया सिस्टम जोधपुर में है। प्राचीन काल में 15 मील दूर से पानी लाते थे। दो इंच बरसात होती तो जोधपुर शहर में उस वक्त आबादी कम थी दो इंच में पानी एकट्ठा हो जाता था और 12 महीनों के जल से सब तालाब भर जाते थे। तो मेरे कहने का आशय यही है कि तालाबों के निर्माण पर, रख-रखाव पर, क्योंकि समय का अभाव है इसलिए ज्यादा समय नहीं लूंगा, तालाबों पर ज्यादा जोर दीजिये। उससे जो भूजल का स्तर नीचे जा रहा है वह भी बना रहेगा और दूर-दूर में भी अगर कहीं पहाड़ी है, उदाहरण दूंगा, ब्यावर के लिए बड़ी समस्या है। सबसे पहले सेंधड़ा को सुखाया ब्यावर के लिए, उसके बाद में नीमाज को सुखाया और आखिर में अब बीसलपुर से जोड़ रहे हैं। अजी हुजूर, इसके पास ही तो अनाप-शनाप पहाड़ियां आई हुई हैं, एक तालाब आप निर्मित कर दो सब कुओं का हल हो जाएगा। ब्यावर को 12 मास पानी दे सकता है वह, लेकिन उधर इनका दिमाग ही नहीं जा रहा है, क्योंकि उनका पिछला व्यावहारिक ज्ञान नहीं है। चार हजार साल तक हम यहां पर कायम रहे हैं, हमारी सभ्यता कायम रही है तो इन तालाबों के बलबूते पर कायम रही है। उस चीज को, उस इतिहास को हम कैसे भूल रहे हैं ? उनके जो गहन अनुभव हैं उसको हम क्यों भूल रहे हैं ? उन्होंने जिस तरह से समस्याओं का हल निकाला है वह एक हमारा आधार होना चाहिए समस्याओं का हल निकालने का। कुएं और बावड़ियां हैं वे सब खतम करवा दीं। कोई आज ऐसा आदमी जिन्दा है जो 90 पुरुष ऊंडा कुआं खोद सके ? परसराम जी के गांव में 70 पुरुष का कुआं है, इनके दादा ने खुदवाया था। चोतीणा चाडो नाम से है उससे प्रसिद्ध हो गये वो खोदने वाले।

(श्री पूनमचन्द विश्नोई)

खैर, अब वे खोदने वाले ही चले गये, लेकिन कुएं जो पुराने हैं वे वापस आप आबाद करो।

श्री भंवरलाल शर्मा (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री) : इनका व्यास कितना होता था ? ये जितने गहरे होते थे ना इनका वह ..

श्री पूनमचन्द विश्नोई : ऐसा है, साहब इनका व्यास चौतीणा है, चार चड़स साथ चलते थे। एक इधर तीन मीस चार चड़स उधर चलते हैं, वह होता था करीबन 15 फीट चौड़ा और लकड़ें होते जाते थे नीचे जाएं ज्यों। तो 15 फीट तो चौतीणा है, एक जोड़ी उधर खींच रही है ऊंट, एक इधर खींच रही है, एक इधर खींच रही है। वे तो खैर, वैसे बने हुए हैं लेकिन अभी बेकार पड़े हैं। गांव की महिलाएं हैं, अब महिलाओं का है उनके गांव में कोई क्लब है नहीं, कोई मिलने-जुलने का नहीं है किसको सिणगार करके बताए। यह सहज प्रवृत्ति है। पहले पनिहारों की झूलरें होती थीं। उस देश को निकम्मा बोला जाता था जहां पर पणिहारों के झूलरे नहीं हों। आपने भी पनिहारी योजना बनाई है, यह हवाई योजना है। पनिहारों का झूलरा है कहां यहां पर ? पहले वो सब होकर के और हर घड़ा लेकर के एक पलाका देकर आती थी तो ड्रेस बदलकर के जाती थी। अब औरतें देखतीं। आपस में मिलतीं, बातें करतीं। आजकल घरों में उनको बंद कर के रख दिया। तो हमारी संस्कृति है, यह इससे जुड़ी हुई है, इन कुओं का करना चाहिए।

अब मैं आता हूं अपनी और शेरगढ़ की समस्याओं पर। आप जानते हैं जितनी भी क्षेत्रीय जलप्रदाय योजनाएं हैं उनमें जिस गांव के अंदर स्रोत है वहां पानी जाता है; उससे अगले गांव में पानी जाता है और उसके अगले गांव और लास्ट गांव तक तो कभी कभी जाता है और ज्यादातर में जाता ही नहीं है। पानी के नाले फट जाते हैं तो पानी के पास तालाब भर जाते हैं, लेकिन इतने आपके पास आदमी ही नहीं हैं कि उनका पता लग जाए कि वहां पर नल फूट गया है। कानून होते हुए भी आपने शायद ही किसी का चालान पेश किया हो। रास्ते में है, पाइप लाइन फोड़ देते हैं और वहीं जानवर पिलाते हैं या पानी भरते हैं। इसका कानून सख्त है पहले से ही क्योंकि वे एसेंशल सप्लाई है लेकिन कभी कोई चालान या तत्परता से कार्यवाही उसमें नहीं की जाती। इसलिए आप लोगों के जो सरकारी कर्मचारी नीचे स्तर पर हैं उनकी आप संख्या बढ़ाइये, कि टूट-फूट हो जाती है उसको सम्भालें। आखिरी गांवों तक पानी पहुंचे, यह आपकी व्यवस्था होनी चाहिए। मेरे क्षेत्र में ...

श्री सभापति : संख्या तो इनकी बहुत है, काम की गति बताएं।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : अब ये बातें किलोमीटर की कर रहे थे। मेरे एक चाखू गांव है उस गांव का क्षेत्रफल एक लाख पच्चीस हजार बीघा है। वह 18 मील लम्बा है कोकड़ और 10–11 मील, अभी किलोमीटर तो आये नहीं हैं, पुरानी पीढ़ी के हैं मील याद रहता है। तो इतनी दूर है

(श्री पूनमचन्द बिश्नोई)

जिसमें जाटों की ढाणी मिडल स्कूल पाया हुआ है। वहां से 15 किलोमीटर से जिन के पास ऊंट और छकड़ा है वह तो ले आता है, माथे पर उठाकर कैसे पानी लाएं ? तो क्या है कि दूरियां देख करके उसके अनुसार आपको नलकूप, हैण्ड पम्प ये सब निर्मित करने चाहिए। पुराने कुएं हैं उन सबकी अगर जीर्ण-शीर्ण अवस्था है तो उनको दुरूस्त कराया जाना चाहिए।

एक ये बहुत-से हैण्ड पम्प खोदे गये हैं मेरे क्षेत्र फलोदी में लेकिन अभी तक उनको चालू नहीं किया। एक नयी विधि आयी है जिसमें हवा के प्रेशर से हैण्ड पम्प चलाये जाते हैं, वह हमारे जहां पर मशीन नहीं लगी है हैण्ड पम्प की वहां पर लगाएं। मेरे यहां पर आज से सात साल पहले बाप से सोड़ादड़ा, खेदरक, सहारनपुरा आदि जांबाज ढाणी की योजना स्वीकृत हुई थी और अभी तक उसका काम कोई 1/4 भी नहीं हुआ है। इस तरह की कई जगह हैं, नलकूप स्वीकृत हुए हैं। जैसे गोदारों की ढाणी मोखड़ा, पचायत समिति बाप डेढ़ साल पहले नलकूप स्वीकृत हुआ। मरुस्थल का क्षेत्र और वहां पर उसका निर्माण नहीं हुआ है। नये बहुत से नलकूप स्वीकृत करने हैं उनके संबंध में मैं आपको अलग से एक तालिका दे दूंगा, तो उनका निर्माण कराएं।

मैं पिछले दिनों यह गांव जहां पर विस्फोट हुआ था उससे अगले गांव में मेरे रिश्तेदार रहते हैं, वहां पर गया था। वैसे तो खैर, योजनाएं हैं जैतसिंह जी की उनकी बात मुझे तो कहने की जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी मैंने देखा कि बाधा से बाया शेरगढ़ एक योजना है। तो उसके क्या है पाइप वगैरह टूटे हुए थे और लास्ट विलेजेज में पानी जा नहीं रहा था, कलाऊ से भीम सागर वाया दासानियां है। तो मेरे सामने लोग इकट्ठा हो गये थे। मुझे देखा तब शिकायत की कि सब ढाणियों में पानी पहुंचता नहीं है। नीबो का तला डाउनियां ये सड़क पर ही आता है, वहां पानी पहुंचता नहीं है। मेरे यहां भी कई क्षेत्रीय योजनाएं हैं, बहुत पुरानी हैं, लम्बा-चौड़ा एरिया है वहां पहुंचता नहीं है पानी, तो कृपया आप देखिये। वैसे इंजीनियर जो हैं, स्थानीय ठीक हैं, ध्यान रखते हैं, काफी मेहनत भी करते हैं लेकिन हमारी समस्याएं हैं वे बिलकुल एक दूसरे तरह की समस्याएं हैं। वहां पर पानी अगर नहीं हो, तो चंद घंटों में आदमी सूखकर मर जाएगा, इतनी गर्मी पड़ती है, इतनी लू चलती है। उसमें मवेशी का क्या हाल होगा ? मेरा आपसे नम्र निवेदन यह है कि आपके डिपार्टमेंट में, खैर, अब तो पशुओं के लिए भी व्यवस्था कर दी, पहले ढाणी में नहीं समझते थे। मैंने प्रश्न उठाया 1967 में, मैंने कहा कि सब ढाणियों को पानी मिला ? उन्होंने कहा कि ढाणी क्या होती है ? मैंने कहा कि एक सैटलमैंट समझ लो। छोटी जो आबादी होती है या बिखरी है, खेतों में बसते हैं, उसको ढाणी कहते हैं। खैर, अब ढाणियों वाला भी हो गया लेकिन फिर भी अभी इसमें बहुत कमियां हैं और आपको इसमें सुधार करना चाहिए। एक ही इलाज है कि पुराने जितने तालाब हैं

(श्री पूनमचन्द बिश्नोई)

इन सबकी मरम्मत करके उनका जीर्णोद्धार करवाएं। पानी जो व्यर्थ में बहकर जा रहा है, चाहे तो ऊपर छोटे एनीकट जैसे सुझाव दिये हैं वह, चाहे तालाब निर्मित करके और नहीं तो भूगर्भ का सर्वेक्षण करवा करके जहां पानी रह सकता है, बाढ़ के पानी को डाइवर्ट करके उस क्षेत्र में ले जाकर वह जमीन में प्रवेश कर जाए, यह व्यवस्था आपको करनी चाहिए। आपने मुझे समय दिया उसके लिए आपको मैं धन्यवाद देता हूं।

श्री सभापति : श्री ओमप्रकाश शर्मा।

श्री ओमप्रकाश शर्मा (बूंदी) : सभापति महोदया, मांग संख्या-27 पर मैं भी अपने-आपको सम्मिलित करते हुए कई बातें निवेदन करूंगा। मैं भारतीय जनता पार्टी के मुख्य मंत्री जी और जलदाय मंत्री जी को बहुत–बहुत धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने राजस्थान के लिए एक नीति बनाई और नीति बनाकर गांवों में और शहरों में किस प्रकार पीने का पानी लोगों को मिले उसकी व्यवस्था की। उसके लिए मैं चार पंचवर्षीय योजनाओं की ओर ध्यान दिलाना चाहूंगा। छठीं पंचवर्षीय योजना में 90

(13.00 बजे)

करोड़ रुपये नगरीय क्षेत्र में और ग्रामीण क्षेत्र में 8248.34 लाख रुपये खर्च किये गये। सातवीं पंचवर्षीय योजना में नगरीय क्षेत्र में 196.8 करोड़ रुपये खर्च किये और ग्रामीण क्षेत्र में 398.84 करोड़ खर्च किये। आठवी पंचवर्षीय योजना में 640.91 नगरीय क्षेत्र में खर्च किये और 918.53 करोड़ रुपये ग्रामीण क्षेत्र में खर्च किये। हमारी सरकार ने 443.79 करोड़ रुपया नगरीय क्षेत्र में और ग्रामीण क्षेत्र में 559.69 करोड़ रुपया आठवीं पंचवर्षीय योजना में ज्यादा खर्च किया सातवीं पंचवर्षीय योजना से। इससे साफ नजर आता है कि हमारी सरकार गांव और शहर के लोगों को जहां पानी नहीं था, पानी पिलाने के लिये कितनी तत्पर है। नवीं पंचवर्षीय योजना में इसी प्रकार नगरीय क्षेत्र में 895 करोड़ और ग्रामीण क्षेत्र में 1575 करोड़ रुपये व्यय किया जाना प्रस्तावित किया है। यह बात मैंने इसलिए निवेदन की है कि कई माननीय सदस्य यहां बता रहे थे कि हमारे यहां पानी नहीं है। आखिर चालीस साल तक राज किया है इन्होंने, इनकी योजना इसमें रखी हुई है। सभापति महोदय, अभी आयोजना मद में आठवीं पंचवर्षीय योजना में रखा 548.21 करोड़ रुपया नगरीय क्षेत्र के लिये और 421.80 करोड़ रुपया रखा ग्रामीण क्षेत्र के लिये। नवीं पंचवर्षीय योजना में 795 करोड़ नगरीय क्षेत्र के लिये और ग्रामीण क्षेत्र के लिये 963 करोड़ रुपया रखा गया है।

इसके साथ ही एक निवेदन करना चाहूंगा, सभापति महोदय। मंत्री महोदय, अपने अधिकारियों को निर्देशित करें कि राजस्थान का जो जल स्तर नीचे गिर रहा है इसको रोकने का उपाय किया जाए, इसको व्यवस्था की जाए। जैसे मेरे बूंदी जिले में 1984 से 1996 के मध्य 13.60

(64)

(श्री ओमप्रकाश शर्मा)

मीटर की गिरावट आई है। अगर इसी प्रकार जल स्तर नीचे जाता रहा तो जितनी भी हम योजनाएं बनाएंगे वे सारी योजनाएं व्यर्थ जाएंगी। ट्यूब वैल लगाते हैं, पानी नीचे से आता है, जब जल स्तर ही गिर जाएगा तो यह सारी योजना बेकार होगी। इसलिए मेरा निवेदन है कि इस ओर ध्यान देना चाहिए। बूंदी जिले में 1997–98 में हमने 20 ट्यूब वैल और साढ़े सात सौ हैण्ड पम्प लगाये हैं, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा मंत्री महोदय को। बूंदी जिले में ऐसे गांव हैं जहां पर हर वर्ष पीने के पानी को लेकर लोग मरते थे, जैसे गरदड़ा। गरदड़ा में पंगाना, खटकड़, रेबाड़पुरा, पच्चीपुरा ये ऐसे स्थान थे जहां पर चार-चार, छः-छः किलोमीटर दूर से पानी लाया जाता था और पानी के अभाव में लोग मरते थे। मैं धन्यवाद दूंगा मंत्री महोदय को जिन्होंने यह सारी की सारी योजना चालू कर दी, मंजूर कर दी और वहां टंकियां बन रही है, कुएं खुद रहे हैं। इसी के साथ बूंदी में अभी नैनवां, इन्द्रगढ़ और लाखेरी तीनों नगरों की लगभग 4 करोड़ रुपये की योजनाओं को भी मुझे जानकारी मिली है कि मंजूर कर दिया। उसके लिये हम बूंदी के दोनों विधायक, बूंदी की जनता की ओर से आपके आभारी हैं। वास्तव में बड़ी परेशानी थी।

इसके साथ मेरे बूंदी विधान सभा क्षेत्र में जो वन्य क्षेत्र माना जाता है, जहां आदिवासी लोग रहते हैं, वहां पीने के पानी का भारी संकट था। छः-छः किलोमीटर दूर से पानी लाया जाता था। गोवर्धनपुरा, बड़कू जहां आबादी तो नहीं है परन्तु पीने का पानी नहीं था, उसकी योजना मंजूर की आपने। उसके लिये भी मैं मन से, दिल से और जनता की ओर से बधाई देना चाहता हूं। इसके साथ बड़कू, सूंथला और बुद्धपुरा ये योजनाएं भी मंजूर कर दी गई हैं। यह सारा का सारा क्षेत्र आदिवासी क्षेत्र है, मजदूरों का क्षेत्र है, जहां खनिज होते हैं वह क्षेत्र है। वहां की योजना मंजूर की उसके लिये मैं वास्तव में आभारी हूं। बूंदी नगर की आपने 4 करोड़ 29 लाख की योजनाएं मंजूर की हैं, उसके लिये भी बूंदी की जनता आपके माध्यम से उनकी आभारी है। बूंदी में उच्च जलाशय के. जी एल. आर. की योजनाएं लागू कीं, 10 करोड़ रुपये से ऊपर की योजनाएं मंजूर की हैं। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा—(व्यवधान) हुई है मंजूर अब ही बता रहा हूं। जब नहीं हुई थी, मांग की थी। हुई तो बता रहा हूं कि यह हुआ है।

सभापति महोदय, अभी एक योजना बनाई कि जिन स्कूलों में....(व्यवधान) नहीं होते थे वह अब हुए हैं, धन्यवाद दे रहा हूं।

सभापति महोदय, जहां प्राथमिक स्कूल खोले गये हैं, बच्चे पीने के पानी के लिये दो सौ मीटर दूर, तीन सौ मीटर दूर क्लास छोड़कर जाते थे। राज्य सरकार की एक योजना बनी कि जहां प्राथमिक स्कूल होगी, जहां पीने के पानी की व्यवस्था नहीं होगी वहां हैण्ड पम्प खोदे जाएंगे। उसके तहत भी सब जगह स्कूलों में हैण्ड पम्प लगाये गये हैं।

श्री मोहनलाल मोदी : सब जगह नहीं लगाये हैं, आपके यहीं लगाये होंगे।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, इंटरप्ट नहीं करें। आज सभी को पानी पर बोलना है, बिराजिए। सदन का समय व्यर्थ न करें, बैठिए।

श्री मोहनलाल मोदी : सारी जगह नहीं लगे, मैं यह कह रहा हूं।

श्री सभापति : आपकी बारी आए तब आप बोल देना, इंटरप्ट नहीं करिये एक दूसरे को। संशोधन जब आपकी बारी आए तब कर लेना।

श्री ओमप्रकाश शर्मा : सभापति महोदय, कुछ गांव ऐसे हैं जैसे केयूदा, आमथून, रघुबीरपुरा, लाम्बाखो, राजपुरा, लाडपुरा, ममाखेडा और घड़िया सुराई एक ही गांव है लाडपुरा में और लक्ष्मीपुरा और धनेश्वर यहां पर टंकी बनाई जाए, यहां पर पीने के पानी की व्यवस्था कराई जाए।

श्री सभापति : अब आप समापन करें।

श्री परसादीलाल मीणा : पांच साल में तो बोले नहीं बूंदी के बारे में।

श्री ओमप्रकाश शर्मा : पांच साल में बहुत बोले जब ही तो मंजूर हुआ है। जब ही मंजूर हुआ है।

श्री बद्रीप्रसाद गुरुजी : परसादीलाल जी, हमने तो आपको भी पानी पिला दिया है, हमने आपको भी पानी पिला दिया।

श्री ओमप्रकाश शर्मा : जो अच्छा काम हुआ है उसके लिये धन्यवाद देना चाहिये और आपको भी देना चाहिये। जो नहीं हुआ है ...

श्री मदन दिलावर : हमने अच्छों–अच्छों को पानी पिलाया है।

श्री परसादीलाल मीणा : रामनारायण मीणा ने हाड़ौती को पानी पिला दिया और माननीय दिलावर साहब भी साफ हो गये उसमें।

श्री ओमप्रकाश शर्मा : मैं पुनः आपके माध्यम से मंत्री महोदय को धन्यवाद देता हुआ ...

श्री रामस्वरूप मीणा : विधान सभा चुनाव में देख लेना, यहां की जनता पानी पिलाएगी आपको। लोक सभा चुनाव में तो 5/25 और अब आगे देखना 50/200, बात बना रहे हो।

श्री ओमप्रकाश शर्मा : चलो देखो, आ रहा है वक्त। सभापति महोदय, जो योजनाएं मंजूर की हैं उसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद दे रहा हूं राज्य सरकार को, राजस्थान के मुख्य मंत्रीजी को, हमारे मंत्री जी को। आपने मुझे समय दिया उसके लिये धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री बनवारीलाल शर्मा।

(66)

श्री बनवारीलाल शर्मा (धौलपुर) : सभापति महोदय, पेयजल की मांग पर चर्चा हो रही है। पेयजल की समस्या के बारे में चाहे इधर बैठने वाले सदस्य हों चाहे उधर बैठने वाले सदस्य हों, सभी चिंतित हैं और यह भी बात निश्चित है कि मंत्री महोदय भी इस समस्या से चिंतित हैं और अपना पूरा प्रयास कर रहे हैं। लेकिन फिर भी मुश्किल है। एक समय था कि पानी की समस्या सिर्फ रेगिस्तानी इलाके में ही थी, लेकिन पानी का जल स्तर जिस प्रकार गिर रहा है उससे यह समस्या पहाड़ी इलाके में या पठारी इलाके में भी इसी प्रकार से पैदा होती जा रही है। मैदानी इलाके में तो हमको और आपको सोचना पड़ेगा कि किस तरीके से इस समस्या का समाधान किया जा सकता है गम्भीरता से अपने को सोचना पड़ेगा, क्योंकि आज हम जो भी पानी की समस्या का समाधान कर रहे हैं सिर्फ भूगर्भ से पानी निकालकर ही कर रहे हैं। हम जो भी पेयजल उपलब्ध करा रहे हैं, शायद 95 प्रतिशत भूगर्भ से करा रहे हैं और मुश्किल से 5 प्रतिशत नदी या तालाबों से करा रहे हैं। इसी का परिणाम है कि पानी का स्तर घट रहा है। आज जहां पेयजल के लिए पानी की आवश्यकता है उसके साथ ही भूगर्भ से ही हम सिंचाई के लिए भी पानी दे रहे हैं और जिस प्रकार से उद्योग बढ़ रहे हैं, उन उद्योगों को भी पानी की आवश्यकता है। ऐसी स्थिति में हमको और आपको, सबको मिलकर विचार करना पड़ेगा कि आखिर इस समस्या से किस तरह से निपट सकते हैं।

माननीया सभापति महोदया, मैं मंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहता हूं, एक तो यहां जमीन में पानी नहीं है और दूसरे, आसपास कोई नदी या तालाब भी नहीं है। पानी अगर है तो खारा है, फ्लोराइडयुक्त है। तो एक तो आपकी यह समस्या है, दूसरा आर्थिक साधनों की समस्या है। योजना तो बना सकते हैं, लेकिन आर्थिक कमी की वजह से आप उनको उतनी जल्दी नहीं कर पाते हैं। तीसरी, मेरे ख्याल से समस्या है विभाग की नासमझी की। उनमें इतनी सूझबूझ नहीं है उसकी वजह से भी कोई समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। इस स्थिति में हमको और आपको यह सोचना पड़ेगा कि आखिर हम किस तरीके से इन समस्याओं का समाधान कर सकते हैं।

मैं अपने क्षेत्र के बारे में निवेदन करूं। मैं आपका आभारी हूं कि धौलपुर में पानी की समस्या को देखते हुए आपने वहां पर पुनर्गठित योजना को स्वीकार किया। लेकिन आज आप देखिये, दो वर्ष हो गये इस योजना को स्वीकृत हुए लेकिन विभाग की नासमझी की वजह से आज तक इस पर कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया। आप अंदाजा लगाइये, माननीय मंत्री महोदय, इस योजना को बनाने से पहले विभाग ने यह ही तय नहीं किया था कि कहां पर हम स्टोर टैंक बनाएंगे, कहां पर हम फिल्टर हाउस बनाएंगे, और योजना स्वीकृत कर दी। दो साल भूमि की अवाप्ति में लग गये और इस कारण से उस योजना का लाभ आज तक धौलपुर की जनता नहीं उठा पा रही

(67)

(श्री बनवारीलाल शर्मा)

है। सबसे बड़ी बात यह है कि फिल्टर हाउस जहां बनना था उसकी भूमि प्रवाप्त करने की कार्यवाही में कुछ कानूनी अड़चनें आ रही थीं उसमें समय लगता तो लगाते, लेकिन इसके साथ शहर में पाइप लाइन डालने का काम था, तीन टंकियों को बनाने का काम था, और कई कार्य थे, पैरेलल अगर वे काम चलते रहते तो भूमि प्रवाप्त होने के बाद में फिल्टर हाउस बनाने के बाद में इतना समय नहीं लगता। मेरा तो आपसे निवेदन है कि आप इसको देखिये। पता नहीं कैसे माननीय सचिव महोदय के हिसाब के कम्प्यूटर से धौलपुर निकल गया, वरना उनको एक मिनट में ही इसका अंदाजा हो जाता है और दो वर्ष हो गये उनका ध्यान इस ओर नहीं जा पाया है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि मेहरबानी से उस योजना के ऊपर कार्य शीघ्र ही प्रारम्भ करें।

श्री भंवरलाल शर्मा : एक आप मदद करें। भूमि प्रवाप्ति की जो स्थिति है, यदि आप उसमें कोई मिडिएट करके तय कर लें तो मैं समझता हूं जल्दी ही अच्छा होगा।

श्री बनवारीलाल शर्मा : मेरी जानकारी में शायद वह भूमि प्रवाप्ति का कार्यक्रम पूरा हो गया। दो वर्ष हो गये, मेरा तो यह निवेदन था कि विभाग सजग होता तो शायद इसमें इतनी देर नहीं लगती।

दूसरा, मंत्री महोदय, मेरा यह निवेदन है कि मेरे यहां पर चम्बल के किनारे बसई-मील एक गांव है, वहां पर गंधक का पानी आता है, बदबूदार पानी आता है। लैबोरेटरीज में भेजा, उसकी जांच रिपोर्ट भी आयी। वास्तव में वहां पर हैण्ड पम्प सक्सैसफुल नहीं होते हैं। विभाग ने एक योजना भी बनायी करीब सवा 11 लाख रुपये की। वहां का स्थानीय विभाग महसूस करता है कि वास्तव में पानी की दिक्कत है, लेकिन जहां लाखों रुपये का सवाल आ जाता है वहां पर यह सोच लिया जाता है कि हैण्ड पम्प से ही काम चल जाएगा और हैण्ड पम्प वहां सक्सैसफुल होते नहीं हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

माननीय सभापति महोदया, दो मिनट के लिये मुझे बोलने दीजिये।

श्री सभापति : आपको सूचना दी है, आप पूरा करें।

श्री बनवारीलाल शर्मा : मैं मतलब की बात ही निवेदन कर रहा हूं।

मोरोनी की एक योजना है। डांग क्षेत्र में मोरोनी एक गांव है, वहां की योजना है। आप देखिये, चम्बल से वहां पर पानी सप्लाई करते हैं लेकिन चार महीने चूंकि चम्बल नदी बढ़ जाती है, उसमें उफान आ जाता है, चार महीने उस योजना से उस क्षेत्र के लोगों को पानी उपलब्ध नहीं कराया जाता है। अगर कराया भी जाता है तो बिलकुल गंदा पानी कराया जाता है, वहां पर आज तक फिल्टर-हाउस नहीं बनाया गया है। मेरा आपसे निवेदन है कि उन

(श्री बनवारीलाल शर्मा)

चार महीने भी पानी उपलब्ध हो और फिल्टर हाउस बनाकर उस क्षेत्र की जनता को आप मेहरबानी करके स्वच्छ पानी दिलवाने की व्यवस्था करें।

इसी प्रकार से मगरोली की योजना है। मगरोली की योजना में आपने टंकी बना दी, स्टोरेज बना दिया, जी.एल.आर. बना दी। लेकिन जी.एल.आर. ऐसी बनायी कि पानी डालते ही, टैस्ट करते ही लीक हो गया, खराब हो गया। पाइप लाइन नहीं डालते हैं। अभी चम्बल की बाढ़ आयी उसमें पाइप लाइन टूट गयी। वहां फिल्टर प्लांट भी लगाया नहीं गया है। तो मेरा यह निवेदन है कि ऐसी योजना को बनाने से लाभ क्या है? मुश्किल यह होती है कि योजना बना देते हैं, प्रारम्भ कर देते हैं और उसके भरोसे से जो लोगों के अपने और साधन हैं उनसे भी वंचित रह जाते हैं। जहां पर बिजली पहुंच जाती वहां पर लालटेन घर पर नहीं मिलती हैं, जहां पर यह पाइप लाइन या योजना पहुंच जाती है वहां बाल्टी और रस्सी नहीं मिलती हैं, तो वहां पर और परेशानी आती है। इसलिए मेरा यह निवेदन है कि आप ऐसी योजनाओं पर ध्यान दें।

बिरोंदा की स्कीम है। बिरोंदा की स्कीम मंजूर हुई, एक साल हो गया, पता नहीं क्यों उस पर कार्य प्रारम्भ नहीं किया जा रहा है। आपका पैसा अलाट हो गया, स्कीम मंजूर हो गयी है, ट्यूब वैल खोद दिया है लेकिन उस पर कार्य प्रारम्भ नहीं किया जा रहा है। मेहरबानी करके इसकी भी आप जानकारी करें। पुरानी छावनी में आज कम से कम 6 या 7 हजार की आबादी है, डायरेक्ट पानी आप सप्लाई कर रहे हैं। यहां पर आज तक आपने टंकी नहीं बनायी है, एक ट्यूब वैल बनाया है, उससे पूरी सप्लाई नहीं हो पाती है। तो उसके लिए आप ध्यान दें। कसीमा है, आज से 20–25 साल पहले योजना बनायी गयी थी। अब जनसंख्या बढ़ गयी, एरिया बढ़ गया, लोगों की आवश्यकताएं बढ़ गयी। ऐसी स्थिति में विभाग ने यह महसूस किया कि वास्तव में वहां पर आवश्यकता है और 19 लाख रुपये की एक योजना बनायी, लेकिन पता नहीं वह कहां अटक रही है। मेरा आपसे निवेदन है कि आपके डिपार्टमेंट में प्रपोजल्स आ चुके हैं, उनको जल्दी से निकालें। सैंपो की टंकी है, करीब 1967 में उस टंकी को बनाया गया था। टंकी की हालत इतनी जर्जर हो गयी है कि वह टाइमबार हो गयी है और अगर उसको नहीं तोड़ा गया, कभी भी कोई खतरा हो सकता है। जिला कलक्टर ने भी अभी मीटिंग में वहां पर वार्निंग दे दी कि अगर विभाग ने इस टंकी को नहीं तोड़ा तो मैं खुद तुड़वाऊंगा और उसका खर्चा विभाग से लूंगा। जब विभाग महसूस करता है कि कोई खतरा नहीं हो जाए, कोई अप्रिय घटना नहीं हो जाए तो मेहरबानी करके उस टंकी को तोड़ें और उसकी जगह कोई दूसरी टंकी बनाएं। वहां पर पुन- र्गठित योजना दुबारा बनाएं। आपने डिसाइड किया कि 1500 की आबादी पर एक रीजनल स्कीम बनाएंगे, लेकिन रीजनल स्कीम अभी तक

(श्री बनवारीलाल शर्मा)

आपने नहीं बनायी, चाहे वह कासिमपुर है, चाहे वह भैंसना है, चाहे वह सतवारा है। दूसरा एक निवेदन है माननीय मंत्री महोदय से कि जहां रीजनल स्कीम में जी. एल. आर. बनाते हैं, गांव में सिर्फ एक जी. एल. आर. बनाते हैं चाहे वह 10 हजार गैलन का है, चाहे 15 हजार गैलन का है, चाहे 20 हजार गैलन का है। मेरा आपसे निवेदन है कि बजाय एक जी. एल. आर. बनाने के गांव में आप 2-3 छोटे-छोटे जी. एल. आर. बना दें उतनी कैपेसिटी के तो वहां की जनता शायद ज्यादा लाभ उठा सकेगी। थोड़ा पाइप आपका जरूर ज्यादा खर्च होगा, वरना एक जी. एल. आर. एक कोर्नर में बन जाता है, वहां पर पाइंट लगा देते हैं और लोग इतना लाभ नहीं उठा पाते हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

धौलपुर में एक ड्रिलिंग का ए.ईएन. आफिस का कार्यालय भरतपुर से ट्रांसफर हुआ था।

श्री सभापति : अब आप समापन करें।

श्री बनवारीलाल शर्मा : सभापति महोदया, मैं सिर्फ दो मिनट में ही समाप्त करता हूं।

11-1-95 से, आप देखिये कि इतने वर्ष हो गये। कार्यालय आज वह कागजों में धौलपुर के नाम से ही चल रहा है लेकिन वह आफिस वहां पर ट्रांसफर नहीं हुआ। आखिर क्या कारण है? जब आदेश हो गये, आज भी धौलपुर के नाम से तनख्वाह उठायी जा रही है तो मेहरबानी करके उस कार्यालय को धौलपुर में भिजवाने की कृपा करें।

मेरा आपसे एक और निवेदन है कि धौलपुर इलाके में चम्बल नदी बहती है, सरमथुरा-बाड़ी का जो इलाका है वहां पर आजकल तो वह बांध टूट गया है वरना पार्वती बांध से इतनी ज्यादा कैपेसिटी में पानी रहता है कि सरमथुरा के पहाड़ी इलाके से सिंचाई विभाग से सम्पर्क करके उस क्षेत्र के लिए कोई योजना बनाएं तो निश्चित तौर पर उस क्षेत्र के लिए लाभ मिल सकता है।

अन्त में मेरा आपसे यह निवेदन है कि हैण्ड पम्प की जो मरम्मत है, मेहरबानी करके पंचायत समिति को मत दीजिये। मेरी जानकारी से 400 रुपये पर हैण्ड पम्प आप पंचायत समिति को देते हैं और पंचायत समिति उससे लोगों को कोई भी राहत नहीं दे पाती है। अल्टीमेटली आपको साल में 3-4 महीने का एक अभियान चलाना पड़ता है, तब कहीं जाकर मरम्मत हो पाती है। मेरा आपसे निवेदन है कि ऐसी डेमोक्रेसी में फायदा क्या है जहां पर कि लाभ नहीं मिल सके। इस मरम्मत कार्य को आप पंचायत समिति के बजाय विभाग के द्वारा ही कराएं तो ज्यादा उपयुक्त रहेगा और ज्यादा लोगों को राहत मिल सकेगी। यही मेरा निवेदन है कि धौलपुर की इन समस्याओं के बारे में आप ध्यान दें। वैसे आप का धौलपुर से लगाव है, आप हर चुनाव में आते हैं। तो वहां

70

(श्री बनवारीलाल शर्मा)

की समस्याओं का समाधान भी करें। धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री रामेश्वरजी भारद्वाज।

श्री रामेश्वर भारद्वाज (किशनपोल) : माननीय सभापति महोदया, आज पेयजल के सम्बन्ध में यहां चर्चा हो रही है, मैं भी अपने आपको इसमें सम्मिलित करना चाहता हूं। जल सबको प्राथमिकता से देने का प्रत्येक सरकार का संकल्प है। कोई भी परिस्थिति हो, पानी देने का सबसे पहला कर्तव्य सरकार का है। अनेक योजनाएं बनाकर राज्य सरकार ने पूरे प्रदेश में, प्रत्येक जिले और गांव–गांव में पानी देने का भरसक प्रयास किया है। उसके आंकड़ों के सम्बन्ध में अनेक माननीय सदस्यों ने अपने विचार रखे हैं।

जयपुर शहर के सम्बन्ध में तत्कालीन सरकारों ने कोई ऐसी व्यापक योजना नहीं बनायी कि जयपुर शहर को आखिर पानी देने की क्या व्यवस्था होगी। माननीय मंत्री महोदय को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि जब से उन्होंने यह विभाग सम्भाला है, अनेक ऐसी योजनाएं बनाकर जयपुर शहर को पेयजल उपलब्ध कराने का भरसक प्रयत्न किया है। नलकूप सैंकड़ों की संख्या में बनाये हैं, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र को पानी देने के लिए कई पाइप लाइनों का जाल बिछाया है, और शहर में लगभग 1300 हैण्ड पम्प नये बनवाये हैं। सरकार का संकल्प था कि हम सामान्य व्यक्ति को जल उपलब्ध करवाएंगे, तो कच्ची बस्तियों में हजारों की संख्या में फ्लैट रेट पर पानी के कनेक्शन दिये। जिन बस्तियों में पानी की लाइन जाना बहुत मुश्किल था और व्यक्ति उपेक्षा भाव से देखता था, आज वह बहुत प्रसन्न है और सामान्य खर्चे पर पीने का पानी उसको उपलब्ध हो रहा है। इसी तरह से जिन लाइनों में अवरोध आ गये थे, पुरानी थीं चार-दीवारी के अन्दर, ऐसी पुरानी पाइप लाइन को नई लाइन में बदलने के लिए भी 20-22 लाख की योजना का प्रावधान किया और अनेक ऐसी कालोनियों में जो छोटी लाइनें थीं, शहर में वे लाइनें बदली गयीं।

श्री परसादीलाल मीणा : आप कोई सुझाव दें।

श्री रामेश्वर भारद्वाज : आप सुनने का माद्दा रखेंगे तो मैं सुझाव भी दे दूंगा। परन्तु धैर्य से सुनें थोड़ा-सा। तब कुछ भी कहेंगे तो पूछ लेना मेरे से।

ऐसी अनेक जो छोटी लाइनें थीं उनको बड़ी लाइन में परिवर्तित किया है और जहाँ दूर से भी पानी लाना पड़ा तो उसको भी लाकर शहर में पानी उपलब्ध कराने का भरसक प्रयत्न किया है। कई सारी ऐसी टंकियां बनाकर पानी का दबाव ठीक से बना रहे और अच्छी मात्रा में उपलब्ध हो, उसका भी आपने बहुत अच्छा प्रबन्ध किया है। कई सारी टंकियां निर्माणाधीन हैं। कई सारी टंकियां आपने स्टोर के परपज से भूमिगत भी बनायी हैं, उनका भी कार्य

(श्री रामेश्वर भारद्वाज)

सुचारू रूप से चल रहा है। लेकिन कई बस्तियों में लीकेज की जो समस्या है उस लीकेज की समस्या के सम्बन्ध में मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि हमारा बहुत सारा जल व्यर्थ जाता है। इस संबंध में आपके विभाग में कोई अलग से व्यवस्था करें, ताकि वह लीकेज को देखें और समय रहते उसको ठीक करें। तो जिन बस्तियों में थोड़ा-बहुत पानी कम दबाव से आता है, वह भी ठीक हो सकता।

आज कई बस्तियों में पानी देने में थोड़ी-बहुत भेदभाव की नीति रहती है। यह भेदभाव दूर हो। कुछ बस्तियों में आप दो समय पानी देते हैं, कुछ बस्तियों में एक समय देते हैं। मैं आपको मेरी ओर से निवेदन करना चाहूंगा कि सबको दोनों समय जल उपलब्ध कराएं। खास तौर पर जिन बस्तियों को आप एक समय पानी देते हैं वे कमजोर बस्तियां हैं। जिन बस्तियों में दो समय पानी देते हैं उन बस्तियों में सबके पास साधन हैं, स्टोर भी कर सकते हैं। घर में 10 बर्तन होते हैं वह भी भर सकते हैं। परन्तु सामान्य परिवार हैं, मध्यम श्रेणी के जो परिवार हैं उन बस्तियों में उनके पास न इतने बर्तन होते हैं, न पानी स्टोर करने के कोई साधन होते हैं। तो मैं आपसे यह निवेदन करूंगा कि मानवता के नाते इन बस्तियों को भी आप दोनों समय पानी उपलब्ध कराएं।

कई बस्तियों में पानी की मात्रा बहुत अधिक और कुछ में कम रहती है, इस विसंगति को भी आप ठीक से दिखवाएं। उदाहरण के लिए, यदि हम चांदपोल के ही दो हिस्से करें तो पुरानी बस्ती में तीसरी मंजिल पर पानी आएगा तो तोपखाना में पहली मंजिल पर भी नहीं आता है। इसको भी आप ठीक में दिखवाएं अपने अधिकारियों से।

जिन बस्तियों में सोसायटी द्वारा मकान बनाए गये हैं, ऐसी अनेक बस्तियां पानी की सुविधा से आपने जोड़ी हैं। कुछ में आपने जन सहभागिता के आधार पर पाइप लाइन डाली। इसमें मुझे लगता है कि अधिक सफलता नहीं मिल रही है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि जो सोसायटी के द्वारा बसी बस्तियाँ हैं उनमें भी आप पानी उपलब्ध कराएं। सरकार अपनी ओर से भी पानी की सुविधा दे तो मैं समझता हूं कि सभी बस्तियों में पानी ठीक प्रकार से उपलब्ध हो सकता है। कई सारी टंकियां निर्माणाधीन हैं इनमें भी कहीं न कहीं शिथिलता आयी है। कारण आप अपने विभाग से ही पूछे दो मिनट और लूंगा।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

उसमें गति लाने का प्रयास करें। मैंने 3-4 बस्तियों की जो आवश्यकता है, उनकी टंकी के प्रपोजल आपसे बनवाए हैं। व्यास कालोनी में आपने टंकी बनाने के लिए सैंक्शन दी हुई है। आपने इंजीनियरिंग कालेज से उसकी जाँच भी करवा ली। इंजीनियरिंग कालेज ने भी उसकी पुष्टि कर दी कि यहां टंकी बन सकती है, उसके बाद भी यह मामला बहुत लम्बित है।

72

(श्री रामेश्वर भारद्वाज)

शास्त्री नगर और रामनगर में तो आपने भूमिगत टंकियां बनायी हैं। गर्मी से पहले ये शुरू होनी थीं लेकिन अभी तक भी ये शुरू नहीं हुई हैं। इसको भी आप ठीक प्रकार से देखें।

कई सारी अभी तक पुरानी लाइनें हैं जयपुर शहर में और कई-कई स्थानों पर तो कास्टिंग की भी लाइनें हैं, उनको भी आप ठीक से दिखाएं। अन्यथा वहां पानी व्यर्थ जाता है। कई सारे नलकूप खराब हैं और बंद हो गये हैं। ठीक कराने की कई बार चर्चा के बाद हां की जाती है, पर ठीक नहीं हो पाते हैं। जो नाकारा साबित हो गये हैं उनकी जगह आप दूसरे हैण्ड-पम्प शीघ्र लगाने की व्यवस्था करें। गत वर्षों मे आपने जयपुर शहर को कोई हैण्ड-पम्प नहीं दिये हैं। मैं आपसे यह निवेदन करना चाहूंगा कि अनेक ऐसे स्थान हैं जहां पानी की समस्या रहती है। आप नये हैण्ड-पम्प शहर को भी दें। कुछ ऐसी बस्तियां हैं जिनमे पानी की लाइन डालने में तकलीफ आयी है। आप तत्कालिक व्यवस्था के आधार पर वहां पानी टंकियों से सप्लाई करते हैं, लेकिन यह कोई बहुत स्थाई और अच्छी व्यवस्था मुझे नहीं लगती है। रोज-रोज शिकायत भी आती है। इन बस्तियो मे भी किसी तरह से स्थायी रूप से हम पानी दे सकते हैं, चाहे वह इन्दिरा ज्योति नगर हो, श्री राम का टीला हो, बिहारी टीला हो, बड़ी संख्या में यहां नागरिक रहते हैं, आप उसको भी ठीक प्रकार से देखें।

कई जगह पानी देने में समय की भी कोताही बरती जाती है। ऐसी कच्ची बस्तियों में शिवाजी नगर के आस-पास की बस्ती है, वहां रात में ढाई बजे आप पानी सप्लाई करते हैं। एक मजदूर दिन भर अपनी मजदूरी करता है, तन तोड़कर मेहनत करता है और उसके विश्राम का जब समय होता है, जब अपने घर आकर के वह विश्राम करता है तो ढाई बजे पानी देना मैं समझता हूं कि मानवता के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ है और आप इसी गम्भीरता से इसको लेंगे। आप अगर सी-स्कीम में इसको ढाई बजे दे देंगे तो चलेगा क्योंकि उनके पास टैंक होते हैं, आप जितना नल खोलेंगे उतना पानी पूरा उनको मिलेगा। आधा घंटा देंगे तो आधा घंटा लेंगे और तीन घंटे देंगे तो तीन घंटे लेंगे। लेकिन इस गरीब को आप मात्र आधा घंटा पानी देते हैं, और वह भी ढाई बजे रात्रि के समय। यह घोर अन्याय है उस व्यक्ति के साथ, आप इसे तत्काल सुधार करवाइये।

मैं आपसे यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि आपके जितने भी पानी सप्लाई के स्थान हैं, आपके मानदंड के अनुसार वहां पर्याप्त सामग्री रहती है परन्तु जब अधिकारियों से बात करो तो नाकारा ही जवाब मिलता है। मुझे जानकारी मिली है कि दिसम्बर से अब तक पाइप नहीं खरीदा गया है, उसके अभाव में कई सारी योजनाएं लम्बित पड़ी है। इसका क्या कारण रहा होगा, इसे भी आप चैक करवाइये। जितनी भी आपकी पानी सप्लाई की चौकियां हैं उनमें पर्याप्त सामग्री रखें ताकि छोटी-सी भी

(श्री रामेश्वर भारद्वाज)

पाइप लाइन खराब होने पर उसको रिप्लेस किया जा सके, तो मैं समझता हूं कि बहुत अच्छा रहेगा। इसी तरह से आज भी कई बस्तियों सीकर हाउस, माली कालोनी, और सिन्धु नगर कालोनीज के आस-पास गन्दा पानी आ रहा है। मैं आपसे क्षमा चाहते हुए यह निवेदन करना चाहूंगा कि एक-एक महीने अधिकारियों को बताने के बाद भी इस पर ध्यान नहीं दिया जाता है। बल्कि न्यू-कालोनी में गन्दा पानी आने लगा। तो साल भर कोई न कोई उलटा उत्तर देने की जो एक आदत पड़ी है, इसमें कहीं–न-कहीं चैक लगना चाहिये। हम कहेंगे कि आज पानी की लाइन चालू हो जाएगी तो वे कहेंगे कि कल हो जाएगी। ठीक, पर उस पर भी पन्द्रह-पन्द्रह दिन निकल जाते हैं। तो ऐसी अनदेखी करने वाले अधिकारियों के खिलाफ आप सख्त कार्यवाही करें। आपको अवगत कराने के बाद भी वह ठीक नहीं होती। शहर में बहुत सारे ऐसे लोग रहते हैं जो बहुत संवेदनशील हैं, कई माननीय अधिकारियों की शिकायत बराबर बनी रहती है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आपके इतना बढ़िया काम करने के बाद भी यह शिकायत बनी रहे तो आपने इतना सारा प्रयास किया है इस सब पर इससे काफी सारी आंच आती है। कई

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

सारी कालोनियों में जो दबाव से पानी नहीं आ रहा....

श्री सभापति : समापन करें।

श्री रामेश्वर भारद्वाज : मैं कह रहा हूं, माली कालोनी, विश्वकर्मा, सिन्धु नगर कालोनी, शिव--शक्ति कालोनी, शंकर कालोनी, नया खेड़ा, अम्बाबाड़ी, लोहा मंडी ऐसी अनेक बस्तियां हैं जो आज भी पानी के कम दबाव की शिकायत करती रहती हैं। आपके अधिकारियों के पास भी शिकायत है। इसके लिए बीसलपुर की योजना लम्बित थी, अभी सिंचाई की मांगों पर जब चर्चा हुई, उस लम्बित योजना में एक आशा की किरण जगी है कि ईसरदा बांध से जयपुर शहर को पानी मिलेगा। इसकी चर्चा यहां पर हुई है। माननीय मुख्य सचेतकजी ने भी इसके लिये बहुत सारे प्रयास किये, मैं उनको बधाई देना चाहता हूं। शीघ्र इस योजना से जयपुर शहर को पानी उपलब्ध कराने के लिये निश्चित रूप से सरकार इसको प्राथमिकता से लेगी। अन्यथा शहर में प्रतिदिन सैकड़ों की संख्या में हैण्ड पम्प खुदते जा रहे हैं और धीरे-धीरे ऐसा लगता है कि यह नीचे कहीं समुद्र बन जाएगा। यही स्थिति यदि जयपुर शहर की आ गयी, आपके मानदण्डों के हिसाब से तीन सौ फीट में एक के बाद दूसरा हैण्ड पम्प नहीं खुदना चाहिये परन्तु प्रत्येक घर में एक हैण्ड पम्प खुद रहा है, तो क्या स्थिति आपकी बनेगी? इसलिए बाहर से पानी

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

लाने का जो यह प्रयास शुरू किया है इसे प्राथमिकता दें। आपने समय दिया, सभापति महोदया, इसके लिये धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री आर. पी. शर्मा।

श्री आर. पी. शर्मा (भरतपुर) : माननीय सभापति महोदया, पेयजल की मांग संख्या-27 के सम्बन्ध में चर्चा में मैं अपने आपको सम्मिलित करते हुए निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान की जनसंख्या आज लगभग पांच करोड़ चालीस लाख है जो हिन्दुस्तान की जनसंख्या का 5 परसेंट आती है। यह जनसंख्या हमारे लगभग 222 नगरों, 38 हजार गांवों और 45 हजार ढाणियों में बसती है। अगर हम पानी की वास्तविक समस्या को देखें तो हम पाते हैं कि हिन्दुस्तान का एक परसेंट स्रोत ही हमारे राजस्थान में उपलब्ध है। इसलिए यह समस्या हमारे राजस्थान के लिये बहुत ही गम्भीर और विकराल समस्या है और भविष्य में इसके क्या रूप होंगे, मैं नहीं कह सकता।

माननीय सभापति महोदया, पानी की समस्या पर सोचने से पहले मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि पानी से ही हमारे जो 90 परसेंट रोग हैं, वे पैदा होते हैं। इसका मतलब यह है कि अगर पानी शुद्ध पीने को नहीं मिलता है तो प्रदेश के रहने वाले व्यक्तियों के स्वास्थ्य पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। इसलिए पानी की बहुत महत्वपूर्ण समस्या के प्रति हमारी सरकार को सोचना चाहिये। पानी की आवश्यकता चाहे औद्योगिक क्षेत्र में हो, चाहे कृषि क्षेत्र में हो, चाहे पशुओं के लिये हो, बहुत ही महत्वपूर्ण आवश्यकता है। इस समस्या के समाधान हेतु मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि हमारे यहां जो हैण्ड पम्प स्कीम चालू की गयी है, उसमें आज सरकार का लगभग 2200 करोड़ रुपया खर्च हो गया है। वह स्कीम मेरे हिसाब से मैं कह सकता हूं कि पूरी फेल है, क्योंकि हैण्ड पम्प की मरम्मत की जो समस्या है आज तक सरकार इसको पूर्ण रूप से हल नहीं कर पायी है। हमारे यहां मेंटीनेंस का जो सैल है वह पूर्ण रूप से सक्षम नहीं है। इसलिए मेरा इसमें एक निवेदन है कि अगर हैण्ड पम्प स्कीम को हम रीजनल स्कीम मे कन्वर्ट कर देते हैं तो निश्चित रूप से हम इस समस्या के समाधान में कुछ कदम उठा सकते हैं।

दूसरा, मंत्रीजी को मालूम है कि 1994 में मामड़ाजी की अध्यक्षता में एक पेयजल समस्या समाधान समिति गठित हुई थी और उस समिति ने अपनी रिपोर्ट दी थी। उस समिति की रिपोर्ट को अगर हम गौरपूर्वक देखें, समझें, तो या तो पी.एच.ई.डी ने समिति की उस रिपोर्ट पर गौर नहीं किया या उस पर क्रियान्विति नहीं की। उस कमेटी की रिपोर्ट का हम देखें तो हम पाते हैं कि पेयजल समस्याओं के मूल में जो बातें हैं उन सबका उसमें सम्मिश्रण है और उसके साथ-साथ समाधान की भी उसमें एक योजना बतायी गयी है। सबसे महत्वपूर्ण बात जो उस कमेटी ने कही है, वह कही है कि यह सुनिश्चित किया जाए कि भूमिगत जल प्रांत के किस-किस भूभाग में कितनी-कितनी मात्रा में उपलब्ध है, उपलब्धता के अनुरूप भूमिगत जल के कृषि कार्यों व अन्य प्रयोजन हेतु दोहन पर नियंत्रण के उद्देश्य से मापदण्ड निर्धारित किये जाएं और पानी के दुरुपयोग को रोकने के लिये कानून भी बनाये जाएं।

दूसरा, उन्होंने कहा है कि समिति

(श्री आर. पी. शर्मा)

स्थाई समाधान के लिये सुझाव देती है कि प्रांत के लिये एकीकृत जल नीति बनायी जाए और इसकी क्रियान्विति के लिये एक पृथक विभाग की भी स्थापना की जाए। इसमें बहुत महत्वपूर्ण सुझाव दिये गये हैं। इसमें कहा गया है कि जल नीति में एनीकट निर्माण, उसके रख-रखाव और पारस्परिक जल स्रोतों की मरम्मत, रख-रखाव के लिये भी व्यवस्था की जाए। बूस्टर लगाने पर प्रतिबन्ध लगाये जाएं। भूगर्भ जल स्तर में वृद्धि की दृष्टि से गंदे पानी व अन्य अतिरिक्त पानी को डगवैल्स के माध्यम से या अन्य तरीका अपना कर भूमिगत किया जाए। इस समिति की रिपोर्ट माननीय मंत्रीजी के पास भी है, विभाग के पास भी है, जो इसमे सुझाव दिये गये हैं, एक से लेकर चौदह तक सुझावों की क्रियान्विति के लिए सरकार अगर कदम उठाए तो मैं कह सकता हूं कि राजस्थान प्रदेश की जनता के लिये, हमारे लिये बहुत अच्छा रास्ता हो सकता है और हम पेयजल समस्या पर काबू पा सकते हैं।

महोदया, मैं एक निवेदन और करना चाहता हूं, राजस्थान सरकार ने पम्प और टैंक स्कीम शुरू की, उसकी हालत क्या है? टैंक बनते हैं, वे कुंआ लेवल पर बनते हैं, उससे पानी नहीं पहुंच पाता है। निश्चित रूप से यह स्कीम भी हमारी फेल हुई है।

इन सब समस्याओं के सन्दर्भ में जैसे कि और अन्य क्षेत्र के विधायकों ने अपनी-अपनी बात कही, भरतपुर क्षेत्र के पीने के पानी की समस्या के लिये मंत्रीजी को मालूम है और इसमें दो राय नहीं है कि उनकी भावना और मन निश्चित रूप से इस क्षेत्र में काफी काम करने का है लेकिन या तो अधिकारियों की हठधर्मी या कोई पैसे की समस्या हो सकती है कि हमारे क्षेत्र में पानी की समस्या के काम पूरे नहीं हो पा रहे हैं। मैंने एक क्वेश्चन पूछा था मंत्रीजी से और कल हमारे राजेन्द्र सिंह राठौड़ बड़े खुले रूप से कह रहे थे कि मंत्रीजी को जो विभाग जवाब देता है, पूर्ण रूप से असत्य होता है या मिथ्यापूर्ण होता है। उसमें एक तरह से यह बू आती है कि विभाग यह सोचता है कि या तो हमारे मंत्रीजी या असैम्बली में जो विधायक बैठते हैं, उनको पता नहीं है और जानबूझकर विभाग वाले मंत्रीजी को और विधायकों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। मंत्रीजी से

(समय–समाप्ति-सूचक घण्टी)

मैंने एक प्रश्न मेरे क्षेत्र के बारे में पूछा था। मेरे क्वेश्चन में था कि विधान सभा क्षेत्र भरतपुर के लिए अधिशासी अभियन्ता, भरतपुर द्वारा पेयजल समस्या के समाधान हेतु कब-कब, कितनी-कितनी योजनाएं प्रस्तावित कर सरकार को भिजवायी गयी? इसका लम्बा-चौड़ा जवाब दे दिया और योजनाएं बता दी। मैंने क्वेश्चन पूछा है इस विधान सभा के सत्र में और जवाब दे दिया कि 1977 में हमने ये काम कर दिये। मंत्रीजी, अगर इस जवाब को आप ढंग से पढ़े तो इसमें एक से बारह स्कीम बतायी गयी है जो या तो पहले चालू थीं या जिनमें ट्यूब वैल खराब हो गए, उनको चालू

76

(श्री आर. पी. शर्मा)

करने के लिए काम चल रहा है। लेकिन कुछ योजनाएं जो मैंने बनवायी थीं-सिवाना की, अगापुर की, सुनारी की और बड़ाखुर्द की उनका इसमें कहीं जिक्र नहीं है। आपके यहां सबसे बड़ी कमजोरी क्या है विभाग में कि योजनाएं बनकर आती हैं और पड़ी रहती हैं, एक-एक साल तक उन योजनाओं पर क्रियान्विति नहीं होती। कभी कोई फाइनेंशल प्राब्लम आती है, कभी कोई टैक्निकल प्राब्लम आती है। एक कहावत है कि आदमी जिंदा ही नहीं रहेगा तो फिर उसके लिए डाक्टर की आवश्यकता क्यों होगी। पानी की समस्या जो जल्दी सॉल्व हो सकती है, जिसमें आपका खर्चा भी कम हो या जिन के समाधान में आपको ज्यादा दिक्कत नहीं है, ऐसी छोटी-छोटी बातों का भी आपके विभाग द्वारा निस्तारण नहीं किया जाता है। इसलिए मंत्रीजी, थोड़ा आप इनके ऊपर पकड़ बनाएं। मेरा जो जवाब आया है, मैं आपसे बाद में मिलकर बता दूंगा। आप निश्चित रूप से विभाग के अधिकारियों के साथ कड़ा रूख अपनाएं, अगर ये गलत जवाब देते हैं तो इनको दंडित करें। तब ही यह विभाग सुधरेगा, क्योंकि इंजीनियरिंग विभाग बहुत ही लाल-लाल विभाग होता है। इसलिए आप मेहरबानी करके यह व्यवस्था करें।

दूसरा मैं आपसे भरतपुर की छोटी-छोटी दो समस्याओं को बताना चाहता हूं। हमारे यहां फिल्टर प्लांट एक है, वह आज से कोई 30-35 साल पहले लगा था जब भरतपुर की आबादी मुश्किल से एक लाख होगी। आज भरतपुर की आबादी 1 लाख 80 हजार है एक फिल्टर प्लांट से उस आबादी को हम पीने योग्य शुद्ध पानी नहीं दे सकते। इसलिए एक तो मेरा निवेदन है कि दूसरे फिल्टर प्लांट की स्वीकृति के लिए संबंधित कार्यवाही करें।

तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं भरतपुर शहर में जो पीने का पानी मिल रहा है उसके बारे में। गांधी पार्क में हमारा जो ट्यूब वैल लगा हुआ है वह बिलकुल सुजान गंगा नहर जिसमें शहर का गंदा पानी आता है, उस नहर के बराबर में लगा हुआ है, उसका पानी पीने योग्य नहीं है। कई दफा हमारे यहां लोगों ने प्रदर्शन किया, ज्ञापन दिए, धरने दिये लेकिन आपका विभाग सुनता नहीं है। वह पानी, मैं कहता हूं खारा तो है ही, लेकिन अगर उस पानी को रेगुलर कोई आदमी पीता रहे तो विभिन्न तरह की बीमारियाँ हो जाएंगी। दूसरा, हमारा रणजीत नगर का पानी है वह पीने योग्य नहीं है। हमारा एटर बांध का पानी है वह पीने योग्य नहीं है। मैं

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

आपसे निवेदन करना चाहूंगा, भरतपुर में अगर पीने के पानी की समस्या का समाधान कोई है तो वह चम्बल लिफ्ट योजना है, जो आज से 10 साल पहले बनी थी। वह योजना क्यों बंद हो गयी ? अगर आप भरतपुर का भला चाहते हैं, भरतपुर के साथ यह चाहते हैं कि न्याय हो, भरतपुर के लोगों को पीने का पानी मिले

(श्री आर. पी. शर्मा)

तो उस योजना को चालू करें, क्योंकि भरतपुर की भूमि खारी है, वहां खारा पानी है और स्रोत हमारे हैं नहीं। यह चामड़ा जी की रिपोर्ट है, इसमें लिखा है "चम्बल नदी का लगभग एक करोड़ क्यूबिक फीट पानी व्यर्थ में बहकर यमुना नदी में चला जाता है।" इसके साथ लिखा है उसमें, "भरतपुर जिला पूर्व में बाढ़ से ग्रसित रहता था लेकिन अब इस जिले में पेयजल का गंभीर संकट उत्पन्न हो गया।"

मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि जहां हमारा लगभग एक करोड़ क्यूबिक फीट पानी वेस्ट जाता हो, वहां भरतपुर को पीने के पानी का केवल एक ही साधन कोई हो सकता है तो वह है चम्बल लिफ्ट योजना। मेहरबानी करके भरतपुर के पीने के पानी के लिए चम्बल लिफ्ट योजना द्वारा आप इन्तजाम करें, ऐसा मैं आपको सुझाव देना चाहता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ मंत्रीजी से यह उम्मीद करते हुए कि आप हमारी जो छोटी—छोटी समस्याएं हैं उनमें विभाग के अधिकारियों का सामंजस्य बिठाकर भरतपुर की पीने के पानी की समस्या के समाधान करने में मदद करेंगे, धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री सभापति : श्री शांतिलाल जी चोईवाल।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम (सांगानेर) : पाइंट आफ इन्फार्मेशन। सभापति महोदया, अभी मैं निगम की मीटिंग में गयी थी अस्पताल होकर, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। वहां से मैं निगम की मीटिंग में गयी, इसलिए अभी देर से आयी। जब मैं मीटिंग में आ रही थी तो मैंने देखा कि हमारी निगम की जो पार्षद हैं, पांच महिला पार्षद—इन्द्रमणि दीक्षित, लोचन भाटी, नूरजहां बेगम, रबिया बेगम, शाहजहां और उनके साथ और पांच—सात जने, सब बिलकुल लहूलुहान, पिट-पिटाकर वहां से आ रहे थे। इन्द्रमणि दीक्षित बेहोश थीं, उनको उठाकर ला रहे थे। मैंने उनसे पूछा कि तुम्हें क्या हुआ, मैं तो तुम्हारी मीटिंग में आ रही थी। तो उन्होंने बताया कि हमको तो महापौर ने और सारे लोगों ने मिलकर मारा है। उनकी बहुत बुरी हालत है। फिर मैं उनको लेकर ज्योति नगर थाने में गयी, वहां रिपोर्ट दर्ज करायी है जिसकी कॉपी मैं लेकर आयी हूं। अब अस्पताल देखकर आयी हूं ताकि उनको (व्यवधान) अभी सुनो, देती हूं।

श्री सभापति : पाइन्ट आफ इन्फार्मेशन है यह। बिराजें आप। पाइंट आफ इन्फार्मेशन वे दे रही हैं, दे दिया उन्होंने। बाकी आप बिराजें। आप बिराजें।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : सभापति महोदया, यह मामला इतना गंभीर है कि वहां पांच-सात जनों को लहूलुहान हालत में .. (व्यवधान)

श्री महेन्द्र कुमार मीणा (सिकराय) : सभापति महोदया, कुछ तो जवाब दिलाओ। (व्यवधान) बहुत गंभीर मामला है। (व्यवधान)

श्री सभापति : इनको बोलने तो देते हैं नहीं। (व्यवधान)

(78)

श्री शैलेन्द्र जोशी (बांदीकुई) : कांग्रेस के जीते हुए पार्षदों पर इस तरह से हमला हुआ तो यह विषय बहुत चिन्ताजनक है। (व्यवधान)

श्री महेन्द्र कुमार मीणा : भारतीय जनता पार्टी के महापौरजी ने जानबूझकर ... (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : वे नगर पार्षद की जीती हुई....(व्यवधान) कांग्रेस की पार्षद हैं और इस तरह का हमला होता है एक जन–प्रतिनिधि पर तो वह कोई गंभीर विषय नहीं माना जाना चाहिए ? (व्यवधान)

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : (व्यवधान) मार-मार उनको बेहोश कर दिया। (व्यवधान) इन्द्रमणि दीक्षित को भर्ती कराने जा रहे हैं (व्यवधान)

श्री महेन्द्र कुमार मीणा : (व्यवधान) अन्याय कर रहे हैं....(व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : अच्छा, भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों की पिटाई हो तो आपके लिए यह विषय चर्चा का है.... (व्यवधान)

श्री सभापति : हो गया, पाइंट आफ इन्फार्मेशन हो गया। (व्यवधान) सूचना हो गयी, माननीय सदस्य। बिराजें। सूचना हो गयी, बिराजें।

श्री शैलेन्द्र जोशी : यह राजनैतिक भेदभाव नहीं होगा। यह गलत बात है। (व्यवधान)

श्री महेन्द्र कुमार मीणा : सभापति महोदया, महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, उनको पीटा जा रहा है (व्यवधान) भारतीय जनता पार्टी...(व्यवधान)

श्री सभापति : हां, सूचना हो गयी न। (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : यह पार्टी स्पिरिट पर जो काम हो रहा है, यह बहुत ही दुःखद स्थिति का परिचायक है। (व्यवधान)

श्री सभापति : बिराजिए। (व्यवधान)

श्री जगदीप धनखड़ (किशनगढ़) : यह आरोप लगाया गया है। (व्यवधान)

श्री सभापति : बिराजिए; सूचना हो गयी। जानकारी ली जाएगी, बिराजिए।

श्री जगदीप धनखड़ : आप तो खुद महिला हैं।

श्री सभापति : हां, तो ठीक है। आपकी सूचना आ गयी न। (व्यवधान) महिला होने की क्या बात है ? (व्यवधान)

श्री जगदीप धनखड़ : आप चाहते हैं कि एक तिहाई उनको प्रतिनिधित्व मिले। (व्यवधान)

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : उनकी पिटाई हुई, वे बेहोश हो गयीं। (व्यवधान)

श्री सभापति : सूचना हो गयी। (व्यवधान)

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : उनमें से एक हैं इन्द्रमणि दीक्षित । अभी भी बेहोशी की हालत में पड़ी हैं अस्पताल में । (व्यवधान)

श्री सभापति : आप विराजिए । विराजें आप ।

श्री जगदीप धनखड़ : अस्पताल में भर्ती हैं, चूड़ियां उनकी तोड़ दी गयीं ।

श्री सभापति : माननीय धनखड़ जी, विराजिए । सूचना हो गयी ।

श्रीमती कमला : गृह मंत्री महोदय को निर्देशित करें कि वे इस सूचना की बाबत.. (व्यवधान)

श्री सभापति : आपकी सूचना ले ली, आप विराजें । सूचना ले ली ।

श्रीमती कमला : आप उनको निर्देशित तो करें ।

श्री जगदीप धनखड़ : मंत्री महोदय कुछ तो कहें । (व्यवधान)

श्री सभापति : मंत्री महोदय जानकारी लेंगे, विराजिए आप । (व्यवधान)

श्री जगदीप धनखड़ : नहीं, जानकारी तो है मंत्री महोदय को । ऐसा नहीं हो सकता है कि इनको जानकारी में नहीं है । (व्यवधान)

श्री सभापति : विराजें ।

श्रीमती कमला : मंत्री महोदय को निर्देशित करें ।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : मंत्री महोदय जानकारी दें कि क्या हुआ निगम में.... (व्यवधान)

श्री सभापति : इन्दिराजी, विराजिए । आपकी सूचना हो गयी, विराजें ।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : सदन में स्वायत्त शासन मंत्रीजी बैठे हैं, निगम में.... (व्यवधान) बाहर भी रो रही हैं ...(व्यवधान)

श्री सभापति : स्वायत्त मंत्रीजी बैठे हैं, सूचना ले ली ।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : चुनी हुई महिला सदस्यों को मारा–पीटा जा रहा है ..(व्यवधान) उनकी चूड़ियां तोड़ दी गयी । उनके हाथ-पैरों में दाग हो गये । बेहोश पड़ी हैं । (व्यवधान)

श्रीमती कमला : माननीय सभापति महोदया, मात्र सूचना का मतलब नहीं है, गंभीर मुद्दा है, इनको कहिए कि जवाब दें । (व्यवधान)

श्री सभापति : वे मात्र सूचना ही देना चाहती थीं । उनको पूछिए वे क्या करना चाहती थीं । विराजें । (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : यह बात हल्केपन से नहीं ली जानी चाहिए, इस तरह की घटनाएं बड़ी गंभीर हैं । ये गंभीर घटनाएं

(80)

(श्री शैलेन्द्र जोशी)

हैं, इस तरह से नहीं ली जानी चाहिए। (व्यवधान)

श्रीमती कमला : जवाब तो दिलवाइए। (व्यवधान)

श्री सभापति : बिराजें। वह उन्होंने सूचना दी है। सूचना हो गयी और क्या होगा ? (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : ये गंभीर घटनाएं इस तरह से नहीं ली जानी चाहिए। हल्केपन से नहीं ली जानी चाहिए। माननीय सभापति महोदया, यह इतने हल्केपन से जो घटना की गयी है, यह आने वाले प्रजातांत्रिक समय के लिए खतरनाक बात है.... (व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य, बिराजें। (व्यवधान) बिराजें आप। (व्यवधान)

कुछ माननीय सदस्य : मीटिंग के समय से पहले कैसे लहूलुहान हो गये ये लोग, यह देखने की बात है। ....(व्यवधान)

श्री सभापति : आप उनको तो बोलने देते नहीं (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : सरकार की ओर से वक्तव्य दिलाया जाए इस बात का — (व्यवधान) माननीय गृह मंत्रीजी से वक्तव्य दिलवाया जाए और इसके लिए आज ही समय निश्चित किया जाए। (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय राजेन्द्र जी चौधरी, बिराजिए। (व्यवधान)

श्री जगदीप धनखड़ : माननीय सभापति महोदया... (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय धनखड़ जी, बिराजिए। बिराजिए, धनखड़जी। (व्यवधान) धनखड़ जी, बिराजिए (व्यवधान) शैलेन्द्र जोशी जी, बिराजिए। (व्यवधान) माननीय सदस्य, बैठिए।

श्री महेन्द्र कुमार मीणा : माननीय स्वायत्त शासन मंत्रीजी से इस बात का वक्तव्य दिलवाया जाए....(व्यवधान)

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : मंत्री जी यह तो कहें कि जांच करा लूंगा। (व्यवधान)

श्री सभापति : आपके कहने से मंत्री जी नहीं कहेंगे, बिराजिए। शासन की व्यवस्था होगी। (व्यवधान)

श्रीमती कमला : आपके कहने से तो कहेंगे न। (व्यवधान)

श्री सभापति : शासन की व्यवस्था होगी। बिराजिए। (व्यवधान) आप तो वरिष्ठ सदस्या हैं, बिराजिए। बिराजिए आप। (व्यवधान)

श्री जगदीप धनखड़ : मंत्रीजी, पूरा जवाब दीजिए। (व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा (स्वायत्त शासन मंत्री) : सभापति महोदया, कई सदस्य एक साथ बोले तो समझ में नहीं आया कि क्या बोल रहे हैं। (व्यवधान) फिर वही बात। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र चौधरी : अलग-अलग बोले हैं। (व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा : बोले होंगे, पर यही बोले होंगे....(व्यवधान)

श्री सभापति : महिलाओं के नाम पर सारे आप बोलें। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र चौधरी : बात का पता नहीं चला, यह बता रहे हैं। (व्यवधान)

श्री जगदीप धनखड़ : पांच महिलाओं के साथ मीटिंग में दुर्व्यवहार किया, जो पार्षद थीं, जिनके चोटें आयीं, जिनकी चूड़ियां तोड़ दीं और प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज हो गयी और कोई नहीं बोल रहा। अब आपकी समझ में आ गयी ? अब आप बताइए इसमें सरकार क्या करने जा रही है ? (व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा : बताऊंगा, आप सुनो तो सही मेरी बात। वह तो जब सांगानेर से आने वाली माननीय सदस्या ने बोला तब ही मेरे कुछ बात तो समझ में आ गयी थी, लेकिन आप जब बोलते रहे बोलते रहे, (व्यवधान) तो समझ में नहीं आया कि क्या बोल रहे हैं ? (व्यवधान)

श्री सभापति : ये महिलाओं को बोलने नहीं देते, महिलाओं के नाम से ये बोल लेते हैं। (व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा : अभी-अभी आपने ....(व्यवधान)

श्री सभापति : कर रहे हैं...(व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा : अभी जवाब क्या देना ? दो मिनट पहले कोई बात आपने कही अभी–अभी हाउस में और तुरन्त आप यह चाहते हैं कि मैं इसका जवाब दू। आप समझो। आप यह बताइए क्या यह सम्भव है ? मैं आपसे यह चाहूंगा... (व्यवधान) अब आप फिर बोल रहे हैं। (व्यवधान) मुझे तो अभी पता लगा है ना .. (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : आप समय निर्धारित कर दीजिए, माननीय सभापति महोदया, कि आज सायकाल इतने बजे तक आप वक्तव्य देंगे इसकी सही जानकारी के बारे मे। (व्यवधान) आप समय निर्धारित कर दीजिएगा। (व्यवधान)

श्री जगदीप धनखड़ : स्वायत्त शासन मंत्रीजी को इसकी जानकारी नहीं होगी, इस विषय की ....(व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा : फिर आप सब बोल रहे हैं। (व्यवधान)

श्री जगदीप धनखड़ : आप यह मानने को तैयार हैं क्या कि आपको सबसे पहले जानकारी सदन से मिली है ? (व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा : हां-हां, बिलकुल। (व्यवधान)

श्री जगदीप धनखड़ : आप मेहरबानी कर सदन का समय रहने तक स्टेटमेंट दें इस पर। (व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा : आप मेरी बात तो सुनें। मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं.... (व्यवधान)....

श्री जगदीप धनखड़ : आप स्टेटमेंट दें। (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय मंत्रीजी, एक मिनट बिराजिये। जो इन्होंने महापौर का नाम लिया है, इसको एक्सपंज करिये क्यों कि यह इधर की ही परम्परा है कि जो सदन का सदस्य नहीं हो उसका नाम नहीं लिया जाएगा। (व्यवधान) एक्सपंज करिये इसको। बिराजें आप।

श्री जगदीप धनखड़ : सभापति महोदय, प्रथम सूचना रिपोर्ट में महापौर का नाम है। (व्यवधान)

श्री सभापति : आप बिराजिये।

श्री जगदीप धनखड़ : उस रिपोर्ट में लिखा हुआ है। (व्यवधान) महापौर का नाम... नहीं, जो रिपोर्ट को पढ़ रहे थे, रिपोर्ट में अंकित है यह। (व्यवधान)

श्री सभापति : इसमें महापौर का क्या लेना-देना है नगर निगम की बैठक में ? (व्यवधान) नगर निगम की बैठक में महापौर का क्या काम है ? (व्यवधान)

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : मैंने तो पद का नाम लिया है, आदमी का नहीं लिया। पद का नाम लिया है, पद के नाम में कोई .. (व्यवधान)....

एक माननीय सदस्य : इसमें महापौर का क्या लेना-देना है ? महापौर का नाम बिलकुल हटाया जाए। (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : रिपोर्ट में महापौर शब्द लिखा हुआ है। अगर रिपोर्ट में महापौर का नाम किया जा रहा है तो क्या गलती है ? (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : नामजद रिपोर्ट है। (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : जब एफ. आई. आर. में महापौर का नाम है तो उसमें.... (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र चौधरी : एफ आई.आर. में दर्ज है। महापौर का मुकदमा दर्ज है.... (व्यवधान)....

श्री जगदीप धनखड़ : महापौर को एक्सपंज की कहां दरकार पड़ गयी ? कोई आपत्तिजनक बात नहीं कही गयी। प्रथम सूचना रिपोर्ट में बताया गया है। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : महापौर निगम की मीटिंग ले रहे थे... (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र चौधरी : आपत्तिजनक क्या बात हुई है ? इसमें तो केवल यह कहा गया है... (व्यवधान)....

श्री शांतिलाल चोईवाल : सभापति महोदया, हाउस को आर्डर में लाइये ताकि मैं मेरी बात शुरू कर सकूं। (व्यवधान)

श्री सभापति : आप बोलना शुरू करिये। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : महापौर ही निगम की मीटिंग की अध्यक्षता कर रहे थे।

श्री शैलेन्द्र जोशी : क्योंकि महापौर बी. जे. पी. का है इसलिए महापौर का भी नाम नहीं लिया जाए। (व्यवधान)

श्री गोपीराम जाट (आमेर) : बी.जे. पी. का है तो बहुमत से जीते हैं, आपकी मेहरबानी से जीत कर नहीं आये हैं। (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : आप रहने दीजिये, आप क्या बोलेंगे? आपने तो चुने हुए महिला प्रतिनिधियों को पिटवाया है और आप उनका संरक्षण कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री गोपीराम जाट : आपकी मेहरबानी से नहीं आया हूं।

श्री शैलेन्द्र जोशी : आपने इन्द्रमणि दीक्षित पर हमला कराया जो जीती हुई पार्षद हैं, फिर आप ऐसे लोगों का प्रोटेक्शन दे रहे हैं। (व्यवधान)

श्री सभापति : विराजें आप। (व्यवधान)

श्री शांतिलाल चोईवाल : राजेन्द्रजी, आपकी बात पूरी हो गयी। (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : सारी मान-मर्यादा आपने समाप्त कर दी क्या? शालीनता खतम हो गयी आपकी?

श्री राजेन्द्र चौधरी : नाम दर्ज है, उसमें कोई आपत्तिजनक बात थोड़ी कही है।

श्रीमती कमला : माननीय मंत्री महोदय, हमें बता दें कि कब आप इसके बारे में सूचना वापस देंगे? समय बता दें। बहुमत होने का यह मतलब नहीं है कि वहां पार्षदों की पिटाई करवाएं। (व्यवधान)

श्री सभापति : विराजिये, माननीय कमला जी। जब सूचना मिलेगी तब जवाब हो जाएगा। विराजिये। (व्यवधान)

श्री जगदीप धनखड़ : सूचना तो पता नहीं कब मिलेगी, आप बाध्य कीजिये उनको।

श्री सभापति : सूचना मंगायी जाएगी, विराजिये। बाध्य नहीं करेंगे।

श्रीमती कमला : बाध्य करने की क्या बात हुई? आज किसी को वक्त देवें, यह तो बोलें। (व्यवधान)

श्री जगदीप धनखड़ : 10 किलोमीटर से सूचना नहीं मिलेगी इनको?

(८५)

श्रीमती कमला : बाध्य कैसे नहीं करेंगे, यह क्या बात हुई ?

श्री जगदीप धनखड़ : सभापति महोदया, आपने ऐसे कई मुद्दे उठाये हैं और आपने कहा है....(व्यवधान)....

श्रीमती कमला : यह क्या बात हुई, बाध्य नहीं करेंगे ? (व्यवधान) हर बात में ही बाध्य नहीं करेंगे ? (व्यवधान)

श्री सभापति : विराजिये ।(व्यवधान)

श्रीमती कमला : सरकार काहे के लिए बैठी है फिर ?

श्री राजेन्द्र चौधरी : मंत्री महोदय जानकारी लेकर सदन को अवगत करा दें, हम यह नहीं कह रहे हैं कि अभी का अभी दें ।

श्री सभापति : विराजिये ।

श्री राजेन्द्र चौधरी : जानकारी लेकर सदन में दें । इस बात की जानकारी दे दें, बाद में सारी सूचना लेकर दे दें ।

श्री जगदीप धनखड़ : संवेदनशील बनिये और बताइये कब इसके बारे में बयान देंगे ?

श्री राजेन्द्र चौधरी : आज ही सदन के अन्दर इस बात की सूचना लेकर दे दें ।

श्री सभापति : आप मंत्रीजी को सुनना ही नहीं चाहते ।

श्री जगदीप धनखड़ : हां, बोलिये ।

श्री भंवरलाल शर्मा : यह अभ्यास नहीं है कि मैं बोलूं और आप बार-बार सब खड़े हो जाओ और फिर मेरे से बात करो। यह कौनसा तरीका है ?

श्री जगदीप धनखड़ : नहीं, आप बोलिये ।

श्री भंवरलाल शर्मा : एक बात आयी, कोई घटना घटी है । अच्छी घटी, बुरी घटी, जानकारी कर के जो कार्यवाही करना हो वह तो करना ठीक होता है लेकिन आप सुनने को ही तैयार नहीं हैं । यह मैं आपसे आशा नहीं करता हूं । इसीलिए कहता हूं कि अभी जब आज मांग चल रही है तो फिर मैं बोलूंगा, तब फिर आप इस तरह से बोलोगे तो इसका कोई अर्थ ही नहीं है । इसको संसेशन क्यों बनाना चाहिये ? एक घटना घटी है, जो अपराधी है उसके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिये । कौन अपराधी है, कौन नहीं है, यह तो अभी बिना देखे कोई कह ही नहीं सकता । मुझे जानकारी करने दीजिये क्या स्थिति है, क्या नहीं है । यह एफ.आई.आर. मुझे पढ़ा दीजिये क्या है, तो मैं बात करता हूं । लेकिन यह बात कहने से पहले ही आप इस तरह बोलते हैं तो फिर क्या करें ।

श्री राजेन्द्र चौधरी : ठीक बात है ।

श्री सभापति : श्री शांतिलाल जी चोईथवाल ।

श्री शांतिलाल चोईथवाल (राजसमंद) : माननीय सभापति महोदया, आप तत्काल

(श्री शांतिलाल खोईवाल)

हाउस को आर्डर में ले आए, इसके लिए मैं आपका और मंत्रीजी का भी आभार व्यक्त करता हूं।

आज सदन में महत्वपूर्ण मांग संख्या-27 पर चर्चा हो रही है। पूरी राजस्थान की जनता पेयजल की सुविधा चाहती है। मैं सबसे पहले माननीय मंत्री महोदय का और विभाग का इस बात के लिए आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि इस भीषण गर्मी में पेयजल की तत्काल जो समस्या उठी थी उनका समाधान बड़ी सजगता से, तत्परता से और गम्भीरता से आपने किया। हैण्ड पम्प जो सूख गये थे, ज्यों ही अनुरोध किया कि इनको गहरे कराने की जरूरत है, विद् इन 48 आवर्स वो गहरे हो गये। यही नहीं, और भी, जिस तरह की समस्या के बारे में भी जानकारी विभाग के अधिकारियों को दी जाती थी उसका निवारण तत्काल हुआ, इसके लिए मैं इस विभाग का बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूं। जहां-जहां नये हैंडपम्प खोदने की जरूरत थी वहां हैंडपम्प खोद दिये, जहां कुंए गहरे कराने की जरूरत थी तत्काल कुंए गहरे कराये, जहां नये कुंए खोदने की जरूरत थी वहां पर नये कुंए खोदने के लिए स्वीकृति जारी हुई। इससे ज्यादा सजगता, सतर्कता और पेयजल की समस्या के निवारण के लिए गम्भीरता होना सम्भव नहीं है।

सभापति महोदया, मैं इस बात के लिए भी मंत्रीजी का आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि मेरी रेलमगरा तहसील में दो पेयजल योजनाओं को मंत्रीजी ने वहां की गम्भीरता को ध्यान में रखते हुए तत्काल स्वीकृति दी। सांमेरा, गमेरपुरा के लिए 32 लाख रुपये स्वीकृत किये और चोकड़ी के लिए 18 लाख रुपये स्वीकृत किये। मंत्रीजी को यह जानकारी है और विभाग के अधिकारियों को भी यह जानकारी है कि रेलमगरा तहसील मुख्यालय पेयजल संकटग्रस्त कस्बा है। वहां पर पिछले पांच साल से जो मैं देख रहा हूं, विभाग के बहुत प्रयास करने के बावजूद थोड़ी बहुत पानी तो उपलब्ध हो जाता है लेकिन प्रयासों में कोई कमी नहीं रखी। इस वर्ष ज्यों ही मैंने वहां पर जानकारी दी कि वहां पांच दिन से एक बार पानी उपलब्ध हो पा रहा है तो विभाग ने तत्परता से दो ट्यूबवैल खोदे, एक कुआं खोदा, एक कुंए को गहरा कराया। लेकिन पानी नहीं है। मेरे कहने का मतलब यह है कि पिछले पांच साल में लगभग 70 लाख रुपये एक छोटे-से कस्बे की पेयजल समस्या के निवारण के लिए खर्च किये। लेकिन जितना पैसा खर्च किया उतना लाभ नहीं हुआ। अब पी.एच.ई.डी. के अधिकारी यह सोच रहे होंगे कि 70 लाख रुपये तो हमने नहीं दिये। डी.डी. आर.डी.ए. के माध्यम से या जो अन्य योजनाएं हैं उनके माध्यम से भी कई तरह की मद में से पैसा खर्च हुआ है। इस प्रकार 70 लाख रुपये खर्च करने के बावजूद जितना लाभ मिलना चाहिये उतना नहीं मिला। इसके दो मुख्य कारण हैं। सभापति महोदया, एक कारण तो है कि वहां पर हिन्दुस्तान जिंक की दरीबा माइंस इतनी गहरी है कि वहां का जमीन का आसपास का पानी है सारा रिसाव में उस खदान में चला जाता है और, जो पाल्यूट हो जाता है तो उसको पम्पआउट कर बाहर फेंक दिया

(86)

(श्री शांतिलाल चोईवाल)

जाता है। वह दो किलोमीटर गहरी है। दूसरा कारण यह है कि बनास नदी के किनारे रेलमगरा बसा हुआ है। बनास नदी के ऊपर नमाड़ा बांध बंधा हुआ है, भीकलबास बांध बधा हुआ है इसके कारण डाउन स्ट्रीम क्षेत्र का जल स्तर वैसे भी काफी नीचे चला जाता है और जिस तरह की सर्वे हो रही है उससे भी स्पष्ट है कि हर वर्ष राजस्थान के 26-27 जिलों में एक या दो मीटर नीचे जल स्तर चला जाता है। बरसात भी कम हो रही है। इन सारे तथ्यों के कारण, सभापति महोदया, वहां का जल स्तर बहुत नीचे चला गया है, जमीन में पानी नहीं है। हमने किसी बात के लिए अनुरोध किया, हैंडपम्प खोद दिये सूखा निकला, कुए खोद दिये सूखा निकला, ट्यूबवैल खोद दिये सूखा निकला। तो आखिर हमारी लोंग टर्म प्लानिंग क्या है, इसके बारे में इस विभाग को चिन्तन करना पड़ेगा। हैंडपम्प खोदना कोई निवारण नहीं है, ट्यूबवैल खोदना कोई समस्या का निवारण नहीं है। कुंए गहरे करना कोई निवारण नहीं है। कितनी बार कुंए गहरे कराओगे? कितना पैसा खर्च करोगे? इसके लिए मेरा अनुरोध है मंत्रीजी से कि आपको भू-जल विभाग से, सिंचाई विभाग से को–आर्डिनेट करना पड़ेगा, सभापति महोदया, इस बात के लिए कि वहां बरसात का पानी रोकना पड़ेगा।

श्री महावीर प्रसाद जैन : गलत खर्च करवा दिये पैसे।

श्री शांतिलाल चोईवाल : हां, वो 70 लाख रुपये गलत खर्च हो गये, लेकिन थोड़ा बहुत टेम्प्रेरी निदान हो गया, उसका स्थायी निदान नहीं हुआ। ऐसी स्थिति में मेरा मंत्री महोदय से अनुरोध है कि भू–जल विभाग से और सिंचाई विभाग से कोआर्डिनेट करके वहां का जो बरसाती पानी है, जो बनास नदी में बहता है वहां पर तीन एनीकट निर्माण कराने की आवश्यकता है। तीनों एनीकट्स में तीन करोड़ रुपये से ज्यादा नहीं लगेंगे। यदि वहां पर एनीकट का निर्माण हो जाता है तो वहां का जो भू-जल है उसका वह रीचार्जिंग हो जाएगा। आपको नये हैंडपम्प नहीं खोदने पड़ेंगे, नये कुंए नहीं गहरा कराने पड़ेंगे, नये ट्यूब वैल नहीं खोदने पड़ेंगे और इतने ही पैसे में आपके उस भूमि में पानी का रिसाव हो जाएगा। यह जब तक प्लानिंग नहीं करेंगे, चिन्तन नहीं करेंगे तब तक आप अरबों- करोड़ों जितना पैसा खर्च करते जाइये, पेयजल का निवारण हो जाए, मुझे विश्वास नहीं होता।

माननीय सभापति महोदय, इसी के साथ निवेदन करना चाहूंगा कि आपने मेरी दो जगहों की पेयजल योजनाएं इस बार स्वीकृत कर दी, लेकिन एक सापोला पेयजल योजना आपके पास पैंडिंग है। वहां पानी की विकट समस्या है, बहुत दूर से लाना पड़ता है। उसकी जनसंख्या भी दो हजार से ज्यादा है, विभाग ने भी अपनी ओर से प्रस्ताव भेजा है। मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि यह राजसमंद तहसील में है, इस प्रस्ताव को स्वीकार करें और जनता को राहत प्रदान करने की कृपा करें।

(14.00 बजे)

(श्री शांतिलाल चोईवाल)

जहां रीजनल स्कीम्स का प्रश्न है, जिस तरह आपने सांसेरा और दमेरपुरा रीजनल स्कीम्स को सेंक्शन किया है और 32 लाख रुपये स्वीकृत किये हैं, इसी तरह मेरा अनुरोध है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में मात्र दो पंचायत मुख्यालय हैं। इसके बाद बचेंगे वे हैं गोगाथला और लापसिया। गोगाथला और मालीखेड़ा को रीजनल स्कीम्स में इन्क्लूड कर लें। इसी तरह लापसिया को खण्डेल से रीजनल स्कीम में इन्क्लूड कर लेंगे तो आपका जो पापुलेशन का मापदण्ड है वह भी पूरा हो जाएगा और इन गांवों की पेयजल की समस्या का निवारण हो जाएगा।

इसी तरह रेलमगरा तहसील में बड़ी गम्भीर समस्या है फ्लोराइड युक्त पानी की। 40 गांवों की परेशानी है। पहली बात तो उस जमीन में पानी है नहीं और थोड़े बहुत पानी होगा तो वह फ्लोराइड युक्त पानी है जो कि पीने योग्य नहीं है। आपकी लेबोरेट्री कहती नहीं है कि इस तरह के पानी को आप पीओ। ऐसी स्थिति में फिर मैं दुबारा उन्हीं शब्दों को रिपीट करूंगा कि फ्लोराइड युक्त पानी की समस्या के निवारण के लिए भी आपको वहां पर एनीकट्स के निर्माण करने पड़ेंगे ताकि मीठे जल के स्रोत का प्रादुर्भाव हो जाए। वो भी बनास नदी में निर्माण करने पड़ेंगे। मैंने निवेदन किया था कि बामनीकला में एक एनीकट बनाना जरूरी है, मैंने निवेदन किया कि एक सूरेज के पास बनास नदी पर एनीकट बनना जरूरी है। मैंने निवेदन किया कि अमलोई पर, आप चाहे 10 करोड़ रुपया खर्च कर दीजिये वहां पानी नहीं आएगा जब तक कि वहां पर एनीकट्स का निर्माण नहीं हो जाए, माननीय सभापति महोदया।

मैं चित्तौड़ जिले के बारे में निवेदन करना चाहता हूं कि चित्तौड़ कस्बा आज पेयजल से त्रस्त है। पहले वहां पर शंकर घाट पर दैड़े में पानी भरा रहता था, वह पानी आजकल सूख गया है। पिछले 5-7-10 सालों से पानी शंकर घाट पर भरा नहीं रहता है और वहां पर और कोई स्रोत पानी का नहीं है। मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा वहां के कलक्टर सी. पी. व्यास का और वहां के माननीय सदस्य नरपतसिंहजी राजवी का कि उन्होंने हिन्दुस्तान जिंक के अधिकारियों से सामंजस्य बिठाकर घोसूण्डा डैम से पानी उपलब्ध करवाया पेयजल के लिए। लेकिन घोसूण्डा डैम की भी एक सीमा है, माननीय सभापति महोदया। सीमा इसलिए है कि घोसूण्डा डैम पर मूल रूप से अधिकार हिन्दुस्तान जिंक का है। न तो पी. एच. ई. डी. का है और न ही सिंचाई विभाग का है। मैंने कल भी निवेदन किया था कि घोसूण्डा डैम की दीवार ऊपर और बढ़ा दी जाए, बांध ऊपर बढ़ा दिया जाए और उसकी भराव क्षमता बढ़ा दी जाए तो चित्तौड़ कस्बे की पेयजल की समस्या का स्थाई निवारण संभव हो जाएगा। वहां पर हिन्दुस्तान जिंक की कालोनी तक तो उन्होंने पाइप दबा रखे हैं और जब बहुत ज्यादा अनुरोध किया जाता है तब थोड़ा बहुत चित्तौड़गढ़ कस्बे के लिए पेयजल उपलब्ध करवा दिया जाता है।

(श्री शांतिलाल खोईवाल)

हिन्दुस्तान जिंक ने एक अनुबन्ध कर रखा है सिंचाई विभाग मे, मैं चाहूंगा कि पेयजल मंत्रीजी इस पर कोआर्डिनेट करके घोसुण्डा डैम को ऊपर उठाएं। भराव क्षमता बढ़ जाएगी तो इसका निवारण हो जाएगा। ज्यादा पैसा तो खर्च होता है बांध की नींव में और पहले चरण में, उसकी दीवारें ऊपर बढ़ाने में ज्यादा खर्च होने की संभावना नहीं है। यही नहीं, वहां की जो भराव क्षमता है कि इतना पानी भरेगा, उसके मुआवजे का भुगतान भी हो चुका है और पानी की आवक बहुत है उस बांध में। पहली बरसात यदि अच्छी हो जाती है तो बांध भर जाता है और जब दो-चार बार बरसात होती है तो पानी सरप्लस होकर ओवरफ्लो होकर आगे नदी में बह जाता है। ऐसी स्थिति में इस बांध की ऊंचाई और ऊपर बढ़ाने की जरूरत है। यदि इस बांध की ऊंचाई बढ़ा दी गयी तो उस जिले का भला हो जाएगा। चित्तौड़गढ़ कस्बे में आपने करोड़ों रुपये खर्च किये टेम्परेरी निवारण के लिए हर वर्ष, उसमें इस तरह पैसा खर्च करने की फिर जरूरत नहीं पड़ेगी। मात्र दो करोड़ रुपये उस बांध की ऊंचाई को बढ़ाने के लिए खर्च करेंगे तो मैं समझता हूं कि पूरे जिले को सिंचाई का फायदा भी हो जाएगा, भूमिगत जल स्रोत का प्रादुर्भाव हो जाएगा, पेयजल की समस्या का निवारण हो जाएगा और इस बांध के नीचे वाले गांवों को जो परेशानी हो रही है उस बांध के कारण, उनकी समस्या का भी निवारण हो जाएगा।

सभापति महोदया, एक छोटी--सी समस्या और मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा।

श्री सभापति : अब आप पूरा करें।

श्री शांतिलाल खोईवाल : मैं पूरा कर रहा हूं, सभापति महोदया।

कांकरोली की पेयजल योजना तीन साल पहले स्वीकृत की थी, उसका आपने रीआर्गेनाइजेशन किया। उस स्कीम में जगह-जगह नये पाइप दबवाने की भी व्यवस्था की, फिल्टर प्लांट का भी निर्माण किया लेकिन वहां का वार्ड नं. 3 जहां एस. सी., एस. टी. और ओ. बी. सी. के लोग बसते हैं-घाटरियावास, वहां पर कस्बे में पाइप दबाये हुए नहीं हैं। बहुत ज्यादा खर्चा नहीं है, माननीय मंत्री महोदय। यदि आप पांच लाख रुपये भी हमें उस समस्या के निवारण के लिए दे दें तो वे गरीब लोग आपको दुआएं देंगे और मैं समझता हूं कि जिला मुख्यालय पर जिस तरह का जलदाय विभाग ने इन्फ्रास्ट्रक्चर कर रखा है पेयजल योजना के लिए, उसका लाभ उनको भी मिल जाएगा। मैं इतनी बात कहकर आपने समय दिया, इसके लिए धन्यवाद ज्ञापित करता हूं।

श्री सभापति : श्री हीरालाल विश्नोई।

श्री हीरालाल विश्नोई (सांचोर): सभापति महोदया, मांग संख्या 27-पेयजल पर जो चर्चा हो रही है उस चर्चा में अपने आपको सम्मिलित करते हुए मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित

(श्री हीरालाल विश्नोई)

करना चाहता हूं। मैं सांचोर तहसील से चुनकर आता हूं। यहां से सांचोर तहसील, जिला जालोर 800 किलोमीटर की दूरी पर है। वह इलाका ऐसा इलाका है कि एक तरफ तो गुजरात का बार्डर लगता है, एक तरफ रण आफ कच्छ है और एक तरफ बाड़मेर का इलाका लगता है। आज हमारे इलाके में पानी को लेकर समस्या चल रही है। वैसे पानी की समस्या पूरे राजस्थान के हर क्षेत्र में चल रही है, चाहे सामने हों पक्ष के माननीय सदस्य हों, चाहे प्रतिपक्ष के माननीय सदस्य हों। एक बार सरकार में रहते हुए वाहवाही तो करनी ही पड़ती है मगर आखिरकार बात इनको भी यही करनी पड़ती है कि मेरे एरिये के अन्दर यह समस्या है; इस समस्या का समाधान हो।

सभापति महोदया, मेरे एरिये में पिछले आठ साल से, जब से भारतीय जनता पार्टी का शासन आया, मैं यह व्यक्तिगत रूप से भारतीय जनता पार्टी के राज के ऊपर आरोप लगा रहा हूं, आठ साल से आज दिन तक कोई काम नहीं हुआ। एक भी विकास की योजना नहीं बनी। पानी को लेकर एक भी योजना नहीं बनी कि वहां के लोगों की समस्या का समाधान हो सके। मैंने हर सत्र में यहां पर कई तरह से प्रश्न उठाकर जवाब चाहे हमारा एक नेड इलाका है जहां 40 किलोमीटर की दूरी में कहीं पानी की समस्या हल करने जैसा कोई समाधान है नहीं। उस नेड एरिये के अन्दर जमीन खारी होने के कारण सुरावा और टांपी की दो रीजनल स्कीम बनी हुई थीं, उन स्कीम्स से उन गांवों तक पानी पहुचाया जाता था। 1988-90 में जो जी.एल.आर. और पाइप लाइन लगी हुई थी, उससे उन गांवों में पानी पहुचता था। उसके बाद अभी 1990-91 में जो बाढ़ आयी उस बाढ़ के अन्दर एक प्रश्न लगाया, उसमें जवाब आया कि 38 लाख रुपये खर्च किये। उस स्कीम के तहत 10-15 गांव ऐसे हैं जहां आज दिन तक भी पानी नहीं पहुंचा, तो यह 38-40 लाख रुपया कहां खर्च किया? किस योजना पर खर्च किया? जो मरम्मत की थी, पाइपें चेंज किये थे, अभी इस तूफान के अन्दर थोड़ी-सी बारिश हुई उससे दो फुट पानी नदी में आया और वहां के अधिकारियों ने कह दिया कि पाइप बह गये। यह गढ़ी-गढ़ाई साजिश है, वहां की जनता के साथ धोखाधड़ी है। जो भी अधिकारी वहां जाते हैं वे कहते हैं कि पानी नहीं है। आज पानी नहीं आया, बिजली नहीं थी। हमेशा यह समस्या सुनने को मिलती थी। मैंने पिछले दो सालों में प्रयास किया, मंत्री महोदय मेरे साथ पधारे थे, एरिये की समस्या सुनी थी। ये सामने बिराजमान हैं, मैं अगर कोई बात असत्य कहूं तो ये मेरे को टोक सकते हैं। कम से कम 20 गांवों में जहां जी. एल. आर. से पानी जुड़ा हुआ था, मैं नयी स्कीम की भी बात नहीं करता था, जी.एल.आर. से, पाइप लाइन से जुड़े हुए गांवों में लेकर गया, वहां एक बूंद पानी नहीं मिला। मंत्री महोदय, अगर मिला हो तो आप बता दें। उसका दो साल में कोई निवारण नहीं। अधिकारियों से बात की गयी, तो पानी नहीं है। आपने आदेश दे दिया आप योजना

(श्री हीरालाल विश्नोई)

बनाइये । अब योजना बनकर आयी हमारे परावा से चितलवाना की । परावा रीजनल स्कीम जो बनकर आयी, दो साल से डेढ़ साल से यहां पड़ी है, हर बार कुछ न कुछ उसके ऊपर आब्जेक्शन लग जाता है । तीन साल पहले आपने किये नहीं और अब दो साल से वह स्कीम रोज जालोर और जोधपुर जिले से होती हुई यहां आती है और वापस जाती है । तो, मंत्री महोदय, आखिर एक दिन आदमी....

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

सभापति महोदया, मेरी समस्या पूरे राजस्थान से अलग है । मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं मेरी बात पूरी करने दें । वहां पर पानी नहीं है और जो पानी है भी वह नौ-दस फ्लोराइड कंटेंट का पानी है । परावा का पानी पिला रहे हैं आप लोग जनता को । मालवाड़ा-परावा की जो स्कीम है, मेरे साथ चलिये आप, मैं आपको बताऊं, हर गांव में 2-3 आदमियों में आपको कूबड़ापन नजर आएगा । घुटने उनके दुखते हैं, उठ नहीं सकते, बैठ नहीं सकते, इस तरीके की बीमारी है । इसलिये 1985-86 में परावा चितलवाना की स्कीम बनी थी । चितलवाना पंचायत समिति उप तहसील खुली है, बड़ा गांव है । वहां जितने भी आपके एस. आर., जी.एल.आर. आज से 8-10 साल पहले बने थे, इनमें आज दिन तक बूंद पानी नहीं गया । बड़ी समस्या है । और जो गांव रीजनल स्कीम से जुड़े हुए हैं उनमें पांच-पांच साल से पानी नहीं जाएगा तो हमारा क्या होगा ? जनता कैसे वहां रह सकती है । हमारी आधी जनता गुजरात की तरफ पलायन कर गयी है । आप गये थे, आपको भी एक गांव में 5-10 आदमी से ज्यादा नहीं मिले ।

सभापति महोदया, मैं आपके मार्फत निवेदन करना चाहता हूं कि दूसरी हमारी स्कीम टापी की है । टापी बंधा कुंआ की स्कीम के लिये भी आप लोगों को कहा, आप लोगों ने जो हुक्म फरमाया उस दरम्यान स्कीम बनकर यहां आ गयी । वह स्कीम भी दो साल से अधरझूल में पड़ी है । सुरावा की हमारी स्कीम है, सुरावा से सांचोर और नेड़ इलाके की स्कीम बनी हुई है । सुरावा और दुगाला के बीच में बार-बार पाइप लाइन टूट जाती है । कई बार मैंने एक्स ईएन. को कहा, ए.ईएन. को कहा, कोई वहां सुनने वाला नहीं है । दूसरी बात, सुने तो कौन सुने, हमारे सात जे ईएन. की पोस्ट हैं, एक भी जे ईएन. हैडक्वार्टर पर आज दिन तक नहीं मिला । हमने मंत्री महोदय को कहा, हमारे चीफ को कहा, एक्स. ईएन. साहब को कहा, ए.सी. साहब को कहा । सब जे. ईएन के जहां-जहां हैडक्वार्टर हैं, मैं आपको नाम गिनाना चाहता हूं—सांकड़ा, देवड़ा, टापी, मीलू, सांचोर, सब के सब जे ईएन. वहां नहीं रहते, सांचोर के अन्दर ही रहते हैं । सांचोर से अब जे.ईएन. हैडक्वार्टर पर

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

नहीं जाएंगे तो वहां की जनता की समस्याओं का समाधान कैसे होगा ? वहां के जे ईएन., ए ईएन के ऊपर मेरा खुला आरोप है कि वे लोग लाइनमैनों के मार्फत रोज बिजली की मोटर जलाकर पैसा लेते

(श्री हीरालाल बिश्नोई)

हैं। पैसा लेने के कारण लाइनमैन उनकी बात मानते नहीं, कतई नहीं मानते। तूफान से पहले ए. सी. साहब, एडिशनल चार्ज उनके पास था, वे आये थे कि आपकी बहुत समस्या है। मैंने कहा, कोई समस्या नहीं है। जल स्तर है, पानी है लेकिन हमारे कर्मचारियों-अधिकारियों की लापरवाही की वजह से पानी नहीं जा रहा। मेरे साथ एक रात ए. सी. साहब के गांव में रहने से उन दस गांवों में पानी पहुंचा। चावल, हाड़ेचा जितनी भी रीजनल स्कीम थीं वहां पानी पहुंच गया। वहां जो पम्पमैन होते हैं, लाइट जाती नहीं है, बंद करके सो जाते हैं। वह कोई काम करने के लिये ही तैयार नहीं है।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

समापति महोदया, मेरा आपकी मार्फत निवेदन है कि हमारे टेल एण्ड के गांव हैं, पिछले आठ साल से एक में भी पानी नहीं गया। कोई भी बता दे। सांगलवाड़ में आज आठ साल से पानी नहीं गया, कोलियों की ढाणी बोचावाड़ी, घणे की धाड़ी बोचावाड़ी, ब्राह्मणों की धाड़ी बोचावाड़ी, सनवाना गांव, भोले की खूंटो, माणमिक बिश्नोई की ढाणी और बरूणवा हाई स्कूल के पास जो रीजनल स्कीम से जुड़ा हुआ है। वहां ये कहते हैं कि 38 लाख रुपया हमने जाड़ के अन्दर खर्च किया लेकिन बरूडवा स्कूल के पास दस फुट पाइप टूटी हुई है, उसके पाइप नहीं लगे आज आठ साल से। अब वैसे तो कल्याणकारी सरकार का नाम देते हैं और....

श्री समापति : माननीय सदस्य, आप पूरा करिये। देखिये, मुझे बहुत लोगों को देना है समय।

श्री हीरालाल बिश्नोई : समापति महोदया, मेरी बात मेरे को कहने दीजिये। आप स्कूलों की बात करते हैं कि स्कूलों में पानी देना है लेकिन मेरे इलाके के अन्दर सैकण्डरी स्कूल है जहां कम से कम तीन-चार सौ लड़के पढ़ते हैं, उस जी.एल. आर. के अन्दर सिर्फ दस फुट पाइप के लिये आठ साल से वह स्कीम बंद पड़ी है। इसी तरीके से बरूणवा हायर सैकण्डरी स्कूल, बरणोदा, बिश्नोईयों की ढाणी, केसुरी गांव जो बहुत बड़ा गांव है, वह भी पड़ा है। सीलू सजारा और मैं दूसरा आपसे निवेदन करना चाहता हूं....

श्री समापति : मैं अगला नाम पुकारती हूं। माननीय सदस्य, 4.30 बजे गुलबंद होगा और मंत्रीजी का जवाब भी कराना है। सबको मौका देना है। पूरा करिये आप।

श्री हीरालाल बिश्नोई : समापति महोदय, वह जो जवाब मुझे दिया गया....

श्री समापति : अब आप रखिये। इसके बारे में लिखित में ही जो करना है करें। मैं अगला नाम बोलती हूं।

श्री हीरालाल बिश्नोई : समापति महोदय, 66 गांव की हमें लिस्ट दी कि वे पूर्ण हो गये। उसमें दस गांव तो हमारे एम.पी., एम.एल.ए. कोटे में स्वीकृत थे....

श्री समापति : बिराजिये अब।

(92)

श्री हीरालाल बिश्नोई : वे भी नहीं हुए और दूसरे जो बताए वे भी अपूर्ण काम हैं। अब इनकी बात कितनी सत्य है, कितनी असत्य है, वह आप देखिये। जो लिस्ट में अपूर्ण गाँव बताये गये....

श्री सभापति : माननीय सदस्य, बिराजिये। मुझे सबको अवसर देना है, बिराजिये आप। मैं अगला नाम बोलती हूं। मैं अगला नाम बोल रही हूं।

श्री हीरालाल बिश्नोई : मैं निवेदन करना चाहता हूं मंत्री महोदय से कि मेरी दो रीजनल स्कीम आपके पास हैं बंधाकुआ, डांपी की....

श्री सभापति : बिराजिये।

श्री हीरालाल बिश्नोई : सांचोर रीजनल स्कीम, जो ढाई सौ गाँव की है ... (व्यवधान)

श्री सभापति : बिराजिये आप, बिराजिये।

श्री हीरालाल बिश्नोई : आप जब उत्तर दें उसमें जरूर जवाब दें कि ये रीजनल स्कीम सैंक्शन हो गयी हैं और कब तक काम हो जाएगा....

श्री सभापति : माननीय सदस्य, बिराजिये आप।

श्री रामेश्वरलाल भारद्वाज : पाइंट आफ इन्फार्मेशन।

श्री हीरालाल बिश्नोई : जो भी है वह आप स्पेसिफिक जवाब दें। एक स्वीकृत स्कीम 12 लाख की, पादोड़ी से हेमागुड़ा की, एक साल से पैंडिंग पड़ी है, एक पैसे का वहाँ काम नहीं हुआ है....

श्री सभापति : बिराजिये अब। आप बिलकुल आसन की मानना ही नहीं चाहते क्या? आपको मैंने पूरा समय दिया, दूसरों को भी देना है मुझे। बिराजिये, एक मिनट में काम नहीं होने वाला। अब आप कितनी देर तक बोलोगे? दूसरों को भी मौका देना है मुझे। .... (व्यवधान)

श्री हीरालाल बिश्नोई : इनसे बोल-बोलकर मैं आठ साल से थक गया, कोई सुनने को तैयार नहीं है। पानी जैसे मामले में जो भेदभाव के तरीके से काम कर रहे हैं।

श्री रामेश्वरलाल भारद्वाज : पाइंट आफ इन्फार्मेशन।

श्री सभापति : बिराजिये आप, बिराजिये। मुझे सभी माननीय सदस्यों को समय देना है, बिराजिये आप।

श्री हीरालाल बिश्नोई : मेरा आरोप है मंत्री जी के ऊपर। आप देखकर आये वहाँ। आप अगर उसको निपटाना चाहते तो हमारी ये स्कीमें एक साल से चालू हो जातीं। आपकी तरफ से ढिले होने के कारण आज भी हमारी स्कीमें अधूरी पड़ी हैं।

श्री सभापति : अब आप बिराजिये।

श्री हीरालाल बिश्नोई : सभापति महोदय, मंत्री महोदय से मैं फिर निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी जो भी स्कीमें पेंडिग पड़ी हैं वह मेहरबानी करके स्वीकृत करें। अधिकारियों को हिदायत दें, जो लापरवाही बरतते हैं, जो भेदभाव के तरीके से काम करते हैं, वे काम ईमानदारी से करें।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप बिराजें। आप आसन को मजबूर मत करें।

श्री हीरालाल बिश्नोई : सभापति महोदय, आपने हमें जो टाइम दिया, उसके लिए धन्यवाद।

श्री सभापति : हां बोलिये।

श्री रामेश्वर भारद्वाज (किशनपोल) : सभापति महोदय, सांगानेर से आने वाली माननीय सदस्या ने यहां जो सूचना दी है नगर निगम की, वह निराधार है, गलत है। बल्कि कांग्रेस के पार्षदों ने महापौर पर हमला किया, उनके माइक तोड़े हैं। (व्यवधान) यह कांग्रेस की बोखलाहट साबित कर रही है। चुनाव जैसे-जैसे नजदीक आ रहे हैं ... (व्यवधान)

श्री महेन्द्र कुमार मीणा : भारतीय जनता पार्टी के लोगों में महिला पार्षदों के ऊपर हमले किये हैं, उनको पीटा है.... (व्यवधान)

श्री सभापति : बिराजिये। (व्यवधान)

श्री महेन्द्र कुमार मीणा : सभापति महोदय, गलत है ....(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : महिलाओं के साथ अत्याचार कर रहे हैं....(व्यवधान)

श्री महेन्द्र कुमार मीणा : जो कांग्रेस की महिला पार्षद थीं उनको नगर निगम की मीटिंग के अंदर पीटा गया है...(व्यवधान)

श्री रामचन्द्र रावत : मंत्री जी क्यों नहीं दे दें, यही बात....(व्यवधान)

श्री महेन्द्र कुमार मीणा : ये माननीय सदस्य गलत सूचना दे रहे हैं, सदन का समय नष्ट कर रहे हैं। यह जो घटना हुई है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है ....(व्यवधान)

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : सभापति महोदय, सदन में आकर जानबूझकर गलत बयान....(व्यवधान)

श्री सभापति : बिराजें, माननीय सदस्य।

श्री शांतिलाल चाईवाल : महापौर पर इस तरह का....(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, बिराजें। अंकित नहीं होगा।

श्री महेन्द्र कुमार मीणा : ×××

××× अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(९५)

श्री गोपीराम आट : ×××

श्री सभापति : अंकित नहीं होगा। माननीय सदस्य, विराजें।

श्री किशन गोपाल कोगटा : ×××

श्री महेन्द्र कुमार मीणा : ×××

श्री सभापति : माननीय सदस्य, विराजें।

श्री शांतिलाल चोईवाल : ×××

श्री सभापति : विराजिये, माननीय सदस्य।

श्री रामेश्वर भारद्वाज : ×××

श्री हीरालाल बिश्नोई : ×××

श्री सभापति : वे बैठ गये हैं। आप खड़े हुए हैं, वे बैठे हुए हैं। कृपया आप भी विराजें।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : ×××

श्री रामचन्द्र रावत : ×××

श्री किशन गोपाल कोगटा : ×××

श्री सभापति : श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास। विराजिये, माननीय सदस्य।

श्री जगदीप धनखड़ : ×××

श्री रामेश्वर भारद्वाज : ×××

श्री सभापति : विराजिये, माननीय सदस्य।

श्री कालीचरण सराफ : हाउस में पाइन्ट ऑफ इन्फार्मेशन देकर गलत सूचना देने के लिए आप इनको प्रताड़ित करिये।

श्री सभापति : विराजिये आप।

श्री जगदीप धनखड़ : मंत्री जी को जवाब देने दीजिये।

एक माननीय सदस्य : आप बोल रहे हैं हमला किया गया।

श्री महेन्द्र कुमार मीणा : सभापति महोदय, मंत्री महोदय को कोई पता नहीं है (व्यवधान) यह जो किशनपोल से आने वाले सदस्य हैं इनकी नजरों में डाल दिया है।

श्री जगदीप धनखड़ : विधि मंत्री जी का कार्य क्षेत्र है ?

श्री सभापति : आप भी विराजें, मंत्री महोदय।

श्री कालीचरण सराफ : महापौर को विधान सभा....

श्री महेन्द्र कुमार मीणा : इसलिए मंत्री महोदय को कोई मालूम ही नहीं है। आपको मालूम होना चाहिए....(व्यवधान)

××× अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री जगदीप धनखड़ : ..गैर जिम्मेदाराना....(व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज । बिराजिये ।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : मंत्री महोदय को ...(व्यवधान) जो यह गलत बयानी ...(व्यवधान)

श्री सभापति : बिराजिये, माननीय सदस्य । आप भी बिराजिये । श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास ।

एक माननीय सदस्य : हमला करके यह ...(व्यवधान)

श्री सभापति : बिराजिये ।

श्री मोहनलाल मोदी : सभापति महोदय, ये आपके ही मंत्री बैठे हैं ।

श्री सभापति : बोलने दीजिये, माननीय सदस्य । माननीय सदस्या बोल रही हैं । बिराजिये ।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (जोधपुर) : माननीय सभापति महोदय, आज सदन जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं में से एक मांग संख्या 27–पेयजल पर चर्चा कर रहा है । मेरा विधान सभा क्षेत्र पिछले कई वर्षों से इस समस्या से जूझ रहा है । शहर के लोगों को भी याद है कि पेयजल समस्या के समाधान के लिए जोधपुर में पानी रेलगाड़ी से लाया जा रहा था । सभापति महोदय, मैं जोधपुर के बारे में बताऊं, समस्या के समाधान में....

श्री सभापति : एक मिनट, माननीय सदस्य । मेरा सभी सदस्यों से निवेदन है कि जिनको भी बोलना है कृपया 5-5 मिनट में अपने सुझाव दें तो सबको अवसर मिलेगा । इसके बाद मंत्री जी का जवाब और फिर साढ़े चार बजे मुलतवंद भी है इसलिए आप इस पर....मैंने किसी को 15-20 मिनट नहीं बुलाया । आप आरोप नहीं लगाएं । यहां एक–एक मिनट का हिसाब है । आपके सदस्य जिद करके खड़े रहते हैं तो उसका कोई उपाय नहीं है। मैंने किसी को अलाउ नहीं किया है । आप ऐसे सदन पर आरोप मत लगाइये ।

श्री हीरालाल बिश्नोई : उनका तो काम यूं ही हो रहा है ।

श्री सभापति : अब आप क्यों खड़े हो गये ? किससे पूछकर खड़े हो गये ? बिराजिये । आप पांच-पांच मिनट में अपने सुझाव दें । साढ़े तीन बजे मंत्री जी को जवाब देना है, साढ़े चार बजे मुलतवंद होगा।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : सभापति महोदय, मैं 5-10 मिनट से ज्यादा बोलती नहीं हूं, आप मुझे बोलने दीजिये ।

श्री सभापति : आप पांच मिनट में ही पूरा करिये ।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने इंदिरा गांधी लिफ्ट नहर का शोर बहुत किया परन्तु जहां वर्ष, 1990 तक 31 करोड़ रुपये खर्च हुए वहीं माननीय श्री भैरोंसिंह जी की सरकार के कार्यकाल में अप्रेल में अब तक 225 करोड़

(96)

(श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास)

रुपये खर्च किये गये एवं हिमालय का पानी जोधपुर पहुंचाया गया।

श्री सभापति : देखिये, बोलने दीजिये, माननीय सदस्या बोल रही हैं। आपको इंट्रप्ट उन्होंने नहीं किया था।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : न केवल यही बल्कि इस पानी को साफ करने....

श्री सभापति : विराजिये। माननीय विश्नोई जी, अब मुझे आपको ...

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : .... हेतु कायलाना पर 60 एम.एल.डी. लीटर क्षमता का फिल्टर हाउस भी स्थापित किया गया। इस पर 11 करोड़ रुपये खर्च हुए। जोधपुर शहर के लोगों को आज प्रति दिन 132 लाख गैलन कायलाना फिल्टर हाउस व 150 लाख गैलन चौपासनी फिल्टर हाउस, कुल मिलाकर 282 लाख गैलन पानी प्राप्त होता है। इसमें से 65 लाख गैलन जोधपुर विधान सभा क्षेत्र में उपलब्ध करवाया जा रहा है। इसी प्रकार पानी को साफ करने हेतु झालामंड में भी फिल्टर हाउस स्थापित हुआ और आज प्रति दिन 50 लाख गैलन उपलब्ध कराया जा रहा है। कांग्रेस राज्य के समय जोधपुर शहर विधान सभा क्षेत्र में 30-35 लाख गैलन पानी उपलब्ध होता था। शेखावत सरकार के भागीरथी प्रयास व माननीय जलदाय मंत्री जी के सहयोग व जोधपुर के तीन जन-प्रतिनिधियों के सहयोग से....

श्री सभापति : माननीय मंत्री जी।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : शायद इस वर्ष शहर को पेयजल समस्या से निजात दिलाने में सफल नहीं होंगे क्योंकि इन्द्र देवता इस बार पश्चिमी राजस्थान पर मेहरबान नहीं हैं। अतः इस बार फिर से जोधपुर शहर को पेयजल उपलब्ध कराने हेतु अथक प्रयासों एवं समुचित मात्रा में धनराशि उपलब्ध करवाने की आवश्यकता है।

श्री सभापति : अब आप सुझाव दें।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : हां मैं दे रही हूं। सभापति महोदय जोधपुर शहर में एक समय ऐसी स्थिति थी कि पानी के लिए घर-घर और बार-बार भटकना पड़ रहा था। भैरोंसिंह जी शेखावत की सरकार और भारतीय जनता पार्टी की सरकार और जलदाय मंत्री जी को मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूं कि आज जोधपुर शहर के अंदर पानी इतनी मात्रा में मिल रहा है। उससे कुछ कहा नहीं जा रहा है। उनको बधाई दूं जितनी भी, कम है। मैं ही नहीं बधाई दे रही हूं, जोधपुर की पूरी जनता इनकी जय-जयकार कर रही है और इनको बधाई दे रही है। मैं, माननीय सभापति महोदय—

श्रीमती कमला : उन मैम्बर को बोलने दीजिये जिनके यहां समस्या है। यहां तो आनंद-मंगल हो रहा है, जरूरत क्या है बोलने की।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : सभापति महोदय, मैं कुछ मेरे सुझाव देना चाहूंगी। कम दबाव वाले क्षेत्र मट्यों की पोल ...

श्री सभापति : आर्डर प्लीज। इंट्रप्ट नहीं करें।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : जैसे मट्यों की पोल, कविराज जी का बाड़ा, नई सड़क कन्दोई बाजार, मोती चौक, पोकरण की हवेली, मारुक चौक, सुसरखाना, गणेश मार्ग, नया बास, हनवन्त स्कूल व थलियों का बास इत्यादि। मान्यवर, उपरोक्त क्षेत्रों में पेयजल की समस्या का सुधार व उपलब्ध कराने हेतु कन्संवेन्सी की 8 इंची पाइप लाइन नया बास होते हुए चित्रा सिनेमा के पीछे तथा कन्दोई बाजार तक लगभग 1000 मीटर बिछाई जानी आवश्यक है। बाई जी महाराज आश्रम से आने वाली पाइप लाइन में दूरी अधिक होने से उचित पेयजल का दबाव नहीं रहता। परन्तु दोनों योजनाएं जो स्वीकृत हैं, उनमें कन्संवेन्सी की 8 इंची पाइप लाइन बिछाने हेतु प्रावधान नहीं लिया गया है। आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए दोनों योजनाओं की बचत राशि में यह कार्य प्रस्तावित किया जा सकता है जिससे समस्त कम दबाव वाले क्षेत्रों में पेयजल के दबाव में आशातीत वृद्धि होगी।

मान्यवर, अकाल की स्थिति से निपटने के लिए पूर्व में हैण्ड पम्प खुदवाने की व्यवस्था की गई थी। इसके अतिरिक्त पिछले वर्षों में 58 एयर लिफ्ट पम्प व टंकियां भी स्थापित की गई थीं। इन पुराने हैण्ड पम्पों को और भी गहरा करवाये जाने की आवश्यकता है क्योंकि पानी का स्तर और नीचे चला गया है।

इसी प्रकार शहर के प्राचीन जल स्रोत शहर के लोगों को पानी की सप्लाई का एक प्रमुख केन्द्र रहे हैं। परन्तु उचित रख-रखाव एवं जल स्तर के नीचे चले जाने से इन प्रमुख स्रोतों से भी पेयजल मिलना संभव नहीं हो पा रहा है।

मेरा माननीय जलदाय मंत्रीजी से निवेदन है कि हैण्डपम्पों को गहरा करने एवं प्राचीन जल-स्रोतों के जीर्णोद्धार के लिए भी उचित धनराशि की व्यवस्था कराई जाए। जोधपुर की जनसंख्या बढ़ रही है इसलिए जोधपुर लिफ्ट कैनाल का दूसरा चरण भी स्वीकृत किया जाए।

सभापति महोदया, मैं सिर्फ दो बात कहकर मेरी बात खतम कर दूंगी। जोधपुर शहर के अन्दर जलदाय मंत्रीजी के सहयोग से और मुख्य मंत्रीजी के आदेश से इतने एस. आर. बने जिनकी कोई तुलना नहीं की जा सकती, जैसे कि हनुमानजी की भाखरी, बाईजी का तालाब, जसवंतथड़ा, भीखा प्याऊ, पांच बत्ती, इन्दिरा कॉलोनी, जगह-जगह जोधपुर शहर में पानी उपलब्ध कराने के लिए इस तरह से व्यवस्था की गई, इसलिए मैं उनको बहुत-बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूं। कांग्रेस के कुछ लोगों ने एक अखबार में छापा कि यह योजना तो हमारी पहले की थी। आपकी योजना जरूर होगी मगर आपकी योजना बस्तों में बन्द थी, आपकी योजना बाहर नहीं आई। भैरोंसिंह शेखावत सरकार ने ये सारे काम किए। कुछ हमारे शहर की

(श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास)

महिलाएं पानी के ऊपर टाइलानी की तरफ जाती हैं तो वहां महादेवजी का मंदिर है, वहां दर्शन करने के लिए सावन के महीने में जाती हैं। तो आकर मुझे कहा, कम से कम 80-80 और 90-90 वर्ष के लोगों ने, कि ... (व्यवधान) ... माननीय सभापति महोदया, मैं ऐसे भी कब बोलती हूं, मुझे तीन मिनट ही हुए हैं।

श्री सभापति : तीन मिनट नहीं हुए हैं, मेरे पास सब हिसाब है। आप पूरा कीजिए।

श्रीमती सूर्यकांता व्यास : मैं मेरी बात पूरी कहूंगी, कहां हो गए छह मिनट ?

सभापति महोदया, उन्होंने यहां तक कहा कि या तो बनाई आप महाराज उम्मेदसिंहजी ने बनवाया या भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने और भैरोंसिंह शेखावत ने यहां पर यह फिल्टर हाउस बनाया। कुछ लोगों ने कहा कि यह पहले ही बन सकता था तो क्यों नहीं बनाया ? हमने आपको रोका थोड़े ही था। यह तो जमीन पहले से ही पड़ी थी, आपने क्यों नहीं काम करवाया ? बस्तों में बंद क्यों रखा ? शेखावत सरकार ने जोधपुर की पानी की समस्या को मद्दे नजर रखा। सभापति महोदया, मेरे शहर में कई जगह पानी की पाइप लाइन नहीं डाली गई है, उसके बारे में मैं विस्तार से बताना चाहूंगी।

श्री सभापति : माननीय सदस्या, लिखित में सुझाव दीजिए।

श्रीमती सूर्यकांता व्यास : मैं दो मिनट में अपनी बात पूरी कर दूंगी। दो मिनट और बोलूंगी।

श्री सभापति : दो मिनट नहीं, एक मिनट। मुझे बहुत लोगों को अवसर देना है, कम से कम 40 लोग बोलने वाले हैं।

श्रीमती सूर्यकांता व्यास : सभापति महोदया, उनको 15 मिनट तक बोलने दिया था। मेरे क्षेत्र में बकरा मण्डी से सिवांची गेट, बकरा मण्डी से निसार अहमद का मकान, सुभानन्द अगोची से बाणनाथ का मंदिर, बकरा मण्डी से बहुर की पोल, कुम्हारियां कुआं से कुम्हारों की ढाल, खाण्डा फलसा से हुसैन कालोनी, इतनी योजनाएं बाकी हैं।

श्री सभापति : यह सारा आप लिखित में मंत्रीजी को दीजिएगा, अब समाप्त करें।

श्रीमती सूर्यकांता व्यास : लिखित में दे दूंगी लेकिन मेरी बात तो बताने दो आप। आखिर हुसैन कालोनी से हुसैन कालोनी, मूलजी की होटल से पुंगलपाड़ा, कुम्हारिया कुआं से आडा बाजार, सिटी पुलिस, चित्रा सिनेमा से नया बास, ये लाइनें मेरे डालनी हैं, यह मैं आपको बता रही हूं-भजन चौकी से पूरा मोहल्ला, कबूतरों का चौक से पुरबियों की गली, मायावतों का चौक से कल्लों की गली, कटारिया का चौक से पीरों का कुआ, खाण्डा फलसा से मालियों की गली व शेखों का बास, जंक्शन पाइंट से रावतों का बास, पीपलिया महादेव मंदिर से फोफलिया की गली, जंक्शन पाइंट से धोबियों

(श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास)

की पोल, आलप मोहल्ला। माननीय सभापति महोदया, यह बताना तो पड़ेगा न। नाथावतों की गली, नव चौकिया से ईशरा वाली गली, लूंकड़ों की गली, गांधियों की गली व डोडीवारों का मोहल्ला, बोहरों की गली, मेड़ती गेट....।

श्री मोहनलाल मोदी (नीमकाथाना) : सभापति महोदया, बीच में बोलना पड़ेगा। आप पांच-पांच मिनट का समय दे रही हैं और यह सारा लिखकर, पढ़कर सुना रही हैं। यहां तो कोई कायदा ही नहीं।.... (व्यवधान)

श्री सभापति : ये कहां पढ़कर सुना रही हैं ? आप बिराजें, क्यों समय खराब करते हैं इनका ?

श्री मोहनलाल मोदी : हमको भी समय चाहिए, हमको भी बोलना है फिर।

श्री सभापति : आपको भी मिलेगा, आपके भी माननीय सदस्य पढ़कर सुना रहे थे।

श्री मोहनलाल मोदी : साढ़े चार बजे मुख बंद की बात आ जाएगी।

श्री सभापति : आप समापन करो जल्दी। (व्यवधान) ...।

श्री मोहनलाल मोदी : कोई तरीका तो होना चाहिए।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : किल्लीखाना सड़क से लायकान मोहल्ला, गोल बाड़ी से कम्मेद चौक, किल्ली खाना से पिपली गली, किल्ला रोड प्याऊ से किल्ला रोड, किल्ला रोड प्याऊ से गुमालनाथका मंदिर... (व्यवधान)....।

श्री सभापति : ऐसे आप इन्टरप्ट न करें। (व्यवधान).... देखिए आप, कितने मिनट हुए हैं, मुझे मालूम है और कौन सदस्य कितना बोलता है, यह भी मालूम है। कौन पढ़कर बोलता है, यह भी मालूम है। आप बैठिये,...(व्यवधान)...माननीय सदस्य, आप ऐसे इन्टरप्ट मत करिए। एक सदस्या बोल रही हैं, आपको उनको सपोर्ट करना चाहिए। पूरा करिए आप।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : सभापति महोदया, पाइप लाइन की वजह से सारा काम रुका हुआ है ... (व्यवधान)....

श्री सभापति : श्री हरिश्चन्द्रजी पल्लीवाल।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : सभापति महोदया, एक मिनट, मेरा निवेदन है आपके माध्यम से कि जोधपुर शहर में पानी जहां आ रहा है, वहां समय की पाबंदी करें। रात में कभी दो बजे तो कभी एक बजे पानी देते हैं, इस तरह से पानी न देकर, इसका समय पाबन्द करें। आपने मुझे समय दिया, धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री हरिश्चन्द्रजी पल्लीवाल।

श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल (गंगापुर) : सभापति महोदया, प्रत्येक जीव के लिए पानी की आवश्यकता होती है, प्रत्येक जीव के लिए पानी आवश्यक होता है। कोई भी

(श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल)

सरकार आए, उस सरकार का कर्तव्य होता है कि जिन क्षेत्रों में पानी की कमी है वहां उसकी पूर्ति करे। सभापति महोदय, मुझे तो कुछ ऐसा लगता है कि माननीय जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्रीजी बहुत सीधे-सादे हैं और इनके ऊपर इनका विभाग हावी हो गया है। या हो सकता है कि इनके विभाग वाले यह मानकर चलने लग गए हैं कि हमारे मंत्रीजी न तो हट्टे-कट्टे हैं, न मूछों वाले हैं, न मोटे हैं, जैसे और मंत्री हैं, इसलिए उनको डर भी इनका लगता नहीं है। खैर, यह तो इनकी सोच है। समय तो आप कम देंगी इसलिए मैं मेरे क्षेत्र के बारे में कुछ निवेदन, कुछ सुझाव देना चाहूंगा।

गंगापुर विधान सभा क्षेत्र का उत्तरी-पूर्वी हिस्सा अर्थात 40 गांव खारे पानी से ग्रसित हैं। मुझे याद है, सन् 1975-76 में मैंने एक रीजनल स्कीम बनवायी थी गांव पीलोदा में, जो छह गांवों को फीड करती थी। आठ-दस साल तक वह स्कीम चली किन्तु फिर पता नहीं किन कारणों से नहीं चली। कुछ तो जो ट्यूब वैल खोदे थे उनका जलस्तर नीचे चला गया, कुछ गांव वालों ने पाइप लाइन को क्षतिग्रस्त कर दिया। इस तरह वह स्कीम फेल होकर सिर्फ गांव पीलोदा के लिए रह गई। मैंने इसकी चर्चा इसलिए की है कि मंत्री महोदय जरा गौर से देखें। मैंने बहुत अच्छा धन्यवाद दिया था और आज भी धन्यवाद दूंगा। 1 करोड़ 81 लाख रुपये की बालपुर उदय की 12 गांव की योजना है। उनमें अधिकतर गांव ऐसे हैं जिनमें आज भी टैंकर से पानी ले जाया जाता है। 1 करोड़ 81 लाख की आपने स्कीम बनाई और 6 जनवरी, 1996 को प्रशासनिक स्वीकृति निकाली। विधान सभा में यह घोषणा कर दी कि इसकी स्वीकृति हो गई है, निर्माण कार्य भी चालू किया, आपने आदेश दे दिए, ट्यूब वैल भी खुद गए पांच गम्भीरी नदी पर। वे ट्यूब वैल आज की स्थिति में यूं के यूं हैं, अफसोस की बात है कि आपके विभाग ने ढाई साल के पीरियड में भी पाइप लाइन डालने का काम प्रारम्भ नहीं किया। वहां पर जी.एल.आर. बननी थी, न वह जी.एल.आर. का काम किया। अब बहाना क्या लेते हैं कि बिजली विभाग ने हमको परमीशन नहीं दी, बिजली विभाग ने हमको इतना बड़ा डिमाण्ड नोटिस जारी कर दिया जिसका भुगतान करने में हमें देरी हुई है, हम इसके बारे में सोच रहे हैं।

सभापति महोदय, क्या ट्यूब वैल बनाने में बिजली विभाग आड़े आ गया? जी.एल.आर. बनाने में बिजली विभाग आड़े आ गया? इसमें बिजली विभाग के अफसर आड़े आ रहे हैं, जिन्होंने एग्रीमेंट करके ठेका दे दिया। ठेकेदारों ने बिलो रेट पर ले लिया लेकिन उनको वर्क आर्डर नहीं है। अब उनको वर्क आर्डर क्यों नहीं दिया, यह तो उनका विषय है। मेरा तो आपसे इतना ही निवेदन है कि ढाई साल से आपकी घोषणा के इन्तजार में हमारे क्षेत्र के लोग बैठे हैं। मंत्री महोदय, हमारे यहां 12 गांवों की समस्या थी उसका समाधान हो जाएगा। आपकी 40 लाख रुपए की पाइपें रीको के गोदाम में सड़ रही हैं, गंगापुर के अंदर परचेज की है, वहां पड़ी हुई है लेकिन पाइप लाइन डालने का काम

(श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल)

आज तक प्रारंभ नहीं किया इसलिए मेहर-बानी करके जो 12 गांव योजना है, उसके लिए आप आदेश दीजिए। आप अपने अधिकारियों को आदेश दें कि इसका तुरन्त काम चालू करवाएं। खैर, अब तो बरसात हो गई तो पाइप लाइन खोदने का प्रश्न ही नहीं है। वह तो काली चिकनी मिट्टी का एरिया है, इसलिए वहां पाइप लाइन खोदने का तो प्रश्न ही नहीं उठता।

मैं ग्रामीण क्षेत्र के बारे में आपसे निवेदन कर रहा हूं। 1991-92 में जब आप स्वयं मंत्री थे तब गंगापुर क्षेत्र के विधायक जो आपकी पार्टी के थे, बैद्य गोविन्द सहाय, उन्होंने 1991-92 में खाली दौलतपुर की योजना स्वीकृत करायी थी। वह छह गांवों को पेयजल प्रदान करती, लेकिन आज तक वह योजना पूरी नहीं हुई। उसका एक कारण यह बना कि गांव वालों ने ट्यूब वैल खोदने नहीं दिए। उस पर यह डिसीजन लिया कि ओपन वैल बना दिया जाएं। ओपन वैल भी हमने 1996-97 में बना दिया। लेकिन आज तक जो ओपन वैल बन चुके हैं उनकी स्वीकृति आपके विभाग ने यहां से नहीं भेजी। फाइल आपके यहां हो पेण्डिंग पड़ी है, इसलिए मेहरबानी करके इसके लिए आप स्वीकृत करें।

तीन योजनाएं पनघट योजना की थीं, नौगांव, तलाबड़ा, वे भी स्वीकृति के लिए यहां भेजी हैं। विधायक अभिशंसा पर मैंने 2.50 लाख रुपये ट्यूब वैल के लिए ग्राम तलाबड़ा को दिए, ट्यूब वैल बनकर तैयार हो चुका है। ये भी 1997 में दिए थे, लेकिन आज तक खाली ट्यूब वैल दिख रहा है। बिजली का कनेक्शन भी हो गया, लेकिन वह किसी काम का नहीं है। ग्रामीण क्षेत्र के अन्दर की योजनाएं जिस तरह आपके यहां जयपुर में पड़ी हुई हैं, तलाबड़ा है, नौगांवा है, धोधुपुर बिदरका है. ये तीन पनघट योजनाएं यहां पड़ी हुई हैं, मेहरबानी करके आप इनकी स्वीकृति निकलवा दें जिससे वहां काम चालू हो जाए।

सभापति महोदया, मैं हैण्ड पम्पों के बारे में एक निवेदन और करना चाहूंगा। मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र में खूब हैण्ड पम्प लगे हैं। लेकिन मैंने स्वीकृति करायी है, मैं मेहनत करता हूं। मैंने पटवारी से ढाणियों के लिए लिखाया, जो आपने दिया है कि डेढ किलोमीटर की दूरी होनी चाहिए। मैंने खुद जाकर ढाणियों की लिस्ट बनायी है। पटवारी से लिखवाया, तहसीलदार से लिखवाया, एस. डी. ओ. से लिखवाया और लिखाने के बाद कलक्टर साहब से सिफारिश कराकर आपके विभाग को भेजी। अब भगवान जाने वह माधोपुर से आगे क्यों नहीं सरकी और सरक गई तो कोटा पहुंचते-पहुंचते क्यों आधी रह गई। आप इसकी भी जांच करा लीजिए। हम तो मेहनत करते हैं, क्योंकि आपने मुझे विश्वास दे रखा है कि आप योजना बनाएं, हम स्वीकृति देंगे। आप इसको भी दिखवा लीजिए।

मैं हैण्ड पम्पों की बात बता रहा था। ड्रिलिंग मशीन गंगापुर में खड़ी थी, यह मई, अप्रैल का महीना था लेकिन ड्रिलिंग

(102)

(श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल)

मशीन वालों को जिन–जिन पाइन्टों पर हैण्ड पम्प लगाने थे वहां पाइप नहीं थे, पाइपों की व्यवस्था नहीं थी। पाइप माधोपुर, हिण्डोन और करौली में पड़े हुए हैं। फरवरी के अन्दर महावीरजी का मेला लगा था, मेले के अंदर पाइप लाइन बिछायी थी। वह सारी पाइप लाइन वहां से दुबारा उखाड़ ले गए तथा उसको हिण्डोन के अंदर स्टोर कर दिया। हिण्डोन एक्स.ईएन. को एस.ई. आदेश देता है, एस.ई. को कलक्टर आदेश देता है, लेकिन न तो एस.ई.के और न कलक्टर के आदेशों की परवाह है। एम.एस. के.एस. के पाइप उनको सप्लाई नहीं किए। यह स्थिति बनी। यह तो मैंने अपने रूरल एरिया की बात बता दी।

(समय–समाप्ति–सूचक घण्टी)

माननीय सभापति महोदय, घण्टी बज गई है, अब मैं सिटी में आ रहा हूं। यानी घण्टी यहां बजी है और मैं सिटी में आ रहा हूं, सीटी बजा रहा हूं। मेरा निवेदन गंगापुर शहर के बारे में है। गंगापुर सिटी की जनसंख्या आज एक लाख के करीब हो गई है, वैसे 1991 की जनगणना के अनुसार तो 68 हजार है। आज गंगापुर के अंदर पानी की कमी नहीं है, 58 लाख लीटर पानी का डिस्चार्ज है। 58 लाख लीटर पानी का हमारे पास प्रोडक्शन है, लेकिन हमारे पास स्टोरेज कैपेसिटी नहीं है। माननीय मंत्री महोदय, मैं आपकी बात ही याद दिला रहा हूं, इसी सदन की बात आपको याद दिला रहा हूं। सन् 1996 में आपने मुझे सदन में विश्वास दिलाया था। मैंने कट मोशन भी दिया है और पिछली बार मैंने प्रश्न भी दिया था। आपने कहा था, विधायक महोदय, आपकी तीसरी टंकी बन जाएगी। आपने मुझसे पूछा कि कितने में बनेगी तो मैंने आपको बताया कि 15–20 लाख रुपये लगेंगे। आपने उस टंकी की घोषणा सदन में कर दी, लेकिन, माफ करना, आज तक वह टंकी नहीं बनी। आप स्वायत्त शासन मंत्री भी हैं, आप मालूम कर लेना। आपके अधिकारियों ने बहाना क्या किया कि हमने आठ करोड़ रुपये की एक पुनर्गठन की योजना राजस्थान सरकार को भेजी, उसमें तीसरी टंकी का प्रावधान किया है। सन् 2011 की जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए एक आठ करोड़ की स्कीम आपके यहां भेजी हुई है। वह न जाने कब मंजूर होगी। आप स्वायत्त शासन मंत्री भी हैं, गंगापुर नगरपालिका में कुछ गांवों को तो आपने गंगापुर में सम्मिलित कर लिया, लेकिन उनको रूरल से जो फायदा हो रहा था वह क्या अरबन से हो रहा है? वहां आज की तारीख में पाइप लाइन नहीं है। वहां बुद्धिजीवी निवास करते हैं, कर्मचारी कालोनी में बुद्धिजीवी निवास करते हैं, सैनिक कालोनी है, ग्राम मिर्जापुर सालोद के सारे वार्ड आपने गंगापुर में मिला दिए और आज की तारीख में पाइप लाइन नहीं है।

माननीय सभापति महोदया, मैं सिर्फ एक मिनट और लूंगा। मैं दो सुझाव देना चाहता हूं। मेरा पहला सुझाव तो यह है कि आपने योजनाएं बना दीं, योजनाएं पास कर दीं, टंकी का निर्माण हो गया,

(श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल)

लेकिन उन पर कर्मचारियों की कोई व्यवस्था नहीं है। आपने एक फार्म भरवाना चालू कर दिया है कि ग्राम पंचायत यह लिखकर दे कि इस योजना को हम चला लेंगे। गांव वालों ने लिखकर दे दिया, योजना चालू हो गई। हर चौथे-पांचवे दिन मोटर फुंक रही है; क्योंकि वे तो अनाड़ी हैं, उनकी रोज मोटर जल रही है। गांव वालों को दो-दो, पांच-पांच रुपये की हर घर से भीख मांगनी पड़ रही है तब जाकर वह योजना चल रही है। आपने जो विभाग के अंदर यह पाबन्दी लगा रखी है कि कर्मचारियों की नियुक्ति नहीं की जाएगी, मेहरबानी करके आप इस पाबन्दी को हटा लीजिए। आपने यह पाबन्दी लगा रखी है..

श्री सभापति : इसे पूरा करें, रिपीट नहीं। श्री जोगेश्वर गर्ग।

श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल : सभापति महोदय, मेरा तो मंत्री महोदय से यही कहना है ...

श्री भंवरलाल शर्मा (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री) : यह जो माननीय सदस्य ने कहा कि पिछली बार एक टंकी के निर्माण की बात आपने कही थी और मैंने यह आश्वासन दिया था कि बनेगी। मुझे भी याद आता है, मैंने विधान सभा में आपसे कहा था कि मैं आपकी टंकी बनवा दूंगा। लेकिन जो दूसरी योजना बनी वह आठ करोड़ की है, यह बात सही है और उसी में उन्होंने इसका प्रोविजन ले लिया है, इसलिए वे विचार कर रहे हैं। जब तक वह योजना मंजूर नहीं हो तब तक टंकी नहीं बननी चाहिए और न बन सकती है। यह मैंने अभी बात की है।

मैं आपको यही कह सकता हूं कि जो मैंने घोषणा की है, आठ करोड़ की योजना में इसको अलग निकालकर पहले इसको बनाएंगे।

श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल : मंत्री महोदय, मैं तो यह कहता हूं कि आपके विभाग में सिर्फ दो ही हैं जो तत्परता से स्वीकृति भी देते हैं और कार्य भी करवाते हैं, या तो आप हो या आपके शासन सचिव हैं। उनके पास हम कोई भी खबर भेजते हैं, चाहे टेलीफोन पर बात करते हैं या फैक्स भेजते हैं तो इमिजिएटली एक्शन होता है। मैं तो आप दोनों को धन्यवाद देता हूं। साथ में आपके विभाग वाले हैं उनको भी भगवान सद्बुद्धि दे, कि जैसे आप हैं वैसे ही वे भी तत्परता से काम करें, तब तो राजस्थान की पेयजल की जो समस्या है उसका निवारण होगा। आपने मुझे समय दिया उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालोर) : माननीय सभापति महोदया, सदन के सामने आज की चर्चा का विषय है जल। विद्वानों ने कहा है जल ही जीवन है। जल की उपलब्धि के आधार पर कई सभ्यताएं बसीं और जल समाप्त होने पर सभ्यताएं समाप्त हो गईं। जल उपलब्ध करवाना, जैसा कि किशनपोल से आने वाले माननीय विधायक

(श्री जोगेश्वर गर्ग)

कह रहे थे हर लोकप्रिय सरकार का दायित्व होता है । राजस्थान में जैसी भौगोलिक परिस्थितियां हैं और जलवायु की दृष्टि से जो परिस्थितियां हैं, उनमें जितना कुछ किया जा सकता है सरकार करने का प्रयास कर रही है । सरकार की नीयत कितनी साफ है और सरकार कितनी तत्पर है काम करने को, इसका एक उदाहरण पेश किया अभी-अभी गंगापुर से आने वाले माननीय विधायक ने । 15 लाख की एक टंकी मांग रहे थे और सरकार ने 8 करोड़ की योजना दे दी । अब फिर भी आलोचना करें तो उसका कोई इलाज नहीं ।

श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल : मैंने आलोचना नहीं की ।

श्री जोगेश्वर गर्ग : नहीं की न आलोचना ? धन्यवाद ।

श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल : मैंने तो वस्तुस्थिति से अवगत कराया है ।

श्री जोगेश्वर गर्ग : धन्यवाद । मुझे लगा कि आप आलोचना कर रहे हैं । ठीक वही हाल जालौर जिले का है । पिछले पांच वर्षों में, मैं 8 वर्ष का हिसाब नहीं कर रहा हूं, सिर्फ एक टेन्योर का भी हिसाब करें तो अकेले जालौर जिले की धरती पर जलदाय विभाग की योजनाओं के लिए अलग-अलग मदों में कम से कम 30 से 35 करोड़ रुपया खर्च हो चुका । अभी शायद सांचोर से आने वाले माननीय विधायक हमारे बीच में उपस्थित नहीं हैं, वे आलोचना कर रहे थे कि सांचोर में 8 साल में कुछ नहीं हुआ । सांचोर के नहड़ क्षेत्र में पीने के पानी की भीषण समस्या है, इससे कोई इन्कार नहीं करता । वहां पानी है नहीं, जहां है वह खारा है । यह स्थिति प्राकृतिक रूप से है, कोई इन आठ सालों में नहीं बनी, वह स्थिति तो दशकों से है । दशकों से उस स्थिति को आप लोग भी और हम लोग भी देखते रहे हैं । अब इतने साल तक उस समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ, उस समस्या की तरफ किसी ने ध्यान तक नहीं दिया, उसकी आलोचना नहीं और इन 8 सालों में भारतीय जनता पार्टी के राज में कुछ नहीं हुआ या कुछ हुआ तो कम हुआ, उसकी आलोचना हो रही है । उन 40 सालों का हिसाब कौन करेगा ? नहड़ क्षेत्र में तो पहले भी वैसा ही था, समस्या वही थी, पानी भी खारा था, पानी है नहीं, यह भी समस्या थी पर उसकी तरफ अब तक कोई ध्यान नहीं दिया । उसके बारे में कोई चर्चा नहीं और अब इन आठ सालों में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, केवल उसकी आलोचना करेंगे तो कोई इलाज नहीं ।

माननीय सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से इस सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि केवल इस साल, अकेले 1998 के वर्ष में सांचोर तहसील के लिए, अकेले सांचोर विधान सभा क्षेत्र के लिए कम से कम 7 करोड़ रुपया खर्च करने की योजनाएं सरकार स्वीकार कर चुकी है । इस

(श्री जोगेश्वर गर्ग)

एक वर्ष में माननीय मंत्रीजी स्वयं दो बार जाकर आये थे। एक बार तो मुझे मालूम है, अचानक गये। हमको भी नहीं मालूम था, अधिकारियों को उनके सांचोर पहुंचने के बाद पता चला कि माननीय मंत्री महोदय पधारे हैं। सिवाय सांचोर के विधायक के और किसी को मालूम नहीं था कि मंत्री महोदय आ रहे हैं। अचानक जाकर देखा, सारी परिस्थितियों को देखा, माननीय विधायक जो शिकायतें करते रहते हैं उनकी खुद जाकर जांच की और उसके बाद उनको जो कुछ करना चाहिए था उन्होंने किया। अब मंत्रीजी के पास जादू का डंडा तो है नहीं कि गये, डंडा घुमाया और छू-मंतर जमीन में से पानी बाहर आ गया। मंत्रीजी ने आकर अपने अधिकारियों से चर्चा की होगी। अधिकारियों ने योजनाएं बनायीं, योजनाएं स्वीकृत हुई हैं इतनी लम्बी चौड़ी योजनाएं। कोई 10-20 लाख की योजना हो तो उसमें भी समय लग जाता है तो 7–7 करोड़ रुपये खर्च करने में, उसके लिए निर्माण कार्य करने में, उसके लिए पाइप लाइन खरीदने में, बिछाने में जो समय लगना है वह स्वाभाविक है। उसको कितना कम किया जा सकता है? कम से कम करने का प्रयास हो सकता है पर जो लगना है वह तो लगना है। आप ताबड़तोड़, रातों-रात पानी चाहें तो उसका कोई इलाज नहीं। 40 साल में आप लोग नहीं ला पाये और हमसे आप 40 दिन में उम्मीद करेंगे तो, माननीय सभापति महोदया, यह अन्याय होगा।

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि ये सब बातें तो इस सदन में चर्चा का विषय बन रही है, हमेशा बनती रही हैं और आगे भी बनती रहेंगी। समस्याएं पैदा होंगी, समस्याओं के समाधान की योजनाएं बनेंगी, योजनाएं लागू होंगी। उसके बाद जिस तरह से वर्षा में कमी आ रही है और जनसंख्या बढ़ रही है, इन दोनों स्थितियों को देखते हुए (समय–समाप्ति–सूचक घंटी) और नयी पैदा होती रहेंगी और उनके समाधान के प्रयास किये जाएंगे।

माननीय सभापति महोदया, मैं सबसे महत्वपूर्ण एक बात की तरफ विभाग का, सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं और हम भविष्य की सोचेंगे तो वह काम करना बहुत आवश्यक है लेकिन मुझे लगता है कि उस काम की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है। माननीय सभापति महोदया, जल से जुड़े हुए तीन विभाग हैं। सिंचाई विभाग जमीन के ऊपर जो पानी है उसको इकट्ठा करना और उसका उपयोग, यहां तक सीमित है। भू-जल विभाग, जमीन में कितना पानी है उसका पता लगाओ और फिर उसको कैसे निकाला जाए, कहां निकाला जाए, कहां से कितना निकाला जाए, उसकी व्यवस्था तक है। और जलदाय विभाग, पानी भूतल में है या जमीन के अन्दर है, उस पानी को जनता तक पीने के लिए उपलब्ध कराना। लेकिन इस जमीन के अन्दर पानी पहुंचे इसकी चिन्ता करने वाला कोई विभाग नहीं है, इसकी चिन्ता करने वाला कोई व्यक्ति नहीं, इसकी चिन्ता करने वाला कोई आफिसर नहीं, इसकी चिन्ता करने वाला कोई मंत्री नहीं। वह चिन्ता यदि हम नहीं करेंगे तो जिस गति से हम इस धरती के पेट में

(श्री जोगेश्वर गर्ग)

से पानी को निकाल रहे हैं उससे कितने दिन पानी बचेगा अन्दर ? यह धरती सूखी हो जाएगी। ऊपर से सूखी हो रही है, अन्दर से सूखी हो जाएगी, और वर्षा का स्तर जिस गति से गिर रहा है उसको देखते हुए और अधिक समस्याएं आ जाएंगी। आज सांचोर का नहड़ क्षेत्र परेशान है, कल पूरा जालोर जिला परेशान होने वाला है और उसी गति से पूरा राजस्थान परेशान होने वाला है। मैं अपने योग्य, काबिल, अनुभवी अभियंताओं की जो लम्बी-चौड़ी फौज इन तीनों विभागों में है उन पर कोई आरोप नहीं लगाते हुए यह कहना चाहूंगा कि उन्होंने दूरदर्शिता से काम नहीं लिया है अब तक। एक कार्य पर अपनी नजर जमाकर उस काम को पूरा करने के लिए उन्होंने पूरी ताकत लगा दी, पर उस काम के दायें-बायें असर क्या होने वाला है, साइड इफैक्ट क्या होने वाले हैं उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। जवाई बांध बना लिया, इतना बड़ा बना लिया, उसका जितना उपयोग हो रहा है उतना हो रहा है, पर उसके कारण जो पूरा जालोर जिला सूखा होने जा रहा है उसकी कल्पना जवाई बांध बनाते समय उन इंजीनियर्स को हो जानी चाहिए थी, पर नहीं की गयी। मैं जवाई बांध बनाने वाले उस इंजीनियर से मिला हूं।

(14.57 बजे)

(श्री रमाकांत शर्मा, समापति, पीठासीन)

उससे पूछा कि आपने क्या सोचा था ? जवाई बांध का असर क्या हुआ ? उन्होंने कहा कि हमने सोचा कि इतना सारा पानी इकट्ठा होगा तो सहज आगे निकल जाएगा। माननीय सभापति महोदय, जवाई बांध की हालत यह है कि दो तरफ तो पहाड़ियां हैं और बीच में छोटा-सा स्थान जहां बांध बना है। जहां कठोर चट्टान आ गयी वहां से उस बांध को चूने से बनाया है। एक बूंद पानी उसमें से आगे नहीं जा सकता, सहज कहां से निकलेगा ? डाउन स्ट्रीम में एक बूंद भी जाने की व्यवस्था आपने नहीं छोड़ी और उस बांध को इतना ऊंचा बना लिया कि उसमें कितनी भारी से भारी बरसात हो जाए तो भी उसमें से पानी निकलना मुश्किल हो जाए। 45 फीट से पहले तो कोई गेट नहीं, फिर 15 फीट का गेट बनाया और अब उसको दो फीट और बढ़ा दिया। अति भारी वर्षा हो तो आकर कभी गलती से पानी निकले 10 साल में एक बार। उस स्थिति में डाउन स्ट्रीम में जो गांव आ गये, जो क्षेत्र आ गया, उसका री-चार्जिंग कैसे होगा इसकी बिलकुल कल्पना नहीं की अभियंताओं ने और उसका दुष्परिणाम जालौर भुगतने जा रहा है। आज उस जालौर जिले में जवाई नदी के किनारे-किनारे कम से कम 150 ट्यूब वैल बने हुए हैं, वे सूख रहे हैं। हर साल 15-20 नये बन जाते हैं, पर साल भर में वे सूख जाते हैं। फिर नये बनते हैं, फिर नया बजट, फिर नया पैसा, फिर नये ट्यूब वैल और फिर सूखना, यह क्रम चलता रहता है। अगर हम डिपोजिट नहीं करेंगे तो किसी भी अरबपति, करोड़पति या मल्टी-मिलियनेयर, को भी नाम आप चाहें, अधिक

(श्री जोगेश्वर गर्ग)

से अधिक पैसे वाले व्यक्ति के खाते में से पैसा लगातार निकलता–निकलता रहे, खाते में पैसा आए नहीं तो कितने दिन चलेगा ? वही हालत हमारे जालोर जिले की हो रही है। यही हालत यदि रही तो आने वाले 5–7 साल के अन्दर–अन्दर जालोर जिला सूख जाएगा, जालोर के लोग पानी के अभाव में वहां से पलायन करेंगे। पीने का पानी नहीं होगा, खेती का पानी नहीं होगा तो खाएंगे क्या और पिएंगे क्या ? यह नौबत आने वाली है। इसलिए मैं तो यह कहना चाहूंगा कि आज की तारीख में जालोर की आवश्यकता है कि उस जवाई बांध को तोड़ा जाए। माननीय सदस्य बांध बनने की बात करते होंगे पर धारा के विपरीत चलकर कहना चाहता हूं कि उस बांध को तोड़ा जाएगा तो ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि जालोर जिला रेतीला जिला है, रेत में पानी को संग्रहित करके रखने की ज्यादा क्षमता होती है। आज जितना बड़ा जवाई बांध है, ऐसे-ऐसे 10 जवाई बांध समा जाएं इतनी स्टोरिंग कैपेसिटी जालोर की रेत में है। 70 मीटर से लेकर 400 मीटर तक की गहराई तक कोई चट्टान नहीं है, सब रेत ही रेत है। वह पानी यदि जमीन में स्टोर करेंगे तो इवेपोरेट नहीं होगा धूप के कारण से, सूरज की इतनी तेज गर्मी के कारण से जो पानी उड़ जाता है वह नहीं उड़ेगा। बाहर सरफेस पर पड़ा पानी दूषित हो जाता है, अन्दर पड़ा पानी दूषित नहीं होगा, फिल्टर नहीं करना पड़ेगा। जब जहां चाहो ट्यूब वैल खोदा, मोटर लगाकर पानी निकाला और पिलाया यदि जमीन के अन्दर पानी होगा तो।

(15.00 बजे)

आज सरफेस पर पानी इकट्ठा करके रख रहे हैं जिससे कुछ 100 बीघा जमीन सिंचित होती होगी और कुछ 100 गांव पानी पी रहे हैं। उससे सवाये गांव पानी पी सकते हैं यदि जालोर जिले में इस नदी में पानी स्वतंत्र रूप से बहने दिया जाए मेरा यह दावा है। अब तक 8–9 साल में इस जवाई बांध को लेकर जालोर में जो कुछ समस्या हुई उसका अध्ययन करने का मैंने प्रयास किया है। कई इंजीनियर्स से मैंने राय ली है, कई एक्सपर्ट्स से मैंने राय ली है। इन सबके बाद जो मेरा मत बना, वह यह है कि जवाई बांध होते हुए जितना फायदा दे रहा है उससे कई गुना फायदा जवाई बांध नहीं होगा तो जनता को मिलेगा क्षेत्र में खेती की दृष्टि से, पर्यावरण की दृष्टि से और पीने के पानी की दृष्टि से। माननीय सभापति महोदय, पूर्व में यह बात मैं भी बोला हूं, उस क्षेत्र से आने वाले दूसरे माननीय सदस्य भी बोले हैं, सिरोही से आने वाली माननीया तारा जी भण्डारी भी बोली हैं, जालोर से आने वाले भगराज चौधरी भी बोलते रहे हैं और भी कई लोग बोलते रहे हैं। मैं जोर देकर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जवाई बांध जालोर जिले के लिए समस्या की जड़ है। समस्या का समाधान करने का प्रयास कर रहे हैं, उससे ज्यादा जरूरी है समस्या की जड़, बीमारी की जड़ को

(श्री जोगेश्वर गर्ग)

मिटाना। चोर को मारने की बजाय चोर की मां को मारो जो चोर को पैदा करती है, इस समस्या को पैदा करने वाला है जवाई बांध, उसको तोड़िये या उसको खोलिये, कुछ न कुछ ऐसी व्यवस्था करिये कि रि-चार्जिंग बने, जमीन में पानी डिपोजिट हो। जमीन में पानी नीचे उतरे तो खुश-हाली आएगी, हरियाली आएगी, पीने का पानी उपलब्ध रहेगा, खेती के लिए पानी उपलब्ध रहेगा, खाने को अन्न, फल और सब्जी हर तरह की चीजें उपलब्ध रहेंगी, अन्यथा जालोर जिले का भविष्य आज की तारीख में हमें अंधकारमय नजर आ रहा है। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता में जब सिंधु नदी ने अपना बहाव मोड़ लिया तो सभ्यता उजड़ गई, वैसे जालोर जिला उजड़ने वाला है आने वाले 5–7 साल के अन्दर-अन्दर। यदि यह संकट का समाधान अभी नहीं हुआ, अभी से हमने दूरदर्शितापूर्ण निर्णय नहीं किये और बोल्ड डिसीजन, कठोर डिसीजन, ठोस डिसीजन यदि हमने अभी से नहीं किये तो यह समस्या और गम्भीर होने वाली है। इसकी तरफ जिस दिन मैं पहली बार, विधायक बनकर आया था 1990 मार्च में, तब से लेकर इस सदन के माध्यम से निवेदन करता आ रहा हूं। बहुत कुछ ध्यान आकर्षित हुआ है इस तरफ, सरकार ने माना है कि इसके कारण से समस्याएं पैदा हुई हैं। माननीय मुख्य मंत्रीजी गये साल जालोर पधारे थे उस समय उन्होंने पब्लिक के सामने स्वीकार किया था कि जवाई बांध के कारण समस्याएं पैदा हुई हैं और उसके समाधान के लिए सरकार कुछ सोच रही है। मैं समझता हूं, काफी कुछ सरकार ने अब तक सोच लिया होगा और सोच का अंतिम निर्णय यही निकला होगा कि जवाई बांध का पानी जवाई नदी में छोड़ा जाए। यह इस साल से लागू होना चाहिए था पर दुर्भाग्य से इस साल बरसात नहीं हुई और जवाई बांध में 45 फुट पानी नहीं आए तो छोड़ नहीं सकते। अभी तो 45 फुट से आधा पानी नहीं आया मुश्किल से इसलिए इस बार तो नहीं छोड़ सकते। नहीं छोड़ सकते, कोई बात नहीं पर छोड़ने की योजना हो जाए, कैसे छोड़ना है, कब छोड़ना है, कितना छोड़ना है, यह तय हो जाए तो आने वाले समय में जब भी कभी उसमें पानी होगा वह योजना लागू हो सकेगी। अब तक जो चिन्तन सरकार ने किया है, अब तक जिन निष्कर्षों पर सरकार पहुंची है उस निष्कर्ष को आदेश के रूप में कहीं कुछ ठोस रूप दे दें तो भविष्य में जो भी अफसर बाद में इस विभाग में आएंगे या और किसी के पास यह विभाग जाएगा तब वे लोग इसके बारे में ठोस कार्य कर सकेंगे। आपके माध्यम से मैं यही निवेदन करना चाहता था, आपने पर्याप्त समय दिया, उसके लिए मैं आपका आभारी हूं। धन्यवाद।

श्री सभापति : माननीय श्री भगराज चौधरी।

श्री भगराज चौधरी (आहोर) : सभापति महोदय, आज बहुत ही महत्वपूर्ण मामले पर सदन में चर्चा हो रही है। वैसे

(श्री ममराज चौधरी)

तो पेयजल के दृष्टिकोण से राजस्थान, विशेषकर पश्चिमी राजस्थान में समस्या बहुत पुरानी है। सन 1952 में सरकार बनने के बाद इस समस्या के समाधान के लिए निरंतर प्रयास किये जाते रहे और उनका कुछ लाभ भी मिला, कुछ हद तक कुछ क्षेत्र में इस समस्या का समाधान भी हुआ। जैसा कि गर्ग साहब ने कहा, सरकार बनने के पहले रियासती काल में भयंकर समस्या थी, न ट्यूबवैल थे, न इतने कुंए ही थे। जो कुंए थे वे बहुत ज्यादा गहरे नहीं थे, इसलिए भूमिगत जल का स्तर बहुत नीचे होने के कारण से समस्या ज्यादा थी। सरकार बनने के बाद में इन्होंने प्रयत्न तो किया, फिर भी अभी तक समस्या बराबर बनी हुई है, इसका क्या कारण है? हमने करोड़ों रुपये खर्च किये और करते जा रहे हैं, मगर समस्या की गम्भीरता के बारे में, उसके कारणों के बारे में, उसके निवारण के बारे में सही दृष्टिकोण अपनाकर हमने गम्भीरता से विचार नहीं किया। हमारे इंजीनियर्स योजना बनाते रहते हैं कि कहाँ पर ट्यूब वैल बनना चाहिए, क्षेत्रीय योजना कितनी बड़ी बननी चाहिए, लेकिन इन सारी बातों में मैं समझता हूं कि स्थानीय समस्या के बारे में सब लोगों को साथ लेकर, विशेषकर जन-प्रतिनिधि इस सदन में वहां के माननीय सदस्यों की राय लेकर क्योंकि उन्हें क्षेत्र की ज्यादा जानकारी होती है, उनकी सहायता में ट्यूब वैल का निर्माण होना चाहिए। उस सन्दर्भ में मैं थोड़ा-सा निवेदन करना चाहूंगा कि मुख्य तौर पर समस्या दो प्रकार की है। एक समस्या तो यह है कि जो व्यवस्था पहले से चालू है, उस व्यवस्था का रख-रखाव और संचालन सुचारू रूप से नहीं हो पाता है। संचालन कर नहीं पाते, कर नहीं पा रहे हैं। इसके कारण से जहाँ कुछ गांवों में आलरेडी जल समस्या बनी हुई है, वहां दूसरे ऐसे गांव हैं जहां पर अभी तक पेयजल की समस्या के कारण से पानी पहुंचा नहीं है। यह दो प्रकार की समस्या है। पेयजल योजनाओं के माध्यम से हमने पेयजल आपूर्ति की व्यवस्था कर रखी है, मगर उन योजनाओं से जुड़े हुए गांवों में भी आज समस्या क्यों है, इसके क्या कारण है? इसका मुख्य कारण तो यह है जैसा मैंने कहा, कि समस्या के समाधान के लिए पेयजल की व्यवस्था करने के बावजूद भी नीचे के स्तर पर समस्या को चालू रखने के लिए, उसका संचालन करने के लिए हमारी पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। स्टाफ तो लगा हुआ है मगर स्टाफ में ढिलाई बहुत ज्यादा है। एक्स. ईएन. स्तर के अधिकारी तो काम करते हैं मगर उसके नीचे के जो अधिकारी हैं, मैं समझता हूं, एक्स. ईएन. के स्तर पर एडमिनिस्ट्रेटिव क्षमता कम होने के कारण वह नीचे के अधिकारी से काम नहीं ले पाता है। मगर उस पेयजल व्यवस्था का सुचारू रूप से संचालन किया जाए तो मैं समझता हूं कि वे गांव जो उनसे जुड़े हुए हैं वहां पर इतनी समस्या नहीं होगी जितनी कि आज है। ऐसी कई पेयजल योजनाएं भी हैं जहां पर स्रोत छोटे पड़ रहे हैं, पानी नीचे चला गया, आबादी बढ़ गई, पाइप

(श्री मगराज चौधरी)

लाइन छोटी पड़ रही है। ऐसी समस्याओं में हमें शीघ्र अतिरिक्त स्रोत बनाकर, अतिरिक्त पाइप लाइन बिछाने की व्यवस्था करके उनका समाधान करना चाहिए।

इसके अलावा चालू योजनाओं के ठीक ढंग से संचालन करने के बारे में कुछ सुझाव देना चाहूंगा। उनमें मुख्य तौर से हमारी नीचे की मशीनरी, खासकर ए.ईएन. और जे. ईएन. वे अगर सक्रिय रहते हैं, उनसे अगर हम काम ले पाते हैं तो मेरे ख्याल से हमें समस्याओं का समाधान करने में राहत मिलेगी। जे. ईएन. के सर्किल में जो गांव होते हैं, कम से कम जो समस्याग्रस्त गांव हैं, हफ्ते में एक बार जे. ईएन. को वहां जाना ही चाहिए। मगर मैंने देखा, मेरा क्षेत्र बहुत समस्याग्रस्त गांव है, महीना-महीना भर जे. ईएन जाते ही नहीं उन गांवों में। तो कम से कम हफ्ते में समस्याग्रस्त गांव में भी वह जाए, यह आप लाजिमी तौर से प्रबन्ध करें। साथ ही ए. ईएन. भी कम से कम अपने सर्किल में एक फोर्टनाइट....

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

सभापति महोदय, ये क्या कर रहे हैं ? मैं तो....

श्री सभापति : समय नहीं है, माननीय सदस्य। 15-20 मिनट बाकी हैं।

श्री मगराज चौधरी : I would not take much point. I am only just giving the points.

श्री सभापति : कम से कम 30 माननीय सदस्य बचे हैं, 10 मिनट नहीं है समय।

श्री मगराज चौधरी : I am just giving the points.

श्री सभापति : पांच मिनट में समाप्त कीजिये आप।

श्री मगराज चौधरी : फिर तो आप बहस ही मत कराइये।

श्री सभापति : समय नहीं है।

श्री मगराज चौधरी : आप ऐसे ही बातें फरमा दिया करें।

श्री सभापति : समय नहीं है, मैं क्या करूं।

श्री मगराज चौधरी : साल भर में एक बार तो समय मिलता है और समस्याग्रस्त ग्राम इतने हैं कि....

श्री सभापति : परन्तु आज मुश्किल है। सुझाव दे दीजिए फटाफट।

श्री मगराज चौधरी : I am not making a broad speech. I am only giving points.

श्री सभापति : भूमिका नहीं, अपने सुझाव दीजिए फटाफट।

श्री मगराज चौधरी : I am only giving points. मैं सुझाव दे रहा हूं।

श्री सभापति : टेलीग्राफिक लैंग्वेज में सुझाव दीजिये आप फटाफट।

श्री मगराज चौधरी : अजीब बात कर रहे हैं, लोग मर रहे हैं और आज यह हमको हक मिला। हम सुझाव दे रहे हैं। सुझाव देने के लिए हम खड़े हुए हैं।

श्री सभापति : आप इतनी देर में तो अपनी बात समाप्त कर देते जितनी देर से बात बोल रहे हैं जल्दी खतम कीजिये।

श्री मगराज चौधरी : मैं तो कह रहा था कि जे. ईएन. अपने क्षेत्र में जाए हर हफ्ते के अन्दर। दूसरा, ए.ईएन भी कम से कम फोर्टनाइट में एक बार जाए, यह व्यवस्था पुख्ता तौर पर करें ताकि उन योजनाओं का बराबर संचालन हो। दूसरा, जो अफसर लापरवाह हैं, जो फील्ड स्टाफ आपका लापरवाह है जे. ईएन. से नीचे का, जो वहां ठहरता नहीं, काम नहीं करता, मेहरबानी करके उनसे काम लेने के लिए उनका तबादला करने का भी आप थोड़ा दिमाग बनाइये। कई बार हमने बात की है कि लाइनमैन वहां ठहरता नहीं है, फिटर वहाँ ठहरता नहीं, टूट-फूट ठीक करता नहीं, मगर जब स्टाफ को तबादला करने की बात करते हैं तो उनके जैसे कोई छाती पर सांप सूंघ गया हो, वैसी स्थिति हो जाती है कि साहब यह तो नहीं कर सकते। आप में इतनी भी क्षमता नहीं है? प्रशासनिक दृष्टिकोण से उनसे अगर आप काम नहीं ले पाते हैं तो उनका तबादला दूर कर दें, ताकि दूसरा कोई स्टाफ आए वह ठीक रहे।

दूसरा, कई पम्पसैट्स आपके स्टाफ की लापरवाही से जल जाते हैं, तो आप कम से कम स्टाफ की अकाउंटेबिलिटी तय करिये। मेरे क्षेत्र में एक साल में कम से कम चार सौ, पांच सौ पम्पसैट्स बिलकुल जल गये। लाखों रुपये का उन्होंने पम्पसैट्स की रिपेयरिंग करने वालों से मिलावट करके घपला कर लिया। क्यों नहीं आप अकाउंटेबिलिटी तय करते हैं कि ये इतने पम्पसैट आपके क्यों जल रहे हैं? यह तो आप व्यवस्था कर ही सकते हैं, कोई न कोई तो मानदंड होना ही चाहिए इसका। एक जे. ईएन. के क्षेत्र में महीने में कितने पम्पसैट जले, तो क्षमा कर सकते हैं, तो हम ए. ईएन. को क्षमा कर सकते हैं। वरना वो वे जानबूझकर जलाते हैं और मिलावट करके रिपेयरिंग के नाम पर पैसा बटोरते हैं।

इसके अलावा हैण्ड पम्प्स की समस्याओं के बारे में आप ध्यान करें मेहरबानी करके हैण्ड पम्प्स पर जब आपने लाखों-करोड़ों रुपये खर्च किये हैं तो उनकी रिपेयरिंग के लिए भी पुख्ता व्यवस्था करिये। समिति स्तर पर नहीं, आपके विभाग के अन्दर खंड स्तर पर, उपखंड स्तर पर आप स्टाफ दीजिये और छोटी-मोटी एक्सेसरीज भी दीजिए जिससे कि छोटी-मोटी रिपेयरिंग होती रहे। चालू जल योजनाओं में जहां एक-एक, दो-दो गांव, तीन-तीन गांव भी हैं, जनता जल योजना की जो आपने स्कीम बनाई है बहुत अच्छी स्कीम है। उसमें अगर कुछ गांव जुड़ सकते हैं और कुछ गांव उस योजना के तहत लाभ उठा सकते

(श्री मगराज चौधरी)

हैं, आने को तैयार हैं तो आपको अधिक से अधिक अपने गांवों को जनता जल योजना में देने का दिमाग बनाना चाहिए। मगर उसमें दिक्कत एक आ रही है, केवल मात्र पांच सौ रुपये महीने का रेमुनरेशन देकर एक आदमी को आप बांधे रखना चाहते हैं, कैसे सम्भव है ? आज मजदूरी की दर 44 रुपये प्रति दिन हो गई, वेजेज आप बढ़ाते जा रहे हैं मगर एक आदमी को महीने भर के लिए पांच सौ रुपये देकर जनता जल योजना का आप उससे मेंटीनेंस करवाना चाहते हैं। मेरा सुझाव है कि इसमें पांच सौ की जगह कम से कम हजार रुपये करें। मैं उम्मीद करता हूं कि कम से कम ऐसे गांव जहां पर एक ट्यूब वैल से 2-2, 3-3 गांव जुड़े हुए हैं एक ही पंचायत के अन्दर, और उन्हें जनता जल योजना के अन्दर पंचायत लेने को तैयार है, उन्हें शामिल करना चाहिए।

इसके अलावा मीठे पानी और खारे पानी के लिए थोड़ा-सा फर्क करना पड़ेगा। यह एक समस्या है, जैसा कि पहले भी थी, कि आज मीठा पानी स्नान में भी जा रहा है, कपड़े धोने में भी मीठा पानी जा रहा है, बच्चों की सफाई करने मे भी जा रहा है। अगर चौका लगाना है तो भी मीठा पानी जा रहा है, घरों में सफाई करो तो उसमें मीठा पानी जा रहा है। तो आप मीठे पानी को कम से कम पेयजल तक ही सीमित रखकर ऐसी व्यवस्था करिये कि खारे पानी के जो सोर्स गांव में बने हुए हैं, पंच का है....

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें। बाकी माननीय सदस्यों का मुझे ध्यान है, उनको भी समय चाहिए न जैसे आपने चाहा।

श्री मगराज चौधरी : I am taking my party's time. Please, don't bother. I am giving very good suggestions. आप जरा सुनिये तो सही।

श्री सभापति : यह साढ़े तीन बजे समाप्त हो जाएगा। 15 मिनट हैं, अब आप टाइम ले रहे हैं तो फिर अन्य सदस्यों का नाम नहीं बोला जाएगा।

श्री मगराज चौधरी : I have given some good suggestions.

श्री सभापति : ठीक है, आप यदि सारी पार्टी की तरफ से बोलें तो बोले जाइये, मुझे कोई ऐतराज नहीं है।

श्री मगराज चौधरी : मैं पाइंट्स दे रहा हूं।

श्री सभापति : यदि आप सारी पार्टी का समय लेकर बोलें तो बोले जाइये, कोई एतराज नहीं है मुझे।

श्री मगराज चौधरी : मैं पाइंट्स दे रहा हूं सिर्फ। तो महरबानी करके आप पंच की बावड़ियां जो हमारे एडिशनल सोर्सेज हैं, उनका उपयोग किसी भी कीमत पर लें जिससे मीठे पानी का उपयोग हम केवल मात्र पीने तक ही ले सकें। यह व्यवस्था आप करने की कोशिश करें।

(श्री भगराज चौधरी)

इसके अलावा जी. एल. आर से पानी भरते समय मैंने देखा जाकर कि सैकड़ों घड़े पानी दिन भर बेकार बहता रहता है क्योंकि वहाँ टूंटियां नहीं हैं मगर टूंटियां हैं भी तो पानी भरते समय ढुलता रहता है। अगर वहाँ पर प्लेटफार्म बना दें और नीचे उस पाइप को जोड़ दें पशु पेयजल कुंड से, तो वह पानी निकल कर कम से कम फिजूल नहीं जाएगा। पशु पेयजल कुंड में वह पानी एकत्रित हो सकता है और उसी पानी को हमारे मवेशी पी सकते हैं, और एक्स्ट्रा पानी वहां पर देने की जरूरत नहीं रहेगी। व्यवस्था करिये।

दूसरा मैं एक बात और निवेदन करना चाहूंगा कि अकाल के दौरान पश्चिमी राजस्थान में काफी कुछ घरों में टांके बनाये गये थे। मैं यह तो नहीं कहता कि आप टांके बनाइये, मगर कम से कम आप ग्रामीण क्षेत्र में ऐसा वातावरण बनाएं जिससे आपके विभाग को उन टांकों का संधारण करने में मदद मिल सके। वहां पर लोगों में हम यह हैविट डवलप करें, उनमें एक यह विचार हम पैदा करें कि बरसात का पानी भी है तो आप सीमेंट के पत्थरों से या लोहे के पत्तरों से छोटा-मोटा अपना कुंड घर में बना लीजिये छोटी-मोटी लागत से और पानी इकट्ठा करिये जिससे चार-छः महीने तो आपके निकल ही जाएंगे इस पानी से। वह भी हमें इस प्रकार का विभाग बनाना चाहिए, बहुत-से गांवों में अभी तक नहीं है।

दूसरा आप गांव में नल दे रहे हैं, और नल में भयंकर भ्रष्टाचार है आपका। पहले तो पांच हजार की आबादी की सीमा थी अब आपने चार हजार कर दी। मगर कई गांव ऐसे हैं जहां 3-3 सौ, 4-4 सौ संख्या की आबादी है और वहां पर भी नल है। तो इस बीमारी को आप कैसे रोकेंगे ? तो मेरा सुझाव है कि आप चार हजार तक की सीमा मत करिये, आप दो हजार पर आइये उससे आपको रेवन्यू मिलेगी और मैं समझता हूं कि पानी का मौके पर जो ज्यादा नुकसान हो रहा है एक संग पानी भरने में, उसमें थोड़ी कमी आएगी।

श्री रतनलाल ताम्बी : अब बहुत है।

श्री भगराज चौधरी : दूसरा, आपकी पेयजल योजना के मेंटीनेंस में जोइंट्स हैं, एक्सेसरीज हैं, बोल्ट्स हैं ये भी आप एस. ई. के लेवल पर या एक्स. ईएन. के लेवल पर उपलब्ध करवाएं जिससे छोटी-मोटी बात के लिए बार-बार ऊपर नहीं आना पड़े, समय नहीं लगे।

एक मैं आपको और कहूंगा कि एक तरफ तो हमारे पास में पाइप लाइन की कमी है दूसरी तरफ सैकड़ों किलोमीटर....

श्री सभापति : अब इनके बजाय मैं ये तीन सदस्य बुलवाऊंगा क्योंकि आप 13 मिनट बोल चुके हैं।

श्री भगराज चौधरी : मैं अब समाप्त कर रहा हूं।

श्री सभापति : उधर पांच-पांच मिनट दूंगा, तीन सदस्य बुलवाऊंगा क्योंकि आप अपनी पार्टी का टाइम ले रहे हैं।

श्री मगराज चौधरी : मैं समाप्त कर रहा हूं।

श्री सभापति : कहां समाप्त कर रहे हैं आप ? आप सबके साथ सहयोग कीजिये, सबको पांच-पांच मिनट देने की बात है।

श्री मगराज चौधरी : मैं सहयोग कर रहा हूं साहब।

श्री सभापति : यह सहयोग करना थोड़े ही होता है।

श्री मगराज चौधरी: शुरू में लगी हुई पाइप लाइन जो आइडल पड़ी है, उस पाइप लाइन को काम नहीं ले रहे हैं उसको निकालिये। प्रत्येक क्षेत्र के अन्दर सैकड़ों किलोमीटर आपकी लाइन आयी हुई पड़ी है और दूसरी तरफ आपको नयी पाइप लाइन मिल नहीं रही है आर्थिक कंस्ट्रेंट्स के कारण से, तो पुरानी पाइप लाइन को भी आप काम में लीजिये

श्री सभापति : माननीय श्री अर्जुनलाल जीनगर।

(अनुपस्थित)

श्री मगराज चौधरी : एक मैं निवेदन और करूंगा।

श्री सभापति : माननीय श्री शिवकिशोर सनाढ्य।

(अनुपस्थित)

माननीय श्री उगम राज जी मेहता।

श्री मगराज चौधरी : अन्त में मेरी एक मांग है....

श्री सभापति : कोई अंकित नहीं होगा आपका।

श्री मगराज चौधरी : × × ×

श्री उगमराज मेहता (ब्यावर) : सभापति महोदय, बीसलपुर योजना पर 153 करोड़ रुपये खर्च हुए और मैं माननीय भंवर लाल जी शर्मा का बहुत-बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूं कि उन्होंने ब्यावर की जल समस्या का समाधान किया। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने इस हाउस की एक हाई पावर कमेटी बनाई जिसकी अध्यक्षता वर्तमान उप मुख्य मंत्री जी और तत्कालीन अध्यक्ष कर रहे थे और माननीय महावीर प्रसाद जी जैन, चीफ व्हिप उनके साथ में थे। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं श्री महावीर प्रसाद जी जैन को भी कि उन्होंने बार-बार ब्यावर में, बीसलपुर में और यहां

× × × अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री उगमराज मेहता)

आकर इन अधिकारियों की खिचाई की और समय पर ब्यावर में पानी पहुंचाया।

माननीय सभापति महोदय, ब्यावर में पानी पहुंच गया ओवर हैड टैंक बन गये और छावनी में एक टैंक बन रहा है। पिछले एक साल से मैं बार-बार कह रहा था कि सब पुलिया से जो पाइप लाइन जोड़नी है उसका काम युद्धस्तर पर किया जाए, पर सभी इंजीनियर्स को यह अब ध्यान में आया और छावनी से पाइप लाइन जा रही है, चांद गेट पर पाइप लाइन लाकर ब्यावर में अन्दर की जो तीन टंकियां है उसमें पाइप लाइन अब मिला है। अब चालू किया है वह अब पूरा होने जा रहा है। उसके बाद एक 20 फीट पाइप लाइन जोड़नी है, उसके लिए इन्होंने साल भर लगा दिया।

माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय भंवर लाल जी शर्मा को एक बात याद दिलाना चाहता हूं। माननीय मंत्री महोदय, जिस समय आप पढ़ते थे, कालेज में आपका नाम था और आपके नाम से डरते थे लोग बाग कि भंवर लाल जी आ गये। आप उस दिन को याद करिये और इन अधिकारियों को कहिए कि इस प्रकार काम करें ताकि जनता मे हो कि हमारे अधिकारी समय पर काम करते हैं। वैसा आप अपना काम हाथ मे लें, वह कालेज वाली स्टाइल अपने हाथ में लें। जैसा माननीय सदस्य कह रहे थे, हमारे मंत्री बहुत सीधे-सादे नहीं हैं, अगर वे ठान लें तो बराबर सारे अधिकारियों को बैठा कर परेड करा सकते हैं, उनमें ताकत है।

मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान मेरे ग्रामीण क्षेत्र की ओर दिलाना चाहता हूं। सूरजपुरा लोटाना की स्कीम डी.आर. डी. ए. में पड़ी है पर वहां पर एस. ई. लेकर बैठ गये। दो लाख रुपये पिछले दो साल में खर्च हुए डी. आर. डी. ए. के मार्फत इसी प्रकार कोटड़ा में, रुपये, क्या हुआ उन स्कीमों का ? उन्हें जल्दी से जल्दी पास करवाइये। मैं आभार प्रकट करना चाहता हूं, एक बड़ा खेड़ा स्कीम आपने पास कर दी। वर्क आर्डर हो गया, टेण्डर हो गया, वर्क आर्डर उसे मिल गया; मैं बहुत-बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूं। कालिदर में दो हजार की पापुलेशन है उसको भी इस स्कीम में लीजिये। एक निवेदन करना चाहता हूं कि पूरा एरिया फ्लोराइड वाटर का है, वह पानी जो समोखी से ब्यावर आ रहा है, सेंदरा से ब्यावर आ रहा है, जाले से ब्यावर आ रहा है उस पाइप लाइन को डाइवर्ट करिये मेरे ग्रामीण क्षेत्र की ओर ताकि वहां पर जो फ्लोराइड वाटर पीने को मिलता है उसकी समस्या का समाधान हो सके। अभी मखेड़ा, जालिया, समोखी....

(15.20 बजे)

(श्रीमती तारा भण्डारी, सभापति, पदासीन)

यह पानी जो ब्यावर में अभी तक सेमिलर चल रहा है वह किस कारण से चल रहा है ? बीसलपुर की पाइप लाइन अभी जम रही है, कभी टूट-फूट भी हो जाती है

(श्री उगमराज मेहता)

इसलिए उसका भी पानी काम में लिया जाता है। उस पाइप लाइन को जब यह काम नहीं आये तो ग्रामीण क्षेत्र की ओर, मेरे क्षेत्र की ओर मोड़िए। मंत्री महोदय, मेरे साथ में दोमादा बांध चलिए आप और वहां निरीक्षण करिये कि दोमादा बांध का पानी उस ग्रामीण क्षेत्र की जनता के लिये मिल सकता है कि नहीं मिल सकता। पेयजल की उनकी समस्या का समाधान करने के लिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप दामोदा बांध का निरीक्षण मेरे साथ चल कर करें ताकि वहां के ग्रामीण वासी जो अभी फ्लोराइड युक्त पानी पी रहे हैं, उनकी समस्या का समाधान हो जाए। आपको घंटी बजाने की कोई जरूरत नहीं, आपने समय दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री रतनलाल जी ताम्बी।

श्री रतनलाल ताम्बी (जहाजपुर) : माननीय सभापति महोदया, जल जीवन है, इस सिद्धान्त को हम सब मानते हैं।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, मैं समझती हूं आप भूमिका बनाये बिना बोलें। सुझाव सभी लोग दे दें तो सबको मौका मिल जाएगा। मैं राइट 4 बजे मंत्री जी का जवाब करा दूंगी।

श्री रतनलाल ताम्बी : मैं भूमिका नहीं बना रहा हूं, डायरेक्ट ही करूंगा। बिलकुल मैं उसी ढंग से चल रहा हूं।

इस महत्वपूर्ण समस्या के लिये जिस गम्भीरता के साथ चिंतन की आवश्यकता है उस चिंतन की राज्य सरकार की इच्छा शक्ति मुझे महसूस नहीं होती है। पेयजल के लिये दीर्घकालीन योजनाएं और मास्टर प्लान बनाकर राजस्थान की मूलभूत समस्या के समाधान के लिये मैं लगातार सुझाव देता आ रहा हूं और मांग करता आ रहा हूं। मैं आज भी निवेदन करना चाहता हूं कि सबसे पहले प्रदेश की दीर्घकालीन जल योजना, जल नीति बनाने की आवश्यकता है। उद्योग नीति बना दी, सड़क नीति बना दी और पता नहीं क्या-क्या नीतियां बना दीं, पर इस महत्वपूर्ण समस्या के संबंध में कोई नीति निर्धारित नहीं की गई। मैं मंत्री जी से चाहूंगा कि इसको बहुत गंभीरता से लें और राजस्थान की जल समस्या के निवारण के लिये एक स्थाई जल नीति और योजना तैयार करें।

मैं इस मौके पर समय के अभाव को देखते हुए मोटे-मोटे तौर से कुछ सुझाव देना चाहता हूं। कोटा के बाद चम्बल नदी का पानी यमुना में मिल रहा है और राजस्थान से बाहर जा रहा है। चम्बल की बहुत बड़ी योजनाएं पानी की दृष्टि से तैयार की जा सकती है और उससे पूर्वी राजस्थान के बहुत बड़े हिस्से को लाभ मिल सकता है। बनास नदी के माध्यम से भीलवाड़ा जिले की बहुत बड़ी समस्या का समाधान किया जा सकता है। इस पर कुछ बड़े एनीकट तैयार करके पिकअप वीयर बनाकर और बीसलपुर के पास से योजना में बड़ी पाइप लाइन देकर

(श्री रतनलाल ताम्बी)

भीलवाड़ा जिले के जहाजपुर क्षेत्र, शाहपुरा क्षेत्र, ऊड़ा, बनेड़ा, गुलाबपुरा, आसींद और मांडल इन सारे क्षेत्रों में पानी पहुंच सकता है। इस मौके पर बहुत सारे बंधु धन्यवाद दे रहे थे, लेकिन मैं सोच रहा था कि मैं धन्यवाद क्या दूंगा, धन्यवाद देने के लिये कोई काम नजर आए तो दूं।

श्री टीकमचन्द कान्त : धन्यवाद देने के लिये बड़ा दिल चाहिये।

श्री रतनलाल ताम्बी : मुझे ऐसा लगता है कि राजस्थान की सरकार पानी जैसी समस्या में राजनीतिक तौर पर चलती है। धन्यवाद इधर के लोग दे रहे थे, उधर के लोगों ने कोई धन्यवाद नहीं दिया, एक को छोड़ कर।

श्री सभापति : माननीय ताम्बी जी, आप अपने सुझाव रखिए। देखिए, सबको मौका मिलना चाहिये इसलिए कृपया समाप्त करें।

श्री रतनलाल ताम्बी : मैं निवेदन करना चाहता हूं कि 1989–90 में तो योजना तैयार हुई, उसके जल स्रोत बने हुए पड़े हैं, लेकिन आज 1998 में भी वह योजना कार्यरत नहीं हो पाई। ऊंचा टिकर, कुचरवाड़ाकलां, मेरे क्षेत्र के 8 गांवों की एक बहुत अच्छी योजना तैयार की पर क्रियान्वित नहीं हुई। इसके लिये मुझे कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिये।

मैं इस मौके पर यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि भीलवाड़ा जिले में काफी बड़ी संख्या में गांव फ्लोराइड अफेक्टेड हैं, जहां के लोग कूबड़े हो जाते हैं, जहां के लोग जांडिस के शिकार हैं। उन गांवों के लिये तीन वर्ष पहले कहा गया कि हमने फ्लोराइड का एक प्रोजेक्ट तैयार किया। वह प्रोजेक्ट कहां गया, क्या हुआ? मैं समझता हूं, तीन वर्ष में कोई प्रगति नहीं हुई। मुझे अफसोस इस बात का है कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र जहाजपुर के कोटरी तहसील के 21 गांव की एक योजना बनी थी जो बिसनिया बोरड़ा छापर्नी के नाम से थी। वह योजना मंजूर होने की स्थिति में पहुंची। हमारे मन्त्री महोदय उस बैठक में मौजूद थे पी. पी. सी. वाली बैठक में, उसमें यह कहा कि इसमें कुछ गांव फ्लोराइड के भी हैं, उस सारी योजना को फ्लोराइड प्रोजेक्ट में भेज दो। योजना का सोर्स बन गया, माधोपुर के पास कुआ बना हुआ है बनास नदी पर। उस सोर्स के जरिए उन 21 गांवों को लाभ मिल सकता था, परन्तु 5-6 गांव फ्लोराइड के होने से राजस्थान सरकार अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो गई और उनको गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया के फ्लोराइड प्रोजेक्ट में डाल दिया। मंत्री जी, यह क्या किया आपने? आप नयी योजनाएं तैयार नहीं कर पाए। आपको कई बार हमने पत्र लिखे, क्षेत्रीय योजनाओं की हमने मांग की। बनास पर अच्छी योजनाएं बना सकते थे, वह किया नहीं और एक योजना तैयार, पकी-पकाई, कम्प्लीट है जिसको केवल स्वीकृत होना था, जिसमें राजस्थान सरकार के खजाने से

(श्री रतनलाल ताम्बी)

पैसा नहीं लगे, भारत सरकार से आता रहेगा, इसमें डाल दो, यह बहुत बड़ा काम किया आपने, इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं उस योजना को फ्लोराइड प्रोजेक्ट से निकाल दें। उसका सोर्स बन चुका, वहां की जनता खारे पानी से परेशान है, पानी नहीं है। बिसानिया बोरड़ा के नाम से 21 गांवों की योजना है, मैंने आपका पत्रों के द्वारा भी काफी ध्यान आकर्षित किया लेकिन आपने उस मामले में गंभीरता से गौर नहीं किया। मैं समझता हूं आप इस पर ध्यान देंगे।

अब मैं आना चाहता हूं हैण्ड पम्प योजनाओं पर। हैण्ड पम्प के मामले में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि 1981 की जनसंख्या के आधार पर 1981 से 1985-86 तक हैण्ड पम्प लगे। उनमें से बहुत सारे नाकारा हो गये, खराब हो गये। आपके विभाग के लोग उखाड़ कर उनके पाइप ले आये और उसके बाद उन नाकारा हैण्ड पम्प की जगह कोई लगा नहीं। एक ओर जनसंख्या बढ़ी है, दूसरी ओर हैण्ड पम्प घटे हैं। नाकारा हैण्ड पम्प जहां-जहां भी आपने उखाड़े हैं, वहां बेकार हो गये, उनको वापस लगाने के बारे में भी सोचने की मैं मांग करता हूं। हैण्ड पम्पों के मामले में जहां पानी का स्तर नीचे चला गया, उनमें पाइप जोड़ने का कार्यक्रम खास तौर से आवश्यक होते हुए भी नहीं किया जा रहा है। उसको किया जाना चाहिये। राजीव गांधी मिशन से आप छोटे-छोटे गांवों में पानी देने के लिये 50 की जनसंख्या के लिये सुझाव मांगे थे। बड़ी संख्या में ढाणी और मजरे पानी से वंचित हैं। उस योजना के अन्तर्गत जहां से सरकार के पास सुझाव आ गये, उन सबको पानी की व्यवस्था की जानी चाहिये। जहाजपुर कस्बे में पानी की कोई कमी नहीं है, बनास नदी के सोर्स से पानी उपलब्ध है। वहां पानी उपलब्ध है उसके बाद भी दो टाइम आप पानी नहीं दे सकते। पानी की कमी है वहां नहीं दें, लेकिन जहां पानी मौजूद है वहां दो टाइम पानी क्यों नहीं दिया जाता है? मैं समझता हूं इस ओर भी आपका ध्यान जाएगा।

इन्हीं शब्दों के साथ, आप समय की पाबंदी में चल रहे हैं, मैं यही निवेदन करता हुआ पुनः मांग करना चाहता हूं कि बानस नदी से जहाजपुर क्षेत्र की एक दीर्घकालीन योजना बनाएं, सौ–डेढ़ सौ गांव इसमें आराम से आ सकते हैं। प्रति वर्ष पैसा खर्च करने के बाद सारा सोर्स उपलब्ध है, उसका उपयोग भीलवाड़ा जिले में कई जगह किया जा सकता है, वह किया जाए, यह हमारी मांग है।

श्री सभापति : श्री महेन्द्र कुमार मीणा।

श्री महेन्द्र कुमार मीणा (सिकराय) : सभापति महोदया, मांग संख्या 27 पेयजल की समस्या के ऊपर आज चर्चा हो रही है मैं भी अपने आपको उसमें सम्मिलित करते हुए पी.एच.ई.डी. मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। निवेदन है कि दौसा जिले की समस्त तहसीलें पी.एच.ई.-डी. के ए.ईएन. आफिस से जुड़ी हुई हैं

(श्री महेन्द्र कुमार मीणा)

चाहे दौसा को देख लो, बांदीकुई देख लो, महुवा देख लो, लालसोट देख लो लेकिन सिकराय को राजनीतिक द्वेष की वजह से आज तक भी पी. एच. ई. डी. के ए. ईएन. आफिस से जोड़ा नहीं गया। महोदया, सिकराय, क्षेत्र में 52 ग्राम पंचायतें हैं, 6 बड़े कस्बे हैं, लंबा-चौड़ा क्षेत्र है और वहाँ जलदाय के नाम पर मात्र एक जे. ईएन. है। आप बताइए, जे. ईएन. इतने लंबे-चौड़े क्षेत्र की समस्याओं को कैसे सोल्व कर सकता है। मंत्री महोदय आज से डेढ़ साल पहले बालाजी पधारे थे, उनका भव्य स्वागत हम लोगों ने किया था और उस मौके पर मंत्री महोदय से हमने प्रार्थना की थी कि हमारे यहां ए. ईएन. आफिस खोल दीजिए, यह बहुत लंबे समय से मांग चल रही है। मंत्री महोदय ने उस वक्त हमको और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को आश्वासन भी दिया था कि मैं ए. ईएन. आफिस शीघ्र से शीघ्र खोल दूंगा। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने लड्डू भी बांटे थे। लेकिन, मंत्री महोदय, दुर्भाग्य है, वे लड्डू धरे के धरे रह गये और वे आज आपको गाली निकाल रहे हैं। लोक सभा के चुनाव में उन्होंने बदला ले लिया है, आप वहां से 10 हजार वोटों से हारे हैं। इसलिए मेरी पुरजोर हाथ जोड़कर मांग है कि दौसा जिले के अन्दर जो सिकराय ए. ईएन. आफिस बचा हुआ है वहां आप आज ही जाते वक्त घोषणा करके करने की व्यवस्था करें और सिकराय को ए. ईएन. आफिस दें।

दूसरा, मान्यवर, मेरे क्षेत्र में हैण्ड पम्प आज तक भी नहीं लगे। और तो क्या, जहां 2-2 किलोमीटर, 3-3 किलोमीटर तक धार्मिक स्थान हैं, हजारों की संख्या में जहां लोग आते हैं और प्रति वर्ष मेले लगते हैं वहां मैंने विधायक कोटे से हैण्ड पम्प दिये थे लेकिन वह हैण्ड पम्प भी आज तक नहीं लगे। जैसे मोरोली के हनुमानजी के यहां हर साल लखी मेला लगता है। इसी प्रकार सूरतपुरा में हनुमानजी का स्थान है, वहां भी हमेशा लखी मेला लगता है। इसी प्रकार गढ़मोर के ऊपर पपलाद माता के यहां लखी मेला लगता है, वहां भी पानी के सोर्स नहीं हैं। आसपास घूमरा में महंतजी का आश्रम है, वहां हजारों की संख्या में लोग प्रति वर्ष इकट्ठा होते हैं। ऐसी जगह में जो हमारे विधायक कोटे के गत साल के हैण्ड पम्प हैं वे आज तक भी नहीं लगे तो मान्यवर, इस वर्ष जो हम हैण्ड पम्प देंगे वे कब लगेंगे, आप कल्पना कीजिये। मेरी आपसे पुरजोर प्रार्थना है कि ऐसी जगह जहां प्रति वर्ष लाखों की संख्या में जनता इकट्ठा होती है, धार्मिक स्थान हैं और आसपास पानी का कोई साधन नहीं है, वहां पर हमारे गत साल के विधायक कोटे के हैण्ड पम्प लगाये जाएं।

मान्यवर, तीसरी मेरी मुख्य मांग है कि मेरा विधान सभा क्षेत्र एन. एच. II के ऊपर है। सड़क के आसपास जितनी भी ढाणियां हैं, गांव हैं उनमें, सभापति महोदया, प्राइमरी स्कूल भी हैं, मिडिल भी हैं, सैकण्डरी भी हैं और सीनियर भी हैं लेकिन उन 90 प्रतिशत स्कूलों में हैण्ड पम्प नहीं हैं।

120

(श्री महेन्द्र कुमार मीणा)

माननीयवर, बच्चे पानी के अभाव में सड़क क्रास करते हैं, उधर जाते हैं इधर जाते हैं, भागते फिरते हैं तो कभी ट्रैक्टर के नीचे, कभी ट्रक के नीचे कई एक्सीडेन्ट हो जाते हैं और मासूम बच्चों की मौत हो जाती है। माननीयवर, मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप बड़ी स्कूलों में तो मत दीजिये, सीनियर में मत दीजिये, सैकण्डरी में मत दीजिये मिडिल में मत दीजिये लेकिन जो प्राइमरी स्कूल हैं, जहां मासूम बच्चे पढ़ते हैं उन सभी स्कूलों में तो कम से कम आप हैण्ड पम्प की व्यवस्था करिये जिससे बच्चे इधर-उधर क्रास नहीं करें और उन मासूम बच्चों की मौत नहीं हो।

श्री भंवरलाल शर्मा : जिसकी आप बात कर रहे हो वे राजकीय स्कूल हैं ?

श्री महेन्द्र कुमार मीणा : गवर्नमेंट स्कूल हैं, प्राइवेट तो हैं ही नहीं। वे वेंकवर्ड हैं, सब गवर्नमेंट के स्कूल हैं, उन 90 प्रतिशत स्कूलों में आज हैण्ड पम्प नहीं हैं।

इसी प्रकार, महोदया, मेरे विधान सभा क्षेत्र में एक पालवी ग्राम है जहां से बालाजी मोड़ पर पानी की टंकी बनी हुई है, लेकिन विभाग की भ्रष्टाचार की वजह से जंग लगी हुई, जर्जर पाइप लाइन डाली गयी। वह जिस दिन से डाली गयी आज तक उस टंकी के अन्दर पानी नहीं गया है, शुरूआत ही नहीं हुई है। इसी प्रकार मीणा सीमला, कालोखो, बिदवारा इन ग्रामों के अन्दर जो पाइप लाइन डाली गयी, वह जब से डाली गयी आज तक उनके अन्दर पानी गया ही नहीं। पिछले पांच साल से यह हाल है। गत वर्ष आपने पानी की समस्या दौसा के अन्दर पड़ी थी, उस वक्त मानिटरिंग के लिए हमारे रोहिताश्व जी को आपने प्रभारी मंत्री नियुक्त किया था और मेहरड़ा साहब को अधिकारी नियुक्त किया था। जब अधिकारी लोगों ने उनको गलत सूचना दी कि कालोखो के अन्दर पानी आ रहा है रैगुलर मैंने प्रभारी मंत्री महोदय से निवेदन किया था कि कालोखो 15 किलोमीटर दूर है, अगर ये अधिकारी सत्य बोलते हैं तो मेरे को पनिश कर दीजिये और मैं बोलता हूं तो आप इनको कर दीजिये। मेहरड़ा साहब वहां गये, उन्होंने देखा। माननीयवर, इनको बता रहा हूं कि कितनी असत्य सूचना देते हैं, जिसकी वजह से आपको सदन में झुकना पड़ता है। तो, माननीयवर, मेहरड़ा साहब जब हमारे कालोखो गये तब इन्होंने देखा कि पानी कभी उस टंकी के अन्दर आया ही नहीं, वह टंकी नष्ट हुई-हुई, सूखी हुई पड़ी हुई थी। इस तरह से गलत इन्फोर्मेशन आपके पास आती है तो इनको भी आप प्रताड़ित कीजिये और जहां भी ये पाइप लाइन टूटी हैं उनको दुरस्त कराइये।

इसी प्रकार, मेरे विधान सभा क्षेत्र में जितनी भी एस. सी. की बस्तियां हैं और एस टी. की हैं। करीब सौ घरों की आबादी है, दो-ढाई सौ आदमी रहते हैं, वहां की मैंने लिस्ट आपके आफिस के अन्दर दे रखी है, उन एस. सी. की बस्तियों में आज तक भी हैण्ड पम्प नहीं लगे हैं। मेरा

(श्री महेन्द्र कुमार मीणा)

निवेदन है कि ऐसी एस. सी एस टी. की बस्तियों को जिनके आसपास पानी का कोई स्रोत नहीं है, उनको पानी मिले। धन्य-वाद। जयहिन्द।

श्री सभापति : श्री रामकिशपाल नुवाल।

(अनुपस्थित)

श्री मांगीलाल मेघवाल।

आप बोल गये, बिराजिये।

श्री रामचन्द्र रावत : नहीं, एक साल तक विभाग द्वारा पाइप लाइन नहीं लगे, मंत्री जी इस बात का जबाब तो दें।

श्री सभापति : दे देंगे, बिराजिये। मांगीलाल जी, बोलिये।

श्री मांगीलाल मेघवाल (केशवराय-पाटन) : सम्माननीय सभापति महोदया, मैं आज हाउस में मांग संख्या 27-पेयजल पर अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूं। मेरा विधान सभा क्षेत्र बहुत ही विचित्र है। एक तरफ चम्बल की नहरें हैं जहां वाटर टेबल बहुत ऊपर है लेकिन अधिकांश पानी दूषित हो गया है और दूसरी तरफ 4-5 नदियों के खालों का क्षेत्र है जहां पानी बहुत ही नीचे है। इन विषम परिस्थितियों में हैण्ड पम्प लगाने के लिए अधिकारी वर्ग भी परेशान है। जहां पानी का भराव है, सीपेज के कारण वहां मशीन पहुंच नहीं सकती, और दूसरी तरफ जो खालों का क्षेत्र है वहां भी मशीन पहुंचती नहीं। पहुंचती भी है तो केवल मात्र गर्मी के दिनों में, अप्रैल, मई और जून में, उसके बाद 8-9-10 महीने वहां प्रवेश ही नहीं कर सकती मशीन। इसलिए हर प्लेटफार्म पर चाहे वह विधान सभा का हो, चाहे अधि-कारियों की बैठकें हो, चाहे प्राक्कलन समिति के माध्यम से अधिकारियों से डिबेट करना हो, सभी जगह यही मांग करते हैं कि बूंदी जिले के तालेड़ा और केशव-रायपाटन दो पंचायत समिति क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ विशेष कार्यक्रम बनाकर अगर मशीनें भेजी जाएंगी तभी जाकर हैण्ड पम्प लग पाएंगे और जनता की समस्याओं का समा-धान होगा।

मेरे विधान सभा क्षेत्र में पेयजल की समस्याओं का समाधान करने के लिए मंत्री महोदय ने जो हमको स्वीकृति दी है, मैं तहेदिल से उनका अभिनंदन करता हूं और धन्यवाद देता हूं। मेरे विधान सभा क्षेत्र केशवरायपाटन में 62 लाख की पेयजल योजना रिवाइज्ड, मंजूर होकर पूरी होने को है। कापरी नगरपालिका कस्बा, वहां की 60 लाख की योजना करीब करीब पूरी हो चुकी है। अभी जानकारी हुई है कि मेरे यहां लाखेरी में भी एक करोड़ 80 लाख की योजना स्वीकृत हो गयी है। इसके लिए अधिकारी साहबान को जिन्होंने परिश्रम करके योजना बनायी है व यहां लाकर मंजूर करायी, उन्हें इस प्लेटफार्म के माध्यम से तहेदिल से धन्यवाद अर्पित करता हूं।

ऐसी समस्याएं भी हैं जो वर्षों से

(122)

(श्री मांगीलाल मेघवाल)

अटकी पड़ी थीं। लाखेरी जैसा कस्बा, जिसकी विषम परिस्थितियां हैं, मजदूर बस्ती है, पहाड़ी एरिया है, पठार है उसकी समस्या सुधर जाएगी तो आने वाले 15-20 वर्षों में नगर के लोगों को परेशानी नहीं होगी। मेरे विधान सभा क्षेत्र में जनता जल के नाम से लाखों रुपये की योजना क्रियान्वित हो रही है। कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पीने योग्य पानी नहीं है, वाटर टेबल नहरों के ऊपर आ गया है। जो परम्परागत स्रोत थे वे सब दूषित हो गये, कुओं के ऊपर पानी बिलकुल ऊपर आ गया है, हाथ से बाल्टी भरी जा सकती है। ऐसे क्षेत्रों का चयन हो चुका है, सरकार के सामने है। हर साल जिस तरह से बजट का हमको डिस्ट्रीब्यूशन अनुपात में होता है, मैं चाहूंगा कि इस बजट को विशेष रूप से दुगुना या तीन गुना करके उन क्षेत्रों की समस्याओं का समाधान हो। मैं ज्यादा नहीं कहकर पुन: मेरे क्षेत्र की जो समस्याओं का समाधान हुआ है, जनता को लाभ हुआ है, क्षेत्र की समस्याएं पूर्ण होने से हर क्षेत्र में उसके लिए खुशी है, मैं धन्यवाद देकर अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री सभापति : श्री परसादीलाल मीणा।

श्री परसादीलाल मीणा (लालसोट) : सभापति महोदया, आज पेयजल की मांग पर जो बहस चल रही है उसमें मैंने कटौती प्रस्ताव दिये हैं। विशेषकर मेरे कटौती प्रस्तावों पर मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करूंगा। माननीय मंत्री जी, 1995–96 के बजट भाषण में मुख्य मंत्री जी ने यह कहा था कि इस वर्ष का बजट पेयजल को समर्पित होगा और अब 1500 की आबादी के जो भी गांव होंगे या उससे ज्यादा आबादी के जो भी गांव होंगे, हम उन गांवों को पी. एण्ड. टी. स्कीम से जोड़ देंगे। पता नहीं राजस्थान को तो आपने जोड़ा कि नहीं जोड़ा, पर लालसोट पंचायत समिति में एक भी गांव को नहीं जोड़ा जो 1500 से अधिक आबादी वाले 8-10 गांव थे। केवल एक गांव की स्कीम बनाकर भेजी थी उसको भी आपने पी.पी.सी. कमेटी में मंजूर नहीं किया। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि तीन साल पहले मंत्री जी ने एक योजना हमारे लालसोट के खुर्रा किशोरपुरा महा–रिया की स्वीकृत की थी, लेकिन उस योजना पर एक रुपये का काम भी आज तक नहीं हुआ। दो तीन बार मैं माननीय मंत्री जी से मिल लिया, इनके अधिकारियों से मिल लिया, पर पता नहीं मंत्री जी क्यों उस योजना को नहीं करवाना चाह रहे हैं। आप कहते हैं कि भूमि विवाद हो गया, यह हो गया। हमने इनको कहा था कि आप वहां से योजना बनाइए। अधिकारी वहां से योजना नहीं बनाकर दूसरी जगह से, जहां विवाद हो, जानबूझकर वहां से योजना को बनाते हैं। अब 2-3 महीने में क्या करवाएंगे जब तीन साल में नहीं करवाया? पर आप इस तरह की मीठी गोलियां देकर योजना को राजनीतिक आधार पर रोककर बैठे हैं। हमको भी लालसोट की योजना थी, वह आपको करनी थी। आप वहां चले गये, आपने कर दी।

(श्री परसादीलाल मीणा)

मंत्रीजी, तीन-साढे तीन करोड रुपये जो आपने लगाये, आपने उन तीन–साढे तीन-करोड़ रुपयों को बिलकुल बर्बाद कर दिया। लालसोट के एक भी नये घर को पानी नहीं मिला है, न एक ढाणी को पानी मिला है। जो पहले की योजना वहां पर चालू थी, सिर्फ एक टंकी और 3-4 ट्यूबवैल बनाये। न पाइप लाइन को पुनर्गठित किया, न ढाणियों को पानी पहुंचाया। इनके विभाग ने ढाणियों की स्कीम बनाकर भेजी, उसको वापस लौटा दिया। साढ़े तीन करोड़ रुपये हुडको से वहां पर सैंक्शन हुए लेकिन एक-एक हजार, डेढ़-डेढ़ हजार की आबादी की लालसोट नगरपालिका में ढाणियां हैं, एक भी ढाणी को आपने पाइप लाइन से नहीं जोड़ा। आपके ए.ईएन., जे.ईएल. को जब स्कीम बनाकर भेजने के लिए कहा तो इन्होंने विभाग को स्कीम बनाकर भेजी। आज तक उस स्कीम पर जरा-सी लाइन भी नहीं खिची है।

मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, मैंने आपकी सैक्रेटरी को पत्र लिखा था कि आप रसलांटरा महारिया इन तीन गांवों में 2–2 जी.एल.आर. बनाओगे, 6 जी.एल आर. आपकी बनेंगी उसकी बजाय आप एक एस.आर. बना दो। एक साल पहले पत्र लिखा, आपके विभाग की सैक्रेटरी ने आज तक जवाब नहीं दिया।

दूसरी हालत, आप देखिये, हैण्ड-पम्पों की है। विभाग ने 'एन' कैटेगरी में हैण्ड-पम्प स्वीकृत किये, विधायक कोटे के किये, और योजनाओं के किये। सभापति महोदया, 30 अप्रैल तक तो इनके पास हैण्ड पम्प लगाने के लिए एक मीटर पाइप नहीं था। इन्होंने खरीद नहीं की, विभाग रोक लगाकर बैठ गया। इन्होंने मई में जाकर कम्पनियों को आर्डर दिये, वे पाइप जून में आए। जून के बाद आ गयी जुलाई में बारिश अब हैण्ड-पम्प आप कहां लगाओगे? इस साल जहां कहीं भी देखें, गर्मियों में पानी की भारी किल्लत रही है। सभापति महोदया, इसका कारण? विशेषकर दौसा जिले की मैं बात कर रहा हूं। वहां पर राजनीतिक आधार पर दो-दो परीक्षण इनकी पार्टी के हुए। दोनों लोक सभा चुनावों में बी.जे.पी. के कैंडिडेट वहां बदल बदल कर दिये, उसका गुस्सा मंत्रीजी वहां की जनता को पानी नहीं पिलाकर, योजनाओं की क्रियान्विति नहीं कर, हैण्ड-पम्पों का सामान न देकर ले रहे हैं।

मंत्रीजी, आप भी अपोजिशन में बहुत साल तक रहे थे। आपने जमुवा–रामगढ़ का पानी काटकर, किसानों का गला काटकर जयपुर को दिया था। कांग्रेस का 40 साल तक राज रहा। आपके 1977 में फैसला करने के बाद में हमारी सरकार ने उस फैसले को नहीं बदला और जयपुर को पानी पिलाया। आज जिस तरह की ये कार्यवाही कर रहे हैं, जिस तरह से आपका विभाग चल रहा है इससे जनता का भला होने वाला नहीं है। सभापति महोदया, मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा....

(समय–समाप्ति–सूचक घण्टी)

(श्री परसादीलाल मीणा)

5 मिनट ही हुए हैं । 10 मिनट का टाइम लूंगा, ज्यादा नहीं लूंगा ।

श्री सभापति : आज मिनट का सवाल नहीं है । आज तो सुझाव ही हैं, बस, शार्ट में ।

श्री परसादीलाल मीणा : हां, सुझाव दे रहा हूं । मेरे कट मोशन पर ही बोल रहा हूं, ज्यादा नहीं बोल रहा हूं ।

श्री सभापति : बस आप तो शार्ट में, सवाल ही ।

श्री बनवारीलाल बैरवा : सभापति महोदया, मुझे भी बोलना है ।

श्री सभापति : आएगा, सबका आएगा, अगर आप शार्ट करेंगे तो ।

श्री परसादीलाल मीणा : सभापति महोदया, हमारे वहां पर एक मण्डावरी गांव है, मन्डावरी गांव की योजना 1970 में बनी थी । तब उसकी आबादी तीन–साढ़े तीन हजार थी, आज उसकी जनसंख्या 10 हजार हो गयी । इनको कई बार कहा कि गांव को एक टाइम भी पानी नहीं मिलता है । मैंने इस साल कम से कम 4 बार एडिशनल चीफ इंजीनियर, इनके सुपरिटेंडेंट इंजीनियर, इनके एक्जीक्यूटिव इंजीनियर, इन सबसे मिलकर योजनाओं के बारे में बार–बार बताया । परन्तु कोई जरा–सी भी इनके +++ । मंत्री महोदय, हमारे वहां पर जो गांवों की स्कीमें हैं, मैं आपका ध्यान तलाब गांव-शिवसिंहपुरा स्कीम की तरफ दिलाना चाहूंगा । शिवसिंहपुरा से तलाब गांव पानी जाता है। आपने अपने एक राजनीतिक कार्यकर्ता को फायदा देने के लिए जो तलाब गांव पाइप लाइन जा रही है उसमें 3 इंची का कनेक्शन दे दिया । वह तो खेती कर रहा है और तलाब गांव की जनता प्यासी मर रही है । कई बार कलेक्टर ने आपके एक्स. ईएन. को कहा कि इस कनेक्शन को काट दो । आज तक उसको नहीं काटा है और तलाब गांव के लोग प्यासे मर रहे हैं । इस तरह की आपके विभाग की जो कार्यवाहियां हैं, आप इन कार्यवाहियों को मेहरबानी करके 3–4 महीने में बंद करिये ।

इसके अलावा मैं आपसे कहना चाहूंगा कि जो हैण्ड पम्प आपके स्वीकृत हैं, आपने विधान सभा का एक जवाब भेजा है कि 236 हैण्ड पम्पों में से 100 हैण्ड पम्प, 1997 के जो स्वीकृत हैं "एन" कैटेगरी के, उनको नहीं लगाने के पीछे आपके विभाग के अधिकारी यह कहते हैं कि हमारे पास सामान नहीं है, हमारे पास पाइप नहीं है । मेरे को बहुत खेद है, सभापति महोदया, कि एक महीने तक तो इनके सहायक अभियंता को लगा दिया परीक्षाओं में, और 30 अप्रैल ज्यों ही आयी, उससे पहले ही हमारे लालसोट की जनता पर गाज गिरी । वहां के सहायक अभियन्ता को एक मई को हटा दिया और 2 महीने तक पद खाली रखा ।

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी ।

(श्री परसादीलाल मीणा)

कोई विभाग को कहने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं। ए. ईएन. का पद खाली रहा। न हैण्ड पम्प लगे, न आपकी योजनाओं से पर्याप्त व्यवस्था हो पायी। मंत्री महोदय, ऐसी अव्यवस्थाएं करके दौसा जिले पर आप मत कहर बरपाओ। आपने हमको अलग कर दिया, पहले तो आपकी बड़ी मेहरबानी थी। अलग करने के बाद वहां की जनता ने चारों एम. एल. ए. कांग्रेस के जिता दिये। इसमें हमारा क्या दोष है, अगर जिता दिया? हम राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, आप दो बार पार्लियामेंट में हार गये उसकी दुश्मनी आप इस तरह से मत निकालो। वहां पर जो हैण्ड पम्प सैक्शंड हैं आप उनका वहां पर पर्याप्त रूप से सामान दीजिए। जो योजनाएं आपकी अधूरी पड़ी हैं आप उनको सामान दें। विशेषकर लालसोट योजना का आप उद्‌घाटन करके आए हैं। माननीय मंत्री महोदय, जिस कॉलोनी में आपकी वह टंकी बनी हुई है उस कॉलोनी के लोगों को ही पानी नहीं मिल रहा है। वहां की जितनी ढाणियां हैं, आप ढाणियों को जोड़ने की घोषणा करके आए थे। एक ढाणी को नहीं जोड़ा है आपने अभी तक। आपके साढ़े तीन करोड़ में से जो भी आवंटित पैसे बचे हैं, विभाग के पास पाइप वगैरह बचा है, दूसरी योजनाओं में लगा रहे हैं लालसोट की पाइप-लाइन को। आप उसका एक बार परीक्षण करिये, विभाग के अधिकारियों को निर्देश दीजिए कि उन योजनाओं को वहां समुचित रूप से विकसित करें। आपने समय दिया उसके लिए बहुत धन्यवाद।

श्री सभापतिः श्री लक्ष्मीनारायण बैरवा।

(अनुपस्थित)

श्री प्रभुराम गरासिया।

श्री प्रभुराम गरासिया (पिंडवाड़ा): सभापति महोदय, मेरे पिंडवाड़ा क्षेत्र आबू में वैसे पानी की समस्या तो मंत्री महोदय ने खूब सारी हल की है, लेकिन मेरे 2-4 गावों की समस्या है उस ओर मैं मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। 1988 में जो हमारी ग्राम पंचायत जनापुर, पूजरा और नादिया है, उन्होंने अपने घरों के कनेक्शनों हेतु फाइलें भरी हुई थीं लेकिन आज दिन तक उनको कनेक्शन नहीं दिये गये हैं। उनके पैसे भी भरे हुए हैं। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि इस वर्ष आप उन तीनों गावों को नल योजना से जोड़ें।

मेरे तीन-चार गांव और हैं, जैसे तेलपुर, डींगर, वाटेड़ा, रोहिड़ा, इसरा और आरासना, इन गावों में हमेशा टैंकर से व्यवस्था करनी पड़ती है। इसलिए मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि तेलपुर, डींगर, वाटेड़ा, रोहिड़ा, इसरा और आरासना, इन गावों में पानी की समस्या का समाधान करें। एक हमारे देवधर में टंकी बनाये कम से कम 2-3 साल हो गये हैं, लेकिन अभी तक पाइप लाइन नहीं आने से वहां वह टंकी खराब हो जाएगी। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि पाइप लाइन वहां भिजवाकर तुरन्त लोगों को राहत पहुंचाएं, जिससे अच्छा रहेगा। पिंडवाड़ा में जन-सहयोग से जो टंकी बनवायी है, जब भी जाता हूं मैं वहां आफिस में तो वे कहते हैं कि 6-7 रोज में चालू हो जाएगी। वहां के लोगों का जिन्होंने पैसे दिये हैं उन

(126)

(श्री प्रभूराम गरासिया)

सहयोग से लोग-बाग कहते हैं कि उनका विश्वास ही उठ गया है, हमारे यहां क्या मालूम कि कब चालू होगी और कब नहीं होगी। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वहां तुरन्त ही टंकी को चालू किया जाए। पनघट योजना बनी, उसमें जो टंकियां बनी हुई हैं उनको पाइप लाइन से जोड़ा नहीं गया है, और वैसी की वैसी पड़ी वे खराब हो रही हैं। अपने संगवाड़ा, अहार और सत्रह-अठारह गांव ऐसे हैं, जहां पर पनघट टंकियां बन गई हैं लेकिन अभी तक उन टंकियों में पानी नहीं भरा गया है। इससे वे कड़क होकर टूट जाएंगी और पैसा बरबाद होगा। मेरा यही निवेदन है। आपने मुझे समय दिया उसके लिये धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री भीमसेनजी। वे बहुत समझदार हैं।

श्री भीमसेन चौधरी (लूणकरणसर) : सभापति महोदया, मुझे संक्षेप में अपने क्षेत्र की समस्याओं के बारे में निवेदन करना है। सबसे पहले तो मेरे खबड़या गांव, जो शिड्यूल्ड कास्ट के लोगों का गांव है, वहां के लोग अभी भी ऊंट से अपना कुंआ सिंचित करके पानी की आवश्यकता पूरी कर रहे हैं और विभाग ने जो योजना बना रखी है वहां से उनको पानी नहीं मिलता है। मेरा सुझाव है कि इस गांव में जो परम्परागत कुंआ है उस कुएं में आप मोटर फिट करवा दें, जिससे कि जो ऊंट से पानी निकालते हैं कम से कम उसमें सुविधा मिल जाए। आपने वहां के लिये एक ट्यूबवैल मंजूर किया था, उसको यह कहकर आपने नहीं बनाया कि वहां गांव का पानी खारा है, पीने के लायक नहीं है। मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि गांव के लोग जब ऊंट से पानी निकाल कर वह पानी पी रहे हैं तो आपका यह बहाना है कि पानी खारा है इसलिए हम ट्यूबवैल नहीं बनाते हैं। वह गांव की आवश्यकता है। आपके लिए मैं समझता हूं कि वहां ट्यूबवैल बनाने की आवश्यकता है।

इसके अलावा हमारी क्षेत्रीय योजनाएं हैं। 505 आर. डी. में उसके टेल के गांव हैं अजीतमाना और लखावत, इन दोनों गांवों को कभी पानी नहीं मिलता है। इसके बारे में पाइप लाइन की व्यवस्था अगर सही ढंग से कराएं, तो मौके पर जो कर्मचारी हैं, वे पाइप लाइन के रख-रखाव के लिये काम नहीं करते हैं। मेरा सुझाव है कि ग्राम पंचायत को आप पाइप लाइन मेन्टेन करने का काम दे दें। उसके लिये आपने जो राशि 500 रुपये की है, वह कम से कम एक हजार की आप कर सकें तो मैं समझता हूं कि पाइप लाइन की मेन्टिनेंस का काम पंचायत करा सकेगी। इसी तरह से हमारे हरसेला योजना है, उसमें सात गांव हैं और हरसेला से पानी आता है खियरां तक वहां से आगे तीन गांवों को पानी देना है तो वहां पर एक बड़ा जल हौज बनाने की आवश्यकता है ताकि वहां से तीन गांवों को तीन मोटरें लगाकर के एक साथ पानी दे सकें, वरना वहां पर बिजली इतनी रहती नहीं है। अभी एक गांव को पानी देते हैं, फिर दूसरे गांव को

(श्री भीमसेन चौधरी)

देते हैं, इतने में बिजली खत्म हो जाती है। इसलिए मैं समझता हूं कि वहां पर आप तीन मोटरें लगाएं और एक जल हौज बना दें, जिससे वहां आगे के तीनों बड़े-बड़े गांव हैं उनको पानी ठीक ढंग से मिल सकेगा। इसी तरह से हमारा शेरपुरा गांव है, शेरपुरा से चिला के लिये पाइप लाइन डाले तीन साल हो गये, लेकिन आपने पाइप लाइन की टेस्टिंग का काम भी अभी पूरा नहीं किया है। और मेरे विधान सभा के सवाल के जवाब में सरकार ने गलत जवाब दे दिया कि हमने वहाँ पाइप लाइन टैस्ट करके पानी चालू कर दिया है। यह गलत सूचना दी है। मेरी गांव के सरपंच से कल बात हुई, अभी लाइन टैस्ट नहीं हुई और आपने गलत मेरे को विधान सभा में जवाब दिया कि चिला में पानी दे दिया। माननीय सभापति महोदया, इस बारे में निवेदन करना चाहता हूं कि इसके बारे में पूरी व्यवस्था की जाए। इसी तरह से वहाँ मिमनेरा गांव है, इसमें सरकार के पास योजना बनाकर यहां रखी हुई है राज्य स्तर पर। उन योजनाओं को दो साल से मंजूरी नहीं मिल रही है। इसी तरह से बोरमाना और कदरालिया, ये दो जो बड़ी-बड़ी ढाणियां हैं उन ढाणियों के लिये भी आपकी स्कीम राज्य स्तर पर पड़ी हुई है। उसको भी दो साल से मंजूरी नहीं मिल रही है। मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि इन दोनों योजनाओं को मंजूर किया जाए। यही मैं निवेदन करना चाहता हूं।

श्री सभापति : श्री रामनारायण डूडी।

श्री रामनारायण डूडी (भोपालगढ़) : माननीय सभापति महोदया, मांग संख्या 27 पर समयाभाव के कारण मैं केवल सुझाव ही देना चाहता हूं। सभापति महोदया, जोधपुर जिले के अन्दर आज हमारे सामने पेयजल की बहुत भयकर समस्या है।

(15.55 बजे)

(श्री समर्थलाल मीणा, अध्यक्ष, पदासीन.)

हमने जोधपुर जिले को, जोधपुर शहर को केवल लिफ्ट कैनाल से जोड़ कर प्रशंसा प्राप्त कर ली, मगर ग्रामीण क्षेत्र के अन्दर, अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से निवेदन करना चाहूंगा, वे सुन रहे हैं, चाहे भोपालगढ़ पंचायत समिति हो, चाहे ओसियां पचायत समिति हो, चाहे मण्डोर पंचायत समिति हो, चाहे फलोदी हो, चाहे लूणी हो और चाहे बिलाड़ा पंचायत समिति हो, यहां का जल स्तर बहुत नीचे चला गया है। हमारे अधिकारीगण की सरकार की आंख तब खुलती है जब विकट समस्या पैदा हो जाती है। उसका उदाहरण मैं पुनः नहीं देना चाहता, विश्नोई साहब ने जैसा फरमाया था, जोधपुर अकेले को पानी पिलाने के लिये हमने पाल के एरिये को खत्म कर दिया, डेजल और मथानिया को खत्म कर दिया। दूसरी जगह जहाँ से भी हमें पानी मिला, पानी के जो कस्सी के कुए थे, कस्सी जो हो रहे थे उन सारी योजनाओं को हमने खत्म करके केवल जोधपुर को पानी पिलाया। वर्षों बाद लिफ्ट कैनाल ली। रणसी गांव से जो स्कीम बनायी, वह

(श्री रामनारायण डूडी)

जोधपुर को पानी पिलाने के लिये बनायी, अध्यक्ष महोदय, मगर आज हालत वहां बहुत भयंकर हो गयी। भयंकर इसलिए हो गयी कि पानी बहुत नीचे चला गया, कुए सूख गये और काश्तकारी का जो धन्धा था, वह भी बरबाद होने जा रहा है। मैं, अध्यक्ष महोदय, ...

श्री अध्यक्ष : अभी मुखबन्द का टाइम हो गया....

श्री रामनारायण डूडी : सरकार से इसलिए निवेदन करना चाहता हूं कि पूर्व के अन्दर इन ग्रामीण क्षेत्रों को जोड़ने के लिये और नागौर के क्षेत्र को जोड़ने के लिए लिफ्ट कैनाल की योजनाएं विचाराधीन थीं। मैंने यह प्रश्न पूछा था कि इस खारी बैल्ट को, हार्ड बैल्ट को आप किस प्रकार से अपनी योजना बनाकर पानी पिलाना चाहते हो? तो उन्होंने कहा कि अभी हमारे सामने कोई विचाराधीन ऐसा प्रस्ताव नहीं है।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत शॉर्ट में, वक्त को ध्यान में रखते हुए....

श्री अध्यक्ष : मैं इसलिए निवेदन कर रहा हूं कि मुखबन्द का टाइम हो रहा है। (व्यवधान)

श्री रामनारायण डूडी : आने वाले वक्त को ध्यान में रखते हुए....

श्री अध्यक्ष : आधा घण्टा तो सरकार की तरफ से जवाब में भी लगेगा।

श्री रामनारायण डूडी : दो मिनट में ही। हमारी इन समितियों के अन्दर.... (व्यवधान)...

श्री श्रवण कुमार (पिलानी) : पानी जैसी समस्या पर बोलने का मौका नहीं मिला। उस पर टाइम नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे फिर हम?

श्री बनवारीलाल बैरवा : माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे कट मोशन हैं ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कटमोशन का जवाब सरकार की ओर से पहुंच जाएगा आपके पास।

श्री श्रवण कुमार : बोलने के लिये इतना–सा टाइम नहीं मिला।

श्री रामनारायण डूडी : मैं केवल यह निवेदन करना चाहता हूं कि जोधपुर जिले के ग्रामीण क्षेत्र को जोड़ने के लिये..(व्यवधान) ...

श्री बनवारीलाल बैरवा : आप हमें समय दीजिये।

श्रीमती कमला : ऐसा है, बोलने का माननीय सदस्यों को मौका मिलना चाहिये और..(व्यवधान)....

श्री श्रवण कुमार : ये लम्बे भाषण हो गये और (व्यवधान)

श्री रामनारायण डूडी : जोधपुर ग्रामीण क्षेत्र के लिये कैनाल योजना बनायी जाए और जो हमें पानी नहीं मिल रहा है... (व्यवधान)

श्रीमती कमला : जवाब तो रोज ही देते हैं आप।

श्री बनवारीलाल बैरवा : आप हमें समय दीजियेगा।

श्री रामनारायण डूडी : वह नीचे पानी चला गया, हजारों फीट नीचे चला गया है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अब आप समाप्त करें।

श्री रामनारायण डूडी : उन गांवों को जोड़ने के लिये लिफ्ट कैनाल योजना बनायी जाए। दूसरा मेरे क्षेत्र का मामला है, अध्यक्ष महोदय। मेरे क्षेत्र के अन्दर अठारह बीस गांव हैंड पम्प योजना से जुड़े हुए हैं लेकिन वहां पर पानी नीचे चला गया है। पिछले कई समय से मैं इनसे पूछ रहा हूं, इन्होंने कहा कि यह तो चेंज आफ स्कीम हो गयी। यहां से आब्जेक्शन लगते-लगते आज स्थिति यह है कि पूरी की पूरी अठारह-बीस गांव की आबादी को एक बूंद पानी नहीं मिल रहा है। मेरा निवेदन है सरकार से कि आपको चाहे योजना चेंज करनी पड़े और चाहे कैसे भी करना पड़े, बीस गांवों को आप ज्यादा से ज्यादा लाभान्वित करें। नलकूप खोदकर जोधपुर लिफ्ट कैनाल का पानी उसमें डालकर पिपाड़ बिलाड़ा इस क्षेत्र के अन्दर जहां खारा पानी है उस क्षेत्र के लिए जोधपुर में जो पाइप लाइन रणसी गांव से लगायी हुई है जोधपुर में पानी देने के लिये, उसको फीड बैक दिया जाए ताकि वे गांव लाभान्वित हो सकें। बड़े-बड़े कस्बों जैसे पिपाड़ में आज एक बूंद पानी नहीं आ रहा है। इन गांवों को लाभान्वित करें, यही मेरा निवेदन है। समयाभाव के कारण भी आपने मुझे समय दिया उसके लिये धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री श्रवण कुमार : अध्यक्ष महोदय, मुझे समय दीजिये।

श्री अध्यक्ष : क्या ?

श्री श्रवण कुमार (पिलानी) : अध्यक्ष महोदय, निर्दलीयों में से दो आदमी ही बोले हैं, केवल दो। हमारा नम्बर नहीं आएगा क्या ? औरों का आ गया, बी.जे.पी. वालों का आ गया। (व्यवधान)

श्री बनवारीलाल बैरवा : माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी बात भी कहनी है। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे जिले की तरफ से कोई बात नहीं आयी है। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा : ऐसा है, दो मिनट तो कम से कम सबको दे दो, ज्यादा नहीं दे सकते हो तो कोई बात नहीं है। आधा घंटे बोले हैं आपके सब। (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार : माननीय अध्यक्ष महोदय, निर्दलीयों के अन्दर केवल दो आदमी ही बोले हैं।....(व्यवधान)

(130)

श्री बनवारीलाल बैरवा : माननीय अध्यक्ष महोदय, टोंक जिले की तरफ से कोई नहीं बोला है, मैं .... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : एक मिनट। आप स्वयं जानते हैं कि मुखबन्द का समय निर्धारित होता है।

श्री बनवारीलाल बैरवा : पांच मिनट का समय दें, साहब।

श्रीमती कमला : बढ़ा भी दिया जाता है समय बहुत बार।

श्री अध्यक्ष : सरकार की ओर से जवाब देना बाकी है अभी। (व्यवधान)

श्री बनवारीलाल बैरवा : हां, वह सही है, मान लिया। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे भी अपनी बात कहने का मौका दिया जाए। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, सुनें आप। ग्यारह बजे से बहस कर रहे हैं इस जलदाय के मामले पर, काफी समय हो गया। उसका जवाब आप सरकार की ओर से चाहेंगे, वह भी जरूरी है। (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार : अध्यक्ष महोदय, हमारा नम्बर तो आया ही नहीं। दो मिनट तो कम से कम ....(व्यवधान)....

श्री बनवारीलाल बैरवा : हमारे जिले की कोई बात आपके सामने नहीं हुई तो क्या जवाब आएगा, साहब ? हमारी बात ही जब आपके सामने नहीं हुई तो क्या जवाब आएगा ? (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार : माननीय अध्यक्ष महोदय, दो मिनट तो दें कम से कम।

श्री रामस्वरूप मीणा : दो मिनट तो कम से कम दो हमको। (व्यवधान)

(16.00 बजे)

श्री श्रवण कुमार : माननीय अध्यक्ष महोदय, कम से कम दो मिनट तो दिए जाएं। माननीय अध्यक्ष महोदय, निर्दलीयों में केवल दो आदमी बोले हैं। 21 आदमियों के अन्दर केवल दो आदमी बोले हैं।

श्री बनवारीलाल बैरवा : माननीय अध्यक्ष जी, हमारी बड़ी विकट समस्या है, उसको सुन तो लें आप।

श्री श्रवण कुमार : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं ....(व्यवधान)

श्री बनवारीलाल बैरवा : इतनी देर में तो हम बोल ही लेते। इतनी देर में तो हम अपनी बात का आपसे निवेदन कर लेते।

श्री मोहनलाल मोदी : मुखबन्द का समय बढ़ाया जा सकता है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : मुखबन्द का समय जो समय है वह बढ़ाया जाना चाहिए। (व्यवधान)

श्री बनवारीलाल बैरवा : साढ़े चार बजे समय है मुखबन्द का, तो साढ़े चार तक समय दो न आप।

श्री राजेन्द्र पारीक : एक घण्टा बढ़ा दीजिए।

श्री अध्यक्ष : अब आप बिराज जाएं। बिराजें। बिराजें। दो-दो मिनट में आप अपनी बात कहें, दो-दो मिनट में। श्री बैरवा।

श्री श्रवण कुमार : माननीय अध्यक्ष महोदय,....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री बैरवा से निवेदन किया है मैंने।

श्री बनवारीलाल बैरवा (निवाई) : माननीय अध्यक्ष महोदय, टौंक जिले के अन्दर पेयजल का घोर संकट है, उसके मुख्य रूप से दो कारण हैं। अनावृष्टि तो है ही, अनावृष्टि तो....

श्री अध्यक्ष : आप घड़ी की तरफ भी ध्यान रखें और दो मिनट में अपनी बात समाप्त कर दें।

श्री बनवारीलाल बैरवा : हां, दो मिनट में ही बात करूंगा। मेरी बात बोलने तो दें, अध्यक्ष महोदय। एक तो बीसलपुर बांध बंधा है हमारे यहां पर। बीसलपुर बांध बंधने के बाद में उसका जो डाउन स्ट्रीम का पानी है, वह आना बन्द हो जाता है। वह प्रवाहित होना बन्द हो गया तो नीचे के जो गांव हैं उन सबके अन्दर सूखे की स्थिति पैदा हो गयी, और इसलिए पेयजल का घोर संकट हो गया है।

दूसरी बात यह थी कि हमारे फ्लोराइड की जो समस्या है वह बहुत विकट समस्या है। 145 गांव तो टौंक ब्लॉक में हैं और 23 गांव निवाई के अन्दर हैं। 145 गांवों से ज्यादा फ्लोराइडयुक्त जल कहीं नहीं है पूरे प्रान्त में, पूरे राज्य में कहीं नहीं है। ये दोनों समस्याएं हैं जिनकी वजह से हमें बहुत परेशानी है।

जहां तक फ्लोराइड का सवाल है, उसके लिए तो हमारे यहां से जो स्कीम बनकर आयी है, वह सरकार के पास में देरी हो रही है। उनको क्लीयर करके निकालें तो वह व्यवस्था हमारी हो जाए।

दूसरी बात, यह बीसलपुर का जो बांध है और बीसलपुर के बांध में डाउन स्ट्रीम का जो एरिया है, उसकी बात सरकार की तरफ से उठी। हमने भी कहा कि ईसरदा के ऊपर बांध दें, लेकिन यह तो एक बहुत लम्बा प्लान होगा। तो वह स्थिति तो हमारे सामने आएगी नहीं, हमारी परेशानी बढ़ती जाएगी। इसके लिए निवेदन यह है कि इस नदी के अन्दर तीन-चार जगह आप छोटे एनीकट बांध दें जिससे पानी का संधारण हो जाए या पानी का ठहराव हो जाए तो उससे पानी मिलेगा। हर साल नये कुएं खोदे जाते हैं लेकिन नए कुएं सूख जाते हैं क्योंकि पानी है नहीं, पानी खतम होता जा रहा है। लिहाजा हमारी परेशानी का एक ही निदान है कि आप उसके अन्दर एनीकट बांध दें।

दूसरा, मान्यवर, मेरी निवाई की कुछ विशेष समस्याएं हैं....

श्री अध्यक्ष : एनीकट बनवाना चाहते हैं?

132

श्री बनवारीलाल बैरवा : मासी बांध से हमको पानी दिया जाता है।

श्री अध्यक्ष : एनीकट, बनास में ?

श्री बनवारीलाल बैरवा : एनीकट। बनास में तीन–चार एनीकट बांधे तो उससे हमारी समस्या का समाधान हो जाएगा। इधर बीसलपुर से जो हमको पेयजल दिया जाता है, 35 एम. सी. एफ. टी. तो अभी दिया जा रहा है लेकिन उससे अभी पर्याप्त पानी नहीं मिल पा रहा है। 32 एम. सी. एफ.टी. आप इससे अगर हमको और पानी की इजाजत दे दें तो हमारी समस्या का समाधान हो जाएगा।

दूसरा बिड़ोली बन्ध है। हमारे देहात के अन्दर परेशानियां हैं, पानी खराब है, फ्लोराइडयुक्त है। वहां पर हम पानी वहां से विपरित कर दें तो उस समस्या का समाधान हो सकता है, उसके ऊपर आपकी सरकार को गौर करना चाहिए।

जनता जल योजना के तहत हमारी कुछ स्कीमें यहां आयी हुई हैं सरकार के पास में। सिरस गांव की आयी हुई है, सिरोली गांव की आयी हुई है, दतवास गांव की आयी हुई है, करेड़ा प्रोजेक्ट की आयी हुई है। ये स्कीमें आप मंजूर करके यहां से भिजवाएं तो लोगों को राहत मिल पाएगी। मैं यह देखता हूं कि रात–दिन बहुत सारे यहां पर धन्यवाद आपको देते हैं, क्योंकि आपने कोई स्कीमें पास की होंगी, लेकिन मेरे यहां तो कोई स्कीम पास ही नहीं की। अब मैं धन्यवाद देना भी चाहता हूं माननीय मंत्रीजी को, लेकिन मैं दूं तो किस बात का धन्यवाद ? (व्यवधान) एडवांस में तो मैं जब दूं कि जब ये हां करें। मेरी इतनी सारी स्कीमें आपके पास में पड़ी हुई है, आप उनको....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : नहीं, वे यह नहीं कह रहे हैं। वे बोलना नहीं चाहते, वह दो मिनट का ध्यान दिला रहे हैं। (व्यवधान)

श्री बनवारीलाल बैरवा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मंडावर कस्बे के अन्दर पेयजल योजना है, उससे सीतारामपुरा के लिए भी पानी देने की बात थी। सीतारामपुरा वहां से चार किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। मंडावर के लोग उस लाइन को या तो तोड़ देते हैं या कोई ऐसा ब्लॉक उसके अन्दर आ गया कि सीतारामपुरा में पानी नहीं पहुंचता। इसलिए इस सरकार से मेरा आग्रह है, मेरा मंत्रीजी से आग्रह है कि इसके लिए विशेष रूप से व्यवस्था करावें कि वहां सीतारामपुरा तक पानी चला जाए। पलाने के अन्दर पानी आप दोनों जगह दे रहे थे पहले, अब पलाने के अन्दर अपने आप जल स्रोत उपलब्ध हो गया है और वहां से पूरे पानी की व्यवस्था है। जो हथूनी का जल स्रोत था उससे हथूनी गांव को तो दे दिया पानी.. (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अब आप समाप्त करें, नहीं।

श्री बनवारीलाल बैरवा : अध्यक्ष जी, अब समाप्त कर ही रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : आप थोड़ा वादा तो पूरा किया करें कभी–कभी, माननीय सदस्य। बिराजें।

श्री बनवारीलाल बैरवा : एक सैकण्ड और। एक खांदोर गांव है, माननीय अध्यक्ष जी, उसके अन्दर पेयजल योजना है। लेकिन पेयजल योजना का आधार रहता है बिजली और बिजली हमारे पूरी मिलती नहीं है इसलिए वहां पर समस्या यूं की यूं पड़ी हुई है। नीचे पानी खारा है और फ्लोराइडयुक्त है। इसके लिए कोई और जगह व्यवस्था देखकर वहां पर पानी पहुंचाए। इतनी बात कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। आपने मुझे समय दिया इसके लिए धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : धन्यवाद। श्री रामस्वरूप जी। एक मिनट। (व्यवधान)

श्रीमती कमला : अध्यक्ष महोदय, एक मिनट में कोई अपनी बात बोल सकता है क्या ?

श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम) : अब मेरे दो मिनट आप खराब मत करिये, बड़ी मुश्किल से मिले हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से मात्र दो मिनट में दो बात कहना चाहूंगा। माननीय मंत्रीजी, आज मुझे समय ज्यादा नहीं दिया, इसलिए आप पिछले वायदे को याद कर लें। इसी सदन के अन्दर मैंने एक दिन आपसे निवेदन किया था कि मेरे यहां की चार स्कीमें आपके यहां विचाराधीन पड़ी हुई हैं।

श्री अध्यक्ष : आप माइक का दुरुपयोग नहीं करें, आप वैसे ही बोल लें।

श्री रामस्वरूप मीणा : मेरी चारों स्कीमें जो आपके यहां पड़ी हुई हैं, जिसमें टोडाभीम कस्बे की स्कीम भी है टंकियों की, आपने कहा था कि आप मेरे पास बैठ लीजिए अपन बैठकर इस पर विचार कर लेंगे। मेरे अधिकारी बहुत अच्छे बैठे हुए हैं, मैं उनसे आपका काम करवा दूंगा। मैं आपके पास बैठ लिया और आज फिर बैठ लूंगा आप कहोगे तो। माननीय मंत्रीजी, आप अपने वायदे से मुकर मत जाना क्योंकि +++ आपने बात की है मेरे सामने इसलिए आप इसको जरूर कर देना।

श्री अध्यक्ष : यह निकाला जाए। यह शब्द निकाला जाए।

श्री रामस्वरूप मीणा : दूसरा मेरा निवेदन है, माननीय मंत्री महोदय, आपने यह कहा था मुझसे, सुनिये आप, भ्रष्टाचार का मुद्दा था.... (व्यवधान)

श्री नाथूसिंह गुर्जर (राज्य मंत्री, पंचायती एवं ग्रामीण विकास) : यह एक्सपंज कर दीजिए। यह अच्छा नहीं है।

श्री रामस्वरूप मीणा : हां, कर दो। एक्सपंज कर दो। क्या फर्क पड़ता है इसे एक्सपंज कर देंगे उससे ? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कर दिया।

श्री महावीर प्रसाद जैन (सरकारी मुख्य सचेतक) : आप इन्हें पाबन्द करें कि ये संयम से बात करें। ये ऐसी बात करते हैं जिसके कारण गड़बड़ हो सकती है

+++ अभिव्यक्त अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री महावीर प्रसाद जैन)

यहां। क्या बोलना चाहिए, पता नहीं है इनको। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा : बिलकुल बात सत्य कहनी चाहिए सदन के अन्दर। यह 'सत्यमेव जयते' क्यों लिखा है सदन के अन्दर? 'सत्यमेव जयते' लिखा हुआ है यहां पर। या तो असत्यमेव जयते लिखा जाना चाहिए यहां पर। (व्यवधान) सत्य बोलना चाहिए सदन के अन्दर।

श्री अध्यक्ष : अब आप बिराज जाएं। एक मिनट खतम। बिराजें।

श्री रामस्वरूप मीणा : एक मिनट बस। दूसरा मेरा निवेदन है, माननीय अध्यक्ष महोदय, कि माननीय मंत्रीजी हमारे यहां पर एक बार पधारे थे। नादौती होकर निकले थे आप एक बार, उस समय आपने यह कहा था कि आपके यहां बिजली की व्यवस्था सही नहीं है। मेरे नादौती में जो जल योजना चल रही है, वहां पर बिजली आठ घण्टे मिलती है लेकिन आठ घण्टे वहां पर सप्लाई नहीं हो पाती है। पचासों योजनाएं मेरी वहां पर चल रही हैं। 40 लाख की एक योजना अभी हाणियों की आपने मंजूर करके दी है, वह भी स्कीम अब चालू होने वाली है। पूरी पाइप लाइन बिछ चुकी है उसके लिए तो मैं बहुत-बहुत धन्यवाद आपको देता हूं कि आपने मेरी कई बड़ी-बड़ी स्कीमें पास करके दी हैं, लेकिन इस बिजली की व्यवस्था को आप ठीक करावें। माननीय मंत्रीजी, जो बिराजमान हैं।.... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बिराजें। बिराजें, कृपया माननीय सदस्य।

श्री रामस्वरूप मीणा : उनसे मैं कहना चाहता हूं कि कृपा करके वे बिजली की व्यवस्था ठीक करें जिससे यह कार्यवाही मेरी सिद्ध हो सके। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने जो समय मुझे दिया है उसके साथ मैं आपके जितने भी अधिकारी यहां बिराजमान हैं...

श्री अध्यक्ष : उसका आपने पूरा उपयोग नहीं किया, बिराजें।

श्री रामस्वरूप मीणा : वे भी अच्छे हैं। सेक्रेटरी भटनागर जी यहां बैठी हैं, कृपया आप उनको कह दें। तीन महीने और आपसे कहूंगा उसके बाद तो हम ही कर लेंगे।

श्री अध्यक्ष : माननीय रामस्वरूपजी, बिराजें। तीन महीने-छह महीने का किसको क्या पता है? आप यह कैसी बात करते हैं?

श्री रामस्वरूप मीणा : याद दिलाया था मैंने तो।

श्री अध्यक्ष : श्री मोहनलालजी मोदी।

श्री मोहनलाल मोदी (नीमकाथाना) : अध्यक्ष महोदय, आज मांग संख्या-27 पर चर्चा चल रही है, मैं बहुत अधिक समय नहीं लूंगा। मैं मंत्री महोदय का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि 1995 में मैंने अपने भाषण के अन्दर जो बातें दर्ज करायी थीं,

(श्री मोहनलाल मोदी)

आज तक उसके अन्दर इन्होंने एक काम भी नहीं किया। हम लोग यहां विधान सभा में बोलते हैं, इसलिए बोलते हैं कि ये ध्यान देंगे। मैं समझता हूं कि इनके विभाग ने हमारे भाषण को पढ़ा ही नहीं और उसमें एक पर भी कार्यवाही नहीं की। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि पानी की बहुत बड़ी समस्या है। आपको ध्यान है कि हैण्ड पम्प खुद नहीं रहे थे, मेरे को यहां पर धरना देना पड़ा था तब जाकर प्राइवेट लोगों से हैण्ड पम्प खुदवाये थे। आप थोड़ा सा इस विभाग को सुधारिये। जो हैण्ड पम्प लग रहे हैं, मेरे यहां तो इन हैण्ड पम्पों से ही बिमारी है। न तो आपके यहां कोई टंकियां बन रही हैं और राजीव फाउंडेशन से जो हैंड पम्प आये हैं उनके अन्दर भी आपके विभाग के लोग पूरे पाइप नहीं डालते हैं। नीचे रेत आ जाती है और वह हैंड पम्प निकल कर बाहर आ जाता है, खराब हो जाता है। आपके यहां की अभी रिपोर्ट बता रहा हूं, 709 हैंड पम्प तो खराब थे। मैंने कलेक्टर को फैक्स दिया था कि मेरे यहां पानी की बहुत बड़ी दिक्कत है, 709 हैंड पम्प खराब हैं।

श्री अध्यक्ष : कुल कितने हैं ?

श्री मोहनलाल मोदी : कुल तो 1300-1400 हैं। 308 नाकारा हैं, जो बिलकुल खराब हो गये हैं या रिजैक्ट हो गये। आप कम से कम उन 308 हैंड पम्प को तो लगवाइये। इतना काम तो करिये।

मेरे यहां जैसे रायपुर जागीर में, रायपुर पाटन में ट्यूब वैल बना हुआ है, सोर्स है। वहां के नजदीक काचलड़ा है आधा किलोमीटर, वहां लाइन डाल दें तो पानी मिल जाए। गोपिया विलेज है जिसके अन्दर पहले पानी खराबी की वजह से हैजा फैल गया था। कलेक्टर साहब ने जाकर यह कहा कि इसकी व्यवस्था करेंगे। वह व्यवस्था नहीं हुई। सांसद कोटे से ट्यूबवैल खुदवाया, अब जरा पाइप लाइन ही पड़ेगी थोड़ी-सी, पाइप लाइन डालकर उसको जुड़वा दें।

श्री अध्यक्ष : बिराजें।

श्री मोहनलाल मोदी : मैं तो एक–दो पाइंट और कहूंगा।

श्री अध्यक्ष : नहीं, इससे ज्यादा क्या बोलेंगे ? काफी हो गया।

श्री मोहनलाल मोदी : ठीक है, अध्यक्ष महोदय, आप ध्यान दे लीजिये। 295 में मैंने जो दिया है, कहा है, उन कामों पर जरा ध्यान दे लें। मैं तो इतना ही निवेदन करना चाहता हूं, धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री शंकरलाल अहारी। दो मिनट।

श्री शंकरलाल अहारी (चौरासी) : अध्यक्ष महोदय, डूंगरपुर जिले के कई कस्बों में पानी की बड़ी भारी समस्या है, उसकी ओर मैं ध्यान दिलाता हुआ निवेदन करना चाहता हूं कि करावाड़ा, कस्बा, सीथल, जलाब, सिम्मलवाड़ा, पीठ, चूंडावाड़ा, गामड़िवाड़ा, दम्बोला, कन्दवा,

(श्री शंकरलाल अहारी)

सिलवाड़ा, गैंजी और विकास नगर, इन गांवों में पाइप लाइन डाली हुई है पर पाइप लाइन सब सड़ गयी है, तो इस पाइप लाइन को ठीक कराने की जरूरत है।

दूसरा निवेदन यह है कि मेरे चार गांवों में योजना बनायी थी, वह विचाराधीन है। सीथल है, जलाब है, दम्बोला है, इन दो-तीन गांवों में वह योजना पूर्व से चल रही है, अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मेरी इन योजनाओं को स्वीकृत करायें।

हमारे एक तहसील हैडक्वार्टर है सिम्बलवाड़ा में, वहां पर रेजीडेंट क्वार्टर हैं लेकिन कोई रहता नहीं है। मेरा निवेदन है कि ट्यूब वैल खुदवा दिया जाए तो वहां रहने वाले रहें और हमारी तहसील की भी शोभा बढ़े।

इसी तरह से सिम्बलवाड़ और बोखवाड़ा में रेफरल हास्पिटल है, वहां आये दिन काफी मरीज भर्ती होते रहते हैं लेकिन पानी की व्यवस्था नहीं है। मेरा आपसे आग्रह है कि वहां दोनों जगह ट्यूबवैल खुदवाया जाए और व्यवस्था की जाए। मुझे यही कहना है, धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री राजेन्द्र पारीक। एक मिनट।

श्रीमती कमला : अध्यक्ष महोदय, मेरा भी नाम है सूची में।

श्री अध्यक्ष : मैं बुलाऊंगा आपको।

श्रीमती कमला : कहीं ये साढ़े चार बजा दें।

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर) : अध्यक्ष महोदय, क्षेत्र में तो पानी की समस्या और वहां बोलने के लिए समय नहीं मिले यह समस्या। फिर भी आपने यह समय दिया।

अध्यक्ष महोदय, सीकर में दो तरह की समस्याएं हैं। एक तो है एडमिनिस्ट्रेटिव और दूसरी है फाइनेंशल। जिन स्वीकृतियों पर यहां से सैंक्शन होने के बावजूद भी विभागीय स्तर पर कार्य नहीं हो रहा है, एक तो यह बड़ी भारी समस्या है। मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, जैसे बराल का एक ट्यूबवैल सैंक्शन हुआ आपके यहां से, लेकिन नहीं लगा। आपके यहां से एक एस.आर. बनी जो कमेला की टंकी के नाम से है, उस कमेला की टंकी की क्षमता है सवा दो लाख लीटर की लेकिन उस क्षेत्र में पानी की समस्या आज भी बनी हुई है। उसका मात्र वन फोर्थ पानी यूटिलाइज हो रहा है, बाकी पूरा का पूरा पानी उसमें यों ही पड़ा रहता है। केवल पाइप लाइन जोड़ने की कमी की वजह से वह टंकी काम में नहीं आ रही, कमेला की टंकी के नाम से है।

अध्यक्ष महोदय, सीकर में पिछले दिनों एक घटना हुई थी कि कुए का पानी पोल्यूट हो गया। उसकी वजह से काफी लोग बीमार हो गये, काफी परेशानी हुई। इसका मुख्य कारण यह है कि सीकर में सीवरेज का कोई साधन नहीं है और वहां लोग सोक-पिट बनाते हैं। 50-50 फीट गहराई

(श्री राजेन्द्र पारीक)

के सोक-पिट बनाते हैं, उससे पानी नीचे जाता है। अंडरग्राउंड वाटर जो सीकर का बहुत बढ़िया था, सारा पोल्यूट हो कर धीरे-धीरे उसकी क्वालिटी इतनी इन्फीरियर होती जा रही है कि समय रहते यदि इसमें हमने कोई गौर नहीं किया तो निश्चित मानिये कि आने वाले वर्षों में सीकर शहर का पानी पीने योग्य नहीं रहेगा। यह एक बड़ी भारी समस्या बन रही है। आप पी.एच.ई.डी. मिनिस्टर भी हैं, आप लोकल सेल्फ मिनिस्टर भी हैं, कृपया इस पर खास तौर से गौर करवाएं और उसका सर्वे करवाएं कि सीकर में जो पानी की क्वालिटी का स्तर गिर रहा है उसको कैसे रोका जा सकता है?

श्री अध्यक्ष : कृपया बिराजें।

श्री राजेन्द्र पारीक : अध्यक्ष महोदय, दो मिनट और।

श्री अध्यक्ष : दो मिनट ? दो मिनट तो सारे ही दिये हैं आपको।

श्री राजेन्द्र पारीक : दो ही मिनट लूंगा, ज्यादा नही लूंगा। एक समस्या है तो एक ही मिनट लेता हूं।

अध्यक्ष महोदय, सीकर शहर की स्कीम बनी थी 1967 में, उसके बाद स्कीम री-आर्गेनाइज नहीं हुई। लगातार करीब दो साल से स्कीम सर्वे के लिए विभाग वाले पैसा मांग रहे हैं। सिर्फ ढाई लाख रुपये सर्वे के लिए नहीं दिये जा रहे हैं। सीकर की जो स्कीम है उसके सर्वे के लिए ढाई लाख रुपये दिलवाएं ताकि नयी स्कीम का सर्वे हो और वहां उच्च जलाशय बने ट्यूबवैल बने।

मैं आपको कुछ वहां की ... अब समय नहीं दिया अध्यक्ष महोदय, क्या बोल कर बताएं ?

श्री अध्यक्ष : प्लीज, प्लीज।

श्री राजेन्द्र पारीक : मैं तो यही निवेदन करता हूं कि आप अधिकारी स्तर पर और आप स्वयं बैठ कर सीकर शहर और ग्रामीण क्षेत्र की जो पेयजल की समस्याए हैं उन पर तत्परता से समाधान करें ताकि कुछ हो सके। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती कमला

श्रीमती कमला (बैराठ) : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय को बहुत चिंता के साथ और दुःख के साथ यह पूछना चाह रही हूं कि आपने अधिकारियों को, ठेकेदारों को लम्बी छूट दे रखी है क्या कि वे मर्जी आये जितने समय में योजनाओं को पूरा करें और मर्जी आये जितनी लम्बी उनकी अवधि डालते रहें ? पूरे पांच वर्ष, अध्यक्ष महोदय, होने को आ गये, 1994–95 में योजनाएं मंजूर हुई थीं, 1995-96 में योजनाएं मंजूर हुई थीं, 1996–97 में योजनाएं मंजूर हुई, लेकिन आज तक इनमें से एक योजना भी चालू नहीं हुई। आपके अधिकारियों से आप पूछिये कि आखिर यह क्या कारण है। अगर योजनाओं में काम होते-होते इतना समय हो गया तब तो कोई बात नहीं, लेकिन आप इस बात को सोचिये कि योजनाएं आप स्वीकृत

(38)

(श्रीमती कमला)

करते हैं उनका एक समय निर्धारित होना चाहिये कि इतने समय में वे योजनाएं पूरी हो जाएंगी। आज आपके ठेकेदार बहुत सारी योजनाओं के ठेके ले लेते हैं और पूरी उनसे वो भी होने वाली नहीं होती हैं। राजस्थान भर में, जिले भर में ठेका लेकर उन योजनाओं को लम्बा डालते रहते हैं आपकी प्राइस एस्केलेट होती है और लोगों को परेशानी होती है। आज मेरी एक भी योजना जो 1994–95 से आयी, और आखरी वक्त तक मंजूर हुई, पूरी नहीं हुई है, न चालू हुई है। कहीं पर बोरिंग करके छोड़ दिया है, कहीं पर टंकी बना कर छोड़ दी है। आप मनोहरपुर और शाहपुरा में उद्घाटन कर आये। आपके कार्यकर्ता आपको जल्दबाजी में इसलिए ले गये कि कहीं किसी और को लाभ न मिल जाए। न उस टंकी में पानी आया, न वह टंकी मेन लाइन से जुड़ी, न वार्ड की मेन लाइन से जुड़ी और जैसे ही उसमें पानी डालकर ट्रायल किया, दो-दो बार पाइप बर्स्ट हो गये। आज तक वे पाइप नीचे धरती पर पड़े हैं शाहपुरा और मनोहरपुर में और आपके नाम को बहुत जोर-जोर से बोल रहे हैं, जिन लोगों ने यह करवाया उनको बोल रहे हैं। इसलिए मेहरबानी करके इन योजनाओं का समय निर्धारण करिये कि स्वीकृति के बाद इतने समय में ये योजनाएं पूरी होनी चाहिये।

दूसरा मेरा यह निवेदन है, मंत्री महोदय, कि जितना भी राजस्थान का इलाका है उसमें एस. सी. के लोगों को पानी के मामले में सबसे ज्यादा दिक्कत होती है। चाहे हम कितने ही एडवांस हो गये, कितने ही समझदार और पढ़े-लिखे हो गये लेकिन आज भी छुआ-छूत की बीमारी मौजूद है। इसलिए चाहे आपकी ढाणियों में लगने वाले हैण्ड पम्प हों या और योजनाएं हों, उनके अन्दर एस. सी. की बस्तियों को निश्चित रूप से पानी देने की व्यवस्था करें, चाहे उनकी आबादी कम है या ज्यादा है।

दूसरा मेरा निवेदन है कि हैण्ड पम्प योजना में भारत सरकार आपको पैसा देती है, आपका उसमें कुछ नहीं लगता। लेकिन ठेकेदारों ने धांधली करके, कमीशनबाजी करके अधर हैण्ड पम्पों को लगा दिया, जो 6 महीने के अन्दर बर्बाद हो जाते हैं और रिपेयर के लिए उसका कोई इंतजाम नहीं होता। यहां तक कि मजूरशुदा जो हैण्ड पम्प होते हैं वे भी दो-दो, चार-चार महीने तक लगते नहीं हैं और जो रिडन्डेंट हो जाते हैं उनको रिप्लेस करने की भी कोई व्यवस्था नहीं होती। रिपेयर का तो इतना बुरा हाल है कि पंचायत समिति कहती है हमारे बस की बात नहीं, पंचायत कहती है हमारे बस की बात नहीं, विभाग कहता है हम अभियान चलाएंगे, एक वक्त में तब आपके जो ठीक हो जाएगा वह हो जाएगा। सुबह तो ठीक करके आये और तीसरे दिन कह दिया वे तो खराब पड़े हैं यह। धन का दुरुपयोग हो रहा है, जनता को परेशानी हो रही है और आपके विभाग की बदनामी हो रही है। मेहरबानी करके इसके ऊपर आप गौर करिये, इसको देखिये कि यह क्यों नहीं हो रहा है।

(श्रीमती कमला)

साथ ही एक निवेदन और करना चाहती हूं, आप पानी देना चाहते हैं लेकिन राजस्थान की धरती पर पड़ने वाली एक-एक बूंद को जब तक आप एकत्रित करने का भी काम साथ में नहीं करेंगे तब तक, यह समय आने वाला है कि आप पानी के लिए तरसेंगे। इसलिए बहकर जाने वाले पानी को रोकने के लिए एनीकट बनाकर, बाढ़ बचाओ कार्यों को हाथ में लेकर पानी का ज्यादा से ज्यादा धरती के अन्दर रिसाव करने की भी व्यवस्था करिये।

साथ में अन्त में एक यह निवेदन करना चाहता हूं कि आज-कल जो पानी का उपयोग है, चाहे आप उसको हंसी माने या उस पर मजाक करें, लेकिन मैं कहना चाह रही हूं कि आज जो टंकियां घरों के अन्दर लगी हुई हैं फ्लश की, आप फ्लश की टंकियों को बन्द करवाइये और मरोड़ी देकर जो पानी खोला जाता है उसकी इजाजत दीजिये। साथ में जो आपका नल होता है वह भी अपने आप बन्द हो जाएं, ऐसे नल लगाइये जिससे आपका पानी बचे। एक बार आप फ्लश की टंकी खोलते हैं, टंकी की टंकी पानी जाता है, कितनी पानी की बर्बादी हो रही है। ये छोटे-छोटे मुद्दे ऐसे हैं जिनको हम मजाक की बात कह सकते हैं लेकिन आने वाला समय इतना गम्भीर है कि हमें इस पर चिन्ता करने की जरूरत है।

मैं आपसे यह भी कहना चाह रही हूं कि आज पानी प्रदूषित होता जा रहा है, मेहरबानी करके इसको बहुत गम्भीरता से लीजिये। आज जितना पानी नीचे जा रहा है वह भी जगह-जगह चाहे उद्योगों के कारण से और चाहे लोगों के गलत कामों के कारण से प्रदूषित हो रहा है और जगह-जगह समस्या खड़ी हो रही है, इसलिए मेहरबानी करके इसके ऊपर भी ज्यादा से ज्यादा ध्यान दीजिये। धन्यवाद।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री महावीर प्रसाद जैन (सरकारी मुख्य सचेतक) : अध्यक्ष महोदय, मुखबन्द का समय 5.30 बजे तक बढ़ाया जाए।

श्री अध्यक्ष : नहीं। 5.00 बजे तक।

श्री महावीर प्रसाद जैन : मंत्रीजी के जवाब तक सदन का समय बढ़ाया जाए।

श्री अध्यक्ष : हां, यह ठीक है।

सदन की सहमति से मंत्रीजी के जवाब तक सदन का समय बढ़ाया गया। माननीय सदस्य, एक मिनट में अपनी बात कहें।

मांग संख्या 27 पर विचार

श्री श्रवण कुमार (पिलानी) : पहले तो मैं मंत्रीजी को धन्यवाद दूंगा जो हवा के बाद पानी जैसे महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट के मंत्री हैं, सहनशील और कार्य में मादा रखने वाले हैं। मैं तो एक सुझाव देना चाहता हूं कि राजस्थान में पानी की व्यव-

(श्री श्रवण कुमार)

क्या तब तक ठीक नहीं होगी जब तक कि असैसमैंट इनका सही नहीं होगा। आज राजस्थान में बजट की कोई कमी नहीं है —

सदन की कार्यवाही

मुखबन्द के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, एक मिनट। माननीय मंत्री महोदय का जवाब आने तक मुखबन्द का समय भी बढ़ाया जाता है।

आधा मिनट खर्च हो गया आपका।

मांग संख्या 27 पर विचार

श्री श्रवण कुमार : पानी की व्यवस्था तभी सही हो सकती है जब इनका असैसमैंट सही होगा। आज स्कीम्स दो-दो, तीन-तीन साल से मंजूरशुदा पड़ी हुई हैं, उनका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है। जब तक व्यवस्था सही नहीं होगी वे सुचारू रूप से चालू नहीं होंगी। मंत्रीजी को दुबारा धन्यवाद देना चाहता हूं कि इन्होंने चिड़ावा की एक करोड़ तैंतीस लाख रुपये की स्कीम मंजूर की, लेकिन आज कुछ स्कीम्स ऐसी हैं जो मंजूरशुदा पड़ी हैं, वे चालू नहीं हो रही हैं। आज इनकी खरीद-फरोख्त की जो व्यवस्था है वह सही नहीं है, जैसे हमारे यहां मोटर, पाइप, केबिल वगैरह खरीदते हैं वह चीजें घटिया स्तर की खरीदते हैं जो जल्दी नष्ट हो जाती हैं। आज हम डबल एम्पीयर की जो मशीनें खरीद रहे हैं ये हमारे राजस्थान में सफल नहीं हैं, सही व्यवस्था से पानी नहीं दे सकती हैं। पाइप लगाते हैं और फट जाते हैं इसलिए मैं चाहूंगा कि पाइप खरीदने, मोटर खरीदने, केबिल वगैरह खरीदने और स्विच रूम वगैरह खरीदने की जो व्यवस्था है वह व्यवस्था सुधारें।

नम्बर दो, जो ठेकेदारी प्रथा है वह सही नहीं है। आज ठेकेदार जो कुंआ खोदते हैं, 12 महीने बाद उसको दुबारा खोदना पड़ता है, दूसरी साल पानी का स्तर नीचे चला जाता है। तो वह व्यवस्था सही नहीं बैठती। आज आप राजस्थान में देख लीजिए। एक बार कुंआ खुदवाते हैं दूसरे वर्ष उसी कुंए को दुबारा खुदवाना पड़ता है। जब तक चीफ इंजीनियर, एक्स. ईएन., ए. ईएन और जे. ईएन. इस व्यवस्था को ठीक नहीं रखेंगे और उन कुंओं में सही असैसमैंट नहीं करवाएंगे तब तक व्यवस्था यही रहेगी। माननीय मंत्रीजी की जो व्यवस्था है उसके लिए मैं इनको धन्यवाद दूंगा, वह सुचारू रूप से है लेकिन यहां की मशीनरी सही काम नहीं कर रही है। आज कुछ स्कीम्स ऐसी हैं मेरे क्षेत्र में जो तीन-तीन और पांच-पांच साल से स्वीकृत पड़ी हैं, लेकिन आज तक उनका काम नहीं हुआ है। मैं मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि उन स्कीम्स को शुरू करवाएं। छोटी-छोटी व्यवस्थाओं के लिए वे स्कीम्स बन्द पड़ी हैं। केबिल के लिए पांच लाख रुपये की स्कीम बन्द पड़ी है, छोटे-से 200 मीटर पाइप लाइन के लिए स्कीम बन्द पड़ी है। पांच लाख रुपये लगने के बावजूद 200 मीटर पाइप के लिए स्कीम बन्द पड़ी है, इससे बड़ा और दुर्भाग्य क्या हो

(श्री श्रवण कुमार)

सकता है। पहले मंत्रीजी ने एक बात कही थी कि गांवों के अन्दर 700 रुपये डेली वेजेज पर आदमी रखेंगे जो पंचायत रखेगी और उसका पेमेन्ट पी.एच.ई.डी. करेगा। आज तक वह व्यवस्था नहीं की गयी है। जब तक आप अपने हाथ में व्यवस्था नहीं लेंगे तब तक सुचारू रूप से पानी की व्यवस्था नहीं हो सकती। मैं सुझाव देना चाहता हूं कि खरीद-फरोख्त की व्यवस्था है इसकी मशीनरी में जग लगी हुई है, उसमें थोड़ा ग्रीसिंग करें और व्यवस्था को सही करें। यही मेरा निवेदन है, धन्यवाद।

समिति का प्रतिवेदन

कार्य सलाहकार समिति का 30वां प्रतिवेदन

श्री अध्यक्ष : श्री महावीर प्रसाद जैन, सरकारी मुख्य सचेतक कार्य सलाहकार समिति के 30वें प्रतिवेदन का उपस्थापन करेंगे। वे यह भी प्रस्ताव करेंगे कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के 30वें प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है।

श्री महावीर प्रसाद जैन (सरकारी मुख्य सचेतक) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कार्य सलाहकार समिति के 30वें प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं।

कार्य सलाहकार समिति का तीसवां प्रतिवेदन।

कार्य सलाहकार समिति की बैठक माननीय अध्यक्ष के चैम्बर में दिनांक 20 जुलाई, 1998 को मध्याह्न पश्चात् 3.00 बजे हुई। समिति दिनांक 30 जुलाई, 1998 से 4 अगस्त, 1998 तक सदन में लिये जाने वाले कार्य के बारे में विचार-विमर्श कर सिफारिश करती है कि समय का बंटवारा निम्न प्रकार किया जाए :–

गुरुवार, दिनांक 30 जुलाई, 1998 शुक्रवार, दिनांक 31 जुलाई, 1998 सोमवार, दिनांक 3 अगस्त, 1998 मंगलवार, दिनांक 4 अगस्त, 1998	1. राजस्थान स्टाम्प विधेयक, 1998; 2. राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय विधेयक, 1998; 3. राजस्थान आवासन बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 1998 (1998 के अध्यादेश संख्या 1 को प्रतिस्थापित करने हेतु); 4. राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम सीमा अधिरोपण (संशोधन) विधेयक, 1998 (1998 के अध्यादेश संख्या 2 को प्रतिस्थापित करने हेतु);

(श्री महावीर प्रसाद जैन)

5. राजस्थान मोटरयान कराधान (संशोधन) विधेयक, 1998, एवं

6. राजस्थान स्थानीय क्षेत्रों में माल के प्रवेश पर कर विधेयक, 1998 पर विचार एवं पारण ।

समिति की जानकारी में यह लाये जाने पर कि क्रम संख्या 1, 2, 5 और 6 पर अंकित विधेयक अभी प्राप्त नहीं हुए हैं, समिति इनके सम्बन्ध में यह सिफारिश करती है कि इन विधेयकों के प्राप्त होने पर विचार एव पारण की कार्यवाही की जाए ।

शनिवार, दिनांक 1 अगस्त, 1998 रविवार, दिनांक 2 अगस्त, 1998	बैठक नहीं होगी ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के 30वें प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के 30वें प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है ?

(स्वीकृत)

सदन द्वारा प्रतिवेदन पर सहमति प्रदान की गयी ।

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : आर.एस.ई.बी. की रिपोर्ट पर डिस्कशन होगा, आपने एश्योर किया था । (व्यवधान)

श्री परसादीलाल मीणा : आपने आश्वस्त किया था बिजली पर बहस रखेंगे, बिजली वाली बात तो आयी ही नहीं । आपने आश्वासन दिया था....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप चार-चार बोल रहे हैं । चार-चार बोल रहे हैं ।

श्री परसादीलाल मीणा : आपने हाउस को यह आश्वासन दिया था जब बिजली का मामला उठाया था कि बिजली पर बहस कराएंगे । बिजली की कहीं बात नहीं आयी । अभी भी कोई तारीख तय करेंगे, अध्यक्ष महोदय ?

श्री अध्यक्ष : सुनिये-सुनिये ।

श्री महावीर प्रसाद जैन : अध्यक्ष महोदय, 29 तारीख को बिजली मंत्रीजी का वक्तव्य होगा और उस पर चर्चा होगी ।

श्री अध्यक्ष : चर्चा भी होगी।

श्री महावीर प्रसाद जैन : इसमें संशोधन की जरूरत नहीं है।

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय।

मांग संख्या 27 पर विचार

श्री राजेन्द्र गहलोत : राज्य मंत्री, (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी) अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे अनुमति चाहूंगा कि स्थान बदलकर इस स्थान से बोल रहा हूं, इसकी अनुमति दें।

श्री अध्यक्ष : यह मंत्री परिषद् की सीट है, कहीं से भी बोल सकते हो आप।

श्री राजेन्द्र गहलोत : माननीय अध्यक्ष महोदय, आज सदन में पेयजल समस्या और उसके समाधान के लिये चर्चा हुई। अधिकांश सदस्यों द्वारा महत्वपूर्ण विचार इस सदन से रखे गये जो समस्या के समाधान के लिये उपयुक्त हैं।

मैं सिर्फ पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्र में पिछले कई वर्षों से

श्री चन्दनमल बैद : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक छोटी-सी जानकारी चाहता हूं, क्या राज्य मंत्रीजी ही जवाब देंगे ? मंत्री महोदय नहीं बोलेंगे क्या ?

श्री भंवरलाल शर्मा (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री) : बोलूंगा। आप आए हैं तो जरूर बोलूंगा।

श्री राजेन्द्र गहलोत : पश्चिमी राजस्थान में जहां रेगिस्तानी क्षेत्र है, जहां की जलवायु इस प्रकार की है, जहां लोग बूंद-बूंद पानी के लिये तरसा करते थे, आज स्थिति बिलकुल विपरीत है। आजादी के बाद राजस्थान नहर बनी और राजस्थान नहर मे कई शहर और गांव पेयजल के लिये जोड़े गये। जोधपुर राजस्थान का जयपुर के बाद सबसे बड़ा नगर है, जोधपुर के लोग कभी सोचा करते थे कि क्या जोधपुर में पानी की समस्या का समाधान होगा, क्या 538 साल पूर्व चिड़ियानाथजी ने जो श्राप दिया है उससे जोधपुर की मुक्ति होगी। जब भी जनवरी, फरवरी का माह आता लोग यह सोचते कि जोधपुर में पानी की व्यवस्था कहां से करें, आस-पास में कोई ऐसा स्थान नहीं। कुछ स्थान ऐसे थे जहां के किसानों का पानी देकर जोधपुर की जनता को पानी पिलाना पड़ा। चाहे वह मथानिया बाल बड़ा हो, चाहे पाल हो, चाहे रणसी हो, इन सबका पानी जोधपुर में लाना पड़ा। फिर भी जोधपुर का उससे कोई समाधान नहीं निकला....

श्री रामस्वरूप मीणा : जोधपुर की ही कहोगे ? मंत्री सारे राजस्थान के हो।

श्री अध्यक्ष : कृपया। जोधपुर भी राजस्थान में है।

श्री राजेन्द्र गहलोत : माननीय अध्यक्ष महोदय, 1984 में जब जोधपुर के लिये पानी योजना बनी, उस समय जोधपुर की जनता को तात्कालिक सरकार ने एक सपना दिखाया कि 1985-86 के अन्दर हम जोधपुर में पानी लेकर आ जाएंगे। 1984 के

(श्री राजेन्द्र गहलोत)

अन्दर 38.50 करोड़ की योजना जोधपुर के लिये बनी कि जोधपुर में राजस्थान नहर का पानी पहुंचाया जाए। उसका उद्घाटन उस समय के मुख्य मंत्री माननीय श्री शिवचरणजी माथुर ने किया और 1985 में जब हरिदेव जी जोशी मुख्य मंत्री बने तो उन्होंने एक बार और शिलान्यास कर दिया। दो-दो शिलान्यास हो गये, दोनों शिलान्यास होने के बाद 20 लाख रुपये की स्वीकृति उस समय मिली। जोधपुर की नहर योजना का कार्य प्रारम्भ हुआ और दूसरे शिलान्यास में 2 करोड़ 81 लाख रुपये का जोधपुर के लिये प्रावधान रखा गया।

माननीय अध्यक्ष महोदय, कई माननीय सदस्यों ने कह दिया कि पानी की राजनीति चल रही है। यदि यह सवाल यहां उत्पन्न नहीं होता तो मैं भी आज यहां खड़े होकर अपने विचार आपके समक्ष नहीं रखता। मैं सदन को इस बात से अवगत कराना चाहूंगा 1984 में जो योजना प्रारम्भ हुई, 1990 तक उसमें मात्र 20 करोड़ 72 लाख रुपये खर्च हुए। इस योजना के छह वर्षों के अन्दर कई मंत्री आ गये और एक मंत्री ने तो यहां तक कह दिया था कि 1986 में जोधपुर में पानी नहीं पहुंचेगा तो मैं त्यागपत्र दे दूंगा। उसके बाद सदन में यह कहा गया कि प्रधान मंत्री कार्यालय से इसकी मानीटरिंग हो रही है इसलिये जोधपुर में पानी जल्दी पहुच जाएगा। यह बात बार-बार कही गयी। उसके बाद जोधपुर की जनता को माननीय मुख्य मंत्री भैरोंसिंहजी का आशीर्वाद मिला, भंवर लालजी शर्मा का आशीर्वाद मिला। उसके बाद सारे निर्णय थे कि जोधपुर में पानी पहुंचे, किस प्रकार पानी पहुंचे और समय पर योजना पूरी हो उसके लिये किस प्रकार से काम किया जाए। 1984 के अन्दर जो किसानों की भूमि आ रही थी उसका कम्पनसेशन हमें देना था, वह कम्पनसेशन उस समय नहीं दिया गया था। पाइप लाइन का निर्णय नहीं किया गया था, पम्प हाउसों का निर्णय नहीं किया गया था। सारे निर्णय करने के बाद आज तक 231 करोड़ 92 लाख उस योजना में खर्च हुए हैं। एक शहर में पानी लाने के लिये नहर पर 231 करोड़ रुपये उस समय खर्च किये गये। माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार की यह नीयत थी। लम्बे समय से समस्या है, सोचा नहीं जा सकता जोधपुर शहर को पीने का पानी मिल सकता है, उस नहर से जोधपुर की जनता को पीने का पानी मिला है। मैंने माननीय मुख्य मंत्रीजी और माननीय जलदाय मंत्रीजी से यह निवेदन किया कि आपने जोधपुर पानी पहुंचा दिया है, लेकिन जोधपुर मे घरों में पानी पहुचे, मटकी में पानी पहुंचे, जोधपुर के लोगों की प्यास बुझे, इसके लिये आप क्या व्यवस्था कर रहे है ? तो, मैं माननीय मंत्रीजी को जोधपुर की जनता की ओर से धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने इस योजना के लिये 28 करोड़ रुपये स्वीकृत किये। मैंने कहा यह कम पड़ेगा तो हुडको योजना से 11 करोड़ रुपये... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कृपया व्यवधान नहीं, माननीय सदस्य। माननीय मंत्री महोदय ने

(श्री अध्यक्ष)

आपको सुना है, बड़े ध्यान से सुना है। आपने जो कुछ भी बोला उसमें व्यवधान नहीं डाला, फिर आप क्यों व्यवधान डाल रहे हैं ?

श्री हीरालाल इन्दौरा : आप तो सिवाय जोधपुर के कोई बात नहीं कर रहे है....

श्री अध्यक्ष : मुझे विवश होकर यह आदेश देना पड़ेगा कि व्यवधान अंकित न हो, विवश होकर। कृपया नहीं, बीच में नहीं बोलेंगे आप।

श्री राजेन्द्र गहलोत : 11 करोड़ रुपये योजना बनाने के लिये हुडको से स्वीकृत किये है। आज मैं सदन से निवेदन करूंगा कि 99 परसेंट योजना का काम जोधपुर में पूरा हो चुका है समय पर। वोट आधारित जो काम की बात करते हैं उनसे मैं यह कहना चाहूंगा कि जिनकी इच्छा शक्ति है, राजनैतिक जिनकी इच्छा शक्ति है, जनता के बीच काम करने की इच्छा शक्ति है, वे लोग अपना काम पूरा करवा लेते हैं, काम पूरा कराने के लिये उसमें लगे रहते हैं।

जोधपुर में फिल्टर हाउस 1938 में बना, 1956 में बना और 1975 में बना, लेकिन उसके बाद जोधपुर में खुद पानी मिल जाये इसके बारे में किसी ने कोई चिन्ता नहीं की। लेकिन उसके बाद तीन फिल्टर हाउस इन पांच वर्षों के अन्दर बनाये गये। कायलाना में एक फिल्टर हाउस बनाया गया, झारामन में दो फिल्टर हाउस बनाये गये और उससे चार लाख गैलन रोज की जो जोधपुर की जनता को पानी की मांग है, उस मांग की पूर्ति करने के लिये सारी व्यवस्था की गयी। अध्यक्ष महोदय, उसके साथ-साथ जोधपुर की बस्तियों में पानी पहुंचाया गया, लोगों के घरों तक पहुंच गया इसलिए धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्री महोदय, आप अपनी बात कहें, तालाबों का जवाब नहीं दें, मेरा यह निवेदन है।

श्री राजेन्द्र गहलोत : माननीय अध्यक्ष महोदय, विभिन्न सौ बस्तियों के अन्दर 234 किलोमीटर नई पाइप लाइन बिछायी गयी और जोधपुर के अन्दर 14 जलाशय बनाये गये ताकि जोधपुर में अच्छा प्रेशर होकर पानी मिले। जोधपुर की जनता का जो उपकार किया है ...

श्री रामस्वरूप मीणा : राजस्थान के मंत्री हो। मजाक बना रखी है यहां पर। हम बेकार ही पुकार रहे हैं ? आप एक भी जवाब नहीं दे रहे हैं। सिवाय जोधपुर के कहीं की बात ही नहीं कर रहे हैं।

श्री राजेन्द्र गहलोत : .... और जो व्यवस्था की गयी है उसके लिए माननीय जलदाय मंत्री जी को मैं धन्यवाद देता हूं।

श्री रामस्वरूप मीणा : ये मंत्री हैं कि एम. एल. ए. हैं ?

(146)

श्री हीरालाल इन्दोरा : ये मंत्री की हैसियत से बात कर रहे हैं ? इनका वक्तव्य उस हैसियत से है ?

श्री रामस्वरूप मीणा : वही जोधपुर की बात....

श्री हीरालाल इन्दोरा : आप सदस्य की हैसियत से बोल रहे हो क्या ?

श्री रामस्वरूप मीणा : यह करौली जिला, सवाईमाधोपुर जिला सब बेकार हैं यहां ?

श्री राजेन्द्र गहलोत : माननीय अध्यक्ष महोदय, पश्चिमी राजस्थान के और जिलों के अन्दर जो बजट 1990 के पहले था उसके आंकड़े आप देखेंगे....

श्री बनवारी लाल बैरवा : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह इंटरवीन जोधपुर के लिए हो रहा है ? केवल जोधपुर के लिए इंटरवेंशन हो रही है क्या यह ?

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्री महोदय, शेष राजस्थान का जवाब देंगे, आप तसल्ली रखें।

श्री राजेन्द्र गहलोत : पश्चिमी राजस्थान में चाहे जैसलमेर हो, बाड़मेर हो लोगों को यह लगता था कि वहां पीने का पानी उपलब्ध नहीं होगा। आज वहां भी पानी उपलब्ध हो रहा है। राजस्थान सरकार ने पिछले 8 वर्षों में पेयजल के समाधान के लिए जो संकल्प किया है, जो भागीरथी प्रयास किया है उससे पश्चिमी राजस्थान और राजस्थान के कई क्षेत्रों में जल समस्या का समाधान हुआ है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने समय दिया उसके लिए धन्यवाद।

श्री राजेन्द्र चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी बार-बार जोधपुर में पानी की बात कर रहे हैं, मैं यह पूछना चाहता हूं मंत्री महोदय को ....

श्री अध्यक्ष : कृपया बाद में पूछना।

श्री राजेन्द्र चौधरी : .... आप जिस जगह रहते हैं....

श्री अध्यक्ष : अभी जवाब नहीं मिलेगा। श्री राजेन्द्र जी चौधरी साहब, अभी उसका उत्तर नहीं मिलेगा। थोड़ी वेट करिये, धैर्य रखें, कृपया। दे रहे हैं। मैंने यह निवेदन किया जिसको कुछ पूछना हो वह बाद में पूछ लेना। तो फिर बिराज जाएं। बिराजें।

एक माननीय सदस्य : मंत्री राजस्थान के नहीं हैं ?

श्री अध्यक्ष : कृपया बिराजें।

श्री भंवरलाल शर्मा (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति हो तो मैं अपने विचार रखूं। यह बात सही है कि मनुष्य के जीवन के लिए जिन तत्वों की आवश्यकता है उनमें प्रथम हवा है और दूसरा पानी है। हवा पर अभी तक किसी का कोई नियंत्रण

(श्री भंवरलाल शर्मा)

नहीं है। भगवान जिसको जितनी आवश्यकता है हवा देता है। पोल्यूशन करते हैं वह अलग बात है पर नियंत्रण किसी का नहीं है। वह देता है सबको बिना किसी भेदभाव के। न बंद जी में फर्क करता है न डाक्टर साहब में फर्क करता है। न पुरुष में करता है, न महिला में करता है। जितनी आवश्यकता है देता है, कहीं भी नहीं करता है।

पानी भी देता तो भगवान ही है लेकिन उसको लाना पड़ता है, उसके लिए प्रयत्न करना पड़ता है। कहीं कुंए खोदने पड़ते हैं, कहीं स्कीम बनानी पड़ती है, कहीं कुछ करना पड़ता है और उसे मनुष्य प्राप्त करता है। मेरा जो विभाग है उसका यही काम है क्योंकि जो जल है वह केवल मनुष्य के लिए ही नहीं है, प्राणी मात्र के लिए आवश्यक है, वनस्पति के लिए भी आवश्यक है। लेकिन हमारा विभाग प्राणी मात्र की चिन्ता करता है और उसके लिए व्यवस्था करता है।

मैं यह कहना नहीं चाहता कि राजस्थान में जितनी भी सरकारें रही उन्होंने पेयजल के बारे में कोई काम नहीं किया। यह संभव भी नहीं था कि कोई काम नहीं करें। यह संभव नहीं है। यह हो सकता है कि कोई कम करे कोई ज्यादा करे, कोई देर से करे कोई जल्दी करे, कोई फुर्ती से करे, कोई लम्बे समय तक करता रहे लेकिन करते सब हैं। मेरा यह कहने का मतलब नहीं है कि हमारे पूर्व जो सरकार थी उसने कोई काम नहीं किया। जरूर काम किया है लेकिन काम....

श्री राजेन्द्र चौधरी : सुजान सिंह जी तो ऐसा नहीं मानते हैं।

श्री अध्यक्ष : यह अलग से सवाल है।

श्री भंवरलाल शर्मा : वे उनके विभाग की बात कहते हैं, मैं मेरे विभाग की बात कर रहा हूं। इस विभाग में अगर काम नहीं होता तो अपन जिन्दा ही नहीं रहते, इसलिए काम तो निश्चित रूप से हुआ है। लेकिन यह विचार करना पड़ेगा कि आजादी के 50 साल बाद में जिस प्रकार की उपलब्धि प्राप्त करनी चाहिए वह कर पाये क्या। यदि कर ली होती तो आज सुबह 11 बजे से 5 बजे तक अपन बातचीत नहीं करते और आप कहते, बहुत आनन्द है, भगवान राजी है, काहे को टाइम खराब करते हो। पर हर माननीय सदस्य ने इस समस्या के बारे में चिन्ता की है। और चिन्ता का एक कारण और है, अब हमको चुनाव में जाना है तो जनता में भी जवाब देना पड़ेगा। जनता की समस्याओं के समाधान की जिम्मेदारी हम लोगों की है इसलिए ऐसी संवेदनशीलता, सहानुभूति थोड़ी अधिक भी होती है। इसलिए ये सारे प्रश्न खड़े हुए हैं। आज करीब-करीब 30-35 माननीय सदस्यों ने भाग लिया है। मैं बहुत प्रसन्न हूं, आभारी हूं कि जो चर्चा यहां हुई है, एक-आध को छोड़कर बाकी सबने बड़े ही शुद्ध मन से समस्या के सही समाधान के लिए सार्थक चर्चा की है, निर्देश दिये हैं। थोड़ी देर में अपने आप चल जाएगा।

श्री अध्यक्ष : शुद्ध मन का। विराजें, विराजें।

श्री जगदीप धनखड़ : सर, पाइंट आफ आर्डर।.... आप मेरे पाइंट आफ आर्डर को रिजैक्ट कर दीजिये।

श्री भंवरलाल शर्मा : यह काहे का पाइंट आफ आर्डर है ?

श्री जगदीप धनखड़ : माननीय मंत्री महोदय ने यह कहा है कि एक या दो सदस्यों को छोड़कर....

श्री भंवरलाल शर्मा : यह क्या मतलब हुआ ?

श्री महावीर प्रसाद जैन : अध्यक्ष महोदय, पाइंट आफ आर्डर किसी विषय के समाप्त होने और दूसरा विषय शुरू होने पर आता है। क्योंकि आप बहुत विद्वान हैं इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि पाइंट आफ आर्डर आप तो उठा ही नहीं सकते हो।

श्री जगदीप धनखड़ : मेरे पास महावीर जी का कोई जवाब नहीं है। मैं माननीय मंत्री महोदय से जो रीजनेबल आदमी हैं, जो अपने दिल से बात कर रहे हैं

श्री महावीर प्रसाद जैन : आप कहें तो व्यवस्था पढ़कर सुना दूं।

श्री जगदीप धनखड़ : उनसे हम इतना जानना चाहते हैं कि वे दो सदस्य कौन हैं जो आपकी दृष्टि में सही मन से, शुद्ध मन से विचार व्यक्त नहीं कर रहे थे, क्योंकि जो भी सदस्य यहां शुद्ध मन से विचार व्यक्त नहीं करता है वह सदन का अनादर करता है। यदि आप इसमें कुछ बताने में असमर्थ हैं तो आपको खेद प्रकट करना चाहिए।

श्री भंवरलाल शर्मा : आप जो बात कहना चाहते हो, जिधर इंगित करना चाहते हो, जिधर आप इशारा कर रहे हैं मैं आपके चक्कर में आने वाला नहीं हूं।

श्री जगदीप धनखड़ : नहीं, आपके दल में कई लोग हैं जिनके मन शुद्ध नहीं हैं। दो से ज्यादा संख्या है।

श्री भंवरलाल शर्मा : मैंने शुद्ध नहीं कहा है।

श्री जगदीप धनखड़ : आप पर आक्रमण भी किये होंगे। आप उनके नाम क्यों नहीं बताते हैं ?

श्री भंवरलाल शर्मा : मैंने शुद्ध नहीं कहा है...

श्री अध्यक्ष : अब आपका पाइंट आफ आर्डर आपने ही रिजैक्ट कर लिया। विराजें।

श्री भंवरलाल शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, जितने माननीय सदस्यों ने अपने विचार रखे, मेरे लिए वे मार्गदर्शक रहेंगे। उन कामों में गति लाएंगे जो बातें मेरी जानकारी में नहीं थीं। यदि जानकारी में होतीं तो शायद उनमें गति आ सकती थी। तो मुझे चर्चा का यह लाभ तो हो ही गया। आपने सुझाव दिये हैं, राय बताई,

(श्री भंवरलाल शर्मा)

समस्याएं भी बतायीं और उपाय भी बताये हैं, मैं निश्चित रूप से उस पर काम करूंगा। इसी प्रकार से जो कटमोशन आये हैं उनकी संख्या 219 है, विषय उनका मैंने वर्गीकरण किया है कि कटमोशन में विषय क्या रहे हैं। तो 19 कटमोशन तो इस बात के थे, माननीय सदस्यों ने कहा कि हमारी जो योजनाएं हैं इनको स्वीकृत कर दें। जो काम स्वीकृत होने थे उन योजनाओं का नम्बर 19 है। इसी प्रकार योजना स्वीकृत तो हो गयी लेकिन गति संतोषप्रद नहीं है; उनके लिए जो कटमोशन दिये हैं उनकी संख्या केवल 5 है। जिन्होंने या तो हैण्ड पम्प की मांग की है या हैण्ड पम्प खराब हो गये हैं उनके रिप्लेसमैंट के लिए कहा है या ठीक करने के लिए कहा है, ऐसे कटमोशन की संख्या 22 है। फ्लोराइड वाले क्षेत्रों की समस्या के बारे में चिंता व्यक्त की है और कट मोशन आए हैं उनकी संख्या है 10। पाइप लाइन व टंकी जर्जर हो गई, उसको बदला जाए, नई डाली जाए, उसके लिए कट मोशन आए हैं 12। जो स्कीम स्वीकृत हो गई हैं उनका काम जल्दी चालू किया जाए, उसके लिए 12 कट मोशन आए हैं। इस तरह जो कट मोशन आए हैं उनकी संख्या है 180 और कुल आए हैं 219, तो 39 कट मोशन ऐसे हैं जिनका विषय मैंने बताया उनसे अलग है। इन कट मोशन को मैं अपने विभाग का प्रगति विवरण मानता हूं : यानि 219 तो ऐसे हैं जो सब काम हो गए हैं, 180 कट मोशन ऐसे हैं जो केवल काम हो गया, चल रहा है और जिनको करना चाहिए, बाकी 39 हैं वे विभिन्न प्रकार के हैं। कहीं तो सुझाव ही नहीं आया और आपने बड़ी गड़बड़ की है, आपने पानी नहीं पहुंचाया, ऐसे हैं : ये 180 कट मोशन आएं हैं। यह इस बात को प्रकट करता है कि विभाग ने अपने पांच साल के अर्से में संतोषप्रद काम किया है और माननीय सदस्यों को कोई अधिक शिकायत नहीं हुई है।

श्री अध्यक्ष : कट मोशन सबसे ज्यादा आये हैं।

श्री भंवरलाल शर्मा : हां, वह आते ही। एक हैण्ड पम्प ही नहीं लगता है तो कट मोशन आ जाता है....(व्यवधान).... आप सहमत नहीं हैं मेरी टिप्पणी है, आपकी मर्जी है, आप मत होइये। आप तो मेरी किसी बात को स्वीकार करने को तैयार ही नहीं होंगी। खैर, किसी बात की तो तारीफ करें मेरी, एक बार तो तारीफ कर देना. (व्यवधान)....

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर) : माननीय मंत्रीजी, एक हैण्ड पम्प वाले ने कट मोशन दे दिया लेकिन हमने बांका पट्टी का कट मोशन नहीं दिया, उसका भी ध्यान रखें।

श्री भंवरलाल शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं इसका सम्मान करता हूं लेकिन मेरे समझने के लिए जो बात है, अध्ययन करने की बात है, इसे मुझे इन्फरेंस करना चाहिए। मैं यह मानता हूं कि विभाग ने पिछले चार साढ़े चार साल में जो काम किया वह बहुत अधिक किया और आज राजस्थान में पानी की समस्या अधिक नहीं है। वैसे विकास का तो कभी अंत होता नहीं।

(श्री भंवरलाल शर्मा)

अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात और कहना चाहता हूं, आज से 50 साल पहले, 60 साल पहले कभी ऐसा लगता था क्या कि पानी की इतनी समस्या कल खड़ी हो जाएगी गांव–गांव में ? जहां हम खेती करते थे, खेती के लिए पानी होता था, जानवरों को पिलाने के लिए पानी होता था, पानी बहुतायत में होता था, वहां पीने का पानी नहीं रहेगा, ऐसा अंदाजा किसी ने नहीं किया, एंटीसिपेट नहीं किया था और अब यह सारी प्राकृतिक आपदा आ गई। हमारा जो राजस्थान है उसकी भौगोलिक स्थिति, हमारे लोगों की मानसिकता और हमारी प्राकृतिक स्थिति, इसने भी समस्या को थोड़ा गम्भीर बनाया हुआ है। हमारा अधिकतर पानी जमीन से निकलता है और जमीन में जितना पानी है उससे अधिक स्रोतों से पानी निकालते जाते हैं। आजकल तो एक समस्या और हो गई कि हमने ट्यूब वैल बना दिए। ट्यूब वैल कभी सफल होते हैं, कभी नहीं होते हैं लेकिन जो सफल हो जाते हैं उसके बाद उसके आसपास के रहने वाले काश्तकार, हमारे नागरिक दूसरा ट्यूब वैल वहां बना देते हैं थोड़ी दूर, अधिक गहरा। दूसरा ट्यूब वैल बना देते हैं इसलिए हमारे ट्यूब वैल की क्षमता कम हो जाती है। वह तो एक है ही लेकिन इतने ट्यूब वैल से इतने पानी का दोहन होगा, पानी का रिसाव है उसका डीप्लीट कम होता रहता है और धीरे-धीरे हमारे जो ट्यूब वैल हम चलाते हैं उनका पानी कम होने लगता है और हमको नई व्यवस्था करनी पड़ती है। तो यह समस्या इतनी आसान नहीं है। हमारे यहाँ जो पुरानी योजनाएं बनीं दूर–दूर तक पानी ले जाने के लिए, वे बिजली पर आधारित थीं बिजली 18 घण्टे मिलेगी, यह मानकर। उस समय लोगों ने शायद ठीक समझा होगा कि 18 घण्टे बिजली मिलेगी। 20 घण्टे नहीं तो 18 घण्टे तो मिलेगी, ऐसी धारणा मानकर ऐसी लम्बी-लम्बी योजनाएं बना दीं। अब हम जानते हैं कि 18 घण्टे बिजली नहीं मिलती है। अगर 18 घंटे बिजली नहीं मिलती है तो टेल एण्ड का गांव है, उसको पानी किस तरह से पहुंचेगा, यह समस्या है। आपका राज आए चाहे मेरा राज हो, चाहे मैं मंत्री रहूं चाहे कोई आप में से बन जाए, यह समस्या तो रहने वाली है।

इतनी बड़ी स्कीम, इसके टेल एण्ड पर पानी पहुंचे यह हमारे सबसे बड़ी समस्या है। इस पर हम विचार कर रहे हैं कि इसका क्या रास्ता निकाला जाए। भविष्य में अब जो योजनाएं बना रहे हैं वह 18 घण्टे बिजली के आधार पर नहीं, कम समय बिजली मिलेगी उस आधार को मानकर बनाएंगे, इसलिए अब जो योजनाएं बनेंगी उनमें यह प्राब्लम नहीं आएगी। कभी-कभी यह भी होता है कि आपकी योजना अमुक गांव तक आ गई तो दो किलोमीटर पर ही दूसरा गांव है वहां के लोग भी कहते हैं कि यहां तक तो आ ही गया, साहब, हमारे यहां भी खींच दो लाइन। हम राजनीति के अंदर रहते हैं, समाज के बीच में रहते हैं, कई दबाव में रहते हैं, कई झुकाव रहते हैं, हम कहते हैं, चलो। ले लो भाई। उस वक्त तो दे देते हैं

(श्री भंवरलाल शर्मा)

उसको लेकिन उसके पहले के गांव में ही जब पानी पूरा नहीं आता तो उस गांव तक कैसे जाएगा ? यह व्यवस्था करके इस प्रकार का संकट खड़ा किया हुआ है, इसका समाधान ढूंढ रहे हैं। मैं समझता हूं नई योजनाएं इतनी अधिक बनी हैं जिसके कारण यह असंतोष पैदा हुआ है, लेकिन यह प्राब्लम है हमारे सामने।

हमारे कई माननीय सदस्यों ने जिक्र किया कि बरसात का जो पानी है वह बह जाता है, उसको रोकना चाहिए। यह उत्तम सुझाव है। यह सुझाव शुरू से मान लिया गया होता, जो हमारे पुराने सोर्स हैं, उनकी देख रेख करते और नए इस प्रकार के सोर्स बनाते तो मैं समझता हूं यह समस्या नहीं आती। लेकिन हमने लगाए हैण्ड पम्प, पानी की व्यवस्था कर दी तो लोगों ने टैंक छोड दिए, लोगों ने बावड़ी छोड़ दी, तालाब छोड़ दिए और यहीं आ गए और धीरे-धीरे हमारे जो प्राकृतिक सोर्स थे, जो हमने निर्मित किए थे, वे धीरे धीरे डिप्लीट होकर खतम हो गए और यह समस्या अधिक गम्भीर होकर हमारे सामने खड़ी हुई है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, दूसरा इस समस्या का कारण यह है कि 40 साल पहले, 50 साल पहले योजना बनाई, लेकिन बनाने से पहले यह विचार नहीं किया कि किसी न किसी काल खण्ड में इसकी मेन्टिनेंस की जरूरत पड़ेगी। आखिर पाइप है, उसकी भी तो लाइफ है, कभी न कभी जाकर उसको ठीक कराना पड़ेगा। उसको हम योजना में नहीं रखते थे। 40 साल बाद, 50 साल बाद पाइप खराब हो गए तो एक साथ मांग खड़ी हो गई कि हमारे पाइप बदलो। नहीं बदलोगे तो पानी नहीं पहुंचेगा इसलिए वह सारा बजट एक साथ आ गया, बहुत कठिन बात हुई यह। इसलिए भविष्य में योजनाएं बनाते समय खयाल रखना चाहिए कि 10 साल बाद, 20 साल बाद, 25 साल बाद, यह पैसा हमको चाहिए, उसके लिए अलग से बजट बनाना चाहिए। आपने देखा होगा कि रेल के डिब्बे पर रिटर्न तारीख लिखी रहती है, रिटर्न का मतलब है कि 98 तक है तो वह 98 में मरम्मत के लिए वापस चला जाएगा और मरम्मत हो जाएगी। लेकिन हमारी इन योजनाओं में यह मूलभूत कमी रहती है। हमारी बात ही क्यों, किसी की बात हो, किसी भी योजना की मियाद तो रहती ही है। उसके बाद निश्चित रूप से उसकी मरम्मत का प्रावधान हो, यह भी आवश्यक है। यह हम नहीं कर पाए, इस कारण से भी यह समस्या खड़ी हो गई है आज। कई-कई माननीय सदस्यों ने कहा कि हमारे पाइप लाइन गल गई, टंकी टूट गई। निश्चित रूप से उनकी मियाद पूरी हो गई तो होगा ही, इसलिए समस्या हमारे सामने खड़ी हो गई।

हमने पिछले सालों में जो काम किए उसका थोड़ा-सा उल्लेख करूंगा, क्योंकि ज्यादा समय नहीं है। मैं बहुत लम्बा कहूं कि हमने बहुत काम किए, ज्यादा काम किए तो वह मेरा उद्देश्य नहीं है लेकिन मेरा यह दायित्व है कि जो काम हमने किए

152

(श्री भंवरलाल शर्मा)

हैं, वह कम से कम आपके सामने रखूं। इस विभाग ने 5 साल में क्या काम किया, वह काम इतना था, उसको कम्पेयर करना मेरी मजबूरी है उससे कि पहले के पांच साल में क्या हुआ, तभी तो एप्रिशियेट करेंगे आप। इसलिए पिछले पांच साल में क्या हुआ और हमारे पांच साल में क्या हुआ, मैं केवल नाम भी बताऊंगा कामों के तो बहुत लम्बा होगा, हमने जो धन खर्च किया, इन कामों के लिए, केवल उसका वर्णन करूंगा। पिछले पांच साल से यानी हमारे से पहले के पांच साल में, 1985-90 कहिए उसमें, आपने खर्च किये इन योजनाओं पर 39,884 लाख रुपए और हमने पांच साल में रूरल में खर्च किये 91,852.82 लाख रुपये। यह तो रूरल का है। मैं फिर बोल देता हूं हमारे पांच साल के कार्यकाल में 91,852 82 लाख और पुराने कार्यकाल में 39,884 लाख।

(17.00 बजे)

श्री बनवारीलाल बैरवा : महंगाई के हिसाब से हुआ है।

श्री भंवरलाल शर्मा : महंगाई हुई है, सब कुछ हुआ है। महंगाई कितनी बढ़ी होगी उसको घटा भी दें तो भी ज्यादा रहेगा। महंगाई है तो भी ज्यादा ही है। आप कुछ तो एप्रिशिएट करो। परबन सैक्टर में आपके कार्यकाल में 19,608 लाख और हमारे समय में हुआ है 64091.20 लाख।

श्री चन्दनमल बैद : माननीय मंत्री महोदय, 80 प्रतिशत जनता देहातों में बसती है वहां आपने कम खर्च किया है, 20 प्रतिशत जनता शहरों में बसती है उसमें आपने ज्यादा खर्च किया। इसका मतलब आप किसान विरोधी हैं, देहात विरोधी हैं, यह जो आपने कहा उससे साबित हो गया।

श्री रामस्वरूप मीणा : हवामहल में कितना खर्चा हुआ ?

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : आपने गांवों की कॉस्ट पर शहरों को पानी पिलाया है। गांवों को प्यासा रखा है।

श्री भंवरलाल शर्मा : यह इन्टरप्रिटेशन आपका हो सकता है। मैं तो जो फैक्ट्स हैं, जो आंकड़े हैं वे रख रहा हूं। माननीय सदस्य, मैं तो आंकड़े रख रहा हूं। गांव में ज्यादा खर्च हुआ या शहर में ज्यादा खर्च हुआ, वह बात अलग है। जो खर्च हुआ है वह बता रहा हू। (व्यवधान)

श्री चन्दनमल बैद : मैं आपके आंकड़ों से ही कंक्लूजन निकाल रहा हूं कि आपने 20 परसेंट जनता पर ज्यादा खर्च किया है, 80 परसेंट जनता पर कम खर्च किया। आपका देहातों के ऊपर ध्यान कम है, किसानों की तरफ आपका ध्यान कम है और शहर के लोगों पर आपका ध्यान ज्यादा है। (व्यवधान) आपके ही आंकड़े मैं कह रहा हू। मेरे आंकड़े तो हैं नहीं, आपके ही आंकड़ों से मैं कह रहा हूं।

श्री भंवरसिंह डांगावास (राज्य मंत्री, भूजल) : मंत्री जी की बात तो सुनें।

श्री चन्दनमल बैद : आप क्यों बोल रहे हैं ? मिनिस्टर साहब काफी योग्य हैं। आप तो अभी टेल एण्ड मिनिस्टर बने हैं, ये बहुत योग्य हैं, आठ साल से मिनिस्टर हैं।

श्री भंवरलाल शर्मा : मेरी बात तो सुनें। ....(व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा : भाजपा को शहरों में ही वोट मिलते हैं इसलिए शहरों में किया है। इनको गांवों में वोट नहीं मिले, न आगे मिलेंगे।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : गांवों में भी आपने पांच गुना किया है। और चन्दनमल जी, गांवों का और आपका क्या लेना-देना है ? किसानों पर जितना जुल्म आपने किया है उतना तो कोई कर ही नहीं सकता। (व्यवधान)

श्री चन्दनमल बैद : आपको मालूम होना चाहिए कि मैं 91 प्रतिशत गांवों से ही वोट लेकर आता हूं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : आपने किसानों के बाजरे पर टैक्स लगाया था, किसानों पर मोठ पर टैक्स आपने लगाया था, किसानों के अनाज पर टैक्स आपने लगाया था। आपने किसानों के साथ ज्यादती की। आपकी राजनीति किसान विरोध है। चन्दन मल जी का तो राजनैतिक आधार ही किसानों का विरोध है। (व्यवधान)

श्री परसादीलाल मीणा : .... (व्यवधान) हमने खंभा फ्री दिया है, आपने दो हजार से 12 हजार वसूल किए हैं। (व्यवधान)

श्री चन्दनमल बैद : ऊर्जा मंत्री जी, 29 तारीख को आप भी आ जाना। (व्यवधान)

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : पक्षपातपूर्ण तरीके से आपने काम किया है। (व्यवधान)

श्री परसादीलाल मीणा : किसान को कांग्रेस ने 28 पैसे में बिजली दी है, आपने डेढ़ रुपया लिया है। हमने तार, खंभा फ्री दिया है, आपने 9 हजार कर दिया है। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा : नर्सरी योजना लागू करके 9 हजार के 12 हजार कर दिये, +++ । (व्यवधान)

श्री परसादीलाल मीणा : (व्यवधान) सारे गांवों में बी.जे.पी. का सफाया हो गया।

श्री चन्दनमल बैद : ऊर्जा मंत्री जी, 29 तारीख को देख लेंगे आपको भी। 29 तारीख को आपको ... (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा : पता लगेगा, इस लालबत्ती को लेकर गांवों में घूमना। यह लालबत्ती आपके खतरे की निशानी बन गई है। (व्यवधान) यह लाल बत्ती

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(154)

(श्री रामस्वरूप मीणा)

आपके खतरे की निशानी है, आ जाओ मेरे गांव में, देख लेंगे गांव वाले आपको। गांव-गांव जाएंगे तो पता लगेगा। (व्यवधान)

श्री परसादीलाल मीणा : आपको भंवरलाल जी का विरोध करना चाहिए अगर आपको गांवों में जाना है तो। (व्यवधान) गांव में जाना है या नहीं जाना है ? (व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोड़ा : 500 की जनसंख्या पर आप एक हैण्ड पम्प देते थे और हमारे यहां 20 की जनसंख्या पर भी एक हैण्ड पम्प दिया है। आपने क्या दिया है ? (व्यवधान)

श्री परसादीलाल मीणा : + + + आप तो शहर में हैं, आपको पता नहीं गांवों में क्या हाल है। आपको पता नहीं है।

श्रीमती उजला अरोड़ा : 500 की जनसंख्या पर हैण्ड पम्प देते थे। लोग रो-रोकर मर गए, आपने हैण्ड पम्प नहीं दिया।

श्री परसादीलाल मीणा : सारी योजनाओं का पैसा शहरों में खर्च कर दिया। (व्यवधान)

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर) : अध्यक्ष महोदय, ये सदन का समय नष्ट कर रहे हैं।

एक माननीय सदस्य : ये कभी गांव में गये ही नहीं, ये सिर्फ दिल्ली या जयपुर आते थे। (व्यवधान)

श्री परसादीलाल मीणा : भारतीय जनता पार्टी के हारने के कारण भवरलाल जी होंगे। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : (व्यवधान) वह जो जांच रिपोर्ट है (व्यवधान)

श्री राकेश मेघवाल : अध्यक्ष महोदय, ये धनखड़ जी तो कभी गांवों में गये ही नहीं, ये तो सीधे दिल्ली या जयपुर आते थे।

श्रीमती उजला अरोड़ा : चंदनमलजी तो शहर के लिए लड़े हैं, गांवों के लिए कभी लड़े ही नहीं। चूरू के लिए लड़ रहे हैं। (व्यवधान)

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, पानी की समस्या के लिए न तो गांव होता है न शहर होता है। (व्यवधान) चाहे बिजली की समस्या हो चाहे पानी की समस्या हो, इनका मकसद यह नहीं है। इनका मकसद तो खड़े होकर + + + करने का है ताकि ये राजस्थान की जनता को यह दिखा सकें कि हमने + + + तो किया था। बाकी पानी बिजली की समस्या से इनको कोई लेना-देना नहीं है। (व्यवधान)

श्रीमती कमला : आप कितने भ्रष्ट हैं, गांव वाले सब जानते हैं। (व्यवधान) आप

+ + + शब्द/अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्रीमती कमला)

क्यों ऊंची-ऊंची बातें कर रहे हैं? (व्यवधान)

श्री राकेश मेघवाल : लेकिन करें क्या, इनकी मजबूरी है सदन में। जाकर कहेंगे, हम तो बहुत लड़े थे। बाकी आना-जाना कुछ नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन के बाहर जाकर ये चर्चा करते हैं कि इस बी.जे.पी. की सरकार ने बहुत विकास करवाया, जगह-जगह ट्यूबवैल्स लगवा दिए, मगर इसको रोकें कैसे। इनका उद्देश्य यह है कि सदन में +++ करके जो असली बात मन्त्रीजी कहना चाहते हैं उनको कहने नहीं देते। (व्यवधान)

श्रीमती कमला : गांव वाले सब परख रहे हैं। आपको एक-एक इंच पर, एक-एक कदम पर देख रहे हैं। ऐसा खुला भ्रष्टाचार राजस्थान में है, लूटकर रख दिया जनता को। आने दो चुनाव। (व्यवधान)

श्री राकेश मेघवाल : आप खुद गांवों में गये? एक भी माननीय सदस्य बता दे कि वे कभी जीतने के बाद गांवों में गये क्या? आप खुद शहरों में रहते हैं। आपको पता ही नहीं ढाणी में क्या होता है, गांव में क्या होता है, एक किसान के घर में क्या होता है। आपको क्या पता?

श्री रामस्वरूप मीणा : आप क्यों भाषण दे रहे हैं?

श्री परसादी लाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, इनको बिठाओ।

श्री राकेश मेघवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, पीने का पानी तो गांव वाले को भी चाहिए, शहर वाले को भी चाहिए। जहां पीने के पानी की समस्या थी वहां पैसा खर्च किया, इसमें गांव और शहर कहां आता है? अध्यक्ष महोदय, जब यहां बजट की बात आयी तो गांवों में एक लाख रुपये का कुआ बनता है और शहर में 5 लाख रुपये का एक ट्यूबवैल बनता है, इसलिए शहरों का बजट ज्यादा हुआ है। पानी की समस्या को हल करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बहुत काम किए हैं। (व्यवधान) इससे शहरों में लागत ज्यादा आती है और गांवों में कुओं की कास्ट कम आती है। एक लाख से एक कुआ गहरा हो सकता है, इसलिए एक गांव में एक लाख रुपये से एक कुए से पूरे गांव को पानी की सप्लाई हो सकती है जबकि उसकी बनिस्पत शहर में एक ट्यूबवैल पर 5 लाख रुपये की कास्ट आती है, इसलिए शहरों में बजट ज्यादा हो गया। माननीय सदस्य, आप सब जानते हैं लेकिन आप सदन को गुमराह करना चाहते हैं। (व्यवधान) धनखड़ जी, यह सुप्रीम कोर्ट नहीं है, हाई कोर्ट नहीं है। यह राजस्थान की विधान सभा है। आप किसान के लिए कभी किशनगढ़ गए? कभी किशनगढ़ के गांवों में गए? कभी ढाणी में गए? आपको तो वकालत से ही फुरसत नहीं मिलती। (व्यवधान)

+++ शब्द/अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल : आपके परबतसर में बछिया तो अच्छी मिलती है। बछड़े-बछड़ी अच्छे मिलते हैं परबतसर में। (व्यवधान)

श्री जगदीप धनखड़ : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने...(व्यवधान)

श्री पराक्रम सिंह : धनखड़ जी, आप सुप्रीम कोर्ट छोड़ो, अब विधान सभा में ध्यान दो।

श्री जगदीप धनखड़ : सुप्रीम कोर्ट और विधान सभा में क्या रखा है, किशनगढ़ जाना है। इस बात को छोड़िए। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : ये किशनगढ़ से नहीं लड़ेंगे, ये दूसरी जगह से लड़ेंगे।

श्री जगदीप धनखड़ : मैं मुख्य मंत्रीजी की संस्कृति का आदमी नहीं हूं कि किशनगढ़ छोड़ूं। माननीय मंत्री जी कह रहे हैं हमारे पास....

श्री रामस्वरूप मीणा : अध्यक्ष महोदय, 'एक किलो की 900 ग्राम, मार पड़े तो जय सियाराम' वाह रे भाजपा वालो शहरों के अलावा गांवों को क्या जानो। (व्यवधान)

श्री बद्रीप्रसाद गुरुजी : +++ (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा : मार पड़े तो जय सियाराम। (व्यवधान)

श्री जगदीप धनखड़ : हमारे पांच साल और आपके पांच साल कहां (व्यवधान) उसमें तो आपकी ... (व्यवधान) आप बार-बार कहते हैं कि हमारे पांच साल और आपके पांच साल में, पांच साल में तो आपके भी तीन साल हैं। आप कह रहे हैं.. (व्यवधान)

श्री राकेश मेघवाल : माननीय धनखड़ साहब, किशनगढ़ विधान सभा क्षेत्र में 25 प्रतिशत ही किसान हैं, 75 प्रतिशत व्यापारी हैं। आप व्यापारियों के हितों की बात....(व्यवधान)... किसानों के हितों की बात कहो। खाली यहां पानी पहुंचे, पहुंच रहा है....(व्यवधान) किशनगढ़ में तो प्रत्येक डायमंड पर इतने ट्यूब वैल हैं कि आज तक किसी सरकार ने नहीं खुदवाये हैं। इस सरकार ने खुदाये और नया औद्योगिक क्षेत्र किशनगढ़ डवलप किया। इसलिए धनखड़ जी, आप किसी ग्रामीण क्षेत्र के विधान सभा क्षेत्र को चुनिये, किशनगढ़ को छोड़िये। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बिराजिये। मंत्री महोदय।

श्री जगदीप धनखड़ : इस बात का जवाब दे दीजिये कि कौनसे पांच साल आपके और कौनसे पांच साल हमारे? जवाब दीजिये।

श्री अध्यक्ष : कृपया। मंत्री महोदय।

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री भंवरलाल शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, अब आपके तर्क से यह बात तो साबित हुई है कि जिस सरकार ने यह योजना बनायी, यदि गांव में कम खर्च किया तो वे किसान विरोधी हैं। हो गया हिसाब। यही कहना चाहते हैं न आप? यही है न मतलब? बोलो। आपने जो खर्च किया है उसका अनुपात भी यही है। उसका कारण है। इसमें कोई किसान विरोधी, गांव विरोधी नहीं है। इसका कारण यह है, जैसा माननीय राकेश जी ने कहा, आप भी जानते हैं कि गांव में एक हैण्ड पम्प लग जाएगा तो काम चल जाएगा लेकिन शहर में किसी एक मोहल्ले में एक हैण्ड पम्प से काम नहीं चलेगा। यहां यदि आपने पाइप लाइन डाली तो एक हैण्ड पम्प से काम नहीं चलेगा। तो यह जो गांवों का परिवेश है, ग्रामीण इलाकों में जिस प्रकार के लोग रहते हैं, जैसी उनकी आवश्यकता है उसके हिसाब से और गांवों के हिसाब से अन्तर नहीं था। गांव का आदमी जब सुबह शौच के लिए जाता है तो एक लोटा लेकर जंगल में जाता है, शौच जाकर आता है। एक लोटे में सारे काम निपटाता है और, धनखड़ साहब, आप सुबह उठते ही कितना गैलन पानी फेंकते हो? आप जाओ जंगल में, आपके पास मैदान है, जाया करो। यू कान्ट डू इट। तो व्यावहारिकता से मुंह क्यों मोड़ना चाहिए? इसमें क्या किसान विरोधी? जितने एम. एल. ए. यहां बिराजमान हो, सब गांवों से आते हो, ग्रामीण हो, जाया करो। देखें जंगल में और कुए पर नहाया करो, हैण्ड पम्प पर नहाया करो। वह व्यावहारिक नहीं है इसलिए गांव के परिवेश और अपने परिवेश में अन्तर है वह अन्तर रहेगा। किसान विरोधी कहना, यह तो पोलिटिकल बात है। आप कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं इतना कोई समझना नहीं हूं, ऐसी बात है क्या? आपने कहा जो ही मान लेंगे। आपके भी ये ही फिगर्स हैं। आपने भी गांवों में कम खर्च किया, शहरों में ज्यादा किया है। वह आज भी हुआ, कल भी होगा। इसलिए कोई किसान विरोधी नहीं है। यह तो हमारे ग्रामीण परिवेश में जिस प्रकार के लोग रहते हैं, जिस प्रकार की आवश्यकता है, जैसी जियोग्राफिकल स्थिति है उसकी बात है। वहां तालाब रहता है, गायें पानी पीती हैं, तालाब में जाकर नहा लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं। हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? इसलिए आपको आवश्यकता के हिसाब से यहां पानी अधिक खर्च होता है। इसको कोई किसान विरोधी मत कहना, और यदि किसान विरोधी है तो आपकी सरकार के आंकड़े देख लेना। आपने भी गांव में कम और शहर में ज्यादा खर्च किया है। अब क्या बोलें? इसलिए ज्यादा समय नहीं, आपने यह बात कही, अब आगे बोलने दो। अब आपने कहा कि राजनीतिक भेदभाव....

श्री आर. पी. शर्मा : बिजली के जो कनेक्शन पहले होते थे ग्रामीण क्षेत्रों में उनमें तो 5 हजार और अब एक लाख लगते हैं, यह तो निश्चित है, इसमें आप बतायें। (व्यवधान)

श्री कालूलाल गूजर : आप बिजली की बात कर रहे हो या पेयजल की?

158

श्री भंवरलाल शर्मा : अध्यक्ष महोदय, आपने यह कहा कि हमने खर्चा भी किया है इलाकों में तो उसमें हमने राजनीतिक भेदभाव किया। यह अभी माननीय सदस्य बोल रहे थे, ये आरोप लगाये। आपने जब मीटिंग हुई तब से ही कहा कि राजनीतिक भेदभाव से काम करते हो। अब पता ही नहीं कैसे कह दिया उन्होंने। कोई आंकड़ा तो बताया ही नहीं लेकिन बोल गये। मैंने आंकड़े इकट्ठे किये। (व्यवधान) हमने जो पांच साल में किये हैं वह मैं बताता हूं कि यह राजनीतिक भेदभाव है या नहीं है। अगर मैं आंकड़े रखूंगा तो मेरे जो माननीय सदस्य हैं वे कहेंगे कि अच्छा आपने यह कर दिया क्या इनके लिए, यह मेरे लिए तो उल्टा होगा। अब आप सुनो, बताता हूं। माननीय चन्दनमल जी, आपके क्षेत्र में 5 साल में हमने 1636 लाख खर्च किये।

श्री चन्दनमल बैद : आपने खर्च किये हैं या जर्मन सरकार ने ?

श्री भंवरलाल शर्मा : बाकी तो आप ही करते थे ?

श्री चन्दनमल बैद : फिर आप क्या कर रहे हो ? आपका क्या खर्च हुआ उसमें ? (व्यवधान) हमने समझौता करा दिया। नरसिंहराव जी की सरकार ने जर्मन सरकार के साथ समझौता किया, उसमें आपकी क्या तारीफ है ? जर्मन सरकार के साथ नरसिंहराव सरकार ने समझौता किया उसमें पैसा खर्च हो रहा है, आपकी क्या तारीफ है इसमें ? +++ (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह आपकी योजना किसने बनायी।

श्री चन्दनमल बैद : हमने बनायी। मैंने बनायी। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : यह भारतीय जनता पार्टी थी जिसने....(व्यवधान)

श्री चन्दनमल बैद : 1975 में कहां थे आप ? पैदा ही नहीं हुए थे 1975 में। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : पानी के नाम पर नेतागीरी नहीं की। (व्यवधान)

श्री चन्दनमल बैद : 1975 में शिलान्यास हुआ है इसका, आप पैदा नहीं हुए थे उस समय। +++ उस समय।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : हां, मैं पैदा नहीं हुआ था। वह पानी आ रहा है, पानी आ रहा है इस नाम पर आपने राजस्थान की विधान सभा का... (व्यवधान) किया था। समस्या का समाधान नहीं किया। (व्यवधान)

श्री चन्दनमल बैद : यह तो आपको तारानगर से खड़े हो तो जाकर देना और अपनी हालत देखना फिर। (व्यवधान)

+++ शब्द/अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : यह बात है तो वैसे तो आप मायत हो पर आप चुनौती दे रहे हो तो +++ आपके लिए तैयार है। (व्यवधान)

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : चूरू में आधार खतम हो गया है क्या जो तारानगर जा रहे हो ? (व्यवधान)

श्री परसादीलाल मीणा : +++ मामड़ा जी को भेजो। आप क्यों करते हो, उनको भेजो ? उनसे कहो चुनौती, आप क्यों मागते हो अभी ? यही उम्र है। (व्यवधान)

श्री चन्दनमल बैद : डिप्टी चीफ मिनिस्टर आना चाहें तारानगर, उनका स्वागत है। (व्यवधान)

श्री इन्द्रसिंह पूनिया : वह ठेका अब नहीं ले रहे हैं। भाई राजेन्द्रजी, जोश से काम नहीं अक्ल से काम लो। मामड़ा जी आपको निकालना चाहते हैं, गलती मत कर देना। (व्यवधान)

श्री गुलाबचन्द कटारिया : अभी तो +++ से ही निपट लो।

श्री राकेश मेघवाल : इसका मतलब यह हुआ कि माननीय राठौड़ साहब से तो आप डर ही गये इसलिए माननीय मामड़ा जी की मांग कर रहे हैं। आप माननीय राठौड़ साहब से डर ही गये। (व्यवधान)

श्री परसादीलाल मीणा : मुकाबला तो बराबर से होगा, मामड़ा जी से होगा। (व्यवधान)

श्री इन्द्रसिंह पूनिया : महावीरजी, आपके काम की बात नहीं हो रही है। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : हम तो +++ डर रहे हो क्या ? (व्यवधान)

श्री इन्द्रसिंह पूनिया : महावीर जी, यह आपके मतलब की बात ही नहीं, आप समझ ही नहीं रहे हो, +++ की बात कर रहे हो। (व्यवधान)

श्री चन्दनमल बैद : कोई डरने की बात नहीं है। मैं स्वागत कर चुका हूं, आज फिर स्वागत करता हूं कि आएं मेहरबानी करके आएं, आपका स्वागत है। और कोई दूसरा आना चाहे तो उसका भी स्वागत है, शौक से स्वागत है। (व्यवधान)

श्री परसादीलाल मीणा : मामड़ा जी आएं।

श्री भवरलाल शर्मा : इतना अभिमान मत करो। (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : इतना अभिमान है तो सरदारशहर से लड़ो।

श्रीमती उजला अरोड़ा : आप राजनीतिक +++ राजनीतिक +++ (व्यवधान)

+++ शब्द/अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री चन्दनमल बैद : आप आना चाहो तो आपका स्वागत है, आप भी आ जाओ। (व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोड़ा : आपका मकसद केवल हंगामा करना है। आपका मकसद व्यवस्था करना नहीं है, केवल हंगामा करना है। राजनीतिक +++ है आपका मतलब, और कोई मतलब नहीं है। (व्यवधान)

श्री परसादीलाल मीणा : मामड़ा जी से कराओ, चुनौती उनसे दिलवाओ।

श्री रामस्वरूप मीणा : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह हमारे +++ और इन सब में से ईमानदारों से 30 हैं, 30 हारेंगे। इनमें से 10 भी जीतकर नहीं आ सकते, यह मैं गारंटी देता हूं।

श्री भंवरलाल शर्मा : रामस्वरूप जी +++ माननीय अध्यक्ष महोदय, आदरणीय चन्दन मलजी ने तो कह दिया कि यह पैसा आप लाये तो कहां से लाये। माननीय पूनमचन्द जी विश्नोई, आपके क्षेत्र में पिछले 5 साल में 1671 लाख खर्च किये। अब इसका तो चक्कर नहीं है न कोई? इतने बड़े कांग्रेस के नेता हैं, अगर हमारे मन में भेदभाव होता तो मैं यह कहता कि आपके क्षेत्र में एक पैसा खर्च नहीं हुआ। अब आप उत्तर मत दीजिये मुझे।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : यह खर्च जोधपुर लिफ्ट वाले तो नहीं हैं। मेरे को तो उसका पानी ...(व्यवधान) लिफ्ट का है यह खर्च। (व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा : चलिये, भीमराज जी भाटी साहब ये दो तो कांग्रेस के हैं और एक निर्दलीय का बता देता हूं। पाली में आपके यहां 1062 लाख रुपये खर्च किये, आपका क्षेत्र है।

श्री भीमराज भाटी : अध्यक्ष महोदय, इन्होंने एक हजार और कितने ही लाख रुपये खर्च किये, इनसे पूछो, इसमें से पानी कितने लोग पी रहे हैं। विधायक कोष के दो साल का जो पैसा है, उन पैसों से जी.एल.आर. अभी तक नहीं बनी और ये 1000 लाख की बात कर रहे हैं। जो 10 लाख रुपये विधायकों को मिलते हैं, उसकी जी एल.आर. अभी तक नहीं बनी और धार्मिक स्थानों पर जी.एल.आर. अभी तक नहीं बनी, आप क्या आंकड़े दे रहे हैं?

श्री भंवरलाल शर्मा : वह मैं बताता हूं, वह संख्या भी है मेरे पास। (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, अगर यही स्थिति है तो मैं अपनी मांग पास करने के लिए प्रस्ताव रखता हूं। (व्यवधान) ये हर कदम पर पांच बार खड़े होकर बोलते हैं। हो क्या गया है? नहीं, ऐसा हो क्या गया है? कोई बात लगती है, बात तो सही है तो पर आपको जंचती नहीं है, सुनना तो पड़ेगा

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री भंवरलाल शर्मा)

ना। (व्यवधान) मैं आ रहा हूं। राधेश्याम जी गंगानगर वाले चले गये हैं, अभी इनके यहां पैसा खर्च किया है पांच साल में 4106 लाख रुपये खर्च किया है। अब बताइये, हमारी पार्टी में क्या कमी है? (व्यवधान)

श्री शांतिलाल खोईवाल : आपने गिन गिनकर सलेक्शन किया है इनका।

श्री कालूलाल गुजर : यह सुनकर तो हमें ईर्ष्या हो रही है मंत्री महोदय, कि उनके यहां इतना पैसा खर्च किया है। आपने यह बात कहकर हमारे मन में ईर्ष्या पैदा कर दी।

श्री भंवरलाल शर्मा : वह बात मैं जानता था, मैं यह घोषणा करूंगा, यह जानकारी दूंगा तो आप....

श्री चन्दनमल बैद : आप सब बता रहे हो, आप सब एम.एल.ए. का नाम ले रहे हो, हवामहल में कितना खर्च हुआ पांच साल में?

श्री भंवरलाल शर्मा : आप ऐसा करना, अभी यह अपना कार्यक्रम समाप्त हो जाए तो मेरे चैम्बर में पधारना।

श्री चन्दनमल बैद : नहीं, नहीं, नहीं, आपके चैम्बर में क्यों आ जाऊं, मैं आपका नौकर हूं क्या?

श्री भंवरलाल शर्मा : आपको जानना है तो आ जाइये।

श्री चन्दनमल बैद : नहीं, आपके चैम्बर में मैं क्यों आ जाऊं? आप सबका यहां बता रहे हैं, सब एम.एल.ए. का नाम लेकर बता रहे हैं तो हवामहल पर कितना खर्च किया है?

श्री भंवरलाल शर्मा : नहीं तो मैं आ जाऊंगा आपके पास।

श्री शम्भूदयाल बडगूजर : आपने +++। (व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा : बहुत समय लगेगा।

श्री परसादीलाल मीणा : रतनगढ़ में बता दो।

श्री जगदीप धनखड़ : रतनगढ़ का बताइये ना, चित्तौड़ का बताइये ना। (व्यवधान)

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : आप तो लिस्ट भिजवा देना।

श्री भंवरलाल शर्मा : अब छोड़िये ना। अब मुझे कुछ घोषणाएं करनी हैं। (व्यवधान) मुझे कुछ घोषणाएं करनी हैं और मुझे क्या बताना चाहिए, यह तो मेरा विवेक काम करेगा ना। क्या मुझे बताना

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री भंवरलाल शर्मा)

चाहिए, मेरा विवेक काम करेगा । (व्यवधान) आपको क्या जानना है, उसके तरीके बीस हैं, पूछ लेना । (व्यवधान) हैण्ड पम्प रिपेयर करते हैं हर साल, 1993–94 में 42,734 हैण्ड पम्प रिपेयर किये । (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : आप घोषणा करो ना ।

श्री भंवरलाल शर्मा : ये घोषणाएं नहीं हैं, घोषणा के बीच में थोड़ा-सा विराम है । (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : हम सुनना चाहते हैं, यह क्या मतलब हुआ ?

श्री जगदीप धनखड़ : घोषणा कर दो । (व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा : 1997-98 में हमने 84,000 हैण्ड पम्प रिपेयर किये और 1998 में हमने 88,402 हैण्ड पम्प रिपेयर किये । अब मैं यह कह रहा हूं कि जिन अधिकारियों और कर्मचारियों ने यह काम किया है उनको एप्रिसियेशन मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए ? और यह भी कब हुआ ? पहले तो चुनाव आ गये और बाद में अभी जो परीक्षा हुई थी, उन परीक्षाओं में अध्यापकों की कमी के कारण हमारे इन अधिकारियों को परीक्षा में नियुक्त कर दिया, एक माह करीब उसमें लग गया, उसके बावजूद यह उन्होंने इतना बड़ा काम किया है तो मैं इस सदन के माफंत उनको एप्रिशिएट करना चाहता हूं कि उन्होंने ऐसा काम किया है ।

श्री जगदीप धनखड़ : हैण्ड पम्प चल ही नहीं रहे हैं ।

श्रीमती कमला : आपने घोषणा तो कर दी, यहां खोखे पड़े हैं । (व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा : अब आपके तो खोखे खड़े ही रहेंगे (व्यवधान) कमलाजी, आपके तो खोखे खड़े ही करेंगे ।

अध्यक्ष महोदय, क्योंकि मैं जो बोल रहा हूं, मुखबंद की अवधि में मैं बोल रहा हूं तो मुझे यह ध्यान है कि मुझे शॉर्ट करना चाहिए और मैं अगर शॉर्ट नहीं करता हूं तो आपकी तरफ शॉर्ट होता है इसलिए मैं केवल हमारी जो घोषणाएं हैं, हम जो करना चाहते हैं, वह सदन की अनुमति के लिए रखना चाहता हूं ।

अभी माननीय सदस्य पूनमचन्द जी बिश्नोई ने अपने वक्तव्य में बहुत ही जोरदार और बहुत लाभदायक बात कही थी । उन्होंने कहा कि यह जो बरसात का पानी बहकर चला जाता है, इसको किसी तरह से रोक होनी चाहिए । यह बात ठीक है । अभी कई माननीय सदस्यों ने इस बात को स्वीकार किया और यह एक सामान्य ज्ञान की बात है कि जितना हम बरसात का पानी रोक लेंगे वह तो काम देगा ही देगा । लेकिन जिस प्रकार पहले यह पानी रोककर व्यवस्था होती थी, वह प्रायः नष्ट–भ्रष्ट हो गई है बहुत बड़े पैमाने पर तो सृजित करना इतना आसान नहीं है लेकिन

(श्री भंवरलाल शर्मा)

अब प्रयास करना चाहिए, इसको प्रारम्भ करना चाहिए। उसके लिए हमने यह तय किया है कि बरसात के जल के परम्परागत उद्योग को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से प्रयोग के तौर पर लगभग 100 स्थानों पर बरसात के जल के भण्डारण की योजना क्रियान्वित की है। अभी फिलहाल हमने 100 स्थानों का चयन किया है। यदि आप यह समझते हैं कि ज्यादा उपयोग होगा, ज्यादा लाभकारी होगा तो यह सूची आप उपलब्ध करा देंगे तो चयन के समय में इसका हमको लाभ मिल सकेगा और हम उन स्थानों पर उनका उपयोग करेंगे।

श्री चन्दनमल बैद : हम अपने आप कर लेंगे, आप फिक्र मत करो।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : पानी भेज रहे हैं + + +।

श्री भंवरलाल शर्मा : आप तो जाने क्या-क्या कर लोगे।

अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य सब विधान सभा में समान होते हैं, विधान सभा में कोई छोटा-बड़ा नहीं होता है लेकिन कुछ माननीय सदस्य अपने आपको बहुत बड़ा मानते हैं, सुपर इम्पोज करते हैं, वे अपने बड़प्पन का दुरुपयोग नहीं करें कम से कम मेरे बोलते समय। कोई सवाल पूछना हो तो पूछ लें, मैं उनके घर आ जाऊंगा वहां पूछ लें, पर मुझे बोल तो लेने दें। अगर मैं कोई बात करता हूं तो उसका भी विरोध, यह मनोवृति ठीक नहीं है। मैंने शुरू में कहा था कुछ लोगों का मामला था, अब पता लग गया ना, घनखड़जी।

श्री जगदीप धनखड़ : आप मेरे से पूछ रहे हैं या आरोपित कर रहे हैं ?

श्री भंवरलाल शर्मा : जो गांव में पुराने कुए होते थे, आज भी कई जगह हैं लेकिन वे सूख जाते हैं या टूट जाते हैं, ग्रामीण लोगों की आज यह स्थिति नहीं है कि उनको ठीक कराएं। लेकिन यदि वे ठीक हो जाते हैं तो जल का जो संकट है उसका बहुत बड़ा समाधान हो सकता है इसलिए हमारा सोच है कि सार्वजनिक, पुराने तथा सूखे कुओं की मरम्मत अथवा गहरा कराने हेतु पंचायतों को अनुदान दिया जाए। (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में यह बहुत बड़ी समस्या है। हमारे पुराने स्रोत हैं, परम्परागत व्यवस्था है जिसको हम टी.एस.एस. कहते हैं, यह टी.एस.एस. का काम है। यह ग्रामीण लोग करते हैं, पंचायतें करती हैं, स्थानीय संस्थाएं करती हैं, लेकिन उनके पास भी कोई साधन अधिक नहीं होते और कई बार ठीक से नहीं चल पाते हैं और गांवों में बहुत नुकसान होता है, उसकी हानि होती है। तो हमने यह तय किया है कि 1600 परम्परागत क्षेत्र हैं हमारे, उनको हम जनता जल योजना के

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री भंवरलाल शर्मा)

समान ही लाभ देना शुरू करेंगे, जो शुरू कर दिया है। उस योजना पर 500 रुपये प्रति माह पम्पचालक को देंगे और योजना पर विद्युत खर्च के लिए बिजली का बिल भी सीधा विभाग द्वारा पेमेंट कर दिया जाएगा। बिजली के बिल का पेमेंट हम करेंगे और पम्प के रखरखाव के लिए मोनोब्लाक पम्प पर 1000 रुपये रिपेयर के लिए प्रति वर्ष देंगे। (व्यवधान) कमला जी, आपका ध्यान नहीं हो तो मैं रिपीट कर देता हू। सबमर्सिबल पम्प होगा तो 400 रुपये वर्कचार्ज के हिसाब से उसकी मरम्मत के लिए दे देंगे। तो बिजली का बिल हम चुकाएंगे, 500 रुपये कर्मचारी को देंगे और इसकी मरम्मत के लिए हम 1000 और 400 रुपये देंगे, यह तो इसका काम होगा। अब इस योजना पर किसकी मरम्मत होगी, वह बात अलग है।

कृत्रिम साधनों द्वारा भूजल मात्रा में वृद्धि के प्रयास जयपुर जिले के चक मनोहरपुर, टोंक के महापुरा....

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : किनके क्षेत्र में है मनोहरपुर ?

श्री भंवरलाल शर्मा : मनोहरपुर ? तो इनके है शायद, ये कमला जी के होगा।

अलवर के करोड़ा नाला सेवाड़ में भूजल के कृत्रिम भण्डारण हेतु जलाशय का निर्माण किया जाएगा। झालावाड़ जिले के कुशलपुरा में, राजसमद जिले के सेमल में परकोलेशन टैंक बनाये जाएंगे और बीकानेर जिले के बीछवाल क्षेत्र में रीचार्ज द्वारा भूजल के पुनर्भरण की योजना की जाएगी। राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन के अन्तर्गत प्राचीन नदियों के बहाव क्षेत्र को चिन्हित किये जाने का अध्ययन प्रारम्भ कर दिया गया है।

माननीय सदस्यों और हमारी सभी की चिन्ता का विषय है कि जो फ्लोराइडयुक्त पानी है आखिर उसका क्या किया जाए। अब यह कोई आज से तो है नहीं, मैं समझता हूं कि यह हमारे जन्म से पहले से है और इससे लोग जैसा कि आप अभी चिन्ता कर रहे थे, कूबड़े हो जाते हैं, दांत खराब हो जाते हैं।

श्री कालीचरण सराफ : चन्दनमल जी के टाइम से है।

श्री भंवरलाल शर्मा : नहीं, आप चन्दन मल जी की बात बार-बार क्यों करते हो ?

ये फ्लोराइडयुक्त जो इलाके हैं ये अपन ने किसी ने पैदा नहीं किये, ये तो भगवान की कुकृपा समझिये तब से हैं। ये आज से नहीं हैं और ये जानकारी में नहीं था किसी के ऐसा भी नहीं है। आजादी के पहले भी जानकारी में था और आजादी के बाद तो जानकारी में आ ही गया होगा लेकिन हम इसका समाधान नहीं कर सके। इसके लिए मैं किसी को दोष नहीं देता। वह तो जो गरीब वहां रहते हैं उनके भाग्य की बात है। लेकिन हमने चिन्ता की है और हमने यह तय किया है ...

श्रीमती कमला : रीजनल पाइप लाइन्स इसीलिए बनाई गई हैं।

श्री भंवरलाल शर्मा : अगर आपने सब कर दिया होता तो हमको करने की जरूरत क्या थी ? हमने यह तय किया है कि इस योजना के लिए बजट में इस बार 50 करोड़ का प्रोविजन करके इस समस्या का समाधान करेंगे । अब जैसा किसी माननीय सदस्य ने कहा कि हैण्ड पम्प निरूपयोगी हैं, उपयोगी नहीं है । यह लम्बे रन में बात ठीक हो सकती है लेकिन राजस्थान की जो भौगोलिक परिस्थिति है और जिस प्रकार के लोग रहते हैं, यदि उनमें आज हैण्ड पम्प माइनस कर दो आप तो कोई विकल्प नहीं है । विकल्प इतना आसान नहीं है, पानी आप लाओ कहां से ? जमीन में पानी नहीं है आस-पास में पानी नहीं है ... तो हैण्ड पम्प ...

श्री राजेन्द्र पारीक : मिनरल वाटर भिजवाओ ।

श्री भंवरलाल शर्मा : हां, मिनरल वाटर लाएंगे । तो जो हैण्ड पम्प हैं यही एक सहारा है, बहुत बड़ा हो सकता है । इसको आप टेम्प्रेरी साधन मान लें लेकिन अभी यह जिन्दा रख रहा है लोगों को । तो हमने यह तय किया है । अब ये जो हैण्ड पम्प हैं ये कहां लगाये जाएंगे, इसकी मैं जानकारी देना चाहता हूं, वरना यह बड़ा विवाद होता है । कुछ स्थान हमने तय कर दिये वहां तो लगेंगे ही, उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी । राजकीय उच्च प्राथमिक शालाओं में तथा बालिका विद्यालयों में.. पूरा सुनो ताली बाद में । राजकीय उच्च प्राथमिक शालाओं तथा बालिका विद्यालय किसी भी कक्षा की होगी उनको हम हैण्ड पम्प की व्यवस्था करेंगे, पूरे राजस्थान में ।

श्रीमती कमला : उच्च प्राथमिक की मांग है ।

श्री भंवरलाल शर्मा : प्राथमिक तो कर ही दी हमने, अब उच्च प्राथमिक करेंगे । वह जो बालिकाओं की होगी, कमला जी, आपकी ...

श्रीमती कमला : यह बढ़िया काम किया ।

श्री भंवरलाल शर्मा : हां, बढ़िया । एक बात तो आपने बढ़िया मानी है ।

श्रीमती कमला : यह तो मैंने लिखकर ही भेजा हुआ है ।

एक माननीय सदस्य : इनके यहां खोला कि नहीं खोला ?

श्री भंवरलाल शर्मा : हां, वही किया है, साहब, आपके कहने से ही किया है । हमारे तो दिमाग में ही नहीं था यह ।

श्रीमती कमला : आपके दिमाग तो पहले ही चल पड़े ।

एक माननीय सदस्य : आप ही कह रही हैं ।

श्री भंवरलाल शर्मा : डोन्ट पोज थिंग्स । ऐसा नहीं है कि हम कुछ समझते नहीं हैं । आप ही समझते हो, ऐसा नहीं है । आपका सम्मान अलग बात है, आपके बड़ा होने का सम्मान करते हैं पर बिलकुल नहीं समझते, ऐसी बात नहीं है ।

एक माननीय सदस्य : ये कह रही हैं कि इनको करना है।

श्री भंवरलाल शर्मा : हां, है न, क्यों नहीं है ?

श्रीमती कमला : मैं यह कह रही हूं कि मैंने लिखा था कि उच्च प्राथमिक में भी प्राथमिक के बच्चे पढ़ते हैं इसलिए उसको भी शामिल किया जाए।

श्री भंवरलाल शर्मा : आपने लिखा है वही किया है।

श्रीमती कमला : आपने किया है बहुत अच्छा है, हम आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देते हैं।

श्री भंवरलाल शर्मा : यह आपके लिखने की बात आपके हट जाने के बाद दिमाग में आयी, पहले क्यों नहीं आयी ? पहले तो आप खुद ही थीं इसकी ?

एक माननीय सदस्य : पहले क्यों नहीं आई ?

श्रीमती कमला : नहीं, आपको तो नहीं लिखा मैंने।

श्री भंवरलाल शर्मा : फिर हमारे समाज कल्याण के जो छात्रावास हैं....

श्री मन्नालाल मीणा (राज्य मंत्री, श्रम): जनजाति के भी सम्मिलित कर दो, साहब।

श्री भंवरलाल शर्मा : आ रहा हूं मैं। अब उसमें कई बार पानी की व्यवस्था नहीं रहती है, तो समाज कल्याण के जितने भी छात्रावास हैं वहां हम हैण्ड पम्प लगाएंगे। जनजाति क्षेत्र में जो आश्रम छात्रावास हैं वहां भी अगर पानी की व्यवस्था नहीं है तो वहां भी प्रोयोरिटी के आधार पर हैण्ड पम्प लगाएंगे।

श्रीमती कमला : अनुसूचित जाति की बस्तियों का भी करो।

श्री भंवरलाल शर्मा : आप सुनो, मैं आ रहा हूं। आप डिस्टर्ब मत करिये। आप ठहर जाएं। ऐसी क्या बात है ? आप जानते हैं कि राजस्थान में जहां अपने चिकित्सा केन्द्र हैं वहां लोग जाते हैं, बाहर से भी आते हैं तो और चीज तो साथ ले आते हैं-बाहर से आएगा तो रोटी ले आएगा, कांदा ले आएगा लेकिन पानी का क्या करेगा ? ये राजेन्द्र जी जो मिनरल वाटर ले जाएंगे।

श्री चन्दनमल बैद : कांदा तो मुश्किल से ही लाएगा, कांदा तो कहां से लाएगा ?

श्री भंवरलाल शर्मा : हां, नहीं लाता होगा, वह तो आप खिलाते हो न। चूक से आते हैं। उनको आप खिलाते हो, बस में लाते हो। खाना खिलाते हो या आंदोलन करवाते हो, अब वह क्या करेगा ?

श्री रामचन्द्र रावत : ओ.बी.सी का ध्यान रखा है कि नहीं ?

श्री भंवरलाल शर्मा : अभी आ रहा हूं। वहां लोग बराबर आते हैं, मजबूरी में आते हैं। ऐसे जितने भी राजकीय प्राथमिक

(श्री भंवरलाल शर्मा)

चिकित्सा केन्द्र तथा उप केन्द्र होंगे वहां भी हम हैण्ड पम्प लगाएंगे।

एक माननीय सदस्य : उप केन्द्र में भी कर दो।

श्री भंवरलाल शर्मा : आ गये न, उप केन्द्र बोल दिया न।

श्री शांतिलाल खोईवाल : माननीय मंत्री जी, पचायत मुख्यालय के श्मशान घाट पर भी कर दो।

श्री भंवरलाल शर्मा : अभी वहां जाने में देर है। आ रहा हूं, दे रहे हैं वहां। वह सबसे एण्ड में है।

एक माननीय सदस्य : यह तो कोरी घोषणा है।

श्री रामचन्द्र रावत : ..(व्यवधान).. ये तो खाली घोषणाएं कर रहे हैं।

श्री भंवरलाल शर्मा : हां, श्मशान में आप ही लगाओगे।

श्रीमती कमला : नहीं, ये मजाक की बात नहीं है, गांवों में श्मशान घाटों पर हैण्ड पम्प लगाने की बराबर मांग आती है उसको शामिल करो।

श्री भंवरलाल शर्मा : सुनो तो सही। कमला जी, मैं जब बोल चुकूं न, फिर कोई बात रह जाए तो आई एम ओपन टू करेक्शन।

श्रीमती कमला : नहीं, आप इनकी मजाक बना रहे थे न ? यह वास्तविक चीज है।

श्री भंवरलाल शर्मा : किसकी मजाक उड़ा रहा हूं मैं ? सवाल ही नहीं मेरा मजाक उड़ाने का तो। यह आपको वहम कैसे हो गया, मजाक उड़ाता हूं मैं ?

श्री कालूलाल गूजर : ये कांग्रेस वाले आपस में ही मजाक उड़ाते हैं, साहब।

श्री भंवरलाल शर्मा : कोई मजाक का सवाल ही नहीं है संबंध ही नहीं है। आप बात सुनिये पहले मेरी।

एक माननीय सदस्य : श्मशान का कर दो पहले।

श्री भंवरलाल शर्मा : आता हूं, ठहरो न अभी। अभी अस्पताल तो आने दो।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : अभी इलाज कराने तो दो।

श्री भंवरलाल शर्मा : अभी स्कूल गये हैं, फिर आश्रम गये हैं फिर चिकित्सालय में गये हैं, तो जल्दी क्या है ? हमारे जो धार्मिक स्थल हैं जहां खूब मेले लगते हैं कई बार और हजारों की संख्या में लोग आते हैं, वहां कोई पानी की व्यवस्था नहीं रहती है तो उन स्थानों पर भी हम हैण्ड पम्प लगाएंगे। फिर आप देखते हैं कि जो गांव का निवासी यात्रा करता है, बस स्टैंड पर आता है, गर्मी का मौसम होता है बस स्टैंड पर कई देर कई घंटों इंतजार करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि घर से

(श्री भंवरलाल शर्मा)

निकले, पोर्च में गाड़ी खड़ी है और बैठ कर चल दिये। वहां ऐसा नहीं हैं, उसको इंतजार करना पड़ता है बहुत देर तक। ऐसे जो समस्त पंचायत मुख्यालय हैं, पंचायत समिति के मुख्य बस स्टैंड पर जहां पेयजल की सुविधा उपलब्ध नहीं है वहां हैण्ड पम्प लगाएंगे।

श्री राजेन्द्र पारीक : मोबाइल हैण्ड पम्प की व्यवस्था भी है क्या ?

श्री भंवरलाल शर्मा : हां, है। आप तो ले जाना।

श्री जगतार सिंह कंग : माननीय मंत्री जी,मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आपने तो पदमपुर में लगे हुए पम्प उखड़वा दिये। आप बात करते हो लगाने की, आपने बस स्टैंड पर लगे हुए पम्प उठवा लिये। पंचायत समिति... (व्यवधान)...

श्री भंवरलाल शर्मा : जो माननीय सदस्य की चिन्ता है- स्कूल भी ले गये, आश्रम भी चले गये, अस्पताल भी चले गये बस स्टैंड भी चले गये और प्रश्न का क्या हुआ, वह मैं घोषणा करता हूं कि जितने भी पंचायत मुख्यालयों के श्मशान, कब्रिस्तान या अन्य कोई स्थान हैं जहां इस प्रकार क्रिया होती है वहां भी पानी की व्यवस्था हैण्ड पम्प से करेंगे।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : जिसको जल्दी जाना है प्रायोरिटी बता देगा।

श्री भंवरलाल शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, अब कोई दिक्कत नहीं है, दुविधा नहीं है।

श्री रामस्वरूप मीणा : व्यवस्था कर ली आपने वहां जाने की, अब कोई दिक्कत नहीं है।

श्री भंवरलाल शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, जब गर्मी का समय आता है तो दानवीर या नागरिक पानी की व्यवस्था करते हैं प्याऊ के अ..। दो महीने प्याऊ लगाते हैं, ढाई महीने प्याऊ लगाते हैं उनको बड़ी दिक्कत होती है। हमने यह तय किया है, आगामी ग्रीष्म ऋतु में 15 अप्रैल से 15 जुलाई तक तीन माह की अवधि में प्याऊ हेतु कनेक्शन लेने वाले को निःशुल्क कनेक्शन दिया जाएगा।

श्री राजेन्द्र पारीक : वह तो पहले ही निःशुल्क है।

श्री भंवरलाल शर्मा : नहीं नहीं, है तो चलो ठीक है। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमको एक बड़ी दिक्कत आती है कि गांवों में जो मोटर से योजनाएं चलती हैं वे जल जाती हैं। कई बार दूर-दराज के स्थानों पर उसकी मरम्मत होती है, उसको ठीक कराने में, ले जाने में काफी समय लगता है। उसको कितना भी कम करो तब भी टाइम लगता है। हमने यह विचार किया है कि पंचायतों द्वारा मोटर की रिवाइंडिंग की जिम्मेदारी लेने पर, स्थानीय स्तर पर रीवाइंडिंग की व्यवस्था करने पर ग्राम पंचायतों को जनता जल योजना के सिद्धान्त पर अनुदान दिया जाएगा। वहीं ठीक करा लो, अनुदान ले लो हम दे। इससे

(श्री भंवरलाल शर्मा)

लोगों को काम मिलेगा और जल्दी ठीक होगी, पानी जल्दी मिलेगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, कई लोगों ने लंबे समय से, किसी भी कारण से हो चाहे वह, पानी के कनेक्शन ले रखे हैं, कि पाइप जोड़ दिया और डिपार्टमेंट को पूछा ही नहीं। इसलिए मैं यह घोषणा करना चाहता हूं, आने वाले तीन माह में दीपावली तक जिन लोगों ने अनियमित जल संबंध ले रखे हैं यदि वे एप्लाई करेंगे तो बिना किसी पैनल्टी के हम उसको रेगुलराइज कर देंगे।

श्री राजेन्द्र चौधरी : हर बात तीन महीने के लिये ही क्यों कर रहे हो आप ?

श्री भंवरलाल शर्मा : इतना ही टाइम है। अभी कार्यकाल हो उतना ही करेंगे। हम आपकी तरह मृग मरीचिका में नहीं है। यह देख रहे हैं सरकार यह आई, यह आई, अभी आती है। कभी सुना है क्या ? मृग मरीचिका देखी है क्या ? पड़ी है, यूं ही पड़ी है। चुनाव जीतकर आ जाना मैम्बर बनकर। सुनिए आप, कई बार जब पानी का बिल आता है....

श्री परसादीलाल मीणा : आपके हाथ में है क्या कि आ जाना जीत कर ? अपने बूते पर जीत कर आया हूं।

श्री भंवरलाल शर्मा : आ जाना भाई, आये हो तो क्या हो गया ? कोई आसमान गिर रहा है क्या आ जाओगे तो ? चालीस साल भोगा है आपको, ऐसा क्या है ? फिर रावण राज आ जाएगा। इतना इतराओ मत, इतना घमंड मत करो। बड़े-बड़े....

श्री परसादीलाल मीणा : आप क्या जिताते हो, जनता जिताती है। आपने कहा कि आ जाना जीतकर, +++ जैसे कोई +++करता है .. (व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा : अच्छा, देख लेना।

श्री कालूलाल गुजर : परसादीलाल जी आपके सहयोग से भी कोई नहीं जीतता है।

श्री मदन दिलावर : चुनाव में जीतकर आओगे तब बताएंगे हम आपको।

श्री भंवरलाल शर्मा : छोड़ो, रहने दो; पूरा करने दो।

श्री परसादीलाल मीणा : श्री मदन दिलावर जी दरवाजे के बाहर रहेंगे, नहीं आएंगे दुबारा।

श्री भंवरलाल शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने आम जनता की सुविधा के लिये एक काम और किया है। पानी का जो बिल आता है वह एक माह का आता है और एक महीने का बिल आने के बाद हर कंजूमर को पानी का बिल जमा कराने

+++ शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री भंवरलाल शर्मा)

जाना पड़ता है। जहां वह जमा कराता है, कई बार तो वहां कोई छाया नहीं होती है, लाइन में लगना पड़ता है, बहुत टाइम लगता है। हमने व्यवस्था की है कि जो उपभोक्ता प्रतिमाह राशि जमा कराने की कठिनाई से बचने हेतु एक मुश्त राशि जमा करा देगा तो हम उसको स्वीकार कर लेंगे और जब वह उसके बिल में पूरा होने लगेगा तब उसको नोटिस देकर कहेंगे कि अब तुम्हारा यह अमाउंट खत्म हो रहा है, आगे फिर जमा करा दो। तो हर महीने जाने की जरूरत नहीं है। भले ही एक साल का करा दो। गड़बड़ हुई तो ठीक कर लेंगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जगह-जगह यह शिकायत मिलती है कि पाइप टूट रहा है। जैसे माननीय सदस्यों ने रखा, टंकियां खराब हो गई हैं। इसके रख-रखाव के लिये अभी कोई बहुत बड़े अमाउंट की व्यवस्था नहीं थी, इस बार हम यह व्यवस्था कर रहे हैं कि शहरी योजना हेतु प्रस्तावित व्यय आधुनिकीकरण पर 3.5 करोड़ रुपये, पुराने फिल्टर प्लांट की मरम्मत एवं आधुनिकीकरण हेतु 3 करोड़ रुपये, योजनाओं संबंधी भवनों का सुधार व मरम्मत 1 करोड़ रुपये, प्रदूषण की रोकथाम हेतु पुरानी पाइप लाइन को बदलने के लिये 3 करोड़ रुपये का प्रावधान कर रहे हैं जिससे आपकी जो शिकायत है वह दूर हो सकती है। नये स्रोतों के अनुसंधान पर भी हम इसी प्रकार से अमाउंट खर्च करेंगे।

राज्य में नारू रोग, यह हमारे खाते में आया था। आज यह भगवान की कृपा से खत्म हो गया। आज नारू रोग का कोई व्यक्ति इस प्रदेश में आपको नहीं मिलेगा, यह हमारी उपलब्धि है।

श्री चन्दनमल बैद : हमने ही खत्म कर दिया था, आपके पहले ही खत्म हो गया था।

श्री भंवरलाल शर्मा : आपने तो जाने क्या-क्या खत्म कर दिया था। हमने राजस्थान के प्रत्येक ग्राम को लाभान्वित करने का प्रयत्न किया है और हम लक्ष्य के बहुत नजदीक हैं। हमने यह तय किया है कि जिस गाँव की आबादी 1990-91 के हिसाब से 20 भी है तो हम उसको हैण्ड पम्प से लाभान्वित कर देंगे।

श्री अध्यक्ष : कृपया शांत रहें, माननीय सदस्य, शांत रहें।

श्री भंवरलाल शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, कई बरसों से हमारे विभाग में सहायक अभियंताओं के पद खाली पड़े थे। इसके कारण से कई माननीय सदस्यों ने शिकायत की है कि वहां ए.ईएन. नहीं है, जे.ईएन है, पद ही पद रिक्त हैं। इसलिए हमने इसी वर्ष में अभी दो-तीन महीने में 256 सहायक अभियंताओं का चयन कर काम पर लगा दिया है। जयपुर के बारे में माननीय सदस्य पूछ रहे थे ...

श्री रामस्वरूप मीणा : हमारे यहां जे. ईएन नहीं है नादोती में।

श्री भंवरलाल शर्मा : आपके लगा

(श्री भंवरलाल शर्मा)

देंगे । जयपुर के बारे में बीसलपुर परि–योजना की रिपोर्ट बनकर तैयार हो गई है । अगले वर्ष में इस योजना पर 50 करोड़ रुपया व्यय करने का प्रस्ताव करके इसको करेंगे ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जो काम हम आप सबके सहयोग से कर पाये, उनका लेखा-जोखा मैंने आपके सामने रखा । आपने उसको एप्रिशिएट किया, बहुत अच्छा है । आगे जो काम कर रहे हैं वह भी आपके सामने मैंने विचार रखे । आपने उसका भी स्वागत किया है, मैं उपकृत हूं इससे और आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने पानी जैसे विषय को भी इतनी शांति से सुना, इस कठिनाई को समझा और इतना मेरा सहयोग किया । विधान सभा में ही नहीं, यहाँ आकर कुछ माननीय सदस्य बोलते होंगे लेकिन कोई दुर्भावना नहीं मानता मैं, बाहर मुझसे बड़े प्रेम से बात करते हैं, सलाह देते हैं, हर काम में सहयोग करना चाहते हैं । पर यहाँ उनका यह दायित्व होता होगा कि यह बोलना जरूरी है, यह तो बोलना ही पड़ेगा । नहीं तो कहेंगे कि आप मिले हुए हो क्या उनसे, आप दब गये उनसे ।

श्री राजेन्द्र चौधरी : मंत्री जी के खुद के घर पर पानी नहीं आया है ।

श्री भंवरलाल शर्मा : आपने चाहे किसी भावना से ही मेरा सहयोग किया होगा, मैं इसको अपने ऊपर उपकार मानता हूं और भविष्य में भी आपसे यह आशा करता हूं कि जब कभी आप सामने आकर फिर बैठें इसी प्रकार का सहयोग करते रहें । इन्हीं शब्दों के साथ इस मांग को पास करने का प्रस्ताव करता हूं, यह मांग पास की जाए ।

श्री चन्दनमल बैद : बैठेंगे तो आपके सामने ही ।

मांग संख्या 27 का पारण

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि मांग संख्या 27–पेयजल के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1999 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपए 12,00,85,98000/- (बारह अरब पिच्चासी लाख अठानवे हजार) तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई ।

मुखबन्द

अनुदान की शेष मांगों का पारण

मांग संख्या-1

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 1-राज्य विधान मण्डल के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1999 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 7,57,14,000/- (सात करोड़ सत्तावन लाख चौदह हजार) तक की राशि

(श्री अध्यक्ष)

जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या-2

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 2-मंत्रि-परिषद् के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1999 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 2,99,28,000/- (दो करोड़ निन्यानवे लाख अट्ठाईस हजार) तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या-3

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 3- सचिवालय के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1999 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 47,80,71,000/- (सैंतालीस करोड़ अस्सी लाख इकहत्तर हजार) तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या-4

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 4- जिला प्रशासन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1999 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,36,91,37,000/- (एक अरब छत्तीस करोड़ इकयानवे लाख सैंतीस हजार) तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या–5

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 5- प्रशासनिक सेवाएं के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1999 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 29,01,30,000/– (उनतीस करोड़ एक लाख तीस हजार) तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की जाए ?

मांग संख्या-6

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 6- न्याय प्रशासन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1999 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय

(श्री अध्यक्ष)

को रुपये 85,07,71,000/– (पिच्यासी करोड़ सात लाख इकहत्तर हजार) तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी ।

मांग संख्या-7

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 7- निर्वाचन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1999 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 31,60,59,000/- (इकतीस करोड़ साठ लाख उनसठ हजार) तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी ।

मांग संख्या-8

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 8- राजस्व के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1999 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,55,51,59,000/- (एक अरब पचपन करोड़ इक्यावन लाख उनसठ हजार) तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी ।

मांग संख्या-9

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 9- वन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1999 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,56,56,29,000/- (एक अरब छप्पन करोड़ छप्पन लाख उनतीस हजार) तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी ।

मांग संख्या-10

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 10-विविध सामान्य सेवाएं के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1999 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 15,23,000/- (पन्द्रह लाख तेईस हजार) तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी ।

मांग संख्या-11

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 11-विविध सामाजिक सेवाएं के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1999 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये

(श्री अध्यक्ष)

जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 16,56,80,000/- (सोलह करोड़ छप्पन लाख अस्सी हजार) तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या-12

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 12-अन्य कर के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1999 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 31,49,14,000/-(इकतीस करोड़ उनचास लाख चौदह हजार) तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या-13

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 13 आबकारी के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1999 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,11,38,73,000/- (एक अरब ग्यारह करोड़ अड़तीस लाख तिहत्तर हजार) तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या-14

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 14-बिक्री कर के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1999 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 45,31,74,000/- (पैंतालीस करोड़ इकतीस लाख चौहत्तर हजार) तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या-15

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 15—पेंशन व अन्य सेवानिवृत्ति लाभ के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1999 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 8,93,74,82,000/- (आठ अरब तिरानवे करोड़ चौहत्तर लाख बयासी हजार) तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

(श्री अध्यक्ष)

मांग संख्या–18

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 18-जन सम्पर्क के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1999 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 8,25,32,000/-(आठ करोड़ पच्चीस लाख बत्तीस हजार) तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या-19

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 19-लोक निर्माण कार्य के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1999 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 3,87,96,81,000/- (तीन अरब सतासी करोड़ छियानवे लाख इक्यासी हजार) तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

(18.00 बजे)

मांग संख्या- 20

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 20-आवास के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1999 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 66,78,89,000/- (छियासठ करोड़ अठहत्तर लाख नवासी हजार) तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या-22

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 22-क्षेत्र का विकास के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1999 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 2,64,31,59,000/- (दो अरब चौसठ करोड़ इकतीस लाख उनसठ हजार) तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या-23

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 23-श्रम और रोजगार के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1999 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 73,36,66,000/- (तिहत्तर करोड़ छत्तीस लाख छियासठ हजार) तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त

(श्री अध्यक्ष)

राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी ।

मांग संख्या-25

प्रश्न यह है कि मांग–संख्या 25-कोषागार व लेखा प्रशासन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1999 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 37,92,62,000/– (सैंतीस करोड़ बानवे लाख बासठ हजार) तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी ।

मांग संख्या-26

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 26-चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य और सफाई के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1999 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 7,85,03,56,000/– (सात अरब पिचासी करोड़ तीन लाख छप्पन हजार) तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी ।

मांग संख्या-28

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 28–ग्रामीण विकास के विशेष कार्यक्रम के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1999 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 39,60,90,000/– (उनतालीस करोड़ साठ लाख नब्बे हजार) तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी ।

मांग संख्या-29

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 29-नगर आयोजना एवं प्रादेशिक विकास के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1999 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 77,12,96,000/- (सतहत्तर करोड़ बारह लाख छियानवे हजार) तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी ।

(श्री अध्यक्ष)

मांग संख्या-31

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 31-पुनर्वास एवं सहायता के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1999 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 15,75,000/- (पन्द्रह लाख पिचहत्तर हजार) तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी ।

मांग संख्या-32

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 32-नागरिक आपूर्ति के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1999 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 19,07,59,000/- (उन्नीस करोड़ सात लाख उनसठ हजार) तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी ।

मांग संख्या-35

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 35-विविध सामुदायिक एवं आर्थिक सेवाएं के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1999 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 74,81,12,000/- (चौहत्तर करोड़ इक्यासी लाख बारह हजार) तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी ।

मांग संख्या-40

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 40- राजकीय उपक्रम के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1999 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 2,71,68,000/- (दो करोड़ इकहत्तर लाख अड़सठ हजार) तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी ।

मांग संख्या—42

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 42-उद्योग के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1999 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,55,34,98,000/- (एक अरब पचपन करोड़ चौंतीस लाख अठानबे हजार) तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाए ?

(श्री अध्यक्ष)

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या–43

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 43–खनिज के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1999 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 28, 34,97,000/- (अट्ठाईस करोड़ चौंतीस लाख सतानवे हजार) तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या–44

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 44–लेखन सामग्री एवं मुद्रण के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1999 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 16,09,68,000/- (सोलह करोड़ नौ लाख अड़सठ हजार) तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या–47

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 47–पर्यटन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1999 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 14,72,62,000/- (चौदह करोड़ बहत्तर लाख बासठ हजार) तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या–48

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 48–विद्युत के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1999 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 4,45, 82,26,000/- (चार अरब पैंतालीस करोड़ बियासी लाख छब्बीस हजार) तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या–49

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 49–स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं

(श्री अध्यक्ष)

को मुआवजा और समनुदेशन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1999 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 25,15,49, 000/- (पच्चीस करोड़ पन्द्रह लाख उनचास हजार) तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

विधायी कार्य :विधेयक का पुर:स्थापन

राजस्थान विनियोग (संख्या–3) विधेयक, 1998

विधायी कार्य । पुर:स्थापित किये जाने वाले विधेयक ।

श्री हरिशंकर भाभड़ा, प्रभारी मंत्री राजस्थान विनियोग (संख्या-3) विधेयक, 1998 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिये प्रस्ताव करेंगे ।

श्री हरिशंकर भाभड़ा (उप मुख्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विनियोग (संख्या-3) विधेयक, 1998 (1998 का विधेयक संख्या-3) को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिये प्रस्ताव करता हूं ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (संख्या-3) विधेयक, 1998 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति प्रदान की गयी । प्रभारी मंत्री विधेयक को पुर:स्थापित भी करेंगे ।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विनियोग (संख्या-3) विधेयक, 1998 (1998 का विधेयक संख्या-3) को पुर:स्थापित करता हूं ।

श्री अध्यक्ष : सदन की कार्यवाही सोमवार, दिनांक 27 जुलाई, 1998 प्रात: 11.00 बजे तक के लिये स्थगित की जाती है ।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही 18.11 बजे सोमवार दिनांक 27 जुलाई, 1998 के 11.00 बजे तक के लिये स्थगित हुई)

परिशिष्ट

(नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख की सूचनाएं जो पढ़ी हुई मानी गयी।)

आवासन मण्डल द्वारा अनुचित दुकान बनाकर विधायकों को परेशानी

[श्री ब्रजेन्द्र सिंह सुपा (बयाना)]

हाल में ही आवासन मण्डल द्वारा मानसरोवर में 47/198, 47/199, 47/200 47/201, 47/202 मकान विधायक कोटे में आवंटित किये गये हैं। उन मकानों के पीछे के चौक से चरपेटा देकर एवं मकान से चरपेटा देकर अनुचित रूप से दुकानों का निर्माण चालू कर दिया है। यह कहां का न्याय है एक तरफ सरकार रियायती दर पर सुरक्षित स्थान पर मकानों का आवंटन करना चाहती थी वहीं विधायकों को परेशानी में डालने की नियत से आवासन मण्डल मकानों से चरपेटा देकर दुकानों का निर्माण करा रही है। माननीय मंत्री जी अगर मकानों के पीछे दुकान किसी शराब के ठेकेदार, ढाबा या असामाजिक तत्वों ने आवंटन करा ली तो उन मकानों में रह रहे विधायक एवं विधायकों के परिवार की क्या हालत होगी बताने की आवश्यकता ही नहीं है। विधायक उन मकानों में किसी भी हालत में रहना पसन्द नहीं करेंगे।

उक्त मकानों के पीछे चरपेटा देकर दुकानों का निर्माण कराकर आवासन मण्डल क्या विधायकों को नाजायज परेशानी में डालना चाहते हैं।

अतः माननीय अध्यक्ष जी आवासन मंत्री जी को निर्देश दें कि विधायकों के हितों को ध्यान में रखते हुए तुरन्त प्रभाव से दुकानों के निर्माण पर रोक लगाई जावे।

———

भरतपुर के सड़कों की जीर्ण-शीर्ण अवस्था

[श्री आर0पी0 शर्मा (भरतपुर)]

उक्त नियम के अन्तर्गत मैं सार्वजनिक निर्माण विभाग मंत्री जी का ध्यान आकर्षित कर निवेदन करता हूं कि भरतपुर विधान सभा क्षेत्र की निम्न सड़कों की हालत बड़ी जीर्ण-शीर्ण है :–

(1) सेवर रोड से नुमायश रोड एवं नुमायश रोड से कुम्हेर गेट आटोमोबाइल तक

(2) भरतपुर से वाया रारह मथुरा रोड

(3) कुम्हेर गेट से कुम्हेर रोड अखड़ड तक

(4) भरतपुर अच्छनेरा रोड

(5) अच्छनेरा रोड से इकरन पीपला रोड

(6) नोह रोड से पीपला रोड

(7) नोह रोड से गामड़ी रोड

(8) अच्चेन रोड से ऊंचा गांव

(9) सरकूलर रोड भरतपुर शहर

मान्यवर उक्त सड़कें पहले से ही खराब थी लेकिन 1995 व 1996 की बाढ़ से ये सभी सड़कें बहुत खराब हालत में है तथा सभी सड़कों पर गड्डे हो रहे। यात्रियों एवं वाहनों इत्यादि को आवागमन में बहुत असुविधा हो रही है। सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों द्वारा समय समय पर इस ओर मेरे द्वारा ध्यान दिलाने पर भी विभाग के अधिकारियों ने इस सम्बन्ध में कोई भी उपयुक्त कार्यवाही नहीं की है।

अतः कृपया अविलम्ब इन सड़कों की मरम्मत करवाने की कार्यवाही करवाने की कृपा करें।

राजकीय अस्पताल, जालौर में अव्यवस्था

[श्री मगराज चौधरी (जालौर)]

जालौर राजकीय अस्पताल जिले का मुख्य अस्पताल है। इसलिए सम्पूर्ण जिले एवं बाड़मेर जिले के पड़ौसी क्षेत्रों से विभिन्न प्रकार की बीमारी के मरीज चिकित्सा हेतु जालौर आते हैं परन्तु चिकित्सालय की स्थिति बहुत ही बिगड़ी हुई होने के कारण मरीजों को सन्तोषप्रद चिकित्सा का लाभ प्राप्त नहीं होता है। राजकीय जालौर अस्पताल जिले के मुख्यालय पर स्थित एक मात्र मुख्य अस्पताल होने के बावजूद भी चिकित्सकों द्वारा समय पर चिकित्सालय में समय पर नहीं आने और वहां पर नहीं बैठने, चिकित्सालय में सफाई की व्यवस्था सुचारू नहीं होने एवं कुछ चिकित्सकों के पद काफी लम्बे समय से रिक्त होने एवं अन्य विभिन्न कारणों से अस्पताल में अव्यवस्था होने के कारण स्थानीय जनता में चिकित्सा सेवाओं के प्रति भारी असन्तोष बना हुआ है।

जालौर जिले में स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र आहोर, भाद्राजून एवं चांदराई में तो स्थिति जालौर राजकीय चिकित्सालय से हर दृष्टि से और भी ज्यादा खराब है। आहोर राजकीय चिकित्सालय पंचायत समिति का मुख्य चिकित्सालय होने से उसमें एक्स-रे मशीन की व्यवस्था होने के बावजूद भी मरीजों के एक्स-रे अस्पताल से बाहर करवाये जाते हैं जिससे लोगों में भारी असन्तोष है। इसलिये उक्त वर्णित सभी चिकित्सालयों में व्यवस्था सुधारने हेतु माननीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

अतः चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग से संबंधित मांग चर्चा हेतु नहीं रखी जाने के कारण इस जनहित के महत्वपूर्ण विषय में सरकार का ध्यान आकर्षित करने हेतु अनुमति प्रदान करावें।

विराटनगर, जयपुर को पर्यटक स्थल घोषित नहीं करने से उत्पन्न स्थिति

[श्रीमती कमला (बैराठ)]

विराटनगर एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थान है तथा पहाड़ों की शृंखलाओं के बीच बसा प्राकृतिक सौन्दर्य स्थल है। यहां पाषाणकाल के पत्थरों से बने औजार तथा बौद्धकालीन शिलालेख, सिक्के, बौद्धस्तूपों एवं भिक्षुओं के निवास की लाल बड़ी ईंटों से बीजक पहाड़ी पर बनी आधार शिलायें कायम हैं। एक शिलालेख का हिस्सा तथा चांदी के सिक्के कलकत्ता के राष्ट्रीय म्यूजियम में रखे हुए हैं। महाभारत काल का तो यह राजा विराट की राजधानी प्रसिद्ध विराटनगर है। अर्जुन की तीर से निकली बाणगंगा, गुप्तवास के जंगल और पहाड़, भीमगट्टा, भीमबांध आज भी उस युग की याद दिलाते हैं। मुगलकाल की पहाड़ों के बीच की सिक्के ढालने की जगह, मुगल गेट, मुगल बादशाह के प्रवास का स्थान आदि अभी भी दर्शनीय हैं।

कुछ वर्षों पूर्व मैंने यहां पुरातात्विक गैलेरी तथा ट्यूरिस्ट कैफेटेरिया भी कायम किया था। उसके आसपास सौन्दर्यकरण हेतु वृक्षारोपण भी किया। समीप बने गणेशजी के सिद्ध स्थान को तथा कुण्ड को भी विकसित किया, इस स्थान तक सड़क भी बनाई तथा यात्रियों के लिए स्थान भी निर्माण कराया है।

बहुत ही भारी खेद है कि पिछले अनेक वर्षों से निरन्तर कोशिश के बावजूद भी हम विराटनगर को बाकायदा पर्यटक स्थल घोषित नहीं करा पाये हैं और इसके विकास हेतु कोई परियोजना भी नहीं बनाई गई है जिससे इन ऐतिहासिक स्थानों की सुरक्षा हो सके और पर्यटकों के दर्शनार्थ कार्यक्रम निर्धारित किया जा सके।

अतः मैं मा0 पर्यटन मंत्री महोदया से आग्रहपूर्वक निवेदन करूंगी कि वे अति-शीघ्र विराटनगर को पर्यटक के नक्शे पर विधिवत कायम करें एवं इसकी वांछित व्यवस्थाओं एव विकास हेतु पर्याप्त धनराशि उपलब्ध करावें। मा0 राज्य मंत्री महोदया ने मुझे भरपूर आश्वासन भी दिया है किन्तु अभी तक कोई प्रगति नजर नहीं आ रही है।

आशा है विभाग अतिशीघ्र वांछित कार्यवाही कर क्षेत्र के लोगों की भावनाओं का आदर करेगा।

———

(184)

बांकापट्टी जल योजना, गच्छीपुरा, नागौर की स्वीकृति

[श्री राकेश मेघवाल (परबतसर)]

मेरे विधान सभा क्षेत्र परबतसर में नागौर जिले की सबसे बड़ी पेयजल योजना है, जिसका केन्द्र गच्छीपुरा है। यह योजना 1972 से प्रारम्भ हुई, तब से आज तक इस योजना में कोई सुधार नहीं हुआ, बांकापट्टी क्षेत्र के अन्तर्गत करीब 70 गांवों का क्षेत्र है; इस क्षेत्र में पानी फ्लोराइड की अधिक मात्रा का होना है, जिससे आज भी लूला, लंगड़ा, बहरा, कुबड़ा पैदा हो रहे हैं। यह योजना सुधार नहीं होने के कारण मृतप्राय: है। पूर्व में इस योजना के अन्तर्गत 70 ग्रामों को पानी मिलता था और अब पानी नहीं मिल पा रहा है।

अभी हाल ही में विभाग ने इस योजना के पुनंगठन के प्रस्ताव बनाकर सरकार को भेज दिया है, इस योजना को स्वीकृत करवाने के लिए पूर्व में कई बार माननीय जलदाय मंत्री महोदय को निवेदन किया मगर कोई कारगर कार्यवाही नहीं की गई। पुनंगठन योजना के जोन-1 में नये नलकूप खोदने का प्रस्ताव है, पूर्व में दो नलकूप कार्यरत है। उसमें फ्लोराइड निर्धारित सीमा 1.7 पी.पी.एम. तक है। और नलकूपों का डिस्चार्ज 5000 गैलन प्रति घण्टा है। अतः पूर्व में यह जगह टेस्टिंग है अतः टेस्टिंग करवाने की आवश्यकता नहीं है।

अतः श्रीमान् के माध्यम से निवेदन कर बांकापट्टी जल योजना को शिघ्र स्वीकृत करा कर ग्राम जनता को लाभान्वित करावें। सादर।

——— — —

(185)

पीपल्दा में वर्ल्ड बैंक द्वारा स्वीकृत सड़कों का कार्य लम्बे समय से बन्द होने से उत्पन्न स्थिति

[श्री रामगोपाल बैरवा (पीपल्दा)]

विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा के अन्तर्गत पिछले दिनों में वर्ल्ड बैंक योजना के अन्तर्गत (1) गेता से बम्बूलिया (2) बोरदा से ढीपरी चम्बल (3) बोरदा से ककरावदा (4) गुडला रोड से नीमोला का रोड स्वीकृत किया गया था इसमें ठेकेदारों के द्वारा मात्र अर्थ वर्क तक का कार्य कर बाद में बन्द कर दिया गया व आज भी बन्द है ठेकेदार के द्वारा मनमानी की जा रही है। यहां तक की कार्य बन्द होने से लम्बे अर्से से ग्रामवासी परेशान हैं किसानों को अपना माल मण्डी तक पहुंचाने व आने जाने में विशेष परेशानी होती है।

अतः आप ग्रामवासी व जनहित की भावना को ध्यान में रखते हुये शीघ्र कार्य प्रारम्भ कर लोगों को राहत दिलाने का कष्ट करें।

———

राजस्थानी भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में सम्मिलित किया जाना

[श्री रिछपाल सिंह मिर्धा (डेगाना)]

उपरोक्त विषय में निवेदन है कि राजस्थानी भाषा 8 करोड़ लोगों की मातृभाषा है तथा स्वतंत्रता प्राप्ति को 50 वर्ष बीत जाने के बावजूद भी अभी तक इसको संविधान की आठवीं सूची में सम्मिलित नहीं किया जा सका है। जिससे इसको मान्यता प्राप्त नहीं हुई है। राजस्थान की जनसंख्या 5 करोड़ तथा अन्य प्रान्तों में रहने वाले प्रवासी राजस्थानियों की जनसंख्या करीब 3 करोड़ है इन सभी के द्वारा इस भाषा का प्रयोग नित प्रति दिन किया जाता है। कई अन्य प्रादेशिक भाषा में जिनको बोलने वालों की संख्या राजस्थानी बोलने वालों से कम होने के बावजूद भी मान्यता प्राप्त है। इस भाषा को संविधान की आठवीं सूची में शामिल करने के प्रबल

आधार है जो निम्न है :—

1. राजस्थानी भाषा राजस्थान की संस्कृति की नींव है।

2. इसका अपना बहुत बड़ा साहित्य है।

3. इस भाषा को केन्द्रीय साहित्य अकादमी नई दिल्ली द्वारा सन् 1972 में मान्यता प्रदान की गई।

4. यह भाषा प्रदेश के विश्व विद्यालयों में स्वतंत्र भाषा के रूप में अध्ययन की भाषा है।

5. आकाशवाणी जयपुर अजमेर से इस भाषा में प्रादेशिक समाचारों का प्रसारण प्रतिदिन नियमित रूप से होता है।

6. आकाशवाणी एवं दूरदर्शन से इस भाषा में अनेक कार्यक्रमों का प्रसारण प्रतिदिन नियमित रूप से किया जाता है। उदाहरणतया: करसारी बात, सहेलियां री बाडी, हुकारे बात, राजस्थानी गीत एवं भजनों के ग्रामोफोन रिकार्ड आदि।

7. राजस्थानी भाषा का स्वयं का विशालतम शब्द कोष है। जो राजस्थानी भाषा में लिया गया है "राजस्थानी सबद कोस" लेखक श्री सीताराम लालस।

8. राजस्थानी भाषा में अनेक फिल्मों का निर्माण हो चुका है तथा अनेक निर्माणाधीन है।

9. राजस्थान के विद्यालयों में कक्षा 11 एवं 12 में अध्ययन की स्वीकृत भाषा है।

इन सभी विशेषताओं और आधार को देखते हुए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी एवं शिक्षा मंत्री जी से पुरजोर शब्दों में मांग करता हूं कि राजस्थानी भाषा को संविधान के आठवीं सूची में सम्मिलित करने हेतु केन्द्र सरकार पर दबाव डाला जायें ताकि इस भाषा को मान्यता प्राप्त हो सकें।

खण्डेला उप तहसील की तहसील में क्रमोन्नति

[श्री महादेव सिंह (खण्डेला)]

प्रक्रिया के नियम 295 के तहत मैं लोकहित में राजस्व मंत्री जी का ध्यान खण्डेला उप तहसील को तहसील में क्रमोन्नत कराने की ओर आकर्षित करना चाहता हूं।

श्रीमान् खण्डेला पंचायत समिति के अन्तर्गत 40 ग्राम पंचायतें हैं, नगर पालिका है, थाना है, बिजली के सहायक अभियन्ता का कार्यालय है, जलदाय विभाग के सहायक अभियन्ता का कार्यालय भी है। अर्थात निवेदन करने का तात्पर्य यह है कि यहां की आबादी व क्षेत्र को देखते हुए समस्त सरकारी कार्यालय कार्यरत है।

मान्यवर, बड़े दुःख के साथ आपको यह जानकारी देनी पड़ रही है कि यहां स्थित उप तहसील को जनता द्वारा काफी प्रयास करने के बावजूद पूर्ण तहसील का दर्जा नहीं दिया गया है।

राजस्व मण्डल के माननीय अध्यक्ष महोदय ने भी यहां का दौरा कर इसे तहसील में क्रमोन्नत करने की सिफारिश की है किन्तु इसके बावजूद भी राजस्व विभाग अभी तक इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। मेरा आग्रह है कि राजस्व मंत्रीजी तत्काल इसकी घोषणा करने का कष्ट कर खण्डेला क्षेत्र की जनता की इस समस्या का निदान करने का कष्ट करें।

———

188

गंगरार की सड़कों का डामरीकरण

[श्री अर्जुनलाल जीनगर (गंगरार)]

उपरोक्त विषय में अनुरोध है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र की निम्न सड़कों को डामरीकरण की स्वीकृति के बाद भी दो-दो वर्षों से कार्य पूर्ण नहीं किया जा रहा है। वे स्वीकृत सड़कें निम्नानुसार हैं।—

1. सम्पर्क सड़क कुंवालिया
2. सम्पर्क सड़क सोनगर
3. सम्पर्क सड़क जारनी गोपालपुरा

अतः इन सड़कों को डामरीकरण करने का कष्ट करें।

निम्न पंचायत मुख्यालयों को डामरीकरण सड़कों से जोड़ने का श्रम करावें।

1. सम्पर्क सड़क सादी
2. सम्पर्क सड़क रूपनाथपुरा
3. सम्पर्क सड़क उण्डवा
4. सम्पर्क सड़क चोगावदी
5. सम्पर्क सड़क सालास
6. सम्पर्क सड़क सोमर वालों का खेड़ा
7. सम्पर्क सड़क बेवदा

माण्डलगढ़ नगरपालिका के गांवों को नगरपालिका से निकाल कर पंचायत बनाने के सम्बन्ध में

[श्री बद्रीप्रसाद गुरुजी (माण्डलगढ़)]

माण्डलगढ़ में कांग्रेस के प्रमुख लोगों को चेयरमैन बनाने की दृष्टि से आसपास के होड़ा, तिरोली, कलासिया, कर्णपुरा, बलदरखा, कोतवाल का खेड़ा, जुनुझारपुरा, रातया खेड़ा, मारजी का खेड़ा, धाकड़ खेडी, रामपुरिया, बिहारीपुरा, गेणोली आदि गांवों को मिला कर माण्डलगढ़ नगरपालिका का गठन किया गया जिससे ये गांव विकास के कार्यों से महरूम रह गये नगरपालिका के नियमों के कारण किसानों के लिए भयंकर समस्या पैदा हो गई 10 किलोमीटर तक नगरपालिका क्षेत्रफल हुआ है नगरपालिका की समुचित आय न होने से इन क्षेत्रों को विकास की मूलभूत सुविधाओं से भी वंचित होना पड़ रहा है।

समय–समय पर इन गांवों को निकाल कर गेणोली, बलदरखा होड़ा पंचायत बनाने की मांग मेरे द्वारा की जाती रही है उप खण्ड अधिकारी ने प्रस्ताव बना कर भी राज्य सरकार के निर्देश से राज्य सरकार को भिजवाये हैं परन्तु अभी तक परिणाम नहीं आया है।

अतः इन गांवों को निकाल कर बलदरखा, होड़ा, गेणोली पंचायतों का गठन कर जन जीवन को राहत प्रदान करायें।

————

(190)

गंगानगर शहर में आधारभूत सुविधाओं हेतु धनराशि की स्वीकृति

[श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर)]

महोदय;

मैं प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत माननीय वित्त मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि गत वर्ष भारत सरकार ने स्वैच्छिक आय योजना वी.डी.आई.एस. के अन्तर्गत करदाताओं को अपनी पिछली अघोषित आय को स्वीकृत करने के अलावा एक आय प्रलोभन दिया था कि उनको घोषित की हुई आय की 77.5 प्रतिशत आय उन्हीं के आधार भूत सुविधाओं जैसे सड़कें, सीवरेज, स्वास्थ्य, बिजली आदि उन्हीं के प्रान्त व शहरों में खर्च की जाएगी। श्री गंगानगर शहर में आधारभूत सुविधाओं की बहुत कमी है। श्रीगंगानगर के लोगों ने पूर्ण प्रयत्न कर राजस्थान राज्य की तरफ से इस शहर व जिले से इसमें पूर्ण सहयोग दिया था तथा राजस्थान राज्य में श्रीगंगानगर जिले ने अधिकतम राशि जमा करवाई थी और आशा की थी कि यह राशि वापसी इस शहर व जिले की आधारभूत सुविधाओं में खर्च की जाएगी, परन्तु ऐसा नहीं हो रहा है। राज्य सरकार ने प्रयास कर चार सौ इक्कीस करोड़ चौवन लाख की राशि भारत सरकार से प्राप्त की है जिसमें से लगभग 30 करोड़ की राशि वाले श्रीगंगानगर जिले की तरफ से योगदान दी हुई है।

श्रीगंगानगर जिला दान व सहयोग देने में सबसे अग्रणी है। जिले के विकास कार्यों हेतु यहां से लगभग तीस करोड़ रुपया टैक्स के रूप में भारत सरकार को वी. डी. आई. एस. में भरा है। शहर व जिले के विकास हेतु धन देने की तत्काल आवश्यकता है।

अतः मैं प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत माननीय वित्त मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि श्रीगंगानगर जिले की भावनाओं का आदर करते हुए यहां का दिया हुआ योगदान हिस्सा का रुपया यहां पर शहर व जिले की आधारभूत सुविधाओं पर खर्च करने का प्रावधान किया जाए। मैं आपका आभारी रहूंगा।

धन्यवाद।

——

गंगानगर के सीमावर्ती क्षेत्र में हदबन्दी में आयी भूमि का मुआवजा

[श्री हीरालाल इन्दोरा (केसरीसिंहपुर)]

महोदय,

उपरोक्त प्रक्रिया के अन्तर्गत नियम 295 के तहत मैं आपका ध्यान गंगानगर जिले के सीमावर्ती क्षेत्र के उन किसानों की ओर दिलाना चाहूंगा जिनकी कृषि भूमि सीमा पर की गयी तारबन्दी के अन्दर आ गयी है।

इस हदबन्दी में सीमा क्षेत्र के प्रत्येक काश्तकार की औसतन 3–4 बीघा जमीन आ गई है जिससे ये काश्तकार इस भूमि का पूरा लाभ नहीं उठा सकते हैं।

तारबन्दी में आने से उन्हें अपनी ही भूमि में काश्त करने देखभाल करने के लिए B.S.F. से पास या अनुमति लेकर आना जाना पड़ता है तथा सायंकाल के बाद वहाँ काश्तकार अपनी भूमि में नहीं रह सकता कई बार तो उसे वहां असुरक्षा भी महसूस होती है।

हदबन्दी में कृषक भूमि आने से सबसे अधिक नुकसान उन छोटे काश्तकारों को हुआ है जिनके पास थोड़ी भूमि है और उसका भी अधिकांश भाग हदबन्दी क्षेत्र में आ गया है।

सरकार को चाहिए कि ऐसे किसानों को उनकी तारबन्दी में आयी भूमि के बदले समुचित मुआवजा दिलवाये तथा इन्दिरा गांधी नहर क्षेत्र के अन्तर्गत कृषि भूमि दिलवाने की व्यवस्था करें। राज्य सरकार को इसके लिए भारत सरकार से ऐसे किसानों को मुआवजा दिलवाने की कार्यवाही सम्पन्न करवा कर राहत दिलानी चाहिए।

192

राजकीय चिकित्सालय, केकड़ी की क्रमोन्नति

[श्री शम्भूदयाल बड़गूजर (केकड़ी)]

मान्यवर;

उपरोक्त विषय के क्रम मे निवेदन है कि वर्तमान चिकित्सालय भवन लगभग 60 वर्ष पुराना है। बढ़ती हुई आबादी को दृष्टिगत रखते हुए चिकित्सालय में प्रति दिन 300 रोगी आउटडोर तथा भर्ती रोगी 70–80 रहने के कारण भीड़ बनी रहती है। इसके अतिरिक्त सघन आबादी के बीच हो जाने से चारों तरफ अशान्त वातावरण तथा गन्दगी बनी रहती है। स्थानीय केकड़ी नगर की आबादी लगभग 30,000 तथा क्षेत्रीय (उपखण्ड) आबादी लगभग 1 लाख पच्चीस हजार करीब है, टोडारायसिंह एवं भिनाय तहसील क्षेत्र की जनता भी इसी चिकित्सालय से चिकित्सा सुविधा प्राप्त कर रही हैं जिनके लिए वर्तमान चिकित्सालय भवन एवं 50 रोगी शय्याएं अपर्याप्त हैं। साथ ही इस भवन में आगे बढ़ोतरियां ऊपर की मंजिल बनाना सम्भव नहीं है। अतः उक्त समस्या को मध्य नजर रखते हुए इस चिकित्सालय को 100 रोगी शय्याओं का करवाकर नया चिकित्सालय भवन बनाना आवश्यक है।

उक्त समस्या को मध्य नजर रखते हुए राजकीय चिकित्सालय सलाहकार समिति, केकड़ी द्वारा चिकित्सालय हेतु नये भवन के अजमेर रोड पर केसोलाव के पास स्थिति खसरा नं. 4324/2 में खाली पड़ी भूमि में 25 बीघा भूमि आवंटन हेतु प्रस्ताव किया गया है। उक्त 25 बीघा भूमि जिला कलक्टर, अजमेर द्वारा आरक्षित कर दी गई है।

जिला कलक्टर अजमेर के समसंख्यक क्रमांक 166267 दिनांक 23-2-96 के द्वारा केकड़ी के खसरा नं. 4324/2 रकबा 40-02, 10 बीघा में से 2500-00 बीघा भूमि नवीन चिकित्सा भवन निर्माण हेतु सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, केकड़ी के पक्ष में आरक्षित की जा चुकी है जिसकी पत्रावली शासन उप सचिव, राजस्व (ग्रुप–3) विभाग, जयपुर में लम्बित है।

अतः उपरोक्त नवीन चिकित्सालय भवन के निर्माण हेतु सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा नीलामी की आवश्यक कार्यवाही कर राज्य सरकार द्वारा इस प्राप्त

धन राशि को राजकोष में जमा न करवाकर केवल नया चिकित्सालय भवन बनाने के लिए उपयोग में लेने का स्पष्ट प्रावधान करवाने की कृपा करावें ।

अतः आपसे सादर अनुरोध है कि उपरोक्त परिस्थितियों को मध्य नजर रखते हुए राजकीय चिकित्सालय, केकड़ी को निम्नलिखित स्वीकृति प्रदान करवाने की कृपा करावें :-

1. नवीन चिकित्सालय भवन निर्माण हेतु प्रस्तावित 25 बीघा भूमि को आवंटन की स्वीकृति प्रदान करावें । उप शासन सचिव, राजस्व (ग्रुप-3) से ।

2. राजकीय चिकित्सालय, केकड़ी को 100 रोगी शय्याओं हेतु क्रमोन्नत करने के आदेश प्रदान करावें ।

3. पुराने अस्पताल भवन नीलाम (आक्सन) करवाने की स्वीकृति के साथ आक्सन से प्राप्त राशि को नये चिकित्सालय भवन निर्माण हेतु ही आरक्षित करवाने के आदेश प्रदान करावें ।

————

डूंगरपुर में प्रशिक्षित अध्यापकों को रोजगार

[श्री नाथूराम अहारी (डूंगरपुर)]

डूंगरपुर जिले में प्रशिक्षित अध्यापक हजारों की संख्या में भटक रहे हैं साथ ही प्रशिक्षित अध्यापक जब हजारों की संख्या में भर्ती मात्र सैकड़ों की संख्या में हो रहे हैं। प्रशिक्षित अध्यापकों को सबको नौकरी नहीं दे पा रहे हैं तो फिर हम ट्रेनिंग क्यों दे रहे हैं ? श्रीमान् एक बुराई और बढ़ गई है कि ट्रेनिंग होने के बाद भी हम इण्टरव्यू ले रहे हैं यह तरीका भी रिश्वत लेने, समय बरबाद करने और धन का दुरुपयोग करने का रास्ता ढूंढ निकाला है। डूंगरपुर पिछले माह जिला परिषद में अध्यापकों के इण्टरव्यू लिये थे रिक्त स्थान मात्र 110 के अन्दर थे और फार्म 1800 के करीब थे जब आपके पास रिक्त स्थान कम हैं तो इतने ज्यादा लोगों को बुलाने का क्या कारण है, यह गरीब बेरोजगार व्यक्तियों के पैसा तथा समय का दुरुपयोग किया जा रहा है। श्रीमान् जो प्रशिक्षित अध्यापक भी है, उनकी योग्यता के अनुसार लिस्ट बनाकर नौकरी दिलाने की व्यवस्था की जाये और जितनी जगह है उससे 10 प्रतिशत ही ज्यादा व्यक्तियों को बुलाया जाये ताकि जन, धन व समय का दुरुपयोग नहीं होगा।

धन्यवाद।

जनगणना महिला कर्मचारियों को कनिष्ठ लिपिक पद पर तदर्थ नियुक्ति

[श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (जोधपुर)]

जनगणना विभाग में कार्यरत महिलाओं को दो वर्ष की सेवा अवधि के पश्चात् सन् 1994 में छंटनी कर दी गई। इन महिलाओं में राज्य लोक सेवा आयोग आयोजित विशेष भर्ती कनिष्ठ लिपिक परीक्षा सन् 1996 में पास कर ली थी। टंकण की परीक्षा भी इन महिलाओं ने पास कर ली थी परन्तु टंकण परीक्षा में इनकी गति कुछ कम आंकी गई थी और इसी कारण इन्हें वापस सेवा में ही नहीं लिया गया।

महोदय इन महिलाओं ने समय समय पर माननीय मुख्य मंत्री महोदय को भी प्रतिवेदन भेजे हैं और मैंने भी समय-समय पर माननीय मुख्य मंत्री महोदय से इनकी समस्या के समाधान हेतु निवेदन किया है परन्तु अभी तक भी इनकी समस्याओं का समाधान नहीं हो सका है।

मान्यवर, इन सभी महिलाओं की उम्र 40-45 वर्ष की है और इस उम्र में इनको रोजगार से अलग किये जाने से इनका परिवार भारी संकट में पड़ गया है। पूर्व में भी सरकार द्वारा ऐसी महिलाओं की समस्याओं के समाधान हेतु छंटनी शुदा जनगणना कर्मचारियों को तदर्थ नियुक्तियां की गई थी।

मेरा आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन है कि महिलाओं की ओर विशेष ध्यान देकर इन छंटनी महिला जनगणना कर्मचारियों को तदर्थ आधार पर कनिष्ट लिपिक पद पर नियुक्त करने की व्यवस्था करवाये। इन महिलाओं की संख्या भी लगभग चालीस है। जिस कारण राज्य पर भी कोई अनावश्यक बोझ पड़ने वाला नहीं है।

सादर।

——— ——

196

खरेडा ग्राम तहसील, टोडारायसिंह में चरागाह भूमि पर प्रतिक्रमण

[श्री बनवारीलाल बैरवा (निवाई)]

उपरोक्त विषय में ग्राम खरेडा तहसील, टोडारायसिंह में लगभग 1400 बीघा चरागाह भूमि पर ग्राम के कुछ लोगों ने नाजायज प्रतिक्रमण कर रखा है। उक्त भूमि में से 300 बीघा भूमि बीसलपुर परियोजना के विस्थापितों को प्रावंटित की गयी थी। इन विस्थापितों की ग्राड में यह लोग नाजायज रूप से 3 वर्षों से लगातार काश्त कर रहे हैं। ग्रामवासियों द्वारा लगातार शिकायत करने के उपरान्त भी संबंधित ग्रधिकारियों ने ग्रब तक कोई ठोस कार्यवाही नहीं की है ग्रौर केवल कागजों में ही चरागाह को प्रतिक्रमण से मुक्त किया जाता है। यह लोग लगातार 2–2 फसलें ले रहे हैं।

चरागाह में प्रतिक्रमण करने से ग्रामवासियों के खेत ग्रौर खलिहानों की ग्रोर जाने वाले रास्तों पर भी प्रतिक्रमण कर लेने से किसान ग्रपने खेतों ग्रौर खलिहानों में भी नहीं जा सकते हैं ग्रौर जानवरों के भूखे मरने की नौबत ग्रा गई है। यदि उक्त चरागाह भूमि को प्रतिक्रमण से मुक्त नहीं कराया गया तो किसी भी समय ग्राम में ग्रप्रिय घटना घटित हो सकती है ग्रौर वातावरण दूषित हो सकता है।

चरागाह भूमि पर प्रतिक्रमण करने वाले निम्न व्यक्ति हैं :—

(1) श्री शम्भुदयाल पारीक, भा.ज.पा. ग्रध्यक्ष	7 बीघा पर	प्रतिक्रमण
(2) श्री दशरथ धोबी पुत्र श्री केसरा धोबी	20 बीघा ,,	,,
(3) श्री कस्तुरा खटीक पुत्र श्री भूरा खटीक	18 बीघा ,,	,,
(4) श्री जगदीश पुत्र भूरा खटीक	5 बीघा ,,	,,
(5) श्री भैरू गुर्जर पुत्र कालू गुर्जर	10 बीघा ,,	,,
(6) श्री बिरधा खटीक पुत्र हरदेवा खरेडा	5 बीघा ,,	,,

(7) श्री रामकिशन कुमावत पुत्र कल्याण रघुनाथपुरा 15 बीघा

(8) श्री रामलाल कुमावत पुत्र जगन्नाथ रघुनाथपुरा 8 बीघा

(9) श्री रतन कुमार पुत्र रामलाल रघुनाथपुरा 6 बीघा

(10) श्री रोडु कुमावत पुत्र श्री सुवा 5 बीघा

(11) श्री घासी कुमावत पुत्र गोरू रघुनाथपुरा 15 बीघा

(12) श्री सुखदेव कुमावत पुत्र किशना रघुनाथपुरा 5 बीघा

(13) श्री जगदीश कुमावत पुत्र पोखर रघुनाथपुरा 15 बीघा

(14) श्री बाबूलाल पुत्र श्री गोरू गूजर 5 बीघा

अतः इस प्रस्ताव के माध्यम से माननीय राजस्व मंत्री एवं मुख्य मंत्री का ध्यान आकर्षित कर निवेदन करता हूं कि इस प्रतिक्रमण को मुक्त कराया जावे ताकि ग्रामवासियों को अपने खेत एवं खलिहानों में आने जाने में कोई परेशानी नहीं हो तथा मवेशियों के भी चरने की व्यवस्था हो सके ।

————

डूंगरपुर जिले के पिथापुर व पालिसोडा ग्राम में सड़क नहीं होने से उत्पन्न स्थिति

[श्री शंकरलाल अहारी (चौरासी)]

डूंगरपुर जिले में गुजरात के अन्तिम सीमा पर स्थिति ग्राम पिथापुर पंचायत घुण्डावाड़ा व ग्राम पालिसोडा पंचायत गैंढ में आने जाने का कोई भी मार्ग नहीं है। इन दोनों ग्रामों में रोड़ नहीं होने से वहां का नागरिक राज्य सरकार से मिलने वाली हर योजना से वंचित रह जाता है वह किसी भी योजनाओं से नहीं जुड़ पाये हैं। यह निश्चित है कि ये दोनों ग्राम पहाड़ी क्षेत्र में आते हैं। ये दोनों ग्राम पंचायत समिति बीछीवाड़ा के अन्तर्गत आते हैं। इन्हें अक्सर डूंगरपुर व पंचायत समिति में सरकारी काम व अपने कार्य से जब आना जाना होता है तो काफी परेशानियां होती है।

अतः मैं माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्री का इन ग्रामों में सड़क निर्माण करवाने हेतु अनुरोध/निवेदन करता हूं।

———

कृषि उपज मण्डी द्वारा निर्मित सड़कों के संधारण का अभाव

[श्री गोपीराम (आमेर)]

कृषि मण्डी को गांवों से जोड़ने के लिए सम्पर्क सड़कों का निर्माण कृषि उपज मण्डी समिति द्वारा करवाया जाता है जिससे किसानों को शहर की ओर आने में सहूलियत रहे एवं वह अपनी उपज मण्डी में लाकर बेच सके जिससे उनको उनकी उपज का वाजिब दाम मिल सके। किन्तु जयपुर जिले के आमेर विधान सभा क्षेत्र में कृषि उपज मण्डी द्वारा सड़कों का निर्माण तो करवा दिया गया किन्तु उनके रख रखाव की सही व्यवस्था नहीं होने से इन सड़कों की हालत खराब है वहां वाहन तो क्या पैदल भी चलना मुश्किल है। रात्रि में प्रकाश की माकूल व्यवस्था न होने से आये दिन इन खराब सड़कों पर दुर्घटना होती रहती है। आमेर विधान सभा क्षेत्र की जिन सड़कों की हालत खराब है या जो मरम्मत के कारण अनुपयोगी हो गयी है। उनका मैं उल्लेख करना चाहूंगा।

1. खोरा बीसल से चतरपुरा खराब सड़क 1.65 किलोमीटर राशि की मांग 2.65 लाख।

2. जालसू से खनीपुरा-श्रीपुरा तक खराब सड़क 1.1 कि. मी. राशि की मांग 2.90 लाख।

3. खोरा बीसल से रोजदा खराब सड़क 2.2 कि.मी. राशि की मांग 3.35 लाख।

4. राजावास नांगल से चोप खराब सड़क 2.2 कि.मी. राशि की मांग 3.35 लाख।

5. रोड़ नं. 17 से प्रखेपुरा वाया प्राकेड़ा 10 कि.मी. 1 लाख।

6. रिपेयरिंग सी.डी. वर्क 6 लाख 300 मीटर मोसिंग 1.70 लाख।

7. बिलोची से श्री गोविन्दपुरा खराब सड़क 1.90 कि.मी. मांग 50 हजार।

8. मोड़ी से सिरसली वर्क्स एण्ड मोसिंग पर व्यय की मांग 1.25 लाख है।

उपरोक्त सभी सड़कों का निर्माण मण्डी समिति, लाल कोठी द्वारा करवाया गया था एवं इनकी पूर्व में मरम्मत एवं रख रखाव मण्डी समिति, लाल कोठी द्वारा ही किया जाता था। किन्तु सरकार ने अपनी नीति से परिवर्तन कर वर्तमान में इनकी मरम्मत व रख रखाव पी.डब्ल्यू.डी. द्वारा किया जाता है एवं राशि कृषि उपज मण्डी समिति द्वारा उपलब्ध करवायी जाती है। प्रथम बार यहां यह भी मैं उल्लेख करना चाहूंगा कि नांगल राजावास से चोप जो खराब सड़क है उसमें प्राधे कि.मी. तक बरसात में पानी भर जाता है एवं यहां से पैदल भी चलना मुश्किल हो जाता है। यही हालात खोरा बीसल से रोजदा शुभरामपुरा सड़क की है यहां भी पानी भर जाता है।

प्रतः मैं इस विशेष उल्लेख के माध्यम से राज्य के कृषि विपणन मंत्री का ध्यान प्राकर्षित करना चाहता हूं और प्राशा करता हूं कि वह इस संबंध में शीघ्रता शीघ्र कार्यवाही करेंगे।

(200)

अलवर शहर में सड़कों की खराब हालत

[श्रीमती मीना अग्रवाल (अलवर)]

निवेदन है कि अलवर शहर में सड़कों की हालत बहुत खराब है जिसमें बड़े-बड़े गड्ढे हैं और सड़क टूटी फूटी खस्ता हालत में है जिसके कारण आये दिन दुर्घटनाएँ होती हैं और लोगों को शारीरिक व आर्थिक हानि होती है। सड़कों को ठीक कराने के वास्ते पी. डब्ल्यू. डी. या यू. आई. टी. अथवा नगर परिषद को कहा जाता है तो वे एक दूसरे विभाग का नाम लेते हैं और कहा जाता है कि यह मेरे क्षेत्र में नहीं है दूसरे विभाग के क्षेत्र में है अतः वो ही विभाग इसकी मरम्मत करवायेगा।

सड़कों के खराब होने के बारे में वहां की जनता ने अलवर के एक न्यायालय में सरकार, पी. डब्ल्यू. डी., यू. आई. टी. व नगर परिषद के खिलाफ भी मुकदमा भी चला रखा है। जिसे करीब तीन माह हो चुके लेकिन विभागों ने कोई सन्तोषजनक जवाब या कार्यवाही नहीं की है।

शहर में बस्तियों, स्कीमों और पुल के नीचे भी कई सड़कें काफी समय से रोड़ियों की बनी हुई पड़ी हुई हैं जिनकी रोड़ियां भी वापस उखड़ने लगी हैं लेकिन अभी तक उन पर डामर नहीं किया गया है। जो भी मरम्मत या तारकोल लगाकर मरम्मत आदि की जाती है वह ऐसी की जाती है कि कुछ दिनों में ही वापस उखड़ने लग जाती है। कई बार विभागों को रुपये दिये जाने के बाद भी विभाग सड़कों का कार्य नहीं करते और प्रशासन व विभाग अखबारों में जनता को गुमराह करते हैं कि यह सड़क अभी बनेगी लेकिन उसका कार्य होता ही नहीं है। अलवर राजस्थान का और राष्ट्रीय राजधानी का एक मुख्य शहर है जिसके लिये पहले भी माननीय मंत्री महोदय ने तुरन्त सड़कों की मरम्मत कराने और निर्माण कराने का सदन में एक बार आश्वासन भी दिया था लेकिन मेरे बार-बार उनसे अनुरोध करने पर भी अलवर की शहर की सड़कों का कार्य नहीं किया गया है। इसी प्रकार अलवर के आठ प्रमुख चौराहों पर जिनमें कि भारी ट्रैफिक रहने के कारण बड़े-बड़े गड्ढे आज भी बने हुए हैं उन पर रबड़ मेटिंग बिछाने के वास्ते पी. डब्ल्यू. डी. विभाग ने करीब 12 लाख रुपये का एस्टीमेट सरकार को प्रेषित किया और जिसके लिये मैंने भी मंत्री

महोदय से अनेक बार निवेदन किया लेकिन यह कार्य भी आज तक नहीं किया गया है। और सड़कों के बारे में कभी भी इन विभागों द्वारा कोई जानकारी मांगी जाती है तो कोई जवाब नहीं दिया जाता है ।

सड़कों का निर्माण कार्य स्टेण्डर्ड के मुताबिक नहीं किया जाता तथा सड़कें कुछ ही समय बाद पुनः खराब हो जाती हैं।

मेरा आपसे बार-बार आग्रह है कि अलवर शहर की सड़कों को तुरन्त प्रभाव से ठीक करवाया जावे तथा इसमें लिप्त अधिकारियों को अतिशीघ्र स्थानान्तरित कर अन्यत्र भेजा जावे ।

आदर सहित ।

नगर पालिका, बड़ी सादड़ी के अध्यक्ष के लिये हुए उप चुनाव, में राजनैतिक दखल

[डा. शंकर भानुवा (कपासन)]

महोदय,

नगर पालिका, बड़ी सादड़ी जिला चित्तौड़गढ़ में दिनांक 20–7–98 को अध्यक्ष के लिये चुनाव होना था। वहां पर 7 सदस्य भा. ज. पा. के 7 ही कांग्रेस के व एक निर्दलीय पार्षद था । अगर चुनाव निष्पक्ष होता तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उम्मीदवार श्री लालचन्द की जीत सुनिश्चित थी। परन्तु ऐन वक्त पर स्वायत शासन विभाग, जयपुर से एक फेक्स संदेश चित्तौड़गढ़ जिला कलक्टर के पास आया जिसे कलक्टर ने बड़ी सादड़ी पालिका सभा कक्ष में पीठासीन अधिकारी के पास पहुंचाया। यद्यपि तयशुदा कार्यक्रम के अनुसार उक्त संदेश के बड़ी सादड़ी पहुंचने के 15 मिनट पहले ही मतदान का समय शुरू हो चुका था पर चूंकि तब तक किसी सदस्य ने अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया था अतः मतदान की प्रक्रिया को बीच में रोक कर

202

फैक्स संदेश का परिसंज्ञान लिया गया और जब श्रीमती शांति चौधरी मतदान करने लगी तो उसे रोक दिया गया।

उधर मतदान का परिणाम जानने की लालसा में खड़ी जनता ने सुना कि सत्ता का दुरुपयोग कर अलोकतंत्रीय व अवैधानिक कार्यवाही कर प्रजातंत्र का हनन किया गया है तो वह भड़क उठी। बड़ी मुश्किल से ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष श्री प्रकाश चौधरी व अन्य वरिष्ठ नागरिकों ने उग्र जन समूह को समझा-बुझा कर शांत किया। परन्तु स्थिति अभी भी विस्फोटक बनी हुई है जनता को रोष है कि पूर्व अध्यक्ष श्री तरुण मेहता ने दिनांक 10-6-98 की तीसरी बैठक की सूचना जानबूझकर श्रीमती शांता चौधरी को नहीं दी जिससे वह बैठक में भाग नहीं ले पाई। तथा दिनांक 23-3-98 वाली बैठक की सूचना प्राप्ति पर श्रीमती चौधरी की जगह फर्जी तरीके से संजय मेहता के हस्ताक्षर करवा लिये। इस प्रकार फर्जी दस्तावेज तैयार कर श्रीमती शांता चौधरी को मतदान की प्रक्रिया के दौरान निलम्बित करने की गैर कानूनी कार्यवाही के प्रति प्रबुद्ध जनता में भारी रोष है और मैं प्रस्ताव करता हूं कि इस तरह की जाल साजी करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाय व लोकतंत्र के हित में उक्त चुनाव को निरस्त कर नगरपालिका, बड़ी सादड़ी के अध्यक्ष के चुनाव विधिपूर्वक कराये जाये।

———

203

मुस्लिम शिक्षण संस्थानों में अध्यापिकाओं का शोषण

[श्री शैलेन्द्र जोशी (बांदीकुई)]

स्थानीय मुस्लिम शिक्षण संस्थाओं (अन्जुमन तालेमूल मुस्लेमीन शिक्षण संस्थान) में लम्बे समय से निर्वाह भत्ता के रूप में अध्यापिकाओं का शोषण व उत्पीड़न चला आ रहा है। उक्त संस्थाएं शिक्षा विभाग से अनुदानित शिक्षण संस्थाओं की श्रेणी में है। जहां 70 से 90 प्रतिशत अनुदान राशि शिक्षा विभाग द्वारा स्वीकृत की जाती है।

स्टाईफण्ड टीचर्स के रूप में बीस-तीस साल से कार्यरत अध्यापिकाओं को 500-900 रुपये प्रतिमाह दिये जाते हैं इनकी संख्या 80-85 है। शिक्षा अधिकारियों की मिली भगत के कारण प्रबन्धक समिति बदस्तुर शोषण करती जा रही है। सचिव ही प्रबन्ध समिति में सर्वेसर्वा है क्योंकि अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष सहित चार पदाधिकारी स्वर्ग सिधार चुके हैं विगत 10 वर्षों से प्रबन्ध समिति का चुनाव नहीं हुआ है फिर भी शिक्षा अधिकारी इस शिक्षण संस्थाओं को अनुदान स्वीकृत करते आ रहे हैं।

अतः इस प्रस्ताव के माध्यम से माननीय शिक्षा मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित कर निवेदन करता हूं कि शिक्षण संस्थाओं में विभाग का अपना प्रशासक नियुक्त करें उनकी देखरेख में ही नई प्रबन्ध समिति का चुनाव कराया जावे साथ ही तथाकथित स्टाईफण्ड टीचर्स को उनकी योग्यता अनुसार गैर सरकारी समिति शिक्षा अधिनियम के आधार पर वेतन निर्धारित किया जावे।

जाट जाति को राज्य में अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण

[श्री जगदीप धनखड़ (किशनगढ़)]

निवेदन है कि प्रक्रिया के नियम 295 के तहत मैं सरकार का ध्यान राज्य में जाट जाति के साथ भेदभाव पूर्ण रवैये अपनाते हुए इसे अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण न दिये जाने की ओर आकर्षित कर रहा हूं।

1. मान्यवर, उच्चतम न्यायालय के निर्णय में जो मापदण्ड निश्चित किए गए

है उनके आधार पर जाटों को राज्य में अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण मिलना न्याय संगत होगा।

2. अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण जिन किसान जातियों को प्रान्त में दिया गया है जाटों का उनसे हुक्का पानी का सम्बन्ध रहा है। वे सभी एक ही सामाजिक जाजिम पर बैठते रहे हैं। जाट जाति वर्षों तक सामन्ती व्यवस्था की पीड़ा सहती रही है।

3. सरकारी तंत्र में जाट जाति का प्रतिनिधित्व भी इस जाति की जनसंख्या के अनुपात में नगण्य है। गत 50 वर्षों में राज्य में एक दर्जन आई.ए.एस. व आइ.ई.एस. अधिकारी भी इस जाति के सीधी भर्ती से नहीं आए हैं।

4. 1995-96 में प्रदेश भर में जाट जाति ने जगह–जगह सभाएं कर अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण का मामला उठाया था। जाट जाति के नवयुवक अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण न मिलने से पीड़ित है और आंदोलित हैं। उनके हितों पर भारी कुठाराघात है। उनके लिए अब सरकारी तंत्र में नौकरी पाना असंभव हो गया है।

राजनीतिक क्षेत्र में भी जाटों को अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण न देने से विसंगति उत्पन्न हो गई है जो इस वर्ग में भारी असंतोष को जन्म दे रही है।

5. दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि सुनवाई होने के बाद सरकारी उदासीनता के कारण जाट जाति को अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण राज्य में नहीं दिया जा रहा है।

6. राज्य के अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने जनवरी, 1996 में जाट जाति को अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण देने सम्बन्धी रिपोर्ट प्रेषित की थी। अत्यन्त पीड़ा का विषय है कि उक्त रिपोर्ट पर वांछित कार्यवाही नहीं की गयी।

7. मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि राज्य में जाटों को अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण अविलम्ब प्रदान करें।

————